Sixth Series, Vol. VI No. 4

Thursday, November 17, 1977
Kartika 26, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

4(7) 3
6 12 82

(Vol.VII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 4 00

CONTENTS

No. 4, Thursday, November 17, 1977/Kartika 26, 1899 (Saka)

COLUMNS

Oral Answers to Questions :

*Starred Questions Nos. 61, 62 and 64 to 66. 1—29

Written Answers to Questions :

Starred Questions Nos. 63 and 67 to 80. . 29—47

Unstarred Questions Nos. 601 to 613, 615 to 621, 624 to 676, 678 to 685, 687 to 724, 726 to 733, 735 to 767, 769, 771, 772 and 774 to 800. 47—224

Question of Privilege Against Shrimati Indira Gandhi and others 225—52

Papers laid on the Table . . 253—56

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Reported assault by R.S.S. workers on Shri Damodaran Nair, a Guide of Gandhi Smriti. . . . . 256—86

Committee on Papers Laid on the Table—

(i) Minutes 286

(ii) First Report 286

Public Accounts Committee—

Sixteenth Report 286

Railway Convention Committee—

First Report . . 286

Committee on Absence of Members from the Sittings of the House

Third Report 287

Business Advisory Committee—

Sixth Report 287

Matters under Rule 377—

(i) Statements made by two Central Ministers about Chief Minister of Tamil Nadu . . . . . 287—92

(ii) Working of Grindlay's Bank, Ltd. . . . . 292—93

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Motion *re.* Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
and
Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services against Reserved Quota . . . . 293—350

Shri Kachrulal Hemraj Jain . 294—99

Shri Ram Lal Rahi . . . 299 –308

Shri Eduardo Faleiro . . . . 308—313

Prof. P. G. Mavalankar . . 313—320

Shri L. L. Kapoor . 230—328

Shri Mahi Lal . . 328—341

Shri K. Pradhani . 342—346

Father Anthony Murmu . 346—350

Shri C. N. Visvanathan . . 350

LOK SABHA

Thursday, November 17th, 1977/Kartika 26, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Malaria Epidemics in Delhi

*61. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA:
SHRI GANGADHAR APPA BURANDE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the report that Malaria has broken out as an epidemic in Delhi;

(b) the total number of cases registered so far including those with the private doctors; and

(c) the steps taken to eradicate Malaria from the country?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) 1977 के दौरान दिल्ली में मलेरिया बहुत अधिक रहा है । तथापि, सितम्बर, 1977 के पिछले सप्ताह से मलेरिया के प्रकोप में कमी हुई है ।

(ख) अक्तूबर, 1977 के अन्त तक 1,68,729 रोगी दर्ज किए गये थे । प्राइवेट डाक्टरों द्वारा कितने रोगियों का इलाज किया गया, इस की सरकार को कोई जानकारी नही है ।

(ग) एक विवरण जिसमें इस रोग के उन्मूलन/नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन किया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मलेरिया के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :—

1. पहली अप्रैल, 1977 से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक संशोधित कार्य योजना लागू की जा रही है । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मलेरिया का उन्मूलन करना ही है जिसे वर्तमान में भी जारी रखने का विचार है ।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के मौजूदा यूनिटों को जिलों की भौगोलिक सीमाओं के अनुरूप पुनर्गठित कर दिया गया है । जिला के कार्यक्रम के लिए जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है ।

3. अपेक्षित किस्म की कीटनाशी दवाइयां अधिक मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के अन्तर्गत दी जा चुकी हैं / दी जा रही हैं।

4. ऐसे सभी देहाती क्षेत्रों में जहां एक हजार जनसंख्या के पीछे दो या दो से अधिक मलेरिया की घटनाएं हुई हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

5. राज्य / संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी औषधियों पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। औषधि डिपो / औषधि वितरण केन्द्र / बुखार उपचार केन्द्र खोल दिए गए हैं; जहां से लोगों को मुफ्त मलेरिया-रोधी औषधियां आसानी से मिल सकती हैं। ऐसे कुछेक क्षेत्रों में जहां पर जीवियों पर क्लोरिक्विन प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है, वहां कुनीन जैसी अन्य मलेरिया-रोधी दवाइयां दी गई हैं।

6. शहरी मलेरिया क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्य बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही 28 नगरों में कार्य चल रहा है और इनके अलावा 1977–78 के दौरान 38 और नगरों में भी इस योजना को आरम्भ कर दिया गया है।

7. रक्त लपों के शीघ्र परीक्षण के लिए और पाजिटिव रोगियो का शीघ्र इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

8. फील्ड स्टाफ का सुपरवीजन तेज कर दिया गया है।

9. मलेरिया में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए कदम उठाए गए है।

10. **पी० फाल्सीपरम** के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में गहन अभियान प्रारंभ कर दिया गया है।

11. इस बीमारी के बारे में स्वास्थ्य-शिक्षा देने और इस पर काबू पाने के लिए पंचायतों, स्कूल-अध्यापकों, विद्यार्थियों, युवा-संगठनों, चिकित्सकों आदि जैसे सार्वजनिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए है।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने सभा पटल पर जो विवरण रखा है उसमें 11 आइटम्स दिये गये है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आइटम नं० 4, 7, 9, 10 और 11 में जो कहा गया है क्या इस पर इमप्लीमेंटेशन होता है, इसकी उनको जानकारी है? जब इतने स्टैप्स लिये जाते है फिर भी मलेरिया बढ़ रहा है इसकी **क्या वजह है?**

श्री राज नारायण : जो कुछ सूचना हमने दी है एक से लेकर 11 तक सभी की जांच की जाती है और सब अपनी जगह पर यथा स्थान उचित कार्य करते हैं।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : आइटम 10 में मंत्री जी ने बताया है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की मदद से इंटेन्सिव केम्पेन शुरू किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब से शुरू हुआ है और कब तक जारी रहेगा?

श्री राज नारायण : जो प्रश्न माननीय सदस्य पूछ रहे है उसका उत्तर मैं बहुत थोड़े

में दिये देता हूं "सीता कर दुःख विपद विशाला, बिन हि कहे भल दीन दयाला"। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि सीता का कैसा हाल है, तो हनुमान जी ने कहा कि उसके दुःख को न जानिये यही अच्छा है। तो इसी प्रकार मलेरिया को न छूना ही अच्छा है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने पूछ ही लिया है कि मलेरिया की स्थिति क्या थी, कैसे थी, कब थी, तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि पूरा विवरण सदन के पटल पर रखें और सम्मानित सदस्य पूरी जानकारी से अवगत हो जायें।

MR. SPEAKER: Your first answer was very brief. I thought you would be brief.

श्री राज नारायण : कोशिश करूंगा कि ब्रीफ़ में कहूं। सीता कर दुःख विपद विशाला, बिन ही कहे भल दीन दयाला। यह हनुमान जी राम चन्द्र जी से बोले है। भारत में मलेरिया जन-स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या रही है। देश में 1953 से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के शुरू होने से पहले प्रतिवर्ष अनुमानित 7 करोड़ 50 लाख लोगों को यह रोग होता रहा है। और महामारी के दौरान रोगियों की संख्या इससे दुगुनी होती जाती है। मलेरिया से अनुमानतः 8 लाख लोग प्रति वर्ष मरते थे। इस रोग की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार की स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति ने 1946 में सिफारिश की थी कि सारे देश में एक मलेरिया विरोधी संगठन की स्थापना की जाये। अप्रैल, 1953 में भारत सरकार ने द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के सहयोग से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नाम से एक व्यापक छिड़काव कार्यक्रम शुरू किया। इसके पर्याप्त उत्साहवर्द्धक परिणामों के साथ साथ इस आशंका से कि रोगवाहक मच्छरों में कीट-नाशक दवाओं को हज्म करने की शक्ति पैदा हो जायेगी, भारत सरकार ने 1958 में इसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया। इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भारत अग्रणी रहा है और इसने इस बारे में सारे विश्व का निश्चित नेतृत्व किया है।

सम्मानित सदस्य जरा ठीक से सुनें, हम रात को मेहनत करते हैं। 1958 से 1965 तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने संतोषजनक रूप से प्रगति की। 1965 में कोई मृत्यु नहीं हुई और करीब-करीब रोग खत्म हो गया।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: Is he answering or making a speech?

SHRI RAJ NARAIN: I am giving the information to the House. You do not want to hear the information.

1958 से 1965 तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने संतोषजनक रूप से प्रगति की और इसके जो परिणाम निकले थे, वे बहुत ही असाधारण थे।

MR. SPEAKER: Give substance.

SHRI RAJ NARAIN: I am giving substance.

अब 1965 के बाद आ गया 1966 तो मैं यह कहना चाहता हूं,

श्री वसन्त साठे : 1965 का क्या करना है, अभी तो मलेरिया ब्रेक हुआ है, उसको बताइये।

MR. SPEAKER: Why do you have malaria in the House?

श्री राज नारायण : यह आदरणीय सम्मानित सदन है, इसको किसी राजनीतिक दल का अखाड़ा न बनाइये। यह मलेरिया सारे देश में फैला हुआ है।

1965 में कोई मौत नहीं हुई। अब आ गया 1966, सम्मानित सदस्य जान लें कि 1966 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी का नेतृत्व आ गया । 1966 से ही मलेरिया प्रगति पर है । 1974, 1975 और 1976 का एमर्जेंसी के दौरान का भी पढ़ देता हूं । 1974 में 31,67,658 लोग मलेरिया रोग से ग्रस्त हुए, और तीन मौतें हुई हैं । 1975 में 51 लाख 66 हजार 142 लोग इस से ग्रस्त हुए और 99 मौतें हुई । 1976 में 6 लाख 49 हजार 481 लोग ग्रस्त हुए और 40 मौतें हुई हैं । सितम्बर तक इस साल जब से जनता पार्टी का शासन आया है, सात महीने समझ लीजिए, इन सात महीनों में 3 लाख 21 हजार 864 लोग इससे ग्रस्त हुए । यानी घटाव पर मलेरिया को हम ले जा रहे हैं । ईमानदारी से हम लोगों को सोचना चाहिए, 73, 74, 75 और 76 में पूर्ण रूपेण छिड़काव बन्द हो गया । सारे साधन जुटा कर लगा दिए गए कम्पल्सरी स्टेरिलाइज़ेशन में । मैंने सब राज्यों के हेल्थ डाइरेक्टरों की मीटिंग की इस के लिए कि मलेरिया बढ़ा क्यों ? सभी राज्यों के हेल्थ डाइरेक्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में हम ने यह पूछा कि मलेरिया बढ़ा क्यों तो लोगों ने बताया कि 73, 74, 75 और 76 में सारे जितने सरकारी साधन थे सब जबर्दस्ती नसबन्दी में लगा दिए गए । डी डी टी का छिड़काव बिलकुल बन्द कर दिया गया । मलेरिया मारक दवाओं का छिड़काव बन्द कर दिया गया इसलिए मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया ।

SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA: After the come-back of malaria epidemic particularly because of DDT resistence of the mosquitoes, the epidemic is developing throughout India, not only in Delhi but also in the eastern parts of India and in the tribal areas, and in view of that, may I know from the hon. Minister whether he is sufficiently confident that by his energetic work that he is doing he will be able to check the spread of malaria epidemic throughout India and, secondly, whether he is aware of the fact that in New York and Washington, the immunity and vaccination systems have been developed, and, if so, whether we are doing sufficient research work to develop vaccination for malaria resistence?

श्री राज नारायण : श्रीमन, जहां डी डी टी काम नहीं करती वहां बी एच सी का छिड़काव करते हैं । यह दवा हैं जिस से मलेरिया के कीटाणु मरते हैं .....

श्री वसंत साठे : आयुर्वेद की ?

श्री राज नारायण : अगर आयुर्वेद का मज़ाक कर के देश के विकास को प्रगति की दिशा में ले जाना चाहता है विरोध पक्ष तो मैं चह्वाण साहब से कहूंगा कि क्यों विरोध पक्ष के नेता बने हुए हैं ? छोड़ दें । रोजाना बम्बई से, महाराष्ट्र से आयुर्वेद के उद्घाटन के लिए हमारे पास लोग आते हैं । आज भी चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं ...

MR. SPEAKER: Please don't reply to any interruption; you just answer the question.

श्री राज नारायण : जहां जहां जिन दवाओं की कमी हो रही है उन दवाओं को नया बनवाने के लिए भी हम ने काम शुरू कर दिया है । इस सम्बन्ध में मैं आप को आगे बताऊंगा जब कालाज़ावर के सम्बन्ध में प्रश्न आयेगा । इस समय इतना ही काफ़ी है ।

हमारे मित्र ने पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आप को क्या मदद दी है ? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हम को 2.92 लाख डालर्स की मदद दी है, इस का हिसाब रुपयों में आप लगा लीजिए, क्योंकि डालर का भाव घटता-बढ़ता रहता है ।

SHRI BEDABRATA BARUA: I hope you will ask the Minister to answer the relevant part of the question. So far as national context is concerned, he has not answered that part. I don't think he has answered at all what steps are going to be taken. My main question is about the mosquitoes in Delhi. They have made a come back to Delhi; from the time the Janata Government started the activities of the mosquitoes have also started. By now they are in good form and are spreading everywhere. You know anti-malaria oil is not available and no action has been taken. The drains are full of mosquitoes. I hope the Minister will say something about it and not refer to Mrs. Indira Gandhi or such other things. These mosquitoes are very much there. Why are they not sprinkling anti-malaria oil over the drains that are lying open everywhere?

MR. SPEAKER: You can avoid mentioning about Janata Government. He can avoid mentioning about Indira Gandhi.

श्री राज नारायण : कभी-कभी कोई मनुष्य भी कीटाणु का काम करता है। इसी लिए इन्दिरा जी चव्हान सहाब के लिए सब से बड़ी मलेरिया की कीटाणु बन गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस साल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश भयंकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहे हैं। इतनी ज्यादा बाढ़ आई है कि कहा नहीं जा सकता। इसी तरह तमिलनाडू में बड़ा भारी तूफान आया है, हम ने वहां की सरकार से पूछा है—हालांकि उन्होंने हम से नहीं पूछा—कि वे हम को बतलायें कि हम किन-किन और कितनी दवाओं से उन की मदद करें .....

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM: About the present position of Tamilnadu, our Chief Minister has already sent two letters. (*Interruptions*) He says that they have not received anything from our State. Then there was cyclone in our State. We are going to send, after assessing the entire loss about this cyclone, to the Government of India a statement showing the total loss and other details. In spite of all these things, he says that he has not received anything from Tamilnadu. He has got personal enmity towards our State. Only one hour is allotted for Question Hour and he has already taken a lot of time only for this single question. Tamilnadu is a part of India. (*Interruptions*)

SHRI C. N. VISVANATHAN: They have already sent two letters mentioning the present position of Tamilnadu. Then there was cyclone in our State. They are going to send a statement showing the entire loss. In spite of all these things, he says that they have not received anything from Tamilnadu. (*Interruptions*)

श्री राज नारायण : मैंने जो कहा है—उस में कोई पाप नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है। वहां के स्वास्थ्य सचिव के पत्र को भी मैं वहां के चीफ मिनिस्टर का पत्र मानूंगा। वे कह कर गये हैं कि हम पूरा ब्यौरा भेजेंगे। अगर मेरे मित्र नहीं जानना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमिलनाडू दवाओं के रूप में जो भी सहायता चाहेगा, वह हमारी सरकार देगी।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, 1976-77 के दौरान दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका को सप्लाई की गई सामग्री यह है :—एम० एल० ओ० : 698 किलोग्राम, पेरिसग्रीन: 1700 किलोग्राम, मिट्टी का तेल : 28 किलोग्राम, पेरोसीन एक्सट : 10,000 लिटर, पिरेथ्रम : 900 लिटर और बेटेक्स : 1,000 लिटर।

PROF. P. G. MAVALANKAR: May I submit that 20 minutes have already

passed and still the first Question is going on. Should we not try to cover more Questions? Our names come in the ballot and still our questions are lost!

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : जो डी० डी० टी० पहले छिड़की जाती थी, उस में ज्यादा असर रहता था। क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे कि डी० डी० टी० अब असर क्यों नहीं रखती है ?

श्री राज नारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस से पहले दिल्ली के बारे में जो सवाल पूछा गया था, आप ने उस का जवाब पूरा नहीं होने दिया।

MR. SPEAKER: Please answer his question.

श्री राज नारायण : अगर मलेरिया के कीटाणुओं के पैदा होते ही तत्काल उन्हें मार दिया जाये, तब तो वे मर जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें बढ़ने दिया जाये, तो उन में बाहरी दवाओं के प्रति रेसिस्टेंस की शक्ति बढ़ती है।

मलेरिया के कीटाणुओं में रेसिस्टेंस की शक्ति बढ़ गई है। यही कारण है कि डी० डी० टी० आदि का उन पर कोई असर नहीं होता है।

आनन्द मार्गियों द्वारा विदेशों में भारतीयों पर आक्रमण

+

*62. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे अनेक दूतावासों को न केवल धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं बल्कि विदेशी आनन्दमार्गियों द्वारा हमारे दूतावासों के अधिकारियों पर आक्रमण की घटनाएं भी हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) अब तक कुल मिला कर 12 मिशनों में धमकी भरे पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ii) आक्रमण की वारदातें हमारे कैनबरा और लंदन स्थित मिशनों में तथा एअर इंडिया मेलबोर्न में ही हुई है।

(ग) सम्बद्ध मिशनों ने अपनी-अपनी आतिथेय सरकारों के साथ कर्मचारियों और सम्पति के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध उठाया है। विदेश-स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों/कार्यालयों को यह परामर्श दिया गया है कि वे विभागीय सुरक्षा अनुदेशों का पालन करें तथा स्थानीय विदेश कार्यालय और सुरक्षा अभिकरणों से निकट सम्पर्क रखें। कल कुआला-लम्पुर में एयर इंडिया के कार्यालय में जो घटना हुई है, मैं उस का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं। एयर इण्डिया का दफ्तर चौदह-मंजिला इमारत में है। वहां शौचालय में एक टाइम बम पाया गया। तत्काल पुलिस को खबर दी गई लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह बम फट गया। एअर इंडिया का एक कर्मचारी घायल हुआ है। जिन्होंने बम रखा उनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। बम के साथ कोई पत्र नहीं था लेकिन आज सवेरे कुआलालंपुर स्थित भारतीय हाई कमीशन को एक चिट्ठी मिली है जो यूनिवर्सल प्राऊटिस्ट रेवोल्यूशनरी

फडरेशन की ओर से लिखी गई है। उसमे कहा गया है कि अगर सरकार को छोड़ा नहीं जायेगा तो हमारे प्रधान मंत्री, श्री मोरा जी देसाई की जान खतरे में है। लेकिन इस पत्र में एयर इंडिया के दफ्तर में हुए विस्फोट का हवाला नहीं है यद्यपि सम्बन्ध स्पष्ट है।

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। अभी जैसा माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 12 विदेशी मिशनों में धमकी भरे पत्र मिले हैं, दूसरे स्थानों पर भी इस तरह की घटनायें घट रही हैं, मेरा मन्त्री जी से निवेदन यह है कि जब यह स्पष्ट है कि इन सारी घटनाओं के पीछे आनन्दमार्गियों का हाथ है और वे सब हमारे देश के आनन्दमार्गी हैं जो कि सब कुछ कर रहे है तो इस तरीके के आतंकवादी संगठन के खिलाफ सरकार कोई निश्चित कार्यवाही करे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, विदेशों में जो घटनायें हो रही हैं जिनके अन्तर्गत हमारे कर्मचारी घायल हुए है और हमारे कार्यालयों पर हमले हुए हैं —स्वाभाविक रूप से वह सरकार के लिए और इस सदन के लिए तथा सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन से भी सम्पर्क स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक विशेष सेल कायम किया गया है जो सारे मामले पर कठोर नजर रख रहा है और सुरक्षा की कार्यवाहियां कर रहा है। विदेशों में होने वाली इन घटनाओं के प्रकाश में भारत में क्या किया जाए, यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी है दूतावासों के वे बड़े आतंकित है, भयग्रस्त है इसलिए अकेले वहां की सरकार को कह देने मात्र से क्या उनकी सुरक्षा हो जाएगी? इस संबंध में निश्चित कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे उनके अन्दर जो आतंक और भय व्याप्त है वह दूर हो सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं होगा कि विदेशी मिशनों में स्थित भारतीय कर्मचारियों में बड़ा आतंक है। सच्चाई तो यह है कि उनका मनोबल बड़ा ऊंचा है और बड़ी हिम्मत के साथ वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हमने उनकी सुरक्षा के प्रबन्ध किए है लेकिन एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि यह दूतावास जिन देशों में है उन देशों की सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है कि हमारे दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करें। अपनी ओर से जो इन्तजाम सम्भव है वह हम कर रहे है। हमने उसको और भी कड़ा बनाने का फैसला किया है।

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: May I know from the Hon. Minister whether, in view of the fact that there is threat of attack on about 12 foreign Missions abroad, any arrest has been made so far in this connection? The Minister has just now said that they have been taking precautionary measures and are in contact with foreign countries. I would like to know the reaction of the foreign countries. How far are the cooperative in trying to find out the culprits and in trying to see that such things are put an end to?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We are getting full cooperation from

the foreign Governments concerned. In one case, which was a case of serious nature, Col. Ekbal Singh was stabbed in the chest while he was asleep in his house and then attempts were made to kidnap him. The culprit has been arrested. He is a 26 years old Australian and he has confessed to the crime, giving the non-release of Shri P. R. Sarkar as the motive.

श्री ब्रजभूषण तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि विदेशों में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उन को करने वाले क्या भारत के लोग है या विदेशों के विदेशी लोग हैं और क्या यह किसी बड़े अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का परिणाम है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय इन सब घटनाओं से विदेशी सम्बद्ध है पर इन विदेशियों के पीछे कौन भारतीय हैं इस की हम जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

श्री सोमजी भाई डामोर : अध्यक्ष महोदय हमारे मंत्री जी जब से विदेश मंत्री बने है, वे ज्यादातर विदेशों में रहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन को भी क्या खून की धमकी मिली है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या यह कोई प्रश्न है ? इन्होंने यह क्या पूछा है ?

MR. SPEAKER: This is not a relevant question.

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या विदेश मंत्री जी को इस बात की जानकारी हो गई है कि आनन्द मार्ग की जो संस्था है और जिसके अन्तर्गत यह प्राऊटिस्ट ब्लाक टेररइज्म कर रहा है, इसका स्पष्ट सम्बन्ध इन्टरनेशनल टेरोरिस्टस से हो गया है और उसको वे लोग फाइनेन्स कर रहे हैं जिन का आइडिया फिलीपीन्स से ले कर दूसरे सारे देशों में टेररइज्म फैलाने का है ? यदि सरकार को यह जानकारी हो गई है, तो इस पर भारत सरकार क्या विचार कर रही है और इसके बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी सरकार के लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि ये हमले प्राऊटिस्ट ब्लाक के अतिरिक्त किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रेरित है। तथ्यों का पता लगाने के लिए हम जांच पड़ताल कर रहे है और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम बताएंगे।

SHRI EDURADO FALEIRO: All these threats are to the effect that unless Shri P. R. Sarkar is released unconditionally, they will put these threats in execution. All of us know and the country knows that these are from the Proutist organization, which is the inner core of the Anand Marg and who does this job. In the past, big eminent people including the Chief Justice of India, the Home Minister and the head of the Customs have been connected with Anand Marg. Why is this Government not banning Anand Marg and this Proutist Organization which is committed to violence? Is it because of some pressure which is being brought by the high-ups in the Government who are members of this organization?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Government is not under any pressure from any quarter. The hon. Member has made a suggestion for action which will be considered.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने

धमकी भरे पत्र जिन संगठनों से मिले हैं, क्या उन संगठनों से बातचीत करने की कोशिश सरकार ने की है ? यदि बातचीत की है तो क्या बातचीत की है मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो धमकी भरे पत्र मिले हैं यें क्या उन्हीं संगठनों ने दिए हैं या उन का नाम ले कर किसी दूसरे संगठन या व्यक्ति ने लिखे हैं ? इन बातों की जांच पड़ताल क्या सरकार ने की है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अनेक धमकी भरे पत्र जो मिले हैं, उन में भेजने वाले का नाम नहीं है, पता नहीं है। फिर उन से कैसे बात की जा सकती है और कहां बातचीत की जा सकती है, यह पता लगाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन विदेशों में जो आनन्द मार्गी हमारे दूतावासों के सामने प्रदर्शन करने के लिए आते है , उन्हें हम समझाने का प्रयत्न करते हैं कि श्री सरकार का मामला अदालत में पड़ा हुआ है और इसलिए भारत सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। हम उन से यह भी कहते हैं कि भारत सरकार इस तरह की धमकियों या हिंसात्मक कार्यवाहियों के सामने झुकेगी नहीं।

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: From the reports so far available, it appears that these incidents are happening exclusively and solely in the Commonwealth countries. Is it a mere accident or coincidence or is there any deeper reason for that? When I said solely and exclusively, there may be one or two exceptions, but, by and large, the vast majority of these incidents are happening in the Commonwelath countries. Is it a mere accident or coincidence or is there any deeper meaning in it and if so, will the hon. Minister make a thorough inquiry into it?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I promise to make a thorough inquiry into the matter suggested by the hon Member.

SHRI RAM JETHAMALANI: Can I ask the hon. Minister whether he will be prepared to give an assurance to the House that he will not follow in the footsteps of Mrs. Gandhi and ban any organization until he gets..

Interruptions.

Try to learn the rule of law. It is never too late to learn. Try to understand what democracy and rule of law are ..... (*Interruptions*). I have no. completed my question.

Will the hon. Minister be prepared to assure this House....

MR. SPEAKER: Mr. Ravi, please keep quiet. Otherwise they will also shout.

SHRI VAYALAR RAVI: What is he talking? Our people are dying abroad..... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: In this House everybody has a right to express his opinion and nobody can object to that. you cannot expect him to speak to your liking.

SHRI RAM JETHMALANI: I want an assurance if he is prepared to extend it, that he will not ban any organization whether it be Ananda Marg or any other organization and no decision will be taken against any organization whether it be Ananda Marg or any other organization unless there is clear evidence of their involvement in criminal activities.

श्री उग्रसेन : ये शोर मचा रहे हैं, इसको तो आप रोकिये ।

SHRI RAM JETHAMALANI: They are not prepared to learn democracy even now.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Normally, the government is averse to

ban any organization because government believe that organizations should be fought politically and with the support of the people.

So far as the question of Ananda Marg is concerned, the question should be directed to my colleague, the Home Minister. As for Foreign Minister, I am not in a position to reply to that question.

MR. SPEAKER: Next question, Shri Bhagat Ram. He is absent.

SHRI SAMAR GUHA: rose

MR. SPEAKER: No, please. I have gone to the next question.

SHRI SAMAR GUHA: This is not really fair.

बिहार में डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

*64. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे डाकघरो का दर्जा बढ़ाकर सब-पोस्ट आफिस कर देने की योजना सरकार के विचाराधीन है जो वर्षों से नियमानुसार कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के सहरसा जिले में गांव चौसा, पुरैनी और ग्वालपुर के डाकघर का दर्जा बढ़ाकर सब-पोस्ट आफिस बना दिया जाएगा और उनमें तार और टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : (क) शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें विभागीय मानदंडों और निधियों के निर्धारण के अनुसार उप-डाकघर बनाया जाता है। वर्ष 1977–78 के दौरान देश भर में 200 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप-डाकघर बनाने की योजना है।

(ख) चौसा का डाकघर पहले से ही एक उप-डाकघर है और वहां तार सुविधा उपलब्ध है। उस डाकघर में टेलीफोन की सुविधा देने का प्रताव मंजूर कर लिया गया है। सहरसा जिले के चौसा उप-डाकघर के साथ पुरैनी शाखा डाकघर का लेखा-संबंध है। पुरैनी डाकघर का दर्जा बढ़ाने के मामले की जांच की जाएगी। पुरैनी में तार सेवा पहले से ही उपलब्ध है और वहां टेलीफोन सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।

ग्वालपुर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव की भी पहले जांच कराई गई थी किन्तु उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ था। इस मामले की फिर से जांच कराई जाएगी। ग्वालपुर में तार और टेलीफोन की सुविधाएं देने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : इन्होंने अभी बताया है कि लगभग दो सौ डाकघरों में टेलीफोन और तार की सुविधा प्रदान की जाएगी और उनको सब पोस्ट आफिसिस में कवर्ट करने की योजना है। सुदूर देहातों में इ को खोलने या कनवर्ट करने के बारे में क्या कुछ जन संख्या निर्धारित की है और कहा है कि इतनी जनसंख्या के ऊपर जहां पो ट आफिस पहले से ही कार्यरत है उनको सब-पो ट आफिसि में कनवर्ट कर दिया जाएगा या वहां फोन और तार की सुविधा दे दी जाएगी।

श्री बृजलाल वर्मा : जी हां । डाकखाने खोलने की जो योजना है उस में आठ बातों का ख्याल रखा जाता है जिस में से जनसंख्या भी एक है । वहां खर्च और आमदनी का भी ख्याल किया जाता है । पास में डाकखाना है या नहीं और कितनी दूरी पर है इसका भी ध्यान रखा जाता हैं । कोशिश यह की जाती है कि दो हजार की पापुलेशन में डाकखाना खुल जाए । ऐसे गांव जहां पर दो हजार की पापुलेशन नजदीक-नजदीक है उनका भी ख्याल किया जाता हैं और वहां भी डाकखाना खोलने की कोशिश की जाती है । इसके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि डाकखाना ऐसी जगह होना जरुरी है जहां पर स्कूल हो, ब्लाक हो लोकल बोर्ड द्वारा और कोई वहां पर संस्थाऐं हों और ऐसी जगह भी डाकखाना खोलने की हम सुविधा देते हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डाकखाने खोले जाते हैं ।

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : पुरैनी, चौसा और ग्वालपार जिनकी चर्चा की गई है मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर तार की सुविधा पहले से उपलब्ध थी । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जो ब्यान दिया गया है वह सही नहीं है, जो जानकारी इन्होंने मंगाई है मालूम पड़ता है कि उसमें दोष है, वहां पर तार की व्यवस्था नहीं थी । पुरैनी, चौसा और ग्वालपार सहरसा जिले के अन्तर्गत हैं । वहां सड़कों की सुविधा उपलब्ध है, बसें आती जाती हैं । डाक की व्यवस्था नौगछिया से चौसा को है जो कोसी नदी के उस पार है तो क्यों नहीं इसको सहरसा से सम्बद्ध कर दिया जाता है ? चूंकि ऐसा नहीं किया गया है इसीलिए इनफॅर्मेशन में गड़बड़ी हुई है । मैं चाहता हूं कि पुरैनी , चौसा और ग्वालपार के बारे में जो वस्तुस्थिति है उसको देख करके सहरसा से डायरेक्टली सम्बद्ध करके वहां पर सब पोस्ट आफिस की सुविधा दी जाए । आज लोगों को दस दस मील तार देने के लिए जाना पड़ता है, बिहारी-गंज जाना पड़ता है । इसलिए इन तीनो का सम्बन्ध सहरसा से करके तीनों को सब पोस्ट आफिसिस में कनवर्ट करके वहां पर तार और टेलीफोन की क्या सुविधा प्रदान की जाएगी ?

श्री बृजलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौसा में सब-पोस्ट आफ़िस आलरेडी है, और पुरैनी नाम के दो स्थान हैं, एक पुरैनी है और दूसरा पुरैनी बाजार है । दोनों स्थानों में से पुरैनी में ब्रांच पोस्ट आफ़िसेज़ हैं । बाजार गणेशपुर में से आधा किली मीटर की दूरी पर है और गणेशपुर पर ब्रांच पोस्ट आफिस है । डाकखाना खोलने के प्रस्ताव की भी जांच की गई है कि हमें वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा । पहली जांच 1971 और दुबारा 1973 में की गई उस से पता चला है

MR. SPEAKER: You cannot read out the whole thing. You must give the substance.

SHRI BRIJ LAL VERMA: I am just informing him of that.

MR. SPEAKER: You must read that at home and give the substance.

श्री बृजलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन दोनों गांवों के बारे में फिर से जांच करा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वह चाहते है वह कैसे हम उन को दें ।

श्री छविराम अर्गल : दो हजार की आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जहां पर पंचायत कार्यालय हैं, थाना है, लेकिन टेलिफोन और पोस्ट आफिस की सुविधा नहीं है क्या इस को वहां पर उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री बृज लाल वर्मा: मैं जानना चाहता हूं कि हमारी योजना है कि सारी ग्राम पंचायतों में हम 10 वर्षों में पोस्ट आफिस खोल दें । अभी तक बहुत सी ग्राम पंचायतों में, और बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों में पोस्ट आफिसेज नहीं हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री : क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जितने भी डाकखाने खुले हुए हैं उन में अगले दो सालों में तार सम्बन्ध स्थापित हो जायगा ?

श्री बृज लाल वर्मा : तार का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हम ने एक अलग योजना बनायी है और उस के अन्तर्गत जितने भी ढाई हजार और पांच हजार आबादी के गांव हैं उन सब में हम तार की योजना दो साल के अन्दर पूरी कर देंगे ।

SHRI VIJAYKUMAR N. PATIL: May I konw from the hon. Minister whether he is thinking of reducing the rates of telephone connections in the rural areas, which are from urban exchanges? Secondly, may I know the number of the PBX Centres which are proposed to be opened next year?

श्री बृज लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय , हम दो साल के अन्दर गांवों के अन्तर्गत 4,000 पी० सी० ओज खोल रहे हैं ।

Opening of New Post Offices in Maharashtra

*65. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is a shortage of Post Offices especially in rural areas and in backward localities of the urban areas in several districts of Maharashtra;

(b) if so, whether Government propose to open new Post Offices in the State in the near future i.e. within a year; and

(c) if so, the details thereof?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) सरकार डाक सुविधाओं के अभाव से पूरी तरह परिचित है । अब ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । इस से डाक सुविधाओं का अभाव भी सुनियोजित ढंग से दूर हो रहा है ।

(ख) और (ग) नए डाकघर खोलने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं । ये मानदंड पूरे होने और निधियां उपलब्ध होने पर नए डाकघर निरन्तर खोले जा रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 236 डाकघर और शहरी क्षेत्रों में 20 डाकघर खोल दिये जाएं । इन के अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में चलते फिरते डाकघरों के जरिए 3000 अतिरिक्त गांवों में डाक सुविधाएं दी जाएंगी तथा गांवों में 5000 लेटर बक्स लगाए जाएंगे ।

SHRI R. K. MHALGI: May I know from the hon. Minister in how many villages in Maharashtra State such post offices had been opened since the last thirty years?

SHRI BRIJ LAL VERMA: I have not got the figures with me at present. But, I can say that in all Gram Panchayats of your State, within ten years. there will be post offices.

SHRI R. K. MHALGI: My second supplementary is this. I want to know whether the mobile post offices

in bicycles will be in addition to tempo and taxi post offices.

SHRI BRIJ LAL VERMA: We are giving postal facilities in 3,000 villages this year only in Maharashtra.

SHRI R. K. MHALGI: My question is: whether the mobile post offices include Tempo and Taxi Post offices also apart from the bicycles post offices.

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, डाक की सुविधाएं सिर्फ शहरों और बड़े लोगों के लिये शुरु से हैं, वह चाहे शहनशाही जमाना हो या कोई दौर हो और चाहे आज, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वह जो लम्बे प्रदर्शनी के पुराने तरीके थे, उन से बदलकर, बड़ पैमाने के नहीं, गांधी जी के विचार से छोटे पैमाने पर, ऊपर से नहीं, नीचे से, चाहे एक गांव में एक घर भी हो, वहां लैटर बाक्स लगें और वहां डाकिया, साइकिल पर या पैदल, रोज लोगों को तार और चिट्ठी पहुंचाये, क्या ऐसा प्रोग्राम सरकार बनाने वाली है या नहीं ?

मंत्री जी ने जो 5 हजार लैटर बाक्स लगाने की बात कही, क्या वह इस सदन को और इस सदन के द्वारा देश को यह विश्वास देंगे कि हर जगह लैटर बाक्स लगेगा और रोज डाकिया उस में से चिट्ठियां ले जायेगा ? कम-से-कम यह सुविधा होगी या नहीं ?

श्री ब्रज लाल वर्मा : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि इस साल इसी फाइनेन्शियल ईयर में हो हम एक लाख गांवों में लैटर बाक्स दे रहे हैं और इस वर्ष हम 50 हजार गांवों में आल पोस्टल फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो कि गत 10 वर्षों में भी नहीं हुआ था । उस के बाद जैसी की सदस्य की मान्यता है कि हम गांव की ओर ध्यान अवश्य दें, उसी ख्याल से सारी चीजें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे है कि ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को फैसिलिटीज मिलें ।

श्री फिरंगी प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने नये डाकखाने खोलने के लिए जो नियम या मापदंड बनाये हैं, वे क्या हैं । क्या जनप्रिय सरकार उन्हें और सरल बनाने की व्यवस्था करेगी, ताकि आम जनता को पत्र आदि नियमित रूप से मिलते रहें ?

श्री ब्रजलाल वर्मा : अभी तक जो व्यवस्था है, उस के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल 96 परसेंट गांवों में रोज डाक आदि मिल सके । इसके अलावा हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गांवों में अपनी सुविधायें दे सकें । माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट आफ़िसिज खोलें । इस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद : नये डाकखाने खोलने के बारे में जो मापदंड रखा गया है, मैंने उस के विषय में पूछा हैं ।

Reorganization of G.S.I.

*66. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether a high-power Committee has been constituted for the reorganisation of the Geological Survey of India; and

(b) if so, what is its composition?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the information is laid on the table of the House.

Statement

The composition of the Committee is as follows:

1.	Dr. A. K. Ghosh, Additional Secretary, Department of Mines, Ministry of Steel & Mines	Chairman
2.	Dr. A. B. Das Gupta, Retd. Managing Director Oil India Ltd.	Vice Chairman
3.	Dr. G. R. Udas, Director, Atomic Minerals Division, Atomic Energy Commission	Member
4.	Shri K. R. Parameshvar, Chief Planning and Development, Bharat Heavy Electricals Ltd.	Member
5.	Shri N. T. Srinivasan, Chief, Management Services, Bharat Heavy Electricals Ltd.	Member
6.	Dr. M. V. N. Murthy, Deputy Director General. Geological Survey of India.	Member
7.	Dr. Hari Narain, Director, National Geophysical Research Institute	Member
8.	Shri G. Ghosh, Deputy Secretary, Department of Mines, Ministry of Steel & Mines	Member Secretary

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के साथ जो सूची रखी है, उस से पता चलता है कि इस कमेटी में बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं है । मैंने उन्हें इस सम्बन्ध में पहले ही लिखा था कि पटना यूनिवर्सिटी के श्री आर० सी० सिंहा को, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के जियोलिजिस्ट हैं, इस समिति में सम्मिलित करना चाहिए । बिहार में अभी तक 56 परसेंट मिनरल्ज का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, क्योंकि पिछले 125 वर्षों से यह आफ़िस कलकत्ता में पड़ा हुआ है और उस में बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं है । 1968 में बिहार में एक रिजनल आफ़िस के खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । यद्यपि खनिज सम्पदा के मामले में बिहार सारे भारत में सब से आगे है, लेकिन इसी कारण आज तक उस की खोज नहीं हो सकी है । क्या मंत्री महोदय रांची में रिजनल आफ़िस खोलने के लिए तैयार हैं ?

SHRI BIJU PATNAIK: I would like to assure the hon'ble Member that the issue is much larger than opening a regional office at Ranchi or Patna. The entire matter of Geological Survey of India—which is a 125 years old organisation—is being critically reviewed and Government will take decision in various sectors of the Geological Survey of India after the report of the High-Powered Committee is received.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह डिसिज़न कब तक लिया जायेगा?

SHRI BIJU PATNAIK: I expect the report to be available with the Government by the end of this year after which the Government will take the necessary decision.

SHRI SAMAR GUHA: I would like to know from the hon'ble Minister whether the union of the Geological Survey of India have placed a memorandum before the hon'ble Minister giving their viewpoints in regard to the enquiry? There are so many other institutions—Central Government institutions—concentrated in different parts of India like all the financial institutions which are concentrated in Bombay. Whether it is a fact that some lobby is working that because the Geological Survey of India is having its headquarter in Calcutta for the last 120 years, it should be shifted from that city? Whether the hon. Minister will take a view that because certain institutions are there in certain regions other aspects will be taken into consideration before applying this principle? Whether in the case of financial institutions which are located in other parts of India, the same attitude will be shown?

SHRI BIJU PATNAIK: I will certainly keep the hon. Member's view point in my view.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Economic and Political Relations with West Asian and North African Countries

*63. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any efforts to expand economic and political relations with West Asian and North African countries were made recently; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) Government attaches the highest importance to consolidating, expanding and diversifying India's political and economic relations with the West Asian and North African countries. The Minister for Works & Housing and Minister of Industry, have, over the past two months, visited various countries in this region as the Prime Minister's special emissaries. These visits have given a new impetus to our political and economic relations with these countries.

I may add that the Indo-Iranian Joint Commission met in New Delhi in September 1977, and in June and November 1977 the third and fourth sessions of the Indo-Iraqi Joint Commission have taken place. These meetings have been highly fruitful. Finally, I may mention that this month the annual Haj delegation has left for Saudi Arabia led by Shri Arif Baig, Minister of State for Commerce, Civil Supplies and Cooperation.

Bangladesh Propaganda against India

*67. SHRI S. R. DAMANI:
SHRI SAMAR GUHA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Bangladesh have accused India of complicity in the recent upsurge in that country;

(b) if so, the reaction of Government; and

(c) the action taken to clarify the actual position as far as India is concerned?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The official version of a statement made by the President of Bangladesh in Dacca on 11 October,

1977 contained references implying involvement of India in the incidents that took place in Bogra and Dacca in Bangladesh on 30th September and 2nd October, 1977.

(b) and (c). The matter was taken up immediately with Government of Bangladesh which has assured the Government of India that there has been no intention on the part of Bangladesh Government to imply India's involvement in these inncidents.

संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री द्वारा हिन्दी में भाषण दिया जाना

*68. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिन्दी में दिया था ;

(ख) यदि हां, तो अन्य राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) क्या सरकार अपने उन अधिकारियों को, जो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से संम्बद्ध हैं, इस आशय का निदेश देने की स्थिति में है, कि वे सदैव हिन्दी का उपयोग करें ।?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जी. हां ।

(ख) इस तथ्य पर व्यापक रूप से ध्यान दिया गया कि महासभा के अधिवेशन में पहली बार हिन्दी में भाषण दिया गया ।

(ग) सभी सरकारी अधिकारियों से यह प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान हो और जो भी भाषा वे सुविधाजनक पायें उसका प्रयोग कर सकें ।

Integrated Leprosy Control Programme

*69. SHRI R. D. GATTANI:
SHRI UGRASEN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the integration of leprosy, control programme with general health services relating to multipurpose workers scheme has aroused opposition from the National Leprosy Organisation, Wardha;

(b) whether the National Leprosy Advisory Committee was consulted before this policy decision was taken; and

(c) whether leprosy programme is not like malaria, family welfare or small pox programmes which can be integrated and that the country still needs a vertical leprosy control programme?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) Yes, Sir.

(b) Since integration of all health programmes including Leprosy, Cholera, T.B., Malaria etc. were concerned it was not considered necessary to consult only the National Leprosy Advisory Committee before taking the policy decision.

(c) Leprosy control work will not be integrated with the general health services in the entire country for the present. The intention is that all health programmes will be integrated with the Multi-purpose Workers Schemes in the districts taken up for the implementation of that scheme but the scheme itself will be introduced progressively only in the districts where Leprosy and other public health problems are not in hyper-endemic stage. In other dis-

tricts, Leprosy will continue as a vertical programme.

Legislation to repeal the provision of Pension to Former M.Ps.

*70. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have now considered the question of pensions to former Members of Parliament being eliminated or increased;

(b) if so, the facts thereof, including the manner in which Government propose to implement their decision and when;

(c) if not, reasons therefor; and

(d) whether Government propose to bring forward during the Winter Session, 1977 the legislation for repeal of the provision of pensions to former M.Ps. and if so, broad indications thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). Representations have been received both for repealing the provisions regarding the granting of pension to ex-Members of Parliament and also for liberalising them. The whole matter is still under consideration of the Government. A decision will be taken after Government has had discussion with the Leaders of opposition parties/groups in the two Houses.

Kala Azar in States

*71. SHRI RAJ KESHAR SINGH:
SHRI AHMED HUSSAIN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the incidences of Kala-azar in Bihar, U.P., Gujarat, West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra and Assam;

(b) the number of casualties reported from each of the above States; and

(c) the steps taken by Government to resolve the problem on a national level?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). A statement containing the required information is laid on the table of the Sabha.

(c) Another statement indicating the steps taken to resolve the problem is laid on the table of the Sabha.

Statement

No. of States	Incidence of Kala-Azar and number of casualties reported				Deaths
	No. of cases				
	1974	1975	1976	1977	
Assam	..	4	4		
Tamil Nadu	14	11	14		..
Gujarat	1	1	3	..	2 cases reported during 1976.
West Bengal		75	53	62	..
Bihar	40	822	1587	12667	153

No cases of Kala-Azar have been reported from Maharashtra.

Statement

Steps taken by Govt. to resolve the problems of Kala-Azar on national level

(1) Under the Modified Plan of Operation of the National Malaria Eradication Programme, appropriate type of insecticide is supplied to areas which have two or more cases per thousand population for under taking spray. This automatically comes as a preventive measure for Kala-azar also.

(2) A central Kala-Azar Survey Team has been approved to assess the siuation of Kala-azar in the country.

(3) Production of Antimony Compound, the drug normally required for Kala-azar has been stopped up.

(4) For a few cases which do not respond to treatment by Antimony Compounds Pentamindine vials have been procured as assistance from W.H.O. They are being sent to the affected areas of West Bengal and Bihar.

Participation of Labourers in Management

72. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have adopted any policy for the participation of labourers in the management on different Public Sector Undertakings;

(b) if so, the number of such public undertakings where the labourers have taken such part ; and

(c) the number of such undertakings where the labourers have not taken part and the reasons therefor?

THE MINISTER OF PRALIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a). Government introduced in October 1975 a Scheme for Workers' Participation in Industry in manufacturing and mining units and another in January 1977 in commercial and service organisations in the public sector. The whole policy on workers' participation is now under review by a Committee.

(b) and (c). According to available information almost all eligible Central public sector units numbering 545 have either implemented the Scheme of October 1975 or initiated steps to do so or have made alternative arrangements.

बिहार में अभ्रक की खानें

*73. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अभ्रक की ऐसी कुल कितनी खानें हैं जिनमें 1961 में कार्य चल रहा था तथा अब कितनी खानों में कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि उनमें कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार का अभ्रक उद्योग में काम कम होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए पच्चीस लाख श्रमिकों के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) बिहार में 1961 में चालू अभ्रक खानों की संख्या 432 थी। इस समय बिहार में चालू अभ्रक खानों की संख्या 163 है।

(ख) चालू खानों की संख्या में कमी होने का कारण यह है कि अभ्रक का मुख्यत:

निर्यात होता है और उसकी मांग निम्नलिखित कारणों से कम होती रही है :—

(1) अभ्रक खण्डों के स्थान पर अभ्रक और कृत्रिम पदार्थों से बनी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक और पालिस्टरीन का प्रयोग ।

(2) ट्रांजिस्टर वाले उपकरणों का उपयोग जिसमें अभ्रक की जरूरत नहीं होती ।

(3) अमेरिका द्वारा अपने पास जमा भंडार से अभ्रक की बिक्री ।

(4) विश्व बाजारों में आमतौर पर मन्दी का दौर । बिहार की अनेक खानें उस राज्य में अभ्रक खानों की देख भाल करने वाले व्यापारिक केन्द्रों की आन्तरिक समस्याओं के कारण भी बंद हो गइं ।

(ग) अभ्रक व्यापार निगम द्वारा शुद्ध अभ्रक और अभ्रक से बने माल के निर्यात को बढाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । ये निगम विदेशी सहयोग से कारखोनें लगाने की सोच रहा है जिसमें निम्न लिखित माल तैयार होगा :—

(1) गारा और बारीक अभ्रक पाउड

(2) अभ्रक पत्र और माइकानाइट ;

(3) अभ्रक संधारित्र आदि :

अभ्रक के नए उपयोगों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास सुविधाओं को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ।

ये सब उपाय छोटे अभ्रक खण्डों और अभ्रक कतरणों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभ्रक की मांग में कमी का सामान्यत इन किस्मों पर हीं सबसे बुरा असर पड़ा है ।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन 1976 में एक अभ्रक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो निम्न लिखित बातों पर सलाह देगी :—

(1) अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में सुधार ;

(2) शुद्ध अभ्रक और अभ्रक उत्पादों का विकास; अभ्रक आधारित उद्योगों का विकास और अभ्रक उत्पादों का निर्यात ।

(घ) देश में जिन वर्षों में अभ्रक खानों में सर्वाधिक उत्पादन होता था उन दिनों लगभग 16,000 मजदूर रोजना काम करते थे लेकिन अब यह संख्या घट कर 10,000 से भी कम रह गई है। उपर्युक्त उपायों से अभ्रक के निर्यात में सुधार होने की आशा है और फलस्वरूप स्थिति में भी सुधार होगा ।

Ad-hoc C.G.H.S. Doctors

*74. SHRI VASANT SATHE:
SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 650 *'adhoc'* medical doctors belonging to Central Health Service Scheme are threatened with dismissal from service after having put in more than 10 years of service;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken or proposed to take to absorb these qualified doctors under the Scheme on regular basis?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) to (c). On replacement by the U.P.S.C. selected candidates (335) of the 1977 Examination, the

services of *ad hoc* Medical Officers are expected to be terminated on the basis of "last come first go", if there are no clear vacancies in the Organisations concerned to retain the *ad hoc* Medical Officers. *Ad hoc* appointments are made on the stipulation that the services of *ad hoc* doctors may be terminated when regular doctors become available.

Ad hoc Medical Officers may also take their chance in the UPSC Examination to be held in 1978. There is likely to be a Special recruitment for 175 vacancies in difficult areas on the basis of interviews besides a written examination for about 375 vacancies in other areas. The Upper age limit for these recruitments is also likely to be relaxed.

New Telephone Connections given in Delhi from March 1977 to September 1977

*75. SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of new telephone connections given since March 1977 to September 1977 in Delhi; and

(b) the number of persons who were on the waiting list till September 1977?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) 5,920.

(b) 45, 522.

उद्योगों के प्रबन्ध मे श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

*76. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री के० राममूर्ति :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का समुचित स्थान सुनिश्चित करने हेतु श्रमिक कानूनों और नियमों में सरकार द्वारा कब और क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मई, 1977 में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में प्रबन्ध और इक्विटी में श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी समिति का गठन किया है जिसके सदस्य नियोजकों और ट्रेड यूनियनों के केन्द्रीय संगठनों, कुछ राज्यों तथा कुछ वृत्तिक प्रबन्ध संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। सरकार के संकल्प तारीख 23 सितम्बर, 1977 की प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल-टी-1071/77] समिति से दो महीनों की अवधि के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

Sino-Indian Relations

*77. DR. MURLI MANOHAR:

SHRI DINEN BHATTACHARYA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there have been any indications that the Peoples Republic of China may be willing to hold negotiations with India regarding the Sino-Indian border problems and further normalise its relations with this country; and

(b) if so, whether Government have taken any initiative in this matter?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Government have seen reports about statements of Chinese leaders made to journalists as also on occasion of visits to Peking by leader of other countries indicating

Chinay's desire for better relations with India. When asked about our reaction to these statements, we have clarified that while Government welcome these statements reportedly made by Chinese leaders, there has yet been no specific proposal from the Chinese side made directly to the Government of India on holding negotiations with India regarding the outstanding questios between India and China.

(b) We have already taken several initiative to expand contacts to mutual benefit between India and China on the basis of reciprocity and mutual benefit. We do not believe that the outstanding border question need be an obstacle to the improvement of beneficial bilateral relations, as is proper between two large Asian countries such as China and India.

Indians sent abroad through Registered Recruiting Agencies

*78. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) how many Indians have gone abroad through Registered Recruiting Agencies for jobs in foreign countries during 1976 and 1977 (Upto October);

(b) how many Recruiting Agencies have been authorised by Government to seek jobs for Indians abroad; and

(c) what are the norms and conditions for the Registered Agencies for booking jobs for Indians abroad?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Permission for deployment of 15,902 Indian skilled, semi-skilled and unskilled workers in foreign countries was granted by the Ministry of Labour during the period December, 1976 to October, 1977. The exact number actually deployed is not available.

(b) 254 (upto 31st October, 1977), recruiting agencies have been registered by the Government.

(c) According to the present administrative procedure, an Indian firm/individual applying for registration as a recruiting agent, is granted provisional registration after its/his antecedents have been got verified through proper sources in the Central and State Governments and its/his financial soundness certified by the bankers provided there is no complaint against the agency from our Missions abroad or any other source. A statement containing the terms and conditions on which recruiting agents are granted provisioaal registration by the Ministry of Labour for carrying on the business of recruitment of skilled, semi-skilled and unskilled workers on behaf of foreign employers is laid on the Table of the House.

Statement

Terms and Conditions on which Recruiting Agents are granted Provisional registration by the Ministry of Labour DGE&T for carrying on the Business of Recruitment of Skilled Semi-skilled and unskilled workers on behalf of foreign employers

1. The registration will be valid for a period of one year from the date of issue or until further orders.

2. The registration will not *ipso-facto* entitle the registered recruiting agency to despatch any Indian worker to a foreign employer unless it obtains from the Ministry of Labour a specific permission in each case where the agency desires to cause or assist any person to emigrate. For this purpose, the agency shall apply to the Ministry of Labour in Form-III atleast 45 days before the workers are actually proposed to be deployed. The agency shall furnish five copies of the form alongwith five copies of each of the following documents:

(a) Duly authorised legal power of attorney from the foreign employer authorising the agency to recruit workers on his behalf;

(b) Request from foreign employers to recruit specified categories and number of workers desired to be recruited for their employment, indicating the period when the workers are to be deployed;

(c) Employment agreement form which the foreign employer proposes to be executed with the recruited workers indicating separately the salary and allowances payable to each type of workers; and

(d) Information in respect of selected candidates for the aforesaind recruitment in Form-IV.

3. No application for grant of permission would be considered if it is not supported by the documents as at (a), (b), (c) and (d) above.

4. Before applying for the permission, the recruiting agency will satisfy itself that the employment agreement proposed to be executed with the recruited workers contains *inter-alia* all the provisions mentioned in the guidelines provided in the certificate of provisional registration.

5. If any recruiting agency intends to recruit workers for employment by more than one foreign employer, separate applications for grant of permission would be required to be submitted in each case.

6. The recruiting agency shall not execute the employment contract with any worker recruited for employment abroad unless the permission applied for has been granted by the Ministry of Labour.

7. Every contract of employment (written in English) of recruited workers shall be signed in India by the recruiting agent on behalf of foreign employer and shall be registered by him with the concerned Protector of Emigrants. While the recruiting agency is in any case to be a signatory on the employment contract he could, if he so desires, make the foreign employer also to be a signatory to that effect. The entire responsibility for completing the emigration formalities of every emigrant will be that of the recruiting agency. In no case the emigrant worker should be asked/coerced to sign any other contract subsequently either in India or abroad by the employer or his agents.

8. Every recruiting agency/recruiting agent shall ensure that the workers, before he actually leaves India to take up employment in foreign country for which he has been recruited, is in possession of proper travel documents such as passport, visa endorement, necessary clearance from the Rs-serve Bank of India and health certificate etc.

9. The recruiting agent *shall not charge* any money by way of recruiting fee or otherwise from any worker recruited by him for employment in foreign countries.

10. The worker recruited by recruiting agent shall be provided with full factual information and briefing regarding living conditions in the country where he is being deputed for employment.

11. The recruiting agent shall adopt fair practices in selection (including trade test|medical examination etc.) of right types of workers with due consideration to weaker sections of the community and regional representation.

12. The recruiting agent shall furnish regularly a monthly statistical return in respect of workers Sent by him abroad in the prescribed Form —V to the authority granting the registration within one week of the close of every calendar month.

13. The recruiting agency shall abide by all Government orders and directions issued from time to time in connection with their role as recruiting agent for recruitment of workers on behalf of foreign employers.

14. The registration will be cancelled and the recruiting agent liable for disqualification if he is found to be indulging in any unfair recruitment practices or not complying with the terms and conditions of the registration including Government directions given to them from time to time.

राजनयिक पदों के लिये आवश्यक भाषायें

*79. **श्री मत्यंजय प्रसाद :**
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में कार्य कर रहे राजदूतों, उनके सचिवों, अधीनस्थ कर्मचारियों, क्लर्कों, लेखाकारों, मोटरकार ड्राइवरों, अनुचरों आदि को उस देश की भाषायें, जहां उनकी नियुक्ति हो, जानना आवश्यक है और यदि हां, तो उनसे उस भाषा की जानकारी के किस स्तर तक होने की आशा की जाती है ;

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त ऐसी विदेशी भाषायें कौन-कौन सी हैं जिन्हें उपरोक्त नियुक्तियों के मामले में मंत्रालय आवश्यक समझता है; और

(ग) क्या जिन देशों में भारतीय दूतावासों में ये कर्मचारी भेजे जाते हैं वहां की भाषा सीखने के प्रबन्ध मौजूद हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारतीय विदेश सेवा के लिए संघ लोक सेवा आयोग से सीधे भरती किये गये अधिकारियों को एक विदेशी भाषा में उच्चस्तर की निपुणता प्राप्त करना अपेक्षित है । इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भरती किये गए अनुभाग अधिकारी/अताशे स्तर के अधिकारी के लिए किसी निश्चित विदेशी भाषा में उच्च डिप्लोमा भाग I पास करना अपेक्षित है । अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किसी विदेशी भाषा में निपुणता प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है । सामान्यतः अधिकारियों को इस बात को ध्यान में रख कर ही पदों पर नामित किया जाता है कि उन्हें किस भाषा में निपुणता प्राप्त है । फिर भी विदेशों में तैनातियों का निर्णय एक नियत अवधि में रिक्तियों तथा पूरे विश्व में विभिन्न मिशनों में चक्रानुक्रम के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है । हमेशा यह संभव नहीं होता कि अधिकारियों को उन्हीं देशों में भेजा जाए जहां की भाषा वे जानते हैं ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के अनिवार्य अध्ययन के लिए सरकार ने चौंतीस विदेशी भाषा निश्चित की हैं जो संलग्न सूची में बताई गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

विदेशी भाषाओं की सूची

1. अम्हेरिक	7. चेकोस्लोवाक
2. अन्नामी	8. डैनिश
3. अरबी	9. डच
4. बल्गेरियाई	10. फ्रेंच
5. बर्मी	11. जर्मन
6. चीनी (मण्डेरीन या कैंटोनी)	12. हंगेरियन

13. इटैलियन 24. रूसी
14. जापानी 25. सर्वो-क्रोशियन
15. इंडोनेशियन 26. स्पेनिश
16. केस्वाहिली 27. स्वीडिश
17. मलय 28. सिंहली
18. आधुनिक ग्रीक 29. तिब्बती
19. फारसी 30. थाई (स्यामी)
20. नार्वेजियन 31. तुर्की
21. पोलिश 32. टुर्किश
22. पुर्तगाली 33. गुर्खाली
23. रुमानियन 34. जावी/भाषा

Posting of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Employees near their places of Residences

*80. SHRI MEETHA LAL PATIL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government had issued orders in 1972 that the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be posted near to their residences as far as possible;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said orders have often not at all been complied with in Rajasthan and if so, the reasons therefor; and

(d) the number of applications in this category under consideration in Rajasthan at present and the time by which decisions are proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) No, Sir.

(b) to (d). The questions do not arise.

One Union in one Industry

601. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the study Group on modalities of one union in one industry appointed by the Ministry has submitted its report; and

(b) if so, what are its findings?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) While there was unanimity among the members of the Study Group that the concept of one union in one industry was an ideal before the trade union movement, the Study Group felt that due to several historical reasons, it was not possible to have one union in one industry at this stage. The Group was also of the view that this objective would be achieved by the trade union movement itself and that there should be no interference by the management and the State in this regard. It has also been pointed out by a section of the members that the Union Labour Minister has set up a Committee under his Chairmanship to strengthen the collective bargaining process and amend the Industrial Disputes Act suitably. Accordingly, instead of any further excercise by the steel industry in this matter, the new legislation should be awaited.

भागलपुर में डाक-तार कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण

602. डा० रामजी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए अब तक भागलपुर में कितने रिहायशी मकान बनाए हैं ;

(ख) इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है और उसमें से अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है ;

(ग) इस धन राशि के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के लिए डाक बस्ती के निकट एक विशेष चिकित्सा केन्द्र खोलने का है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) (क) : 74।

(ख) भूमि खरीदने के लिए 1000 रुपये की टोकन व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) भागलपुर में कुल 419 डाक-तार कर्मचारी हैं । वहां 74 क्वार्टर हैं जो 17.6/1 कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं । देश में डाक तार विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबिले करीब 6.5 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए क्वार्टर उपलब्ध है । इस स्थिति को देखते हुए भागलपुर की स्थिति कुछ अच्छी ही है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भागलपुर में कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टर बनाने की इस समय योजना नहीं है । फिर भी, भविष्य में क्वार्टरों के निर्माण के लिए एक मुनासिब प्लाट की तलाश जारी है ।

(घ) भागलपुर में डाक-तार कर्मचारियों की सीमित संख्या होने के नाते वहां एक अलग डाक तार-घर औषधालय खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । डाक-तार कर्मचारियों और उन के परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिए भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल का एक मान्यता प्राप्त अस्पताल है । इसी प्रकार बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए राज्य सरकार के 10 चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत चिकित्सकों के रूप में मान्यता दे दी है ।

Submission of Reports of Committee to look into Treatment given to Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Jayprakash Narayan

603. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Committee appointed by the Government to look into the matter regarding treatment given to Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Jayprakash Narayan, in the Hospitals, have submitted their reports to the Government; and

(b) if so, the details of the findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: (SHRI JAGDAMI PRASAD YADAV): (a) (i) Dr. Ram Manohar Lohia Treatment Inquiry Committee has since submitted its Report.

(ii) The term of the Commission appointed to look into the adequacy of treatment given to Shri Jayaprakash Narayan during detention has been extended upto the 15th December, 1977.

(b) The conclusions of Dr. Ram Manohar Lohia Treatment Inquiry Committee are appended.

Evidence collected from the records interviews with the clinicians and the information given by the consultants gives grounds to the committee to feel that complacency existed in late Dr. Ram Manohar Lohia's preoperative work up, in the choice of operative procedure, in the control of hameorrhage actively and the selection of the antibiotics that were administered to him in the later part of his post-operative period. In spite of the suggestion of accumulated infected material in the depth, adequate

drainage established too late when Dr. Lohia's toxic and septicamic state had reached an irreversible level.

The haemorrhage, long continued deep seated fulfiminant infection and the irrational administration of antibiotics contributed to his death following prostatectomy. The exact cause of death, however, cannot be pinpointed because no post-mortem examination was performed. It is impossible to aportion the blame to any one individual but it may be said that the basic surgical principles and priciples guiding administration of fluds and antibiotics were overlooked by the clicinians. There is no doubt that involment of too many consultants did contrbute to the confusion that existed in not a little, resuling more in feverish activity rather than rational therapy.

दिल्ली में पीलिया रोग के मामले

604. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अगस्त और सितम्बर 1977 के महीनों में पीलिया रोग बहुत अधिक फैला ;

(ख) सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में कितने रोगियों का इलाज किया गया ; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार की भावी नीति क्या है और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी हां, । पिछले महीनों की अपेक्षा अगस्त और सितम्बर, 1977 में संक्रामक यकृतशोध बहुत अधिक फैला था ।

(ख) सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में अगस्त में 313 रोगियों का और सितम्बर, 1977 में 272 रोगियों का इलाज किया गया था ।

(ग) संक्रामक यकृतशोध मुख्यत: जल से होने वाला रोग है । इस की रोकथाम के लिए पीने के साफ पानी और खाद्य पदार्थों की सप्लाई, सफाई की अच्छी व्यवस्था, मल के निपटान की अच्छी व्यवस्था जैसे उपाय नगर पालिका द्वारा किए जा रहे हैं ।

Difference in Call Charges in Raghunathgunge Telephone Exchange, West Bengal

605. SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Raghunathgunge Telephone exchange in the District of Murshidabad, West Bengal serves the Jangipur municipal area and contiguous places including Jangipur Ward of the Jangipur municipality of which Raghunathgunge is also a part though these two wings namely Jangipur and Raghunathgunge are intervened by river Bhagirathi;

(b) whether Government are aware that the call charges in Jangipur and Raghunathgunge are different though both are served by same telephone exchanges the former being double the latter;

(c) if so the reasons for the discrimination in the same exchange area; and

(d) what steps Government propose to take for equalising and rationalising the rates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) to (c). No, Sir. Raghunathgunge Telephone Exchange is not serving Jangipur which has also its telephone system. These two exchanges are treated as separate local exchanges and have separate local areas although they fall in same Municipal area as they are separated geographically by the river Bhagirath. While there is no change for local calls within each exchange, calls from Jangipur exchange to Raghunathgunge and *vice versa* and all trunk calls from the two stations to other places are treated as trunk calls and charged accordingly.

(d) The question of combining the two exchange areas into a single local area will be re-examined.

Extra Departmental Employees in P & T Department

606. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2281 dated 30th June, 1977 and state:

(a) whether Government has since reviewed the wage structure of the Extra Departmental Workers in the Posts and Telegraphs Department; and

(b) if so, the details of decisions taken and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). The wage structure of the extra Departmental Agents is still under review.

Demand for opening P.C.O. at Kotla, Himachal Pradesh

607. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal/demand with Government for opening of a P.C.O. at Kotla in Himachal Pradesh;

(b) whether the Himachal Pradesh Government has made the payment to the Telephone Department for that purpose; and

(c) if so, whether P.C.O. has been provided there and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The PCO has not yet been provided. The P&T line proposed originally for the P.C.O. could not be approved for construction because of parallelism with an Electric Power line and a different line is called for. As a result, revised rental has been quoted to the Himachal Pradesh Government, whose acceptance is awaited.

Expansion Programme of Bhilai Steel Plant

608. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that expansion programme of Bhilai Steel Plant has not been completed by the due-date; and

(b) if so, what was the date of the completion of the expansion programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES.

(SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The original schedule based on Indo-Soviet Protocal signed in April, 1972 for completion of Bhilai expansion to 4. M.T. stage was December, 1976. A critical review made in May, 1974 of the various activities of design, construction etc. had indicated that the commissioning was likely by 1979. Subsequently in February, 1975, having regard to all relevant factors such as resource availability, progress of work, projected deliveries of equipment and other inputs from various sources and collection of design data from suppliers etc., the schedule was revised to December, 1981.

Number of Employees of Orissa in Rourkela Steel Plant

609. SHRI PADMACHARAN SAMANTA SINHERA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total number of employees working in Rourkela Steel Plant class-wise and how many of them belong to Orissa State;

(b) whether the number of employees belonging to Orissa is less than the required quota; and

(c) if so, how and when Government propose to make that up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The total number of regular employees working in Rourkela Steel Plant as on the 31st October, 1977 and corresponding to various groups in Government is as follows:

Group A	2,406
Group B	120
Group C	23458
Group D	10766
Total:	36750

Statistics of employment by place of birth or residence are not maintained.

(c) Does not arise.

Construction of Building of Post Office at Ratnagiri

60. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 3966 (c) dated the 14th July, 1977 and state:

(a) whether any tender for the construction of the building of Post Office at Ratnagiri has been accepted; and

(b) if so, when the construction will commence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) The work has commenced recently.

Rule Re: use of Stabilizing and Emulsifying Agents in Flavours

611. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the reaction of the Users to the draft Rules regarding the use of stabilising and emulsifying agents in Flavours circulated for comments *vide* Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notification dated the 22nd April, 1976, G.S.R. No. 299(E);

(b) whether Rule 61A and 61B, as proposed to be inserted, have been finalised and published in the Gazette of India; and

(c) if so, when and whether the Minister would lay a copy thereof on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). The objections and suggestions received

from the public on the draft rules have been considered in consultation with the Central Committe for Food Standards and the Ministry of Law, Justice and Company Affairs and the final notification of the amended rules is at an advanced stage of finalization. The final notification will be published in the Gazette of India and copies thereof will also be laid on the Table of the Sabha.

Charter of Demands by Bihar Colliery Kamgarh Union

612. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the copy of the representation dated 16th April, 1977 containing the charter of demands by the General Secretary, Bihar Colliery Kamgarh Union concerning the workers of the Bokaro Steel Limited has been received;

(b) if so, what are the demands; and

(c) the action taken to redress these grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Exodus of Trained Medical Men

613. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the extent of exodus of trained medical men in the country to foreign countries during the last three years;

(b) whether Government are aware of the appalling paucity of medical care in this country;

(c) if so, the circumstances under which the medical men from this country who have been trained largely at State expense are not fruitfully utilised here; and

(d) whether Government propose to take any concrete action to utilise the services of such doctors in our country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The Government of India is not maintaining any detailed records of the people who leave this country either for employment or for studies in foreign countries. However, according to the Doctors enrolled in the Indian Abroad Section of the National Register of the Scientific and Technical Personnel maintained by the Council of Scientific and Industrial Research, the position during the last three years is as follows:—

	Total	Returned
As on 1-1-1975 .	3,605	1,929
As on 1-1-1976 .	3,715	1,987
As on 1-1-1977 .	3,831	2,018

(b) Yes.

(c) and (d). This Ministry had not imposed any ban on doctors proceeding abroad for study. However, there are some countries like West Germany and U.S.A. which insist on production of No Objection Certificates from Indiar Doctors who want to go and study abroad. The issue of these Certificates has been carefully considered by this Ministry and orders were issued specifying the fields in which Indian Doctors could be permitted to obtain this certificate for higher studies abroad.

2. The Government of India has been following a careful policy in respect of C.H.S. Doctors who want to go abroad on deputation terms. A complete ban was imposed in December, 1975 on the release of CHS Officers

for going abroad on deputation on foreign assignments.

3. Even before this total ban, deputation abroad to doctors was not ordinarily permitted in respect of the following categories where shortages had developed such as Anaesthesiology Radiology, Pathology, Microbiology, Bacteriology Haematology and Blood-Bank Physiotherapy and Rehabilitation, Dermatology and Venereology.

Safety of Sri Lanka Tamilians

615. SHRI D. AMAT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to news appearing in the Hindustan Times dated the 25th August, 1977 that DMK Leaders approached Prime Minister regarding the riots in Sri Lanka and also demanded to take steps for the Safety of Tamils in Sri Lanka; and

(b) if so, the reaction of the Government in the matter?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) Since the disturbances involved Indian citizens and persons of Indian origin who had applied for repatriation to India, the Government of Iodia have expressed their concern at various levels. The High Commissioner for India in Sri Lanka visited refugee camps and subsequently his officials have visited the disturbed areas to see the progress of rehabilitation, to which the Government of India have also made a token contribution of Sri Lanka Rupees one million. The Government of India have noted the steps taken by the Government of Sri Lanka to restore normalcy and hope that these steps would succeed in restoring the confidence of the Tamil community.

बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराना तथा उनका पुनर्वास

616. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31-10-1977 तक राज्यवार कितने-कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया ;

(ख) बन्धुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के बाद कितने-कितने बन्धुआ श्रमिक परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है तथा कितने कितने बन्धुआ श्रमिक बेघरबार हैं ; और

(ग) क्या पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पृथक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) : (क) से (ग). संलग्न विवरण, जिसमें नवीनतम उपलब्ध सूचना का सार प्रस्तुत किया गया है, 30 सितम्बर, 1977 तक पता लगाये गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाता है। मुक्त गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा इस समय चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न की उन मामलों में जांच की जाएगी, जहां मुक्त कराए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इस समय चल रही योजनाएं पर्याप्त नहीं समझी जाती हैं और या राज्य सरकार से विशेष अनुरोध प्राप्त होता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंधित श्रमिकों की कुल संख्या		
		पता लगाए गए	मुक्त कराए गए	पुनर्वासित किए गए
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,298	1,298	698
2.	बिहार	2,562	2,038	613
3.	गुजरात	42	42	42
4.	कर्नाटक	64,040	64,040	4,668
5.	उड़ीसा	612	312	302
6.	मध्य प्रदेश	1,612	1,500	33
7.	केरल	702	702	186
8.	राजस्थान	6,000	5,580	2,494
9.	तामिलनाडु	2,882	2,882	1,998
10.	उत्तर-प्रदेश	19,242	19,242	12,805
11.	मिजोरम	3	3	—
	योग:	98,995	97,639	23,839

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधाएं

617. **श्री राघवजी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी तहसील, खण्ड और थाने कितने हैं जिनमें टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इन स्थानों पर ये सुविधायें कब तक उपलब्ध किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) स्थिति इस प्रकार है :—

श्रेणीगत स्थान	कितने स्थानों में	
	टेलीफोन सुविधा नहीं दी गई है।	तार सुविधा नहीं दी गई है।
1 तहसील मुख्यालय	कार्य नहीं	कोई नहीं
2 खण्ड मुख्यालय	70	65
3 दरोगा या उससे ऊंचे पद वाले अधिकारी के चार्ज में आने वाले पुलिस स्टेशन	308	296

(ख) 1978-79 के अन्त तक लगभग ऐसे सभी खंड मुख्यालयों और उन जगहों पर जहां दरोगा या उससे उंचे पद वाले अधिकारी के चार्ज वाले पुलिस स्टेशन हों और जो मौजूदा उदार नीति के अनुसार न्यूनतम आय की शर्तें पूरी करेंगे, टेलीफोन और तार की सुविधाएं दे दी जाएंगी।

Survey of Kalazar Incidence in Bihar

618. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:
SHRI ISHWAR CHAUDHRY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether a central team of experts have conducted an exhaustive survey of the incidence of Kalazar in Bihar;

(b) if so, whether the report of the survey team has been received; and

(c) if so, the assistance extended to the Government of Bihar to combat and contain the disease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A central team of experts conducted a random survey of selected villages in four districts of Muzzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamadhi which were mainly effected by Kalazar from 7th to 22nd August, 1977.

(b) Yes.

(c) The assistance extended by the Government of India to the Government of Bihar consists of the following:—

1. Insecticides, spray equipment, operational support has been provided by diversion of funds from National Malaria Eradication Programme.

2. A strategy for control has been worked out in consultation with the Government of Bihar.

3. While the Government of Bihar is procuring the indigenously available anti-mony compounds, Government of India procured Pentamidine, Lomodine drugs through the WHO and supplied them to the Government of Bihar.

4. Provided epidemiologists to continuously evaluate the Kalazar activities.

5. Designed a search in 31 districts by house to house visit by health workers. Due to strike of State Health employees in Bihar this could not, however, be undertaken so far.

चासनाला कोयला खान श्रमिकों को मुआवजा

619. **श्री राम दास सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके श्रमिकों ने तथा अन्य संगठनों ने दिसम्बर, 1974 में चासनाला कोयला-खान (इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) दुर्घटना में मरे 378 श्रमिकों के संतप्त परिवारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ को धनराशि दी है तथा वह कितनी धनराशि है ,

(ख) यह कुल राशि किन-किन मदों पर खर्च की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि एक बड़ी राशि का दुरूपयोग किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा): (क) से (ग) . सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दिसम्बर, 1974 में चासनाला कोयला-खान दुर्घटना में मरे कामगारों के संतप्त परिवारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय खान कर्मचारी संघ को बाहर के देशों से धनराशि, यदि कोई थी, प्राप्त हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Agricultural Workers

620. SHRI CHITTA BASU:
SHRI PHOOL CHAND VERMA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of agricultural workers in the country;

(b) the condition of their life and work; and

(c) the steps taken by Government to ameliorate their conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) and (b). According to the 1971 Census agricultural workers in India number about 47.5 million. Their problems, as highlighted from time to time by various forums and Rural Labour Enquires, are, generally, low wages and the resulting low standard of living, unemployment and underemployment and lack of Organisation.

(c) To ameliorate conditions of life of the weaker section in rural areas, including agricultural workers, 160 Small Farmers' Development Agencies/ Marginal Farmers and Agricultural Labourers Projects were functioning in the country during 1976-77, the main emphasis in the projects being on crop hubandry which includes Intensive Agricultural Multiple Cropping, introduction of high yielding varieties, development of minor irrigation, soil conservation, land development etc. These Agencies have also been authorised to implement the usual animal husbandry programmes like distribution of milch cattle, poultry, goat and sheep rearing, piggery etc. The problems of labour in the unorganised sector, including agricultural workers were discussed at the recent Tripartite Labour Conference held on 6-7th May, 1977. The general consensus at the Conference was that, having regard to the various complex issues involved, a Special Conference be convened to consider the problems relating to unorganised rural labour, including, agricultural workers, and the nature of subjects to be discussed and nature of participants to the proposed Conference settled in consultation with the interests concerned, including the State Governments/ Union Territories, Central Organisations of Workers and Employers etc. The suggestions received from these interests are being examined and steps are being taken to convene the proposed Special Conference soon to discuss the problems of agricultural workers.

White Paper on Farakka Project Agreement

621. SHRI C. R. MAHATA:
SHRI AMAR ROY PRADHAN:
SHRI CHITTA BASU:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to issue a White Paper on the Farakka Project Agreement with Bangladesh?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): The Agreement on sharing of the Ganga waters at Farakka and on augmenting its flows has been placed before the Lok Sabha on 14th November 1977. While laying the Agreement on the Table of the House, the Prime Minister made a statement. In view of this, the Government of India do not intend to issue a White Paper on the Agreement.

Single Price Policy for Metals

624. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce single price policy for metals; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Location of Large Deposits of Bauxite in Semalia Sub-Tehsil in Rewa

625. SHRI Y. P. SHASTRI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India has located a large deposit of bauxite in Semalia Sub-Tehsil in Rewa District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, whether Government propose to utilise this deposit by setting up aluminium factories in Rewa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Geological Survey of India have estimated about 16 million tonnes of bauxite reserves in Semaria area falling in Rewa and Satna Districts.

(b) There is no such proposal.

गुजरात में सौराष्ट्र को तेल मिलों और विलायक निस्सारण प्लांटों के मालिकों को टिन प्लेटें मिलने में कठिनाइयां

626. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सौराष्ट्र की तेल मिलों और विलायक निस्सारण प्लांट के मालिकों को कनस्तर बनाने के लिए टिन प्लेटें मिलने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या सौराष्ट्र तेल मिल संघ जामनगर ने टिनप्लेटों का विशेष कोटा देने के लिए आवेदन किया है; यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सौराष्ट्र तेल मिल संघ को अपने सदस्यों की मांग को पूरा करने के लिए टिनप्लेटों का विशेष कोटा देने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक और कितनी मात्रा और किस प्रकार सप्लाई की जाएगी ;

(ङ) इस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है; और

(च) गत तीन वर्षों में सौराष्ट्र को कितनी टिन प्लेटें सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) टिन प्लेटों के उपभोक्ताओं ने, जिन में गुजरात में सौराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में तेल मिलों और विलायक निस्सारण प्लांट के मालिक भी शामिल हैं, हाल के महीनों में टिन प्लेटों की अपनी पूरी आवश्यकता प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों के बारे में बताया है। यह कठिनाई मुख्यतः टिन प्लेट कम्पनी आफ इंडिया लि०, जमशेदपुर की फैक्टरी अगस्त और सितम्बर, 1977 में कुछ समय के लिए बन्द हो जाने के कारण हुई है। कंपनी के कारखाने में अब काम होना शुरू हो गया है ।

(ख) से (ङ). किसी विशेष कोटे के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय कोटा देने की कोई व्यवस्था भी नहीं है । फिर भी, जब टिन प्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड की फैक्टरी बन्द हुई थी, उस समय राउरकेला इस्पात कारखाने को तेल के कनस्तर के साइज़ की टिन प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया था । इसके अलावा हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों से कहा गया है कि वे मांग और आपूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सतत सम्पर्क रखें । परिणामस्वरूप कुछ उपभोक्ताओं को आयात करने का भी परामर्श दिया गया है और आयात के लिए आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है ।

(च) पिछले 3 वर्षों में राउरकेला इस्पात कारखाने से गजरात को सप्लाई की

गई टिन प्लेटों की मात्रा नीचे दी गई है --

1974-75	2971 टन
1975-76	5020 टन
1976-77	3949 टन

Nuclear Proliferation Treaty

627. DR. BAPU KALDATY:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI F. P. GAEKWAD:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken final decision with regard to signing of non-proliferation treaty;

(b) whether delay in signing of the Nuclear Proliferation Treaty has resulted in getting nuclear fuel from signatories of Nuclear Proliferation Treaty countries; and

(c) whether this has affected the expansion of nuclear energy in the country?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The Government of India has been consistently of the view that the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) in its present form was unequal and discriminatory. There has been no change whatsoever in this policy of the Government.

(b) India needs to import nuclear fuel with regard to only the Tarapur atomic power station. There were some delays in getting supplies but the overdue licence was issued in July 1977. The delay in the supplies of nuclear fuel was not linked to the non-signature of the NPT by India.

(c) No, Sir.

Prosecutions of Beverage Producers

628. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 708 dated the 16th June, 1977 and state the names of beverage producers against whom prosecutions were launched and who have been convicted and those against whom cases are pending in courts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Action against Official Connected with Conspiracy to declare Shri Jagjivan Ram as Heart Patient

629. CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state whether after Dr. Caroli's public statement pertaining to an administrative conspiracy to pressurize him to declare Shri Jagjivan Ram as a serious heart patient with a view to scutttling his election tours, any action has been taken against the concerned officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): The statement of Dr. Caroli that there was an attempt to pressurise hi mto declare Shri Jagjivan Ram as suffering from grave heart illness necessitating his internment in a hospital was taken up for inquiry by the Central Bureau of Investigation. The report of the C.B.I. has not yet been received.

Geological Survey in Tirunelvely and Kanyakumari Districts

630. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey for the mineral deposits in the Tirunelvely and Kanyakumari Districts have been completed;

(b) if so, the details of the report; and

(c) if not, when the survey will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). Geological survey and exploration is a continuous process. However, preliminary surveys conducted so far for minerals other than atomic minerals in different parts of these two districts have indicated reserves of about 3.26 million tonnes of flux grade limestone, about 69 million tonnes of cement grade limestone, about 50 lakhs tonnes of white clay and about 19,000 tonnes of graphite-bearing rocks in Tirunelvely District; and about 1.68 million tonnes of shell limestone and about 2 million tonnes of coral limestone in Kanyakumari District.

बिहार में सहरसा जिले के गांवों में डाकघरों का खोला जाना

631. **श्री विनायक प्रसाद यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सहरसा जिले के किन-किन गांवों ने संबन्ध अधिकारियों को डाकघर खोले जाने के बारे में अभ्यवेदन दिए हैं और ये अभ्यावेदन कब से निर्णय के लिए पड़े हैं ।

(ख) क्या उपयुक्त जिले के कंसाली पट्टी गांव से भी डाकघर खोले जाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें वहां तत्काल डाकघर खोलने की सिफारिश की गई है ;

(घ) क्या इस सिफारिश के बावजूद भी वहां पर अब तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का कब तक यह डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सिंह सुखदेव सई): (क) सहरसा जिले के गांवों में डाकघर खोलने के सम्बन्ध में 27 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । गांवों के नाम और अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीखें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । यह प्रस्ताव सम्बन्धित डाकघर निरीक्षक के पास विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

सहरसा जिले के गांवों में डाकघर खोलने के सम्बन्ध में अनिर्णीत पड़े हुए प्रस्तावों की सूची :

क्रम सं०	गांव का नाम	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख
1.	कोसाली पट्टी	21-2-77
2	चौराहा	29-12-73
3	मलहोद	12-2-77
4	चकला निर्माली	29-8-73
5	बलहामपुर	30-9-75
6	शेखपुर चमन	3-6-75
7	मोहनपुर	18-2-76
8	नारायणपुर	3-12-76
9	फूलपुर	10-11-76
10	तितूहा	23-11-76
11	खारा तेलवा	22-9-76
12	रामपुर खोरा	28-1-77
13	सोमरसा टोला	1-2-77
14	जोपहा	3-3-76
15	शाकहुवा	29-6-77
16	मेनहा खादीपुर	29-9-77
17	वोदलहाटा	11-2-77
18	सिगार	1-9-77
19	सितलपुर	27-9-77
20	बलहा	31-8-77
21	चन्दा	29-9-77
22	कोरापट्टी	14-2-77
23	लालचन्द	7-2-77
24	मोरिशा	12-4-77
25	कुल्लीपट्टी	8-2-77
26	शकपहारपुर	28-6-77
27	भूरा	16-8-77

बंगलादेश से शरणार्थियों का आगमन

632. श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री के० एन० दास गुप्ता :
श्री समर गुह :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री के० मालन्ना :
श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री एम० कल्याणसुन्दरम :
श्री नवाब सिंह चौहान :
श्री लक्ष्मी नारायण नायक :
श्री सी० आर० महाटा :
श्री राज केशर सिंह :
श्री दिलीप चक्रवर्ती :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में भारत में बंगलादेश से कितने शरणार्थी आये;

(ख) उनके भारत में आने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपई) : (क) बंगला देश से भारत में आने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों या तो ऐसे लोग हैं जो वैध दस्तावेज पर आते हैं या ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं। इसलिए उन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता। भारत-बंगलादेश की लम्बी सीमा तथा सीमा के साथ लगने वाले इलाके के स्वरूप के कारण बंगलादेश से अवैध प्रवेशकर्ताओं की ठीक-ठीक संख्या जानना नितांत कठिन है। फिर भी, हमारे पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, पिछले

वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, इस वर्ष भारत आने वालों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है ।

(ख) इस अवैध प्रव्रजन के अनेक कारण हैं जिनमें आर्थिक संकट, उन लोगों द्वारा किये गये झूठे वायदे शामिल हैं जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय आदि बना लिया हैं ।

(ग) देश के बाहर प्रव्रजन की रोक तथा उसके उचित सुधार के लिए कदम उठाने की मुख्य जिम्मेदारी बंगलादेश की है । भारत सरकार अपनी ओर से पूरी सीमा पर कड़ी निगरानी रख रही है तथा इस प्रकार के प्रव्रजन को निरुत्साहित करने के लिए संगत नियमों तथा विनियमों को कड़ाई से लागू कर रही है ।

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये लम्बित आवेदन पत्र

633. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) टलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था न कर सकने के क्या कारण हैं तथा आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) 30–9–77 को कलकत्ते में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया अर्जियों की संख्या 27760 थी । इनमें से 1409 ओ० बाई० टी० श्रेणी में, 1657 विशेष श्रेणी में और बाकी सामान्य श्रेणी में दर्ज हैं ।

(ख) दूर संचार विकास के लिए धन और सामग्री के सीमित साधन उपलब्ध होने के कारण बड़े शहरों में टेलीफोन की अद्यतन मांगें पूरी करना संभव नहीं हो सका है । आशा है कि चालू और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कलकत्ते में 30–9–77 को बकाया मांगों में से अधिकांश प्रतिशत मांगें पूरी कर दी जाएगी ।

Gifting of Purifying Tablets to Flood-hit Villages by Church's Auxiliary for Social Action

634. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Church's Auxiliary for Social Action (CASA) has gifted a million water purifying tablets for distribution in the flood-hit villages; and

(b) if so, the names of the countries which have helped India in gifting medicines for flood-hit areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Memorandum from the Employees of G.S.I.

635. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether his Ministry have recently received a Memorandum from the Employees Union of Geological Survey of India;

(b) if so, the text of the Memorandum; and

(c) the reaction of the Government thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Some representations/resolutions have been received from different Unions/Associations of Geological Survey of India (some of which are not recognised). The main demands contained in these Memoranda are as under:

(i) According recognition or full recognition to Unions/Associations not recognised or partially recognised.

(ii) Regularisation and absorption of contingent workers in Geological Survey of India.

(iii) Early implementation/deferment of the decentralisation scheme in Geological Survey of India (suggested by different bodies).

(iv) Improvement in service conditions of Class III & IV cadres.

(v) Sanction of additional posts in Class III & IV cadres and filling of vacant posts.

(vi) Provision of housing facilities for lower staff.

(vii) Reinstatement of certain employees.

(c) The above demands and suggestions are under consideration of the Government. A high powered Committee has been appointed to examine the structure and performance of Geological Survey of India. The Committee is currently going into the various aspects of Class III and Class IV cadres of Geological Survey of India also. Further action will be considered by the Government on receipt of the Committee's report, which is expected by the end of the year.

बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था करना

636. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ के टेलीफोन विभाग के पास अपनी इमारत नहीं है; और क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण इमारत के निर्माण के लिए नियत धन व्यपगत हो गया है ;

(ख) क्या इमारत न होने के कारण बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था नहीं की जा सकी; और

(ग) क्या बिहार शरीफ से, जो नालंदा जिले का मुख्यालय है हिल्सा उपमंडल के मुख्यालय हिल्सा के साथ कोई सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) इस समय बिहार शरीफ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए विभाग की कोई जमीन या इमारत नहीं है । विभागीय इमारत बनवाने के लिए अभी तक निधि भी निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर की कमी के कारण वहां पहले आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना पर कार्रवाई करना संभव नहीं हो सका । किन्तु, अब वहां के लिए आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर अलाट कर दिया गया है । आशा है कि इस एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1980 तक हो जाएगी ।

(ग) हिल्सा और बिहार शरीफ के बीच ट्रंक यातायात बहुत कम है । इसलिए इन स्थानों के बीच अभी तक सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है ।

Demand of Bonus by Central Government Employees

637. SHRI SIVAJI PATNAIK: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Central Government employees have demanded bonus after the scrapping of the amendment made in 1975 in the Payment of Bonus Act, 1965; and

(b) if so, the reaction of the Government to this demand?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Demands of this nature have been received;

(b) Section 32(iv) of the Act excludes from its purview employees employed by an establishment engaged in any industry carried on by or under the authority of any department of the Central Government or a State Government or a local authority.

Excavation of Minerals at Pharakh, Jammu and Kashmir

638. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have deferred the execution of all new programmes of mineral development and excavation; and

(b) if not whether Government are going to develop and start excavation of minerals at Pharakh in Tehsil Reasi of Jammu and Kashmir State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) No, Sir.

(b) The State Government are taking appropriate steps to explore and develop mineral deposits in the area.

Appointment of non-Career Diplomats

639. SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the policy followed by Government in the matter of appointment of non-career diplomats, including retired Government officers to senior diplomatic posts;

(b) whether the Indian Foreign Service Association has also represented against the induction of retired or retiring Government officers to the foreign service, if so, Government's reaction thereto;

(c) names of retired/retiring Government Officers with their qualifications who have already been appointed to senior diplomatic posts; and

(d) whether no suitable officers are available in the I.F.S. to man these posts and if so, the reasons for not posting to those diplomatic posts from I.F.S. Cadre?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Posts of Heads of Missions and Heads of Posts are filled by the Government at its discretion by appointment of members of the Foreign Service, other persons from public life or occasionally retired members of other services.

While selecting persons for senior diplomatic assignments, the Government is guided by the national interests and the consideration of suitability for the post. Government takes into account the experience, ability and eminence while considering non-career diplomats and retired Government officers for appointment to such posts.

(b) The I.F.S. Association *inter alia* has drawn the attention of the Governmenth to the aspect of the matter; Government's reaction is that suitability and eminence has to be

taken into consideration when appointing non-career persons as Heads of Mission.

(c) A statement is attached.

(d) The question of sending appropriate persons from within the I.F.S. or from public life to represent the country has to be decided not only in the context of availability of suitable officers from within the I.F.S. but also keeping in mind other factors.

Statement

Sl.	Name of Ambassador/High Commissioner	Country	Date of appointment at the station	
1.	Gen. G. G. Bewoor	Denmark	9-2-76	Ex-Chief of Army Staff.
2.	Shri Chhedi Lall	Panama	5-10-76	Retired IAS.
3.	Shri M. A. Quraishi	Saudi Arabia	25-4-76	Retired ICS.
4.	Shri S. Sen.	(a) Permanent Rep. of India to U. N.	28-1-69	Retired ICS/IFS and re-employed.
		(b) Bangladesh	10-7-74	
		(c) Sweden.	13-12-76	
5.	Shri R. Jaipal	Permanent Rep. of India to UN	7-11-74	Retired IFS and reemployed.

राजेन्द्र अनुसंधान चिकित्सा संस्थान पटना का अधिग्रहण

640. **श्री युवराज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजेन्द्र अनुसन्धान चिकित्सा संस्थान, पटना का अधिग्रहण करने और वहां अनुसन्धान कार्य करने की इच्छा व्यक्त की थी और यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या अनुसन्धान कार्य बहुत खर्चीला होता है और भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किये बिना धन और प्रबन्ध की कमी की वजह से यह समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राजेन्द्र अनुसन्धान चिकित्सा संस्थान, पटना में सरकार उच्च अनुसन्धान कार्य कब तक प्रारम्भ करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) से (ग) – मार्च, 1975 में बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि राजेन्द्र मेमोरियल आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को आवर्ती आधार पर 10 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाए । इस बीच राज्य सरकार ने इस संस्थान को भारत सरकार द्वारा पहले दिए गये सुझाव के अनुसार अपने अधिकार में लेने से इन्कार कर दिया ।

यह महसूस किया गया कि चूंकि यह संस्थान कोयला खान कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित कार्य की देखरेख कर रहा है, इसलिए यदि इस मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से परामर्श ले लिया जाए तो ठीक होगा क्योंकि यह परिषद् अहमदाबाद में पहले ही राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का संचालन कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने उक्त संस्थान में एक विशेषज्ञ दल भेजा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर परिषद् ने इस मंत्रालय को यह सूचित किया कि यद्यपि संस्थान के स्थान और उसमें साज-सामान की सुलभता को देखते हुए विशेषज्ञ दल सन्तुष्ट है, तथापि अनुसंधान कार्य और उसमें नियुक्त स्टाफ की क्वालिटी के बारे में उन्होंने काफी टीका-टिप्पणी की है। अतः परिषद् ने इस संस्थान को अपने अधिकार में लेना संभव नहीं पाया।

इस मामले पर इस मंत्रालय में अप्रैल, 1977 में आगे विचार किया गया और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संस्थान को चाहिए कि वह बिहार सरकार के माध्यम से अपना प्रस्ताव भजे। यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च व स्थायी आधार पर वहन करने के लिए सहमत हो गई तो भारत सरकार द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा परन्तु राज्य सरकार से आवश्यक प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

Expert Group on use of Antibiotics

641. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to USQ No. 6279 on the 4th August, 1977 regarding expert group on use of antibiotics and state:

(a) whether the expert group has submitted any report;

(b) if so, whether the said report will be laid on the Table; and

(c) if not, when the report is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No. The group has yet to meet.

(b) Does not arise.

(c) As the expert group has yet to meet, it is not possible at this stage to say when the report will be submitted.

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों की संख्या

642. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों (टेलीफोन मकैनिकों) की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है और इस समय कितने व्यक्ति वास्तविक रूप से काम पर लगे हुए हैं, और उन तकनीशियनों सहित जो दूसरे टेलीफोन सर्किलों में प्रतिनियक्ति पर गये हैं, प्रत्येक एक्सचेंज में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को शीघ्रता-शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली में टेलीफोन-सुविधाओं में बड़े पैमाने पर किये गये या निकट भविष्य में किये जाने वाले

विस्तार संबंधी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में तकनीशियनों के और पदों का सृजन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) (i) तकनीशियनों (टेलीफोन मेकेनिकों) की कुल मंजूर संख्या 1040

(ii) प्रतिनियुक्ति तकनीशियनों के अतिरिक्त कार्यरत तकनीशियनों की संख्या 1018

(iii) खाली जगहें . 22

(iv) अन्य टेलीफोन सर्किलों में प्रतिनियुक्ति पर . 19

एक्सचेंजवार स्थिति अनुबन्ध I में दिखाई गई है। [**मंत्रालय में रखा गया देखिये** संख्या एल टी 1072 / 77]

(ख) मौजूदा कमी पूरी करने और संभावित नये पदों के लिए तकनीशियनों की भर्ती करने की कार्रवाई की गई हैं और इस समय 138 तकनीशियन प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका प्रशिक्षण 31-7-78 तक पूरा होने की संभावना है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर इन्हें तकनीशियनों के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) जी हां, करीब 14 पद बनाए जाने की संभावना है।

(घ) इसके ब्यौरे अनुबन्ध II में दे दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल टी 1072/77]

Settlement of Labour Disputes

643. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether he has solved all the labour problems and disputes referred to him till October, 1977;

(b) if so, how many of them are still under negotiation;

(c) in how many cases the settlement has been reached; and

(d) whether these settlements have eased the labour unrest that was prevailing in the beginning of the year?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). Union Labour Minister was able to bring about amicable settlements in all the seven disputes in which he personally intervened.

Stoppage of Over-Billing and Call-Pilferage

644. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the steps being taken by the Ministry to ease the difficulty being faced by the telephone subscribers for over-billing and requiring them to pay for alls which they never makes;

(b) what are the difficulties in providing a metre for recording calls to each subscriber rather than the metres being installed in the exchanges and reading done in the same way as electric metres; and

(c) till such provision is not made, how will the Government ensure accurate metre readings and stopping over-billing and call-pilferages by certain telephone staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Very few complaints about excess billing are received. Recent statistics show that on an average excess billing complaints are only 1.6 per cent of the bills issued. Whenever such complaints are received, these are examined carefully and the rebate allowed where any technical or human errors is detected or where there is possibility of an unexplained spurt in the metered calls. Keeping in view the subscribers calling habit. Nonetheless, regular testing of meters, sealing of meters and meter rooms, raising of DPs, etc. are some of the steps taken to ensure proper and secured functioning of meters.

(b) A separate meter is associated with each subscriber's line. The circuitry for operating this meter is an integral part of the exchange circuitry and cannot be extended to the subscribers premises. It has not been possible to design circuits which would ensure correct and parallel recording on any meter installed in the subscribers premises.

(c) The provision of a parallel meter in subscriber's premises is not the only method to ensure accurate meter readings or to stop over-billing complaints, but there is other measures have been adopted to see that there is least possible over-billing.

Submission of Report by Working Group on Comprehensive Industrial Relations Law

645. SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER:
DR. BAPU KALDATY:
SHRI K. A. RAJAN:
SHRI S. G. MURUGAIYAN:
SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:
SHRI P. THIAGARAJAN:
SHRI R. KOLANTHAIVELU:
SHRI SHANKARSINHJI VAGHELA:
SHRI RAM DHARI SHASTRI:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Working Group on Comprehensive Industrial Relations Law has submitted its report;

(b) whether the said report was not unanimous;

(c) if so, the manner in which Government propose to resolve the contradictory views expressed in the report; and

(d) the steps Government propose to take on the report?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). The Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and Composition of the Indian Labour Conference submitted its report to the Government in September, 1977. While divergent views were expressed by the Members on the various issues involved, there was a measure of agreement on some of the principal aspects relating to changes in the laws on Trade Unions, Industrial Disputes, and Standing Orders; however, the Committee left it to the Government to take a final decision on the broad framework of a Comprehensive Law in the light of the views expressed during the discussions. Steps are now being taken to formulate proposals for the Industrial Relations Bill.

Subsidies to Mini Steel Plants and their import

646. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government had given some subsidies for the revival of mini steel plants; and

(b) if so, the impact of the subsidies on the mini Steel Plants?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Government have not given subsidies for the revival of mini steel plants; but, in order to improve the viability of the mini steel plants; Government have taken several steps like abolition of excise duty on production of ingots/rolled products, abolition of import duty on melting scrap, abolition of excise duty on certain categories of heavy melting scrap procured from integrated steel plants. It has also been agreed that financial institutions may also consider applications for loans from mini steel plants for purposes of diversification favourably depending upon the viability of the scheme.

Furthermore, Mini Steel Plants have been allowed to diversify into production of certain grades of Alloy Steels. Selective mini steel plants may also be permitted to set up rolling facilities.

From the information available, it seem that as a result of the above measures, the total availability of steel from mini steel plants has increased in the last few months.

Representation of Unions in NJCC Meeting convened by SAIL

647. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Steel Authority of India Limited has convened the meeting of NJCC;

(b) if so, the basis of its representations;

(c) whether the NJCC constitution provides for representation to the Central Trade Union having a recognised union in either of the steel plant;

(d) the reasons for excluding the CITU despite its having recognised union in Durgapur Steel and Alloy Steel Plant;

(e) whether any Central Trade Union has been given representation without having a recognised union in any of the Steel Plant; and

(f) if so, the reason for discriminatory treatment to the CITU?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) The last meeting of the National Joint Consultative Committee for the Steel Industry convened by its Convener-Member (Chairman, Steel Authority of India Limited) was held on 5th and 6th October, 1977. Next meeting is likely to be held sometime towards the end of this month.

(b) This Committee was earlier known as Joint Wage Negotiating Committee for the Steel Industry. It was constituted in pursuance of the decisions taken at the second session of the Industrial Committee on Iron and Steel held on 16th October, 1969 and consisted of 4 representatives of employers and 15 representatives of workers—3 each from the three central trade union organisations (INTUC, AITUC and HMS) and one each from the recognised unions at Jamshedpur, Burnpur, Durgapur, Rourkela, Bhilai and Bhadravati. This system of representation continues.

(c) There is no NJCC constitution as such.

(d) Does not arise in view of what has been stated in reply to Parts (b) and (c) above.

(e) There is at present no recognised union in any of the steel plants affiliated to AITUC which is represented on the Committee.

(f) Does not arise in view of the reply to Part (b) above.

Allotment of Steel Products by Private Dealers

648. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been laid down by Government for the allotment of Steel Products to the private dealers by the three main steel producing units viz. TISCO/ ISCO/HSL;

(b) if so, what;

(c) whether Government are aware of malpractice in the allotment of steel by these three steel producing units; and

(d) if so, the action Government propose to take in the mater?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). There is at present no statutory control on the distribution of steel and Government have not laid down any guidelines for the allotment of steel to private dealers.

(c) and (d). Complaints received from time to time on distribution of steel materials by the main producers are investigated and appropriate action taken wherever found necessary.

केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के ड्रेसरों द्वारा किया गया काम

649. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में काम करने वाले ड्रेसरों को कम से कम एक सौ दवाइयां तैयार करनी पड़ती हैं; छोटे सर्जिकल आपरेशन करने पड़ते हैं और टांके लगाने पड़ते हैं ; और स्टाफ नर्सों की अनुपस्थिति में इन्जेक्शन भी लगाने पड़ते हैं ;

(ख) क्या फार्मेसिस्ट केवल चार घोल तैयार करता हैं और रोगियों को नियमित कम्पनियों की पेटेंट दवाइयां देता है ; और

(ग) यदि हां, तो ड्रेसरों को फार्मस्सिटों वाला वेतनमान न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मेसिस्ट आम बीमारियों के लिए लगभग छः प्रकार के मिक्सचर बनाते हैं। वे चिकित्सा अधिकारियों के नुस्खे के अनुसार रोगियों को सामान्य तथा विशिष्ट इवाइयां देते हैं ।

(ग) भिन्न-भिन्न पदों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों तथा उनकी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं/अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन पदों के वेतनमान तृतीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं। फार्मेसिस्ट के पद की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं मैट्रिकुलेशन तथा फार्मेसी में डिप्लोमा निर्धारित की गई है और इसके साथ-साथ उम्मीदवार फार्मेसी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए जबकि ड्रेसर के पद के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं वे हैं मिडिल स्तर तक की शिक्षा तथा प्राथमिक उपचार परीक्षा । फार्मेसिस्ट के पद की जिम्मेदारियां भी ड्रेसर के पद की जिम्मेदारियों के मुकाबले में कठिन हैं। इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों के पदों के वेतनमानों में समता नहीं हो सकती ।

इस्पात परियोजना का विस्तार

650. **श्री हुकन देव नारायण यादव:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 से 1977 तक देश की इस्पात परियोजनाओं के विस्तार के लिए किन-किन फर्मों के साथ करार किए गये ; और

(ख) क्या उस फर्म को, जिसकी निविदा सबसे कम थी, उसे काम नहीं दिया गया और सबसे ऊंची निविदा वाली फर्म को काम दिया गया, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कालाजार के लिये विदेशी सहायता

651. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाजार रोग के उपचार के लिए भारत सरकार को डाक्टरों और औषधियों के रूप में कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). जी हां, सिर्फ दवाइयों के रूप में कालाजार के उपचार के लिये भारत सरकार को दवाइयों के रूप में निम्नलिखित विदेशी सहायता प्राप्त हुई है लेकिन डाक्टरों के रूप में न तो कोई सहायता मांगी गई थी अथवा न ही मिली है ।

(1) **विश्व स्वास्थ्य संगटन से**

(i) पेटामिडीन की 9,000 शीशियां प्राप्त की जा चुकी हैं और आगामी दो महीनों में उस दवाई की 11,000 शीशियों के मिलने की संभावना है ।

(ii) लोमोडीन की 1,500 बोतलें प्राप्त की जा चुकी है और आगामी कुछ महीनों में 10,500 बोतलों के मिलने की संभावना है ।

2. **लूथरन विश्व सेवा, जनेवा से**

पेटामिडीन की 1,000 शीशियां ।

Project Report on Steel Plant at Visakhapatnam by Dastur & Company

652. SHRI K. SURYANARAYANA:
SHRI S. G. MURUGAIYAN:
SHRI M. KALYANASUNDARAM:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether M/s. M. N. Dastur & Company (P) Ltd. have submitted their project report on Steel Plant at Visakhapatnam; and

(b) if so, the details of the report and the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir. The Detailed Project Report was received by Steel Authority of India Limited (SAIL) in October, 1977.

(b) The Detailed Project Report (DPR) envisages setting up of an integrated steel plant of 3.0 MT of liquid steel to yield 2.43 MT of saleable steel (non-flat products) and 0.136 MT of saleable pig iron. The estimated cost of the Project is Rs. 1926 crores including a foreign exchange component of Rs. 107 crores. The DPR is at present being scrutinised by SAIL, after that it will be sent to the Government for their consideration.

राजस्थान के चुरू और नागौर जिलों से पासपोर्टों के लिये प्रार्थना पत्र

653. **श्री दौलतराम सारण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को पासपोर्टों के लिये सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिए जाने से पूर्व राजस्थान के चूरू और नागौर जिलों से पासपोर्टों के लिए कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए; और

(ख) कितने प्रार्थनापत्र अनिर्णीत हैं और कब से और इस के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली पारपत्रों के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों के जिलावार आंकड़े नहीं रखता । यह इन आवेदन पत्रों का सिर्फ राज्यवार विवरण ही रखता है । क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में राजस्थान राज्य से 1 जनवरी, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक की अवधि में पारपत्रों के लिए 42,451 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में 1 अक्तूबर, 1977 को राजस्थान राज्य से प्राप्त 26856 ऐसे पारपत्र आवेदन शेष थे जिन पर विचार होना था । इन में से 10606 आवेदन पत्र तो ऐसे हैं जिन के संबंध में आवेदकों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है इसलिए उन पर विचार होना बाकी है । 16250 प्रार्थनापत्रों पर कार्रवाई की जा रही है ।

Expansion of US Naval Air bases in Diego Garcia

654. SHRI AMAR ROY PRADHAN:
SHRI M. KALYANASUNDARAM:

SHRI C. R. MAHATA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the "New York Times" on the 26th September, 1977 in regard to the proposed expansion of US Naval and Air bases in Diego Garcia; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) The policy of the Government of India on foreign military presence in the Indian Ocean, including Diego Garcia, is well known to the international community and needs no reiteration. We would like to see the Indian Ocean become a zone of Peace. We are, naturally, opposed to the expansion of Great Power naval presence in the Ocean. Indeed we would like them to extend their full co-operation in the implementation of the UN Resolutions on the establishment of a Zone of Peace in the Indian Ocean.

Visit of Prime Minister and Minister of External Affairs to USSR

655. DR. HENRY AUSTIN:
DR. BAPU KALDATY:
SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and Minister of External Affairs visited Russia in October, 1977; and

(b) if so, details of the discussion held there?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir. The Prime Minister accompanied by the Minister of External Affairs visited the USSR at the invitation of the Soviet leadership form 21—26 October, 1977.

(b) A statement on the results of this visit has been made before this House by the Prime Minister.

Opening of Health Protection Centres in Orissa

656. SHRI JENA BAIRAGI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of rural health centres opened in Orissa on the 2nd October, 1977; and

(b) how many centres are proposed to be opened towards the end of the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No rural health centre was opened in Orissa on 2nd October, 1977. Under the Scheme which was launched on this day, namely Community Health Workers Scheme, Community Health Workers selected by the Community/village at the rate of one per thousand population are to receive training and serve thereafter their community/village.

(b) Setting up of health centres which is under Minimum Needs Programme is the concern of the State Government. In the State of Orissa there are presently 314 Primary Health Centres and 2,038 Sub-centres.

Normalisation of Management Employees relation at N.C.A.E.R.

657. SHRI DILIP CHAKRAVARTY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, which supplies its service on payment of fees, is an industry and covered by the Industrial Disputes Act;

(b) if not, whether the management-employees relations at the NCAER are subject to the provisions of Shops & Establishment Act or any other Act; and

(c) if not, covered by any act, whether Government are taking any step towards normalising management-employees relations at the NCAER?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). Whether the Council is covered by the Industrial Disputes Act, the Shops and Establishments Act, etc. or not will be determined by the provisions of the relevant Acts, and in case of any controversy regarding applicability of Industrial Disputes Act to any establishment, the matter has to be judicially determined. According to the information made available by the Delhi Administration 4 former employees of the Council have filed a writ petition before the Delhi High Court, inter-alia, challenging the management's contention that the Council is not an industry within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947. The petition is pending before the High Court. Meanwhile, Delhi Administration are reported to have referred the case of these 4 dismissed employees to the Industrial Tribunal Delhi for adjudication. Further action, if any, that may be called for in this case will have to be considered in the light of the final judgement of the High Court and Award of the Industrial Tribunal. As far management-employees relations, according to the Delhi Administration, there was some trouble in this establishment during May—July 1977 but that "lock-out" was lifted by the management on 29-7-77 following a settlement between the parties arrived at on July 28, 1977. The establishment is now reported to be functioning normally.

Opening of Telephone Exchange at Chandoli, in Sangli District Maharashtra

658. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to open a telephone exchange at Chandoli in Sangli District, Maharashtra where the construction of Warna Project, costing about Rs. 75 crores, is going on; and

(b) if so, the particulars about the same and the time by which the exchange would be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). So far only one application has been registered for a telephone connection at Chandoli by the Project Authorities. It is being provided as a long distance connection on a rent and guarantee basis from the Islampur Exchange. A telephone exchange will be planned as and when there are sufficient demands for more telephone connections to make the exchange financially viable.

Target for Sterilisation Cases

659. SHRI NIHAR LASKAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of sterilisation operations performed during the last six months;

(b) the target for the current year and the steps taken to achieve the results; and

(c) whether the Government intend to open family planning centres in rural areas and if so, the number thereof, during this year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) As per information available, 346,255 voluntary sterilisations have been done in the first six months (April—September, 1977) of the current financial year 1977-78.

(b) Every year targets for sterilisation and also of other methods are fixed for States in consultation with them so as to achieve the goal of bringing down the birth-rate of 30 per thousand by the end of Fifth Five Year Plan. This year when the meeting with the States took place most of the States expressed difficulty in achieving much in respect of sterilisation on account of wide-spread antagonism aroused against these operations as a result of coercion used in certain parts of the country. As such the word 'target' has been changed to 'levels of achievement'. Also it was decided that for this year the sterilisation targets would not be insisted upon. However, the level of achievement in respect of sterilisation during this year was 4,000,000. To rule out any element of compulsion the word 'sterilisation' is replaced by 'voluntary sterilisation' so that the programme is carried out on purely voluntary lines. The Central Government has requested the State Govts/ Union Territories to implement the programme vigorously without any element of compulsion or coercion. All methods of contraception incluing voluntary sterilisation are being suggested to the potential acceptors who may choose any method according to suitability and convenience. Recently all the Chief Ministers of States/Union Territories have been requested to ensure that the staff working under Family Welfare Programme show no slackness or complacency or diffidence regarding promotion of contraceptive methods in general and voluntary sterilisation in particular.

(c) The State Governments have been allowed to open 200 rural family welfare centres in this year 1977-78. The Planning Commission has also agreed to the opening of 2814 rural sub-centres under the Minimum Needs

Programme which is in the State sector, to cater to the health and family welfare needs of the rural areas.

ब्रिटेन की सरकार द्वारा कालीदेवी सम्बन्धी विज्ञापन

660. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में एक विज्ञापन समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है जिस में काली को बुराई और विनाश की प्रतीक प्रदर्शित किया गया है जिस के कारण न केवल ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की ही बल्कि समूची हिन्दू जाति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकारने इस के विरुद्ध क्या कदम उठाया है और उस का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल (जो कि सरकारी संगठन नहीं है) ने औद्योगिक संस्थानाओं में सुरक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से एक पोस्टर तैयार किया है जिस में हिन्दुओं की देवी काली को विनाश के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है ।

(ख) लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन ने ब्रिटिश विदेश कार्यालय का ध्यान भारतीय समुदाय में यह इस पोस्टर के कारण उत्पन्न रोष की ओर आकृष्ट किया है । भारतीयों ने भी इस पोस्टर के प्रति ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल को विरोधपत्र भेजे हैं । ब्रिटिश सरकार ने उक्त पोस्टर को रद्द करने के बारे में कोई कार्रवाई करने में अपनी असमर्थता के लिए खेद प्रकट किया है क्योंकि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेती है ।

लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन के अनुसार अब तक इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने उक्त पोस्टर वास्तव में वितरित किया है ।

Support to Nationalist Guerillas in Rhodesia and Namibia

661. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government supported the Nationalist Guerillas in Rhodesia and Namibia; and

(b) the other countries which are supporting them?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir. India has always supported diplomatically and otherwise, recognised liberation movements struggling for majority rule and independence in Zimbabwe (Rhodesia) and Namibia.

(b) A large number of countries have recognised and declared their support for these liberation movements. Notable amongst these are the members of OAU, other Non-aligned nations and the Socialist and Scandinavian countries.

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज

662. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद, जो काफी महत्वपूर्ण नगर है, डायल सिस्टम के लिए अपेक्षित टेलीफोनों की औपचारिकताओं को अच्छी तरह पूरा करता है ;

(ख) क्या फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) में (ग). इस समय फिरोजाबाद को 1320 लाइनों की क्षमता वाले एक मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन सेवा मिल रही है। इस समय वहां 1114 टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं और प्रतीक्षा सूची में कोई भी अर्जी दर्ज नहीं है।

विभाग सभी मौजूदा मनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने के लिए काम कर रहा है। लेकिन, साधन सीमित होने के कारण, विशेष रूप से आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर सीमित संख्या में उपलब्ध होने के कारण, आटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने के कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही है। आटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने के लिए लाइनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यतया, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और बड़े मनुअल एक्सचेंजों को प्राथमिकता दी जा रही है।

वर्तमान समय में आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध होने की जो स्थिति है, उसको देखते हुए आशा की जाती है कि फिरोजाबाद एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने की योजना पर कार्रवाई 1978-83 की परिवर्तनशील योजना के अन्त तक शुरू की जा सकेगी और 1983-84 की अगली परिवर्तनशील योजना के दौरान यह योजना पूरी की जा सकेगी।

श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं

663. **श्री हरगोविन्द वर्मा**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां करने में काफी अनियमितताएं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं को दूर करेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा): (क) और (ख). शायद यह प्रश्न शिक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए रोजगार पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की चयन समिति द्वारा किए जा रहे साक्षात्कारों के सम्बन्ध में है। अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। उन व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। इन अभ्यावेदनों की जांच पड़ताल की गई है परन्तु कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

Progress in family welfare programme

664. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the progress of the Family Welfare Programmes during the last six months; and

(b) whether Government consider the same to be satisfactory and adequate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The progress of the Family Welfare Programme during the last six months (April 77—September 77) is at Annexure I and II. [*Placed in Library. See* No. LT-1073/77].

(b) The progress of the Family Welfare Programme during the six months ending September, 1977 cannot be regarded as satisfactory except in the case of the oral pills programme and, in the case of prophylaxis against nutritional anaemia among women. The Family Welfare Programme has no doubt received a set back due to the large scale cases of coercion during the period of emergency reported from certain parts of the country. The effect of the Government is to propagate the programme in a purely voluntary way and in this respect the motivational campaign is being stepped up through Government machinery as well as non-official agencies.

आपात काल में जबरात नसबन्दी के मामले

665. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :**
श्री भगत राम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात काल में जबरदस्ती की गई नसबंदी के कारण प्रत्येक राज्य में कितने लोगों की मत्यु हुई और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो नसबंदी के कारण काम करने लायक नहीं रहे हैं ;

(ख) जिन लोगों की नसबंदी के कारण मृत्यु हुई और परिवारों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई ; और

(ग) नसबंदी के कारण जो लोग काम करने लायक नहीं रहे उनको कितनी आर्थिक सहायता दी गई और कितने लोगों को यह सहायता दी गयी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Accidents in Coal Mines

666. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1530 on the 23rd June, 1977 regarding accidents in coal mines during 1975 and 1976 and state:

(a) the number of accidents that occurred in coal mines and the workers died and injured in these accidents during January to October 1977; and

(b) the steps taken by Government to improve the conditions of safety in coal mines?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) According to provisional figures there were 185 fatal accidents resulting in the death of 202 persons and seriously injuring 33 others in coal mines during the period from January to October, 1977 and 1511 serious accidents seriously injuring 1688 persons during the period from January to September, 1977.

(b) Steps taken by Government to improve conditions of Safety in Coal Mines.

(1) Carry out routine and special inspections of mines to check compliance with law point out violations

if any and take further follow up action where necessary.

(2) Carry out periodic dialogue at various levels of management on results of inspections.

(3) Draw the attention of management to any unusal incidence of accidents/increase in accidents and ask for specific action programme to arrest any such untoward rise in number of accidents.

(4) Strengthen the enforcement agency (DGMS). This includes i) augmenting the strength and (ii) improving the service conditions so as to attract competent and qualified persons to D.G.M.S.

(5) Setting up a SAPICOM (Survey of Accident Prone Mines and Identification of Corrective Measures) unit in D.G.M.S. to identify accident prone mines and carry out indepth studies to eliminate unsafe conditions.

(6) Implementing the recommendations of the Reports of Court of Enquiry and Conference on Safety in Mines. Two high level meetings under the auspices of the Labour Ministry were held in November, 1976 and May, 1977 to review the status of Safety in Mines. The deliberations of the above and the progress in the state of implementation of the recommendations of the Third Conference on Safety in Mines were reviewed in the first meeting of a reconstituted Review Committee on 29th October, 1977.

Governmnt are also examining the recommendations made by Court of Enquiries set up in respect of Chasnalla, Kessurgarh and Sudamdih disasters.

(7) Conduct of Safety weeks as an aid to sustain the spirit of Safety consciousness among workers.

(8) Training of freshly appointed Asst. Managers of the Coal Companies at D.G.M.S.

(9) Organising one-week courses of mines safety for senior managerial personnel of B.C.C.L. and C.C.F.L. in September—November, 1977.

Setting up of Wing to deal with Workers' participation

667. SHRI L. L. KAPOOR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether inspite of the fact that the scheme of Workers Participation in Industry was introduced in 1958, no exclusive Division or Wing has been set up in the Ministry of Labour and, on the contrary the set up existed during the period 1964—69 was also disbanded;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government now intends to take up seriously the scheme and implement it in near future and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b): Though no exclusive Division or Wing was set up in the Labour Ministry to deal with the Workers' Participation, staff was sanctioned from time to time. According to the Report of the National Commission on Labour submitted in 1969 the Joint Management Councils have not been a resounding success at any place either from the point of view of employers or labour.

(c) Later on two new Schemes of Workers' Participation were introduced, one in October 1975 and the other in January 1977. After the new Government took over at the Centre, a Committee has been appointed in September 1977 to suggest a suitable Scheme of Workers' Participation in Management and Equity.

Output of Steel during 1976-77 and 1977-78

668. SHRI O. V. ALAGESAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the output of steel in terms of ingots saleable products value and capacity utilisation with reference to each plant in 1976-77 and in the first six months of 1977-78;

(b) the quantity and value of steel exported in 1976-77 and in the first six months of 1977-78 country-wise and

(c) internal consumption in 1976-77 and in the first six months of 1977-78 in terms of quantity and value?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) The output of steel in terms of ingot steel and saleable steel from each of the integrated steel plants in 1976-77 and during the period April—September, 1977, and the extent of capacity utilisation are indicated in the statement I laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* LS-1074/77].

The estimated value of saleable steel (inclusive of excise duty and Railway freight) in respect of Bhilai, Rourkela, Durgapur and Bokaro Steel Plants is indicated below. Similar information in respect of TISCO and IISCO is being collected and will be laid on the Table of the House.

(Rs. in million)

S. No.	Plant	for production during 1976-77	for production during six months of 1977-78
1.	Bhilai Steel Plant .	3184	1503
2.	Rourkela Steel Plant	3230	1513
3.	Durgapur Steel Plant	1615	751
4.	Bokaro Steel Limited.	1655	987

(b) The country-wise exports of steel in 1976-77 and during the period, April-September, 1977, are shown in the Statements II and III, laid on the Table of the House. [*Placed in Library.* See No. LT-1074/77.]

The total value of exports in 1976-77 and in April-September, 1977, was Rs. 260.51 crores and Rs. 101 crores respectively. It will not be in commercial interest to indicate the value of exports country-wise.

(c) The internal consumption of steel in 1976-77 and during the period April—September, 1977, is estimated at 6.133 million tonnes and 3.493 million tonnes respectively. Information relating to the value thereof is being collected and will be laid on the Table of the House.

Report of working on future growth of Steel Plants

669. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the working group set up by his Ministry on future growth of steel plants has given its report;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether his idea of export-based steel plants has been endorsed by this group?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) to (c). Presumably this refers to the Study Group set up by SAIL on Expansion of Steel Industry.

The Report has since been submitted by the Study Group and recommendations made by them are given in the Statement attached.

In the deliberations of the Study Group during the various meetings, the possibility of setting up an export-based steel plant was also considered.

Statement

Summary of recommendations made by the Study Group on Future Growth of Steel Plants.

1. Expansion of steel industry has to be dovetailed with the national priority of agriculture as the base and industry as the leading factor in the development of the economy.

2. Implement measures to increase the domestic need for steel by mechanisation of farming, water management schemes, development of roads and railways, widening industrial base, electrification schemes and emphasis on regeneration of rural economy.

3. While the main thrust for expansion of steel industry should be to cater to domestic demand, the steel surplus to the domestic requirement may be exported. In export efforts the emphasis should always be on exporting the product with the maximum added value.

4. On specifics of expansion, the Report states:—

(i) Expansion of existing plants should be considered on merits.

(ii) Expansion of existing plants and installation of new plants must go hand in hand to provide continuing base for expansion.

(iii) For the present the ultimate size of the plants may not be very large from strategic and logistic considerations.

(iv) Location of new steel plants should be on techno-economic considerations, keeping in view balanced regional development and commitment already made.

(v) Existing plants which are obsolete/obsolescent should be modernized with the principal object of reducing cost and wastage and improving quality. Steps must be taken to expand/diversify the plants with modernization so that manpower is not reduced.

(vi) There need not be any further expansion of mini-steel plants.

5. On introduction of new technology, the Report has recommended that it should be basically oriented towards economy in material usage, while keeping the national objective of generating maximum employment.

6. On financing, the Report has stressed the need for finding the finance at home, and suggest seeking assistance at the state level only, if outside finance is unavoidable.

7. The Report has recommended that workers and employees should be consulted on question of expansion of steel plants.

Rising of Marriage Age

670. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have made any new scheme regarding the Family Welfare Programme;

(b) whether Government intend to raise the marriage age of boys and girls; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGADAMBI PRASAD YADAV): (a) Government of India have reviewed the Family Welfare Programme. On the basis of this review, the Family Welfare Policy Statement of the Government of India dated 29th June, 1977, has been finalised. A copy of the Statement has already been placed on the Table of the House in the last session of the Lok Sabha, in reply to Question No. 688 on 16th June, 1977.

(b) Yes sir.

(c) The minimum age of marriage is proposed to be raised from eighteen to twenty-one years for males and from fifteen to sixteen years for females. A Bill for the purpose is likely to be introduced in Parliament in the current session.

Cold Rolling Mill Complex, Bokaro Entrusted to American Firms

671. SHRI M. SATYANARAYANA RAO: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1629 on the 23rd June, 1977 regarding installed capacity of Bokaro Steel Plant and state the reasons for entrusting the completion of the cold rolling mill complex at Bokaro to two American firms?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): The work relating to the expansion of the cold rolling mill complex in Bokaro Steel Plant has been entrusted to certain Indian organisations such as MECON, EPI, BHEL, and HEC who are expected to do a major portion of the designing and manufacturing themselves or through other Indian parties. Use will also be made by MECON and EPI of their existing licence agreements with M/s. Wean United of U.S.A. for the rolling mills and the processing lines respectively. Similary, BHEL will use their know-how licence agreement with M/s Siemens of West Germany for systems design for electrical drives and controls.

The main reason for deciding on the aforesaid agreement is to maximise the quantum of work to be done by the Indian organisations with minimum foreign assistance. This will not only create a wider technical base for the indigenous parties but also lead greater self-reliance in an area of highly sophisticated technology in the steel sector. At the same time, this agreement also leaves the options open to us for using the best technology available for specific areas of work.

White attack on Indian Staff in London

672. SHRI RAMANAND TIWARY: SHRI S. G. MURUGAIYAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn towards news item entitled "White Attack Indian Staff in London" (Statesman 24-9-77); and

(b) if so, whether the matter has been taken up with the British Government with a view to provide security to the Indians living there?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes Sir. On 22nd September 1977 at 7.30 p.m., a group of 8 teenage boys threw stones and broke some glass-panes of the Jawaharbagh flats owned by the Government of India in South London in which our junior-level officials are housed.

(b) The matter was taken up with the local police who took up investigation and also made necessary protective arrangements. The police authorities subsequently arrested 8 white boys who confessed to the incident.

सरकार द्वारा भण्डारा जिले में डोंगरी खानें अपने अधिकार में लेना

673. श्री लक्ष्मण राव मानकर: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भण्डारा जिले में डोंगरी खानों के प्रबन्ध को

कोयला परियोजना खनन संगठन कम्पनी से अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) क्या सरकार कोयला परियोजना खनन संगठन कम्पनी के सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को खपाने का विचार रखती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) सम्भवत: प्रश्न का अभिप्राय सेन्ट्रल प्रोविन्सेस मैंगनीज कम्पनी लिमिटेड से है न कि कोयला परियोजना खनन संगठन कम्पनी से। भारत सरकार तथा सेन्ट्रल प्रोविन्सेस मैंगनीज कम्पनी लिमिटेड (सी० पी० एम० ओ०) के बीच हुए एक समझौते के अधीन मैंगनीज और (इंडिया) लि० (मोइल) ने डोंगरी बुजुर्ग खानों में सी० पी० एम० ओ० की अचल तथा चल सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड ने अधिग्रहण करने की तारीख से डोंगरी बुजुर्ग खान में सी० पी० एम० ओ० द्वारा सीधे रुप में भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों को नए सिरे से नौकरी की पेशकश की थी तथा उन सभी कर्मचारियों ने मोइल में नौकरी कर ली है।

Memorandum by National Federation of P&T Employees Union

674. SHRI S. C. MURUGAIYAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether he has received a Memorandum from the National Federation of P&T employees Union stating some of their grievances when he visited Patna in the first week of September; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) A Memorandum was received from the Bihar Circle "Coordinating Committee" of the National Federation of P&T Employees.

(b) The Co-ordinating Committee is not a recognised body and therefore no action was necessary.

IISCO Ltd. as a Subsidiary of SAIL

675. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under consideration to make the Indian Iron and Steel Co. Ltd. a subsidiary of Steel Authority of India Ltd.; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Government have recently taken certain decisions regarding the restructuring of Public Sector Steel Industry. One of the decisions is that, in order to ensure a coordinated development of the Indian Iron and Steel Company Ltd., the shares presently held by Government in this Company should be transferred to Steel Authority of India Ltd. On the transfer of these shares the Company will become a subsidiary of SAIL. A proposal is also under consideration to acquire the shares held by the public financial institutions and others, and to transfer them to Steel Authority of India Ltd., so that the Indian Iron and Steel Company Ltd., will also become a division of S.A.I.L.

Change in Source of Technology for Cold Rolling Mill in Bokaro Steel Complex.

676. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it has been decided to change the source of technology for the cold roll mill expansion of the Bokaro Steel Complex;

(b) if so, whether this decision was taken without consulting with SAIL;

(c) whether this change is likely to cause delay in its implementation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) It was decided to entrust the work of the cold rolling mill complex expansion of Bokaro Steel Plant to the Indian organisations such as MECON, EPI, BHEL and HEC in the interest of achieving greater self-reliance. It is expected that the major portion of the work pertaining to project lay-out as well as the design and manufacture of the equipment required from this complex will be undertaken by these Organisations and Other Public Sector Units in the country.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

CGHS Homoeopathic and Ayurvedic Dispensaries of Gole Market, New Delhi.

678. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the Homoeopathic and Ayurvedic dispensaries working under CGHS located at Gole Market, New Delhi as functional dispensaries; and

(b) if so, when a final decision in the matter is likely to be taken and from which date the said dispensaries are likely to function as functional dispensaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV):(a) No. However, there is a proposal to introduce full day service in one of the existing Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries under CGHS Delhi on an experimental basis.

(b) No specific date for taking a final decision can be given at present.

Statement Regarding Manufacture of Nuclear Arms

679. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that he made a statement in New York that India will never make N-arms;

(b) if so, whether a policy decision has been taken by Government in this respect; and

(c) the salient features of that policy?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) and (b). The statement made before the UN General Assembly on 4th October 1977 reiterated the consistent policy of the Government of India not to go in for nuclear weapons. Extracts of the statement dealing with this subject are laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT/1075/77].

(c) The salient features of the Government's policy on this subject are: (a) India is not only against the proliferation of nuclear weapons but

is against nuclear weapons themselves; (b) Non-proliferation of nuclear weapons should be no tbe confused with non-dissemination of nuclear technology; (c) India remains committed to its programme for the peaceful uses of nuclear energy; (d) India will always oppose any moves or measures which stand in the way of the peaceful utilization of nuclear energy; and (e) India will be prepared to cooperate wholeheartedly with other countries in discussing ways and means of putting an end to the danger of nuclear weapons.

Removal of Unemployment

680. SHRI MANI RAM BAGRI:

SHRI PADMACHARAN SAMANTSINHERA: Will the Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out a plan to remove unemployment in rural areas in ten years;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the number of unemployed, skilled and unskilled labour and educated unemployed persons in Haryana, Rajasthan, Bihar and U.P.?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). Government propose to make all possible efforts to solve the problem of unemployment in the country, including in rural areas in the next ten years. The next five year plan which is currently being formulated is likely to have a high employment content. Concrete policies and programmes are proposed to be formulated as part of the Plan. Additional employment is likely to be created among others, in agriculture and allied fields, in irrigation and cottage industries sectors in the rural areas.

(c) Available information relates to the number of job-seekers registered with the Employment Exchanges as given in the Statement attached.

Statement

*

Number of job-seekers on the Live Register of the Employment Exchanges in the States of Bihar, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh.

State	No. of Job-seekers as on 31-12-1976.			
	Total	Educated (included in total).	Skilled (included in total).	Unskilled (included) in total).
1	2	3	4	5
Bihar	9,86,597	5,05,366	1,77,601	2,48,234
Haryana	2,42,470	1,37,970	11,791	73,430
Rajasthan	2,72,017	1,35,186	5,074	82,849
Uttar Pradesh.	11,12,932	6,33,734	60,462	2,72,727

Note :—*The figures given in Cols. (3), (4) and (5) are not necessarily mutually exclusive.

नेताजी की अस्थियां वापस लाना

681. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से नेताजी की अस्थियां भारत लाने के संबंध में बातचीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्थियों को कब तक भारत लाए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) . 3 अगस्त, 1977 को लोक सभा में एक अन्य माननीय संसद सदस्य श्री समर गुहा ने एक 'अनियत दिन वाला' प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने से संबद्ध सभी पहलुओं की जांच के लिए पहले गठित आयोग और समिति की रिपोर्टों पर भारत सरकार की स्वीकृति के प्रश्न को उठाया था। लोक सभा के पिछले सत्र में इस प्रस्ताव पर बहस अनिर्णीत रही।

चूंकि उक्त प्रस्ताव पर विचार अभी चल रहा है इसलिए इस विषय पर अभी कोई विचार-विमर्श करना असामयिक होगा।

Central Assistance for Building Hospital in Kota

682. SHRI CHATURBHUJ: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to provide special assistance for building a hospital in Kota, Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). A proposal for the grant of assistance by the Central Government for the building of a hospital in Kota is under consideration.

तारघर का जुनागढ़ में स्थानांतरण

683. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गुजरात के जुनागढ़ नगर के मध्य में आजाद चौक में स्थित तारघर को हटा कर दूर स्थान पर किस तारीख को ले जाया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तारघर को आजाद चौंक में पुराने स्थान पर वापस लाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) :

(क) जूनागढ़ संयुक्त डाक-तार घर की शाखा 15-11-1976 को एक नई इमारत में स्थानान्तरित कर दी गई थी। यह स्थानान्तरण इसलिए आवश्यक हो गया था कि डाकघर की इमारत में जगह की कमी थी और काउन्टर के पास कोई खुली जगह उपलब्ध नहीं थी।

(ख) जी नहीं, तार शाखा को को पुरानी जगह पर वापस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Killers on Prowl and the Victims are Nurses

684. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in "THE WEEKLY SUN" Vol. No. 9 of 15th October, 1977 under headline "KILLERS ON THE PROWL AND THE VICTIMS ARE NURSES"; and

(b) if so, what steps Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The news item referred to two incidents—one at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and the other at the G. B. Pant Hospital. So far as the All India Institute of Medical Sciences is concerned, no such incident has taken place and as such the report is not correct.

As regards the G.B. Pant Hospital, one Staff Nurse was found dead in Operation Theatre No. 2 of the hospital on the night of 20-9-1977. Consequently there was a strike by Nurses on this issue. The Executive Councillor (Medical) Delhi Administration took a meeting on 20-9-1977 with the representatives of the Delhi Nurses Association, following which the strike was called off. As a result of the discussions held at the meeting and an inquiry conducted by the Secretary (Medical) Delhi Administration into the complaints of the Nurses, the following steps have been taken:—

(i) The call duty system of the nurses has been suspended.

(ii) The Deputy Nursing Superintendent of the G.B. Pant Hospital has been transferred.

(iii) The monthly meetings with the representatives of the Delhi Nurses Association are being called by the Medical Superintendents of the Hospitals. One such meeting has already been held in October, 1977.

(iv) Additional safety measures for nurses residing in the Nurses Hostel and while on duty in the Hospital have been taken.

An enquiry into the allegations levelled by the Nurses Association at the meeting taken by the Executive Councillor (Medical) was conducted by the Secretary (Medical) Delhi Administration. Follow up action on the Inquiry Report is in progress.

Redistribution Policy of Steel

685. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 2784 on the 7th July, 1977 regarding redistribution policy of steel and state:

(a) whether arrangements have been made by Hindustan Steel Ltd. to open a consignment agency at Gwalior under the redistribution policy of Steel in the country; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). It was proposed originally by Hindustan Steel Limited to have a Consignment Agency at Gwalior. However, State Government of Madhya Pradesh offered land and other facilities for operating the stockyard. In view of this, it was decided by Hindustan Steel Limited to start a departmental yard at Gwalior. The yard has started functioning from 10th November, 1977.

Demands of Employees of Indian Telephone Industries, Palghat, Kerala

687. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 658 on the 16th June, 1977 regarding demands of employees of Indian Telephone Industries, Palghat, Kerala and state:

(a) whether Government have taken a decision on the demands of the workers of Indian Telephone Industries; and

(b) if so, the details thereof and if not the reasons for delay?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) and (b). As demands for revision of wage structure etc. were received from the employees of other units of Indian Telephone Industries Ltd., the matter has been under consideration and the ITI management has recently started negotiations with the Employees' Union.

Expansion of Telephone Exchanges in Himachal Pradesh

688. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is a demand for expansion of Gaggal Yol Civil and Shahpur Telephone Exchanges in Kangra District and Chamba exchange in Chamba District, Himachal Pradesh; and

(b) whether Government propose to expand these telephone exchanges and if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). The position of telephone demand and proposals for expansion of these exchanges are as follows:

Sl. No.	Name of Exchange	Present capacity of exchange.	Working connections	Waiting list.	Expansion programme.
1	Gaggal .	25 lines	14	1	Expansion not required for the time being.
2	Yol .	10 lines	9		Expansion will be taken up whenever additional demands are registered.
3	Shahpur .	30 lines.	26	3	Expansion to 50 lines proposed.
4	Chamba .	200 lines	191		Expansion to 300 lines proposed.

Applications for Telephone connections pending at Telephone Exchange, Jaisinghpur, Himachal Pradesh

689. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether some applications are pending for telephone connections at the telephone exchange, Jaisinghpur, in Kangra District, Himachal Pradesh;

(b) if so, by when it is proposed to provide telephone connections to the applicants; and

(c) the capacity of the telephone exchange and the number of telephone lines working at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes Sir, there are 3 applications pending in the general (non-OYT) category.

(b) The required lines stores are being arranged and the connections will be provided early on receipt of the same.

(c) Capacity of the exchange is 25 lines. There 11 telephone connections working at present.

राजस्थान में टेलीफोन विभाग में लाइनमैन की नियुक्ति

690. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या टेलीफोन विभाग में लाइन मैन के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष तक कुली या अन्य ऐसे पद पर कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों को एक वर्ष सेवा करने के बाद लाइन मैन के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जबकि कुछ व्यक्तियों को वर्षों सेवा करने के बाद भी नियुक्त नहीं किया जाता, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोटा, भरतपुर और राजस्थान डिवीजनों (राजस्थान) में लाइनमैनों की नियुक्ति में भ्रष्ट प्रक्रियाएं अपनाई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) किसी व्यक्ति को मजदूर के रुप में खम्बों पर दी गई लाइनों या केबुल बिछाने से संबंधित या निर्माण कार्य रख-रखाव कार्य करने वाली पार्टी में काम करना पड़ता है। इसके बाद ही उसे लाइनमैन के तौर पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(ख) पात्र उम्मीदवारों को एक निर्धारित परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके बाद ही वे लाइनमैनों के रूप में चुने जाने के लिए पात्र बनते हैं बशर्ते कि खाली जगह उपलब्ध हों।

(ग) जी नहीं।

डाक तथा तार विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति

691. **श्री मीठालाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन तथा तार विभाग में कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति के मामलों की जांच करने के लिए कोई विभागीय पदोन्नति समिति है ;

(ख) क्या उक्त समति हर वर्ष पदोन्नति के मामलों पर विचार करती है ;

(ग) क्या उक्त समिति की राजस्थान डिवीजन की बैठक नियमित समय पर नहीं होती ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में उक्त समिति की बैठकें कब कब हुई और यदि इसकी बैठक नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त समिति की राजस्थान डिवीजन की बैठक भविष्य में नियमित रूप से हो।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां, विभिन्न काडरों के लिए कई विभागीय पदोन्नति समितियां हैं।

(ख) जी हां, आमतौर पर विभागी पदोन्नति समितियों की वर्ष में एक बार या इसी प्रकार बैठकें होती हैं बशर्ते कि खाली जगहें उपलब्ध हों।

(ग) राजस्थान सर्किल और जयपुर टेलीफोन जिले की समितियों की बैठक नियमित रूप से होती रही हैं।

(घ) कृपया अनुबन्ध (क) और अनुबन्ध (ख) देखें। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 1076/77**]

(ङ) जी हां।

Representation Re. Telephone complaints from Dombiwali, district Thana, Maharashtra

692. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a written representation regarding telephone irregularities from Dombiwali, District Thana (Maharashtra) has been received by Government in the month of September or October, 1977; and

(b) if so, what action has been taken in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). Yes Sir. A Written representation was received by General Manager, Telecommunications, Maharashtra Circle, Bombay, on 21-9-1977, from M/s. Bombay Papers, MIDC, Dombiwali, subscriber Telephone No. 2231, regarding working of the said telephone connection. The faults have been rectified and reply has been sent to the party.

Telephone complaints from residents of Ulhasnagar town, district Thana, Maharashtra

693. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there are numerous complaints of various nature from the residents of Ulhasnagar Town, district Thana, Maharashtra regarding the telephones of the town for the last two years or so; and

(b) what action Government have taken or propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Several complaints have been received from Ulhasnagar Exchange subscribers. Prompt action was taken to remove the faults. However, the main demand from Ulhasnagar Subscribers is for replacement of existing manual exchange by auto exchange and provision of STD service to Bombay.

(b) Requisition for land for constructing new building for auto exchange at Ulhasnagar has been placed with local Revenue authorities. Plot earlier earmarked for P&T is said to have been unauthorisedly occupied. Case has once again been taken up with the State Government for allotment of a suitable plot to Posts & Telegraphs.

Grievances of Postal Employees at Thana (Maharashtra)

694. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether attention of the District and Circle authorities of the Posts and Telegraph Department have been drawn to the monthly publica-

tions for the months of July, August and September, 1977 published by Postal Employees organisation class III of Thana (Maharashtra) wherein the organisation has given vent to its various grievances and difficulties;

(b) if so, what action has been taken by the authorities concerned; and

(c) if no action has been taken, the reasons for delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, please.

(b) Some of the grievances mentioned therein relate to All India issues which have already been taken up by the All India Unions and are under various stages of examination. Some of the local issues have been settled and the rest are looked into.

(c) Does not arise.

Copper Plant in M. P.

695. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is not a fact that in May-June, 1975 the Russian experts submitted a report to the Government to establish a copper plant in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Soviet experts had submitted the Detailed Project Report for Malanjkhand Copper Project in Madhya Pradesh, in two instalments, in January, 1975 and in January, 1976.

(b) The salient features of the report are given in the Statement attached.

Statement

Salient features of the Detailed Project Report on the Malanjkhand Copper Project, prepared by the Soviet Consultants are given below:—

(1) This project is likely to cost Rs. 91.90 crores.

(2) This will be the first large-sized open pit mine in hard rock in the country. Mining will be fully mechanised, and will employ heavy earth-moving equipment.

(3) The development of the mine envisages a Preparatory period of 16 months, after which the actual mine construction work will commence.

(4) The ore production of 1 million tonnes per annum (15,200 tonnes of metal equivalent) will be achieved during the fourth year from the start of construction. It will be increased to 2 million tonnes (23,000 tonnes of metal equivalent) in the sixth year from start of construction of the mine.

(5) Apart from the mine, there will be a concentrator plant to treat 2 million tonnes of ore annually. The construction of the concentrator will be for treating 1 million tonnes of ore per annum in the first phase, to be increased later to 2 million tonnes.

(6) The concentrates will be transported from Malanjkhand to the Khetri Smelter.

(7) The project is expected to provide employment to around 1860 persons at full operation stage.

P. C. O. and Telegraph facilities in Ratnagiri and Kolaba Districts Maharashtra

696. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is not a single village having population of 5 thousand in Districts of Ratnagiri and Kolaba, Maharashtra to get the facility of public call office as per the policy of Government;

(b) what norms Government propose for sanctioning public call offices in these villages of two Districts which are backward and inaccessible;

(c) whether Government are aware that out of 1520 villages in Ratnagiri District, telephone facility is available only in 67 villages and Telegraph facility is available only in ninety villages;

(d) whether Government propose to make special efforts to make these facilities available to rural areas of these two Districts; and

(e) if so, how many villages will be given this facility during 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) There are four villages in Kolaba District and six villages in Ratnagiri district with a population of 5,000 and above which are yet to be provided with telecommunication facilities.

(b) According to the present policy of the Government, all villages with a population of 2500 and above in backward areas will be progressively provided with telecommunication facilities even on loss.

(c) Sixty-six villages are provided with telephone facility and eighty villages are provided with telegraph facility in Ratnagiri District.

(d) Special efforts are being made for providing telephone and telegraph facilities in the rural areas on a liberal scale.

(e) During the year 1977-78, five villages in Kalaba District and six villages in Ratnigiri District are likely to be provided with telephone and Telegraph facilities.

Aluminium Project in Ratnagiri

697. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) how many acres of land have been acquired for the aluminium project at Ratnagiri, at what cost and when;

(b) how many acres of land out of the acquired land have been actually used for the project and to what use the remaining land has been put to;

(c) the total strength of staff in the project at Ratnagiri 3 years before and the strength at present and the reasons for the reduction of staff; if any;

(d) whether Geolocigal survey of the Bauxite mines at 'DHANAGARWADI' and 'UDGIR' in Kolhapur District was made before Ratnagiri project was sanctioned; and

(e) whether geological survey of Bauxite mines was again made in September, 77 and if so the reasons therefor?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) About 1000 acres. An advance payment of Rs. 20 lacs has been made; but the final cost is yet to be settled. The land was acquired between 1971 and 1977.

(b) Except for a few temporary quarters; the land has not been put to use for the project.

(c) 15 three years ago, and 10 at present. The reduction is due to temporary redeployment of some employees; and repatriation of one officer on deputation.

(d) Yes, Sir.

(e) No survey as made in September, 1977.

Non-availability of medicines for the treatment of Kala-Azar

698. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that medicine for curing Kalaazar is not available in our country as a result of which Kalaazar is not being controlled;

(b) whether the World Health Organisation has been requested to assist in this matter; and

(c) whether, China, who has reported to have eradicated the disease in that country, has offered to assist India in the eradication of Kalaazar from India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) and (b). No. Antimony compounds which are the most effective drugs for curing Kalaazar are manufactured in the country and the position of their availability is now quite satisfactory. However about 5 per cent cases of Kalaazar may not respond to antimony compounds and such cases are treated with Pentamidine. This drug is not manufactured in the country and hence the W.H.O. have been requested to assist in its supply. Part of the supplies have already been received.

(c) No such offer has been received by this Ministry.

Instant Service Counters (Savings Bank) opened by P & T Department

699. SHRI AHMED HUSSAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of Instant Service Counters (Savings Bank) opened by the P&T Department in the country so for in order to speed up the service at Post Office Savings Banks;

(b) number of instant Service Counters proposed to be opened durinng the current year and number proposed to be opened in Assam; and

(c) whether Government is considering to provide instant service counters also in the rural post offices in Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Till April 1977, the Instant Counter Service has been provided in all Head Post Offices and Higher Selection Grade and Lower Selection Grade Sub Post Offices where there is an exclusive Savings Bank Counter clerk.

(b) Since May 1977, the Service has been extended to LSG Sub Post Offices with three hands or more. In Assam State the service is available in 13 Head Post Offices and 58 Sub Post Offices. It is proposed to be extended it to 5 more Sub Post Offices in the State during 1977-78.

(c) It is already available in 26 Post Offices in rural areas of the State and will be extended to 2 more Post Offices in 1977-78.

250 Million Rouble credit by Soviet Union

700. SHRI D. AMAT: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a proposal is under consideration to utilise the 250 million Rouble credit made available by the Soviet Union for setting up an export oriented blast furnace complex at Visakhapatnam; and

(b) if so, the main features of the proposal?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). 'Development of ferrous metallurgical industry' is mentioned in a general way as one of the projects among others for being financed under the 250 million Rouble credit. Specific projects in the metallurgical industry will have to be identified, formulated and negotiated for purposes of utilising the credit. In this context, setting up of an export oriented blast furnace complex in one of the port towns was mentioned to the Soviet technical delegation that visited our country in August-September, 1977. Secretary (Steel & Mines) also in his recent visit to USSR had some exploratory talks with the Soviet officials in this connection mainly to elicit Soviet reaction to such a proposal. Depending on Soviet Government's response, further details will have to be worked out and proposal formulated. It is premature to visualise at this stage the final outcome.

Problems of Workers of Dugda Coal Washery

701. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether serious problems and sufferings of the workers in regard to manual unloading of raw coal wagons at Dugda Coal Washery regarding their permanent absorption are within his knowledge; and

(b) if so, the action taken by Government to solve these serious problems of the poor workers?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). Presumably the reference is to the engagement of contract labour on the manual unloading of raw coal wagons in Dugda-II Coal Washery of Hindustan Steel Limited and the question of departmentalisation of this work. If so, this is a matter to be decided by the management of the Company and it is already under their consideration in accordance with the overall policy of the Government on such matters.

Convention on industrial relation Policy

702. SHRI RAJ KESHAR SINGH: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Adminstrative Staff College of India, Hyderabad organised a three day convention on Industrial Relation Policy during the second week of August, 1977;

(b) the outlines of the recommendations and guidelines that emerged from the discussion in the areas of Trade Union Legislation, Industrial Disputes Legislation, workers participation in management, bonus and gratuity and labour welfare and social security; and

(c) how far the above recommendation are helpful in drafting a comprehensive labour legislation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Recommendations received from various academic and professional organisations are given due consideration by the Government in framing policies.

डाक तार विभाग में हिन्दी अनुवादक

703. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी अनुवादक से हिन्दी निदेशक तक के पद केवल डाक-तार निदेशालय, नई दिल्ली के लिए ही मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य डाक-तार मंडलों के लिए हिन्दी अनुवादक और

हिन्दी अधिकारियों के पदों का सृजन क्यों नहीं किया गया ;

(ग) क्या सरकार अब ऐसा करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) :(क) जी हां।

(ख) से (घ). डाक-तार सर्किलों के लिए हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी अधिकारियों के पद बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

डाक और तार विभाग में अनुवादकों के वेतनमान

704. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में हिन्दी अनुवादकों का वेतनमान 425–640 रुपये है जबकि अन्य विभागों में हिन्दी अनुवादकों का वेतनमान 550–750 रुपये है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या डाक और तार विभाग में हिन्दी अनुवादकों के लिये पदोन्नति के अवसर नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या विभाग इस दिशा में कोई कार्यवाही कर रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जहां तक डाक-तार विभाग में हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान का प्रश्न है, यह सही है कि उनका ग्रेड 425–640 रुपये है। यह सही नहीं है कि अन्य विभागों में हिन्दी अनुवादक का ग्रेड 550–750 रुपये है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). हिन्दी अनुवादक ग्रेड–II वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर ग्रेड–I में तरक्की पाने के हकदार है। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में हिन्दी के काम से संबंधित सभी पदों के लिए एक केन्द्रीय काडर बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। इस केन्द्रीय काडर में जब डाक-तार महानिदेशालय के हिंदी अनुवादक शामिल कर लिए जाएंगे तब उस काडर में ऊंचे पदों पर अन्य अनुवादकों के साथ ये अनुवादक भी तरक्की पाने के हकदार बन जाएंगे।

श्री सिकन्दर बख्त का राजनयिक मिशन

705. **श्री बृज राज सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री, श्री सिकन्दर बख्त के, जिन्हें प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में मध्य पूर्व देशों को भेजा गया था, राजनयिक मिशन की क्या उपलब्धियां रहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : निर्माण, आवास, आपूर्ति एवं पुनर्वास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त ने प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में सितम्बर, 1977 में संयुक्त अरब अमीरात, कातार, बहरीन, अरब मिश्र गणराज्य और अल्जीरिया की यात्रा की। जनता पार्टी के ये पहले मंत्री हैं जिन्होंने इन देशों की यात्रा की है। इन्होंने इन देशों के नेताओं के समक्ष सरकार की नीतियां स्पष्ट कीं और इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा भारत की विदेश नीति की निरन्तरता एवं गतिशीलता का

भी उल्लेख किया। इन्होंने, इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि भारत अरब-इजराइल संघर्ष के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन करता है, और इजराइल द्वारा गैर-कानूनी ढंग से कब्जा किये गए क्षेत्र को खाली करने पर जोर दिया तथा फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों का समर्थन किया।

इसके अलावा मंत्री महोदय ने भारत और इन देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार की अपरिमित संभावनाओं का पता लगाया। यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि सहयोग के क्षेत्रों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए दोनों देशों से विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान होगा।

आपसी सम्पर्क और मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारे प्रधान मंत्री की ओर से कातार और बहरीन के अमीरों को तथा मिश्र और अलजीरिया के राष्ट्रपतियों को उनके अपने-अपने कार्यक्रमों के अनुरूप यथाशीघ्र भारत की यात्रा करने का निमंत्रण दिया गया।

Kashmir

706. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Kashmir has approached the Union Government for taking speedy steps towards "final settlement" of the problem arising out of illegal occupation of States territory by Pakistan; and

(b) if so, the details and Governments' reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) and (b). A communication has been received from the Chief Minister of Jammu and Kashmir in which he has referred to the problem of displaced persons and divided families in the State of Jammu and Kashmir and urged that it deserves an early solution. The matter is under the consideration of the Government of India.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाये गये मुद्दे

707. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सहासभा के हाल ही के सत्र में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा किन-किन मुद्दों की ओर राष्ट्र संघ का ध्यान आकृष्ट किया गया ;

(ख) क्या उक्त महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा हिन्दी के महत्व पर भी बल दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में दिए गए बयान की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) यह पहला अवसर है जबकि भारत के विदेश मंत्री ने आम सभा में अपना भाषण हिन्दी में दिया है।

(ग) विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य हिन्दी में दिए जाने के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 में संशोधन

708. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या संसदीयकार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा

68 (एच) के अन्तर्गत श्रमिक अपने भविष्य निधि खाते में से तालाबन्दी अथवा कारखाने के बन्द होने के अलावा संकट के समय में भी जमा राशि नहीं निकाल सकते ;

(ङ) क्या जहां औपचारिक रूप से फैक्टरी बन्द न हुई हो या कर्मचारियों की छटनी न की गई हो, परन्तु वे 3–4 महीने से मजदूरी न पा रहे हों और उनके भूखों मरने की स्थिति हो तो भी इस भविष्य निधि से अग्रिम राशि के रूप में सहायता नहीं दी जा सकती ; और

(ग) यदि ऐसा है, तो उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को राहत देने हेतु सरकार का धारा 68(एच) में कब संशोधन करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 68 (एच) केवल हड़ताल के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिए 15 दिनों से अधिक की बन्दी या तालाबन्दी के मामले में और बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार किए गए सदस्यों को अग्रिमों की स्वीकृति की व्यवस्था है ।

(ख) ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन कोई अग्रिम स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) प्राक्कलन समिति की अपनी 116वीं रिपोर्ट (परिशिष्ट VIII पैरा 6.4 में क्रमांक 55) में की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए वापस न करने वाले अग्रिमों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम को और उदार बनाना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

तकनीकी तथा गैर-तकनीकी बेरोजगार व्यक्ति

709. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्ता में आने के समय देश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज तकनीकी तथा गैर-तकनीकी योग्यता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या थी ; और

(ख) उनके सत्ता त्यागने के समय इनकी संख्या क्या थी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). शैक्षिक स्तरों द्वारा वर्गीकृत रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में काम चाहने वालों से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे विवरण में रखी गई है ।

विवरण

शैक्षिक स्तरों द्वारा वर्गीकृत रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 31-12-1965 तथा 31-12-1976 को नौकरी चाहने वालों की संख्या

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	31-12-1965 को चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या	31-12-1976 को चालू रजिस्टर में नौकरी चाहने वालों की संख्या
1	2	3	4
1.	मैट्रिक से कम (अनपढ़ों सहित)	17,43,640	46,80,203
2.	मैट्रिकुलेट	5,80,265	28,28,585
3.	हायर सकेण्डरी पास व्यक्ति (इण्डरमीडिएट/अंडर ग्रेजुएट सहित)	1,75,510	12,55,180
4.	स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित) योग	86,058	10,20,364
	i. कला	45,223	4,68,876
	ii. विज्ञान	20,424	2,65,876
	iii. वाणिज्य	12,424	1,46,459
	iv. इंजीनियरी	3,426	18,385
	v. मैडीसन	491	8,570
	vi. पशु-चिकित्सा	—	502
	vii. कृषि	—*	9,196
	viii. विधि	—	3,195
	ix. शिक्षा	—	90,392
	x. अन्य	4,070	8,913
	योग	25,85,473	97,84,332(सं)

नोट :— 1. सूचना प्रत्येक वर्ष जून तथा दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध-वार्षिक अंतरालों पर एकत्रित की जाती है ।

2. दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन केन्द्रों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

3. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं ।

(सं) संशोधित ।

* आंकड़े "अन्यों" में सम्मिलित हैं ।

Steps to reduce Birth Rates

710. SHRI S. R. DAMANI:
SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI O. V. ALAGESAN:
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the need for reducing the birth rate in the country is recognised;

(b) if so, the targets set for the current year and the details of implementaion and new steps taken for its intensification;

(c) whether it is a fact that the programme is at a very low key in several States; and

(d) if so, the details and reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) As a result of coercion used earlier in certain parts of the country, a widespread antagonism has arisen against these operations and as such the word 'target' has been changed to 'levels of achievement'. Also it was decided that for this year the sterilisation targets would not be insisted upon. However, the levels of achievement fixed for this year are as under:—

Voluntary Sterilisation	4,000,000
I.U.D.	1.000,000
C. C. users@	5,000,000

@Including oral-pills

The Central Government have impressed upon the States/U.Ts. the need for promotion of the small family norm and for propagating acceptance of contraceptive practices according to the choice of the acceptor. All methods of contraception including voluntary sterilisation are being suggested to potential acceptors who may choose any method according to suitability and convenience and it has been suggested that all out efforts should be made to ensure the full achievement of the suggested levels in respect of these methods. An intensive family welfare fortnight was observed in October, 1977. Besides, all the Chief Ministers of States/U.Ts have been requested to ensure that the staff working under Family Welfare Programme show no slackness or complacency or diffidence regarding promotion of contraceptive methods in general and voluntary sterilisation in particular.

(c) The progress of the Family Welfare Programme has not been quite satisfactory in almost all the States.

(d) The performance during the first six months of 1977-78, in comparison to that during the corresponding six months of 1976-77 was as under:

	1977-78 (Apr.-Sep.)	1976-77 (Apr.-Sep.)
Voluntary* Sterilisation	346,255	3,770,931
I.U.D. . . .	106,245	256,623
Conventional Contraceptive users. . .	2,641,495	3,241,435
Oral Pill users. . .	58,360	49,769

*The term "voluntary" is specificallly applicable to the performance since April 1977.

As stated in part (b) of the question, as a result of coercion used earlier in certain parts of the country, widespread antagonism has arisen against this programme in general and against sterilisation in particular, which has undermined the progress of the programme.

Man-Hours lost due to Labour unrest

711. SHRI S. R. DAMANI:
SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI P. THIAGARAJAN:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether inspite of restoration of bonus there is a widespread industrial unrest in the country;

(b) if so, the details thereof including the man hours lost and its effect on production during the last 6 months;

(c) what are the reasons for this unrest; and

(d) the actions taken by Government to secure industrial peace?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). Complete statistics in regard to the number of mandays lost due to industrial disputes after the restoration of bonus by the Payment of Bonus (Amendment) Ordinance in the first week of September, 1977 are still awaited from State Governments; till such reports are available, it is not possible to reach any conclusion.

(d) The situation is under constant watch of the Government and all efforts are being made to improve the industrial climate in the country with the help of the Industrial Relations Machinery both at the Centre and in the States. Wherever necessary the Government is intervening in disputes with a view to promoting settlements.

Capital cost of one tonne of Steel at Visakhapatnam

712. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the capital cost for output of one tonne of steel at the Visakhapatnam Steel Plant as estimated by Messrs Dastur & Company;

(b) the major items of capital outlay that were reckoned to work out the cost;

(c) whether it is a fact that the cost at Bhilai, Rourkela, and Bokaro worked out to much less; and

(d) if so, the details together with reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRL KARIA MUNDA): (a) to (d). Accoording to the Detailed Project Report on Visakhapatnam Steel Project submitted by Messrs M. N. Dastur and Company (P) Ltd., the 'plant cost' is estimated at Rs. 1,672 crores. Besides the plant cost, additional expenses are to be incurred on spares, preliminary activities, construction facilities, training, start-up, township, interest on long-term loan during construction, etc. The plant cost together with these additional investments amounts to a 'total fixed investment' of Rs. 1,926 crores. On this basis the capital cost for the output of one tonne of steel at this plant would work out to Rs. 6420/-.

Figures of capital output cost per tonne are not strictly comparable from plant to plant because of the different time periods of investments and differences on account of investment on captive facilities like mines, collieries, coal washeries, power plant, other auxiliary facilities, degree of sophistication of the finished mills, townships, sources of procurement, etc. However, the position of gross block in res-

pect of Bhilai, Rourkela and Bokaro Steel Plants is indicated below:

	Gross Block (Rs. in crores)	Block per tonne of ingot capacity (Rs. per tonne)
Bhilai Steel Plant 1 MT (58-59)	201·1	2,011
Rourkela Steel Plant 1 MT (58-59)	235·0	2,350
Bokaro Steel Limited.		
4 MT (Estimated)	2,053·30	5,133
4·75 MT (Estimated)	2,173·30	4,575

Threat to Prime Minister from Anand Marg

713. SHRI S. S. SOMANI:
SHRI C. K. JAFER SHARIFF:
SHRI ISHWAR CHAUDHARY:
SHRI K. MALLANNA:
SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a message addressed to the Prime Minister of India threatening a campaign of political assassination to secure the release of the Anand Marg Chief, Mr. P. R. Sarkar, was thrown into the Indian Tourist Office London, on 8-10-77.

(b) if so, whether it is also a fact that some damage to the building of the Tourist Office was also cause;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Indian Government thereon?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) **Yes, Sir.**

(b) **Yes, Sir.**

(c) The front sheet glass window at the Indian Tourist Office was smashed. The broken glass pieces were scattered on the office floor.

(d) The government is naturally concerned about this and other similar incidents which have resulted in damage to property and violence to individuals. The matter has been taken up at the appropriate level for ensuring the safety of our officers.

आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों पर हमले

714. श्री एस० एस० सोमानी :
श्री सुशील कुमार धारा :
डा० हेनरी आस्टिन :
श्री के० लकप्पा :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों और एयर इण्डिया के कार्यालय पर कथित हमले किये जाने के विरुद्ध में आस्ट्रेलिया सरकार को विरोधपत्र दिया है ;

(ख) इन मामलों संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने इन घटनाओं की कोई जांच पड़ताल की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) वहां भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) चूंकि आस्ट्रेलिया सरकार ने कैनबरा में भारतीय सैनिक अताशे की जान पर हुए हमले के प्रति खेद व्यक्त किया है अतः विरोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं । एअर इण्डिया के मामले में जिस कर्मचारी को छुरा मारा गया था वह आस्ट्रेलियाई राष्ट्रकर्ता का है । आक्रमण की कोई अन्य घटना नहीं हुई है ।

(ख) कैनबरा में 14 सितम्बर, 1977 को सैनिक अताशे पर एक आक्रमणकारी द्वारा उस वक्त छुरे से वार किया गया जबकि वे अपने घर में सो रहे थे और इस आक्रमणकारी ने उन्हें तथा उनकी पत्नी को एक कार में चलने के लिए मजबूर किया । कैनबरा से कुछ मील निकल कर सैनिक अताशे और उनकी पत्नी आक्रमणकारी का ध्यान हटाने में सफल हुए और उस पर काबू पाने की कोशिश की परन्तु आक्रमणकारी भाग गया । सैनिक अताशे की तत्काल शल्य-चिकित्सा की गई और अब वे पूरी तरह ठीक हैं ।

एअर इंडिया के कर्मचारी को 19 अक्तूबर, 1977 की सिडनी में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छुरा घोंपा गया था जो पार्सल देने के बहाने आया था । आक्रमणकारी बच निकला ।

(ग) सैनिक अताशे के कथित आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस पर मुकदमा चल रहा है । आस्ट्रेलिया की सरकार भी इन सभी घटनाओं की विस्तृत जांच कर रही है ताकि उस संगठन का ठीक-ठीक पता लगाया जा सके जो इन आपराधिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार है ।

(घ) जांच परिणाम अभी ज्ञात नहीं हुए हैं ।

(ङ) आस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा स्थित भारत का हाई कमीशन और सिडनी स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास की सम्पत्ति एवं कर्मचारियों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को और भी मजबूत कर दिया है ।

Visit to Great Britain by Minister of Health and Family Welfare

715. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether he recently paid a visit to Great Britain;

(b) if so, the purpose of his journey and the duration of his stay; and

(c) whether the said visit resulted into any concrete benefits in the terms of setting up of a National Health Service in India and/or in any other sphere of activity under his Ministerial charge?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) and (c). The Minister visited the U.K. from September 3 to 5, 1977 at the invitation of the High Commissioner for U.K. in India. During his visit to that country, the Minister discussed with the U.K. Government *inter alia* assistance to the Rural Health Service Scheme.

The U.K. Government appreciated the scheme and have agreed to provide 318 fully equipped Mobile Clinical Vans for 106 Medical Colleges. This assistance would be in the form of a gift and is likely to be received by April—May, 1978.

This aid includes spare parts required for these mobile clinics for the coming five years.

Non-working to telephones in Ahmedabad and removal of excess billings

716. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that several telephone connections in and around Ahmedabad are not working satisfactorily, involving cross-talks, abrupt disconnections, dead lines, getting wrong numbers continually, etc.;

(b) if so, the urgent remedial steps being taken to correct and improve the said state of affairs;

(c) whether Government are also aware that several telephone subscribers have been complaining in Ahmedabad about the excessive bills which are wrongly or unjustly charged; and

(d) if so, steps being taken to redress such grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). During monsoon months, there was an increase in the number of cable faults causing cross-talk, wrong numbers and dead lines etc. Cable faults have been attended to and the working of the telephone system is normal from September, 1977.

(c) and d). A few complaints about excess calls are received. However, the number of excess call complaints per hundred subscribers per month during 9 months ending September, 1977 has been lower than that in the last three years. For speedy disposal of excess call complaints, a special call has been formed under the overall supervision of Chief Accounts Officer of the Telephone District.

Death of a Nurse in G. B. Pant Hospital, New Delhi

717. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Times of India' dated the 23rd September, 1977 under the caption, "Nurse was killed after rape" in G.B. Pant Hospital, New Delhi; and

(b) if so, whether any investigation has been made in this regard and the action taken or proposed to be taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under investigation by the Crime Branch, Delhi Police. However, a fact finding enquiry has already been conducted by the Secretary (Medical) Delhi Administration and action taken against the officials found to be negligent in the discharge of their duties.

Search of Gold in Himachal Pradesh

718. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Statesman' dated the 27th September, 1977 under the caption, "Search of Gold in Himachal"; and

(b) if so, the details thereof; steps taken for the search of gold deposits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Yes, Sir.

(b) The newspaper report has referred to deposits of copper. zinc, anti-

mony, nickel, cobalt, mercury and tin, besides those of gold. There are known minor occurrences of alluvial gold in Chamarwin in Bilaspur district, Chargaon in Mahasu district, Hukkal, Dharampur and Jauri in Mandi district and in parts of Sirmur district. While the Geological Survey of India during 1977-78 field season proposes to investigate antimony-lead-zinc occurrences around Bara-Shigri glacier, Lahaul-Spiti district, besides some other minerals in different parts of Himachal Pradesh, exploration for gold is not programmed as the occurrences of gold are of a minor nature.

Report by Committee set up to Calculate Price Index

719. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Committee set up by Government to look into the compilation methodology of index number for working class families has completed the task and submitted its report;

(b) if so, the important features of the report; and

(c) the action taken/proposed to be taken by Government?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) No, Sir. The Committee is expected to submit its report before the end of this year.

(b) and (c). Do not arise.

Voluntary Organisation for eradication of leprosy and rehabilitation of lepers

720. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of voluntary organisations Statewise which are engaged in eradication of leprosy and rehabilitation of lepers;

(b) the estimated allocations of funds provided for these organisations, Statewise, during the 4th & 5th Plan and the amount actually utilised;

(c) whether it is a fact that the incidents of leprosy, particulary among the children below 12 years are on increase and has assumed alarming proportions; and

(d) if so, what are the proposals finalised or under consideration for eradication and rehabilitation of lepers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) A statement containing the required information is enclosed.

(b) No allocation for grants to voluntary organisations for SET work is made Statewise but grants are released to the concerned organisations directly. The grants given have been generally fully utilised. The total amount of grants released during the 4th Plan was Rs. 11.85 lakhs and during the 5th Plan up to 1976-77 is Rs. 33.65 lakhs.

(c) Not to the knowledge of the Government of India.

(d) Does not arise. However, Government have already launched a National Leprosy Control Programme under which intensive measures are being taken for controlling the disease. The Department of Social Welfare also gives grants to voluntary organisations for the rehabilitation of cured leprosy patients. They also consider applications of voluntary organisations working in the field of welfare of physically handicapped including those of cured leprosy patients under their scheme of assistance for physically handicapped persons.

Statement

Number of Voluntary Organisations working for Eradication of Leprosy in Different States.

Name of the State	Number of Voluntary Organisations.
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	2
3. Bihar	14
4. Gujarat	2
5. Kerala	3
6. Madhya Pradesh	1
7. Maharashtra	4
8. Tamil Nadu	6
9. Uttar Pradesh	2
10. West Bengal	1
TOTAL	41

Number of passports issued

721. SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of passports issued since the declaration of new liberalized policy; and

(b) the number of applications received for passports and those in arrears uptil September, 1977?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The total number of passports issued by all the 9 Regional Passport Offices in India for the period 1 August, 1977 to 31 October 1977 is 251110.

(b) The total number of applications for passports received by all the 9 Regional Passport Offices during the period 1 January, 1977 to 30 September, 1977 was 7,61,133. The number of applications for passports pending in the Passport Offices as on 1 October, 1977 was 3,02,008.

Supply of T.B. drugs to Chest Clinic run by Howrah District T.B. Association

722. SHRI SHYAMAPRASANNA BHATTACHARYYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have not supplied anti-T.B. drugs free of cost to the chest clinic run by the Howrah District Tuberculosis Association. Howrah (a charitable Institution) for the last three months; and

(b) if so, the reasons for not supplying the drugs thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Government continue to supply the drugs to the clinic.

(b) Does not arise.

Threat to Indians in Australia

723. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:
SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI M. RAM GOPAL REDDY:
SHRI C. K. CHANDRAPPAN:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI D. AMAT:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Indian missions at Canberra and Air-India's office at Sydney have been damaged by fire recently;

(b) whether an Indian diplomat had been attacked and efforts were made to kidnap him;

(c) whether Government have enquired into these incidents and the extent of loss to the Government; and

(d) whether these acts of sabotage and violence have been masterminded by certain elements and aimed at obtaining political concessions and release of certain prisoners and if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The Chancery of the High Commission of India, Canberra, was partially destroyed on 29th August, 1977. The Air India Office in Sydney has not suffered any such damage.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir, Enquiries have been made and the property lost in fire is under evaluation. The Chancery has since been shifted.

(d) These acts of sabotage and violence have been claimed by an organization calling itself Universal Proutist Revolutionary Federation, which has, in a number of anonymous communications, demanded the release of Shri P. R. Sarkar, the head of the Anand Marg.

The Government is determined to let the law take its course and not to submit to any act or threat of violence.

Patel Chest Institute

724. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission has recommended revised Pay Scale for the whole of the Delhi University Staff and the non-academic class of Patel Chest Institute;

(b) whether it is a fact that the Academic and Research Staff of Patel Chest Institute have resigned Enumarse protesting against the Ministry of Health for not implementing the revised scales of Pay; and

(c) whether Government have taken any decision in the above matter which was pending about last two years, causing frustration among the Academic Research Staff and also affecting new recruitment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The University Grants Commission had recommended the revised scales of pay for the staff of the Delhi University and that of the colleges receiving maintenance grant from the University Grants Commission. Since the Vallabhabhai Patel Chest Institute receives maintenance grant from the Ministry of Health and Family Welfare, the recommendations of the University Grants Commission are not *ipso-facto* applicable to this Institute. The Government of India had, however; approved adoption of these scales of pay in the case of non-academic staff of the Vallabhbhai Patel Chest Institute also.

(b) No, Sir. However, some members of the academic staff of the Institute have forwarded a jointly signed letter in protest against the delay in introducing the University Grants Commission scales to them stating *inter-alia* that this letter may be treated as their three months notice for resignation effective September 1, 1977.

(c) Orders were issued in May, 1976, introducing the revised CHS scales of pay to the academic staff (Medical), of the Vallabhbhai Patel Chest Institute. It was also decided that the revised scales of pay prescribed for corresponding posts in the National Institute of Health and Family Welfare may be adopted in the case of non-academic staff. How-

ever, the academic staff of the Institute has been representing that the University Grants Commission scales of pay may be introduced in their case also. This was considered by a group consisting of representatives of the Director General of Health Services, Vallabhbhai Patel Chest Institute, University of Delhi and the University Grants Commission. This group recommended that before the University Grants Commission scales of pay could be introduced, it would be desirable if the University of Delhi could consider designating the posts of Assistant Director, Senior Research Officer and Junior Research Officers of the Institute as Professors, Readers and Lecturers according to its rules. The decision of the Delhi University in respect of 5 posts only has been received so far and their decision in respect of the remaining posts is awaited.

Reports of Joint Working Groups

726. SHRI C.R. MAHATA:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI M.N. GOVINDAN NAIR:
SHRIMATI PARVATHI KRISNAN.
SHRI YASWANT BOROLE:
SHRI O. V. ALGESAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Joint working groups constituted recently to study the various aspects of steel industry and its expansion have submitted their report; and

(b) if so, the salient features thereof and the actions taken thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Summaries of the Reports of the Study Group' are given in Annexures I to VI. [*Placed in Library. See* No. LT 1077/77.] The Reports are presently under examination in Steel Authority of India Limited and in Government.

Aluminium Project at Ratnagiri

727. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Chief Minister of Maharashtra on the 10th October, 1977 that the Central Government has practically dropped or intend to drop the aluminium project at Ratnagiri;

(b) if so, the facts thereof;

(c) whether Government are aware that a serious misunderstanding has been caused in the minds of the people in Maharashtra over the statement made by the Chief Minister;

(d) whether there is any truth or substance in the said statement made by the Chief Minister; and

(e) if not, whether the Government propose to clarify the matter and inform the Chief Minister of Maharashtra accordingly?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) No, Sir.

(b) to (e). There is no intention to abandon the Ratnagiri Aluminium Project.

विदेश मंत्री की विदेश यात्रा

728. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने 1977 में किन-किन देशों की यात्रा की ; और

(ख) उनकी यात्राओं के क्या-क्या उद्देश्य थे और उनकी यात्रायें कहां तक सफल रहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख). यह सूचना सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या L.T. 1078/77]।

जद्दा में भारतीय कल्याण अधिकारियों के लिए सुविधाएं

729. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्यों से हज यात्रा के लिए जाने वाले भारतीय प्रतिनिधियों तथा कल्याण अधिकारियों को जद्दा बन्दरगाह और मक्का मदीना में कतिपय सुविधायें प्रदान की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) राज्य सरकारें हज के मौके पर सऊदी अरब को कोई शिष्टमंडल या कल्याण अधिकारी नहीं भेजती । लेकिन राज्य हज समितियां भारत के राजदूतावास, जेद्दा के मार्गदर्शन में अपने-अपने राज्यों से हज-यात्रियों की देखभाल के लिए हज स्वयंसेवक भेजती हैं ।

(ख) हज स्वयंसेवकों को सऊदी अरब प्राधिकारियों द्वारा एक "मुफ्त आव गमन अनुज्ञापत्र" के अतिरिक्त और कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाती । इस अनुज्ञा पत्र के आधार पर, जो साधारण हज यात्रियों को नहीं दिया जाता, ये स्वयंसेवक जेद्दा मक्का-मदीना के बीच में निर्बाध रूप से आ-जा सकते हैं जिससे कि वे जेद्दा में बंदरगाह पर अथवा हवाई अड्डे पर हज यात्रियों के आने-जाने वाले दलों की और अगर उन्हें मक्का, मदीना में अधिक ठहरना हो तो उस समय भी उनकी सहायता कर सकें ।

विदेशों में दूतावासों की संख्या

730. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : *क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) विदेशों में ऐसे भारतीय दूतावासों की देशवार संख्या कितनी है जिनमें राजदूत नियुक्त नहीं किये गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये रिक्त स्थान कब तक भरे जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) . (क) एक, यमन लोक जन गणराज्य (अदन) में ।

(ख) और (ग). अदन में भूतपूर्व राजदूत ने उस वर्ष अगस्त में अपने पद का कार्यभार छोड़ा था । उनके उत्तराधिकारी की शीघ्र ही नियुक्ति होने की संभावना है ।

बिहार के जिलों में जन संख्या परियोजना के लिए मानदण्ड

731. **डा० रामजी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय 'भारत जनसंख्या परियोजना' के अन्तर्गत जिलों के चुनाव के लिए

केन्द्रीय सरकार ने क्या मानदण्ड निश्चित किए है ;

(ख) उपरोक्त मानदण्ड की दृष्टि से बिहार सरकार ने किन-किन जिलों की सिफारिश की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त मानदण्ड और बिहार सरकार की सिफारिश के विपरीत कोई निर्णय लेने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना बिहार के उपरोक्त जिलों में कब लागू की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के लिए राज्यों और जिलों के चुनाव हेतु केन्द्रीय सरकार ने जो मानदण्ड निश्चित किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) वे घनी आबादी वाले क्षेत्र ;

(2) वे क्षेत्र जिनमें आर्थिक दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग की प्रतिशतता अधिक है;

(3) वे क्षेत्र जिनमें मृत्यु दर अधिक होती है तथा जिसमें जच्चा बच्चा मृत्यु दर अधिक होती है ;

(4) वे राज्य/जिले जिनमें पहले मध्यम स्तर का कार्य हुआ है और जहां इसके अधिक स्वीकार किए जाने की संभावना है ;

(5) वे जिले जो सारे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें इस कार्यक्रम की सफलता राज्य के दूसरे जिलों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है । जिलों का चुनाव करते समय भोगोलिक सामीप्य और प्रशासनिक सुविधाओं जैसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है ताकि इस कार्यक्रम का प्रबन्ध और इसकी निगरानी कुशलतापूर्वक की जा सके ।

(ख) बिहार सरकार ने जिन जिलों के बारे में सिफारिश की है उनके नाम इस प्रकार है :—

1. सहरसा
2. पूर्णिया
3. कटिहार और
4. भागलपुर ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) अभी तक इस परियोजना की मंजूरी नहीं दी गयी है । आशा है कि यह 1979–80 में शुरू हो सकेगी ।

Trade Union Representations in Indian Labour Conference and Convening its Meeting

732. SHRI SIVAJI PATNAIK: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question of trade union representations on the Indian Labour Conference;

(b) if so, Government's decision thereon; and

(c) when the meeting of the Indian Labour Conference will be convened?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b): Government had set up a 30-Member Tripartite Committee to go

inter-alia into the question of the composition of Indian Labour Conference. At the Committee's meeting in September 1977, the Members expressed their views on the subject of representation. Government has not yet taken a decision on this.

(c) No date has been fixed for convening the Indian Labour Conference.

Seizure of Adulterated Mustered Oil in Delhi

733. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether 127 tins of adulterated mustered oil have been seized in Delhi;

(b) the trade mark given on the containers; and

(c) The action taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of Sabha.

Strike by Workers of India Explosives Limited Factory, Gomia (Bihar)

735. SHRI AHMED M. PATEL:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether workers of the India Explosives Limited Factory at Gomia (Bihar) went on strike in September, 1977;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (c). The matter falls essentially in the State sphere. According to available information, the workers of Indian Explosives Limited, Gomia, Bihar, went on strike on September 20, 1977 in support of their charter of demands relating to reinstatement of dismissed workers, improvements in working conditions, etc. The strike was called off from October 26, 1977 at the intervention of the State Industrial Relations Machinery and the State Chief Minister.

सरकारी संस्थानों द्वारा बोनस का भुगतान

736. श्री उग्रसेन :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी संस्थानों के नाम क्या हैं जिनमें बोनस का भुगतान करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) रेल, संचार, आकाशवाणी, टेलीविजन और 'परिवहन विभागों' में बोनस न देने का निर्णय करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस देने पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के प्राधिकरण पर

किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उनके अधीन चलाए जा रहे किसी उद्योग के किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है ।

(ग) बोनस अधिनियम की परिधि का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का प्रारम्भ किया जाना

737.. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी के 130वें जन्म दिवस, 2 अक्तूबर, 1977 से देश के अनेक जिलों और विकास खण्डों में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारम्भ की है ; और, यदि हां, तो यह योजना मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों और विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई है ; और

(ख) क्या यह योजना मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े जिलों, अर्थात् रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, बस्तर, झबुआ, पन्ना, दमोह, मंडला और धार के समस्त विकास खण्डों में लागू की जा रही है और यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त जिलों के समस्त विकास खण्डों में इस योजना को इसी वर्ष लागू कर देगी क्योंकि इन जिलों के सुदूरवर्ती गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था लगभग नगण्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : (क) जी, हां, इस स्कीम को चलाने के लिए चुने गये जिलों और प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों के नामों का एक विवरण नीचे रखा है ।

(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना फिलहाल रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, बस्तर, झाबुआ, पन्ना, दमोह, मंडला और धार जिलों के एक-एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में चलाई जा रही है । इस योजना को इस साल के अन्दर-अन्दर सभी विकास खण्डों में आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

राज्य क्रम संख्या	मध्य प्रदेश जिला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1.	बालघाट	बेहार
2.	बैतूल	झालर (बैदसदेही)
3.	बस्तर	टोकापल
4.	भिन्द	राउन
5.	बिलासपुर	तख्तपुर
6.	छत्तरपुर	सतई
7.	गूना	भदोरा
8.	दातियां	उन्नाव
9.	छिंदवाड़ा	जमाल
10.	देवास	बागली
11.	दुर्ग	धमदा
12.	होशंगाबाद	बावई
13.	झाबुआ	पोटलावाड़
14.	मण्डला	नैनपुर
15.	मंदसौर	पलसौद
16.	मोरैना	करहल
17.	नरसिंगपुर	सालीचौक
18.	खण्डवा (पूर्वी निमार)	पंधना
19.	बरवानी (पश्चिमी निमार)	सेंदवा
20.	रायगढ़	लौदम
21.	रायपुर	बीशबाड़
22.	राजनन्दगांव	सौराष्ट्र
23.	पन्ना	पावई

1	2
24. भोपाल	बरसईया
25. दमोह	पथरिया
26. धार	तेजगांव
27. ग्वालियर	हस्तिनापुर (मोरार)
28. इन्दौर	देपालपुर
29. जबलपुर	बरोला (बार्गी)
30. रायसन	सांची
31. राजगढ़ (बिग्रोरा)	सुछेलिया
32. रतलाम	खड़वाकला (ग्रलोट)
33. रीवा	रायपुर (गुरह)
34. सागर	दियोरी
35. सतना	मझगांव (चित्र-कूट)
36. सेहोरे	इच्छवार
37. सोनी	चंसौर
38. शाहदोल	ग्रोली-2, गोहपरु (नैरोजाबाद)
39. शाहजहांपुर	आगरा
40. शिवपुरी	करोरा
41. सी,	कुसमी (गोपदब-नास)
42. सूरगुजा	सूरजपुर
43. तिक्कमगढ़	जतरा
44. उज्जैन	खचरौद
45. विदिसा	सिरौज

मध्य प्रदेश के रीवा तथा सतना जिलों में नये डाक तथा तारघर खोलना

738. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अत्यन्त पिछड़े जिले रीवा और सतना, के अनेक गांव में तारघर, टेलीफोन और डाकघर खोलने की मांग की गई है।

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों में, अलग-अलग, टेलीफोन और तारघर तथा डाकघर खोलने का विचार है : और

(ग) इनकी कब तक व्यवस्था हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) जी, हां।

(ख) (i) **टेलीफोन और तार सुविधाएं :-** इन दो जिलों के नीचे दिये गये गांवों में टेलीफोन और तार सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

सतना जिला

(1) सिंहपुर (2) बीर सिंहपुर (3) जायज

रीवा जिला

(1) दभौडा (2) दहीगढ़ी (3) चचाई (4) सेमरिया (5) गढ़ (6) बीडा (7) कटखरी (8) गोरी (9) तिउनी (10) खाजू कलां।

(ii) निम्नलिखित गांवों में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

रीवा जिला

(1) पोपरा कुरुंड (2) गजरी (3) खमरिया चोबेन (4) अमिल्की (5) हिनौता (6) घोपी।

सतना जिला

(1) झिंगोदर (2) पन्ना (3) कृपालपुर (4) गुडा (5) मझगांवों।

(iii) नीचे लिखे गांवों में डाकघर खोलने के प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं।

(1) अभिल्योनी (2) बरखड़ा (3) चितगढ़ (4) बैगंदीह ।

सतना जिला

कोई नहीं ।

(ग) (i) रीवा जिले के दशौरा दहीगढ़ी और सेमरिया को छोड़कर ऊपर (ख) (i) में उल्लिखित अन्य सभी स्थानों में टेलीफोन और तार की सुविधाएं वर्ष 1977–78 के दौरान दे दिए जाने की संभावना है । आशा है कि शेष तीन स्थानों में ये सुविधाएं 1978–79 में दे दी जाएंगी ।

(ii) पहले से स्वीकृत और जांच करने के बाद जिन प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध होगा । उन सभी स्थानों पर वर्ष 1977–78 में डाकघर खोल दिए जाने की संभावना है ।

1,000 रुपये प्रति मास तक वेतन वाले पदों के लिए पंजीकरण

739. **श्री युवराज** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम तथा रोजगार विभाग को वर्ष 1960 से 500 रुपए प्रति मास तक वेतन वाले पदों के लिए रोजगार के लिए बेरोजगार व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त निदेश में अब तक संशोधन नहीं किया गया है हालांकि जो व्यक्ति वर्ष 1960 में 500 रुपए प्रति मास पाते थे, अब मूल्यों में वृद्धि और वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण 1000 रुपए प्राप्त करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ा कर 1000 रुपए तक कर देने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) जी नहीं । रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए कोई वेतन सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

740. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय हैं और ये औषधालय कहां-कहां स्थित हैं और ये कब से चल रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक औषधालय में कितने-कितने कार्ड दर्ज हैं और प्रत्येक औषधालय में डाक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या वाली जमुना-पार की कालोनियों में चार या पांच अतिरिक्त औषधालय खोलने का प्रस्ताव हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT-1079/77]**

(ग) और (घ). जमुना-पार की कालोनियों में अतिरिक्त औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हैं ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मासिक औसत

741. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस महीनों के दौरान औद्योगिक कर्मचारियों (1960-100 आधार वर्ष) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बंधी मासिक तथा 12 महीनों के औसत आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें मूल्य सूचकांक संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). सूचना तीन सभा पटल पर रखे गए विवरणों i, ii और iii में दी गई है **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या LT 1080/77]**

Malaria in the Country

742. SHRI PRASANNABHAI MEHTA.
SHRI RAMJI LAL SUMAN:
SHRI YASHWANT BOROLE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report in the *Sunday Standard* dated the 9th October, 1977 under the heading 'Malaria control set up is sick';

(b) if so, whether this year the country was in the grip of Malaria; if so, the factor responsible for this sudden rise;

(c) how many persons died and how many suffered due to this disease during 1977 in the country; and

(d) the preventive measures taken to meet the challenge?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes.

(b) Though the incidence of Malaria has been rising gradually during the last 10 years or so, on the basis of reports available up to September this year the incidence of positive cases of Malaria is 30,21,864 as against the incidence of 30,98,666 for the same period during the last year. There is thus a decline of about 11 per cent in the incidence of cases this year so far. However, while Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka; Punjab, Rajasthan, Sikkim, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Uttar Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi and Pondicherry have reported increase in the incidence, other States and Union Territories have reported decline.

(c) The positive incidence reported upto September, 1977 is 30,21,864 and 20 deaths directly due to Malaria have been confirmed.

(d) A statement indicating the preventive measures taken to control the disease is attached.

Statement

The following steps have been taken by Government of India for controlling Malaria:—

1. A modified plan of operations is being implemented by the Governments of States and Union Territories for from the 1st April, 1977. While the ultimate objectives of NMEP continues to be eradication of Malaria for the present it is proposed to contain it.

2. The existing N.M.E.P. units have been re-organised to conform to the geographical boundaries of the districts. The Chief Medical Officer of the district has been made primarily responsible for the programme in the district.

3. Increased quantity of the required type of insecticides have been/are being provided with the available resources.

4. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas, which have incidence of two or more cases per thousand population.

5. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been supplied to the States and Union Territories Governments. Drug Depots/Drug Distribution Centres/Fever Treatment Centres have been opened from where anti-malarial drugs are available conveniently to the public free of cost. In a few areas where resistance to choloroquine by parasited has been noticed, alternative anti-malarials like quinine have been supplied.

6. Anti-larvel operations under Urban Malaria Areas Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 towns during 1977-78 besides continuing it in the already existing 28 towns.

7. For early examination of blood smears and providing quick medical treatment, to positive cases, laboratory services have been decentralised to the P.H.C. level.

8. Supervision of the field staff has been tonned up.

9. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in Malaria.

10. Intensive campaign has been started in North Eastern region with World Health Organisation assistance for containing the spread of P. *Falciparum* infection.

11. Steps have been taken for imparting health education regarding the disease and for seeking cooperation of public organisations e.g. Panchayats School teacher students, Youth Organisations, Medical Practitioners etc. in controlling the disease.

Mineral Resources of Himachal Pradesh

743. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the mineral resources tapped in Himachal Pradesh during the last three years; and

(b) the steps being taken to make a survey of all the minerals hidden in Himachal Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) During the last three years major minerals like rocksalt, limestone and barytes; besides minor minerals such as slate, ordinary clays, sand, kankar and building stones were mined in Himachal Pradesh.

(b) Geological Survey of India and State Directorate of Industries are actively engaged in survey and exploration of minerals in Himachal Pradesh. During 1977-78 field season, Geological Survey of India intends to investigate for cement grade limestone in Simla District, clay in Mandi district, slate in Kulu, Kangra and Mandi districts and for antimony-lead-zinc around Bara-Shigri glacier in Lahaul-Spiti district.

Reorganisation of Statutory Tripartite Bodies

744. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have not yet reorganised statutory tripartite bodies like the ESI Corporation, Provident Fund Trustees etc.;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Congress Government constituted these Committees on

the basis of political consideration; and

(d) the steps taken by Government to undo these political consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): (a) and (b). The question of reconstituting the statutory tripartite bodies, assuring broad based representation to the interests concerned is under consideration.

(c) No.

(d) Does not arise.

Withdrawal of victimisation measures by Employers

745. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of PALIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether several employers in the private and public sectors have not withdrawn the victimisation measures taken during the Emergency; and

(b) the steps taken by Government to ensure that private and public sector employers withdraw the victimisation measures?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDIA VAAMA): (a) and (b). Government of India laid down certain guidelines in its letter of April 1977 to all State Governments and the Central employing Ministries/Departments and requested them to ensure the reinstatement of employees who lost their jobs during the period of the emergency as a result of acts of victimisation by their employers. Replies received from the State Governments and Public Sector Corporations indicate that by and large the employees who lost their jobs on account of the operation of Maintenance of Internal Security Act, the Defence and Internal Security of India Rules and the then Government's attitudes to association with banned organisations have been taken back in service. On being informed subsequently that there were still a number of employees to be taken back in service, particularly in the private sector, Government wrote again on the 4th November, 1977, to the State Governments and the Central Employers' Organisations for taking appropriate steps to ensure the reinstatement in service by the employers the remaining affected persons in accordance with the guidelines issued in this regard. The Central Workers' Organisations have also been advised to take up any such pending cases with the concerned State Government.

Setting up of Sponge Steel Plant in Orissa

746. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Government have under consideration any proposal to set up a sponge steel plant in Orissa;

(b) whether TISCO has offered collaboration with the said project; and

(c) if so, the terms and conditions for such collaboration?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) M/s. Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd., a State Government Undertaking are considering implementation of a project, for production of 300,000 tonnes of Sponge Iron per annum. For this purpose they were granted a Letter of Intent on 5-10-77.

(b) The above project does not envisage any collaboration offered by TISCO.

(c) Does not arise.

Contract Labourers

747. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of labourers now working on contract in different organised industries in the country;

(b) the approximate number of Contract labourers in unorganised industries in the country;

(c) whether Government considers that the legislation for the abolition and regulation of the system have proved to be inadequate; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken for making suitable amendments in the existing Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) and (b). While complete and precise information regarding this is not available, on a very rough estimate, there are nearly 1 million persons employed as contract labour in the Central sphere industries.

(c) and (d). While Government do not consider that the legislation in question has proved to be inadequate the position is being reviewed by Government from time to time, in the light of experience in regard to the working of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.

Declaration of Industrial Truce

748. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare 'Industrial Truce for a year or so; and

(b) if so, the general reaction of the organised Trade Union to the said proposal?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). At the Tripartite Labour Conference held in May, 1977, the Union Labour Minister made an appeal for a period of industrial peace so as to allow Government to bring about a change in the machinery and procedure for settling industrial disputes. He again brought the issue to the notice of the representatives of the employers and employees in the Tripartite Committee on Comprehensive Industrial Relations Law and stated that it was necessary that all concerned should agree for a period of industrial peace for a year or so. The proposal was generally welcomed by both the employers and employees.

Pilferage of Foreign Mail

749. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether large pilferage is occurring in the case of foreign mail especially magazines and newspaper; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent such pilferage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) No.

(b) Does not arise.

Rise in prices of anti Malaria drugs

750. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the steep rise in the prices of anti Malaria drugs has effected the eradication of Malaria in the country; and

(b) if so, the steps taken in this regard by Government to control the spread of malaria?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) The rise in the prices of anti-malaria drugs has not appreciably effected the eradication of malaria in the country. The rise in the prices of some of the insecticides e.g. DDT, DHC and Malathion did not also effect the control of malaria during the past few years.

(b) A statement showing the steps taken by the Government to control the spread of Malaria is attached.

Statement

The following steps have been taken by Government of India for controlling Malaria:—

1. A modified plan of operations is being implemented by the Governments of States and Union Territories from the 1st April, 1977. While the ultimate objectives of NMEP continues to be eradication of Malaria for the present it is proposed to contain it.

2. The existing N.M.E.P. units have been re-organised to conform to the geographical boundaries of the districts. The Chief Medical Officer of the district has been made primarily responsible for the programme in the district.

3. Increased quantity of the required type of insecticides have been/are being provided within the available resources.

4. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas, which have incidence of two or more cases per thousand population.

5. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been supplied to the States and Union Territory Governments. Drug Depots/Drug Distribution Centres/Fever Treatment Centres have been opened from where anti-malarial drugs are available conveniently to the public free of costs. In a few areas where resistance to choloroquine by parasited has been noticed, alternative anti-malarials like quinine have been supplied.

6. Anti-larvel operations under Urban Malaria Areas programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 towns during 1977-78 besides continuing it in the already existing 28 towns.

7. For early examination of blood smears and providing quick medical treatment, to positive cases laboratory services have been de-centralised to the P.H.C. level.

8. Supervision of the field staff has been tonned up.

9. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in Malaria.

10. Intensive campaign has been started in North Eastern region with World Health Organisation assistance for containing the spread of *P. Faliparum* infection.

11. Steps have been taken for imparting health education regarding the disase and for seeking cooperation of public organisations e.g. Panchayats School teachers, students Youth Organisations, Medical Practitioners etc. in controlling the disease.

Report of Study Groups of Trade Unions constituted by SAIL

751. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Study Groups of trade unions constituted by the SAIL have submitted their reports;

(b) the nature of recommendations made by the Groups; and

(c) the steps Government propose to take on these recommendations?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) Presumably the reference is to the constitution by SAIL, of six Study Groups consisting of representatives of Steel Plants Managements and Trade unions to study various aspects of the working of the steel industry. The Study Groups have submitted their Reports.

(b) Summaries of the Reports are given in Annexures I to VI. [*Placed in Library. See* No. LT-1081/77].

(c) The Reports are presently under examination in Steel Authority of India Limited and in Government.

Alleged Charges against Officers of Labour Bureau, Chandigarh

752. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the CBI is investigating into serious charges against certain senior officers of the Labour Bureau, Chandigarh;

(b) the nature of the charges and names of officials involved; and

(c) whether Government have taken any action against the officials?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Tripartite Meeting to consider Problems of Unorganised Workers

753. SHRI SAMAR MUKHERJEE:
SHRI D. D. DESAI:
SHRI RAMESHWAR PATIDAR:
SHRI SUBHASH AHUJA:
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government gave an assurance in May, 1977 last to convene a tripartite meeting to consider the problems of unorganised workers;

(b) whether Government have convened such a meeting; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): (a) to (c). The problems of labour in the unorganised sector were discussed at the recent Tripartite Labour Conference held at New Delhi on May 6-7, 1977. The general consensus at the Conference was that, having regard to the various complex issues involved, a Special Conference should be convened to consider the problems relating to rural workers. It also decided that the nature of subjects to be discussed and nature of participants to the proposed Conference should be settled in consultation with the interests concerned, including the State Governments, Union Territory Administrations, Central Organisations of Workers and Employers etc. The suggestions received from these interests are being examined and steps are being taken to convene the proposed Special Conference soon.

Shop/Joint Councils in Central Undertakings

754. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether all the 134 Central Departmental Undertakings/Establishments have Constituted Shop Councils/Joint Councils in their respective units, as recommended in the scheme of Workers' Participation/Joint Committees;

(b) if not, the number and names of Central Undertakings that have constituted them; and

(c) the steps taken to enforce this scheme in all the public undertakings?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). According to the information so far received in the Ministry of Labour almost all the eligible units of the Central Government Public Sector Undertakings numbering 545 have either implemented or initiated steps to implement the Scheme.

(c) In pursuance of a recommendation of the Tripartite Labour Conference held on 6-7th May, 1977, a tripartite committee has been set up to make a comprehensive review of the Scheme of Workers' Participation in Management and Equity.

Import of Contraceptives

755. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether contraceptives like jellies, foam tablets, diaphragm and oral pills. are imported and if so, the value of imports during the past three years;

(b) if not, the names of manufacturers in India of these contraceptives; and

(c) the annual sale value thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Jellies and foam tablets are being manufactured indigenously and during the past three years no import of these items has been made.

(ii) Diaphragms are not manufactured in India. Imports are made as per requirements. No imports have been made in the last three years.

(iii) During 1975-76 oral pills were imported through UNFPA to the tune of Rs. 14.35 lakhs and raw material for pills to the tune of Rs. 8.65 lakhs. Subsequently, the tabletting facilities were developed in the country by M/s. I.D.P.L. and M/s. Haffkine Bio-Pharmaceuticals, Bombay and the raw material worth Rs. 6.54 lakhs was imported during 1976-77 through UNFPA assistance.

(b) At present following firms are manufacturing approved brands of jellies. foam tablets, and tebletting the oral pills:

(i) Jellies: M/s. Ethnor Ltd., Bombay.

(ii)Foam tabets: Ms. Smith Stanistreet and Co. Ltd., Calcutta.

(iii) Tableting Oral Pills: M/s. IDPL, New Delhi (Public Undertaking).

Ms. Haffkine Bio-Pharmaceuticals, Bombay.

(c) During 1976-77 stock of Jellies, foam tablet, diaphargms and oral pills of the following value have been supplied to the State Governments, Union Territories and other organisations.

(i) Jellies:	Rs. 3.47 lakhs.
(ii) Foam Tablets:	Rs. 0.25 lakhs.
(iii) Diaphragms:	Rs. 0.01 lakhs.
(iv) Oral Pills:	Rs. 8.67 lakhs.

Deposit of Sulphur and Borax in Ladakh

756. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total deposit of sulphur and borax estimated in Ladakh area; and

(b) whether Government propose to expedite exploring of these deposits and setting up of a refining unit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). In Ladakh district reserves of 5400 tonnes of borax have been estimated. Besides about 1250 tonnes of borax are getting replenished every year as surface encrustations. About 210,700 tonnes of crude sulphur with

8.65 to 25.45 percent purity are estimated in Puga Valley. There is no proposal for setting up a refining unit in the area or for further exploration of these deposits at present.

Tin Deposits in Bastar District in M. P.

757. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of tin deposits have been found in Bastar District in Madhya Pradesh;

(b) what are the estimated deposits;

(c) whether there is any proposal to extract these deposits in the near future; and

(d) if so, whether the proposed tin mines will be in public sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). Occurrence of tin associated with certain pegmatites has been established in certain parts of Bastar district of Madhya Pradesh. Regional surveys by the Geological Survey of India and detailed exploration by the Department of Geology and Mining, Government of Madhya Pradesh, are still being carried out for estimation of reserves.

(c) and (d). It is premature to consider the extraction and exploitation of these deposits at this stage.

Execution of Orders for Supply of Steel Products by TISCO, IISCO & HSL Ltd. by Private Dealers

756. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that TISCO, IISCO and Hindustan Steel Ltd. are not executing the orders booked by the private dealers for the supply of various steel products manufactured by them for the last 5-6 years although earnest money had been deposited therefor;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the amount of orders still pending for execution with these three units as on 1-10-1977 and steps Government propose to take to ensure that these orders are executed without any further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Grant of Telephone Connections/Extensions to Officers of Telephone Department

759. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any limit has been fixed about the number of parallel telephone connections and extensions which an officer of the Telephone Department can have at his residence and if so, what;

(b) whether any orders have been issued about the period for which an officer can retain his residential telephone with extension or otherwise while he goes on leave, placed under suspension or transferred and if so, what; and

(c) whether he is aware that very large number of officers of Delhi Telephone District are having parallel/extensions connections and unlimited telephone cables etc. at their residence and if so, whether he will get the matter investigated and put a stop to this unhealthy practice by these officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Parallel tele-

phone is provided under IPT Plan 101 and a maximum of 2 telephones can be connected in parallel subject to certain conditions. Plug and Socket arrangement is provided under IPT Plan 102 and a maximum of 4 sockets are permitted. Internal extensions with inter-communication facility is provided under IPT Plan 103 and a maximum of 2 extensions are permitted. External connections with communications facility is provided under IPT Plan 104; only one extension is permitted. Extension without inter-communication facility is provided under IPT Plan 105 and only 1 extension is permitted. These limits applies to official connections provided to the officer of Telephone Department as well.

(b) The Service telephone connections at the residences of the officers of the P & T are permitted to continue in the following cases.

(1) When an officer proceeds on leave and is likely to return to the same station.

(2) When an officer leaves the station on temporary transfer, and

(3) When an officer is deputed by the Department for training or other Departmental work away from the station.

The facility is allowed for a period not exceeding 6 months.

(c) This is being checked and if any non-standard or unapproved facilities are found on residential Service telephones of P & T officers, these will be terminated.

डाकघरों में कटे फटे और खराब नोटों का बदला जाना

760. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार बोर्ड कटे फटे और खराब नोटों को डाकघरों के माध्यम से बदलने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

संचारद मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख). डाकघरों में एसे करेंसी नोट स्वीकार किए जा रहे हैं जो जरा खराब या थोड़ विकृत हों । डाकघरों में कटे फटे करेंसी नोट स्वीकार करने या बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दुर्ग कांग्रेस समिति को 20,000 रु० की धन राशि का भुगतान

761. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के लिए मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने दुर्ग कांग्रस समिति को 20,000 रु० की धनराशि का भुगतान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि इस बीच वसूल कर ली गई है और उक्त इस्पात संयंत्र ने इतनी बड़ी धनराशि दुर्ग कांग्रेस समिति को किस आधार पर दी थी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही ही है?

इस्पात और खान मंत्री श्री (बीजू पटनायक) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि मार्च, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सम्बोधित की जाने वाली सार्वजनिक सभा के मंच आदि का निर्माण करने के लिए भिलाई इस्पात सयंत्र ने दुर्ग कांग्रस समिति को 20,000 रू० की धनराशि दी थी । लेकिन मार्च, 1977

में भिलाई में तत्कालीन प्रधान मंत्री की उपर्युक्त सार्वजनिक सभा के सम्बन्ध में दुर्ग प्रशासन की विशेष प्रार्थना पर कुछ प्रबन्ध किए गए थ जिन में भाषण मंच के चारों और जंगला लगाने, पानी की टंकी और बचाव व्यवस्था शामिल थीं । यह प्रबंध इस स्पष्ट धारणा से किऐ गए थे कि इनका भुगतान कया जाएगा । तदनुसार उपर्युक्त सेवाओं के लिए जिला प्राधिकारियों को भुगतान के लिए 21,985 रुपय के खर्चे के बिल भेजे गए थे । अभी तक इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और कारखाने के प्रबंधक जिला अधिकारियों से इस मामले में लिखा–पढ़ी कर रहे हैं ।

अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति

762. **श्री दयाराम शाक्य : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दसवीं क्षा पास कर्मचारियों कों पांच वर्ष की सेंवा के बाद पदोन्नति देती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में इसी योग्यता वाले ड्रेसरों की पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी किसी तकनीकी पद पर पदोन्नति नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(ख) और (ग) अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में काम कर रहे ड्रेसरों की पदोन्नति सबंधी अवसर वैसे ही हैं कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिये हैं । ये अवसर उच्च ग्रेड में पदों की उपलब्धता और उनके लिये उम्मीदवारों के पास अपेक्षित अर्हतायें होने पर निभर करते हैं । जो ड्रेसर अपने पद पर स्थायी होते हैं और जिनकी अपने ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की सेवा होती है वे ही सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के पात्र होते हैं ।

इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता

763. **श्री दया राम शाक्य : इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों में फालतू पुर्जों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई दल नियुक्त किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल द्वारा क्या सिफारिश की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री करिया मुण्डा) :

(क) और (ख) : जी, नही । फिर भी, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल, 1973 में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं-का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्ति की थी । समिति ने फालतू पुर्जों की आवश्यकातओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

1. सभी इस्पात कारखानों में सर्वनिष्ठ समान रूप से काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, मध्यम तथा भारी श्रेणी के फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना की जाये ।

2. इस्पात कारखानों की इंजीनियरी कर्मशालाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ।

3. केन्द्रीय कर्मशाला के साथ रूपांकन तथा मानकीकरण का एक सशक्त अनुभाग सम्बद्ध किया जाए ।

उपर्युक्त के आधार पर मध्यम भारी श्रेणी के फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था । लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पर काफी धनराशि खर्च होगी और चूंकि देश में फालतू पुर्जे बनाने की क्षमता पहले ही उपलब्ध है, इस प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है ।

भारत में अंधे व्यक्तियों की संख्या

764. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में अंधे व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या है और उनके अंधेपन का कारण उनका नंगे पैर रहना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)

(क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Strike by Nurses of Irwin and Pant Hospitals of Delhi

765. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether nurses of Irwin and Pant Hospitals of the Capital went on a strike recently;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) on what conditions the strike was withdrawn and the steps taken to implement the assurances given to them together with the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) A staff Nurse of G.B. Pant Hospital was found dead in the Operation Theatre on the night of 20th September 1977 and the nursing staff was not satisfied with the preliminary enquiries.

(c) The strike was withdrawn after the Executive Councillor (Medical had a meeting with the Delhi Nurses Association on 23rd September 1977. In pursuance of the assurances given to the representatives of the Delhi Nurses Association, the administration have taken the following steps:—

(i) The call duty system of the nurses has been suspended.

(ii) The Deputy Nursing Superintendent of the G.B. Pant Hospital has been transferred.

(iii) The monthly meetings with the representatives of the Delhi Nurses Association are being called by the Medical Superintendents of the Hospitals. One such meeting has already been held in October, 1977.

(iv) Additional safety measures for the nurses residing in the Nurses Hostel and while on duty in the Hospital have been taken.

Representation against appointment of Chairman Posts and Telegraphs Board

766. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that different P&T employees associations have represented against the appointment of a non P&T cadre man as the Chairman of the P&T Board; and

(b) if so, the details thereof, and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) and (b). The two Federations of P&T Employees and the Telegraph Engineers Association had sent representations against the posting of a non-P&T officer as Chairman, P&T Board and Secretary Ministry of Communications.

The Secretary, Ministry of Communications is also the Director-General, Post and Telegraphs and the Chairman, P&T Board. According to the prescribed procedure, appointments to the post of Secretaries are made after considering the claims of various officers, whether serving in the Government of India or in the States. The appointment of the present Secretary, Ministry of Communications, Director-General, P&T and Chairman, P&T Board has been made by the Government in accordance with the prescribed procedure.

नौकरियों के लिये अरब देशों को गये भारतीय

767. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार की खोज में प्रत्येक अरब देश में गए शिक्षित तथा अशिक्षित भारतीयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अशिक्षित व्यक्तियों से उनको रोजगार हेतु एक अरब देश में भेजने के लिए बीसा प्राप्त करने हेतु पांच अथवा छः हजार रुपए लिए जाते हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए दिल्ली तथा बम्बई में अनेक अप्राधिकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं जहां जाली नामों से रसीदें जारी की जाती हैं ;

(घ) क्या ऐसे व्यक्ति रुपए प्राप्त करके लुप्त हो जाते हैं

(ङ) क्या सरकार का विचार नौकरी की तलाश करने वाले ऐसे व्यक्तियों को विदेश भेजने के लिए कुछ प्रबंध करने का है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अरब देशो में रोजगार की तालाश में गए शिक्षितों तथा अशिक्षितों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है । श्रम मंत्रालय, भर्ती एजेंटों तथा ठेकों तथा उप ठेकों के आधार पर परियोजनाओं के कार्य में लगी भारतीय फर्मों के माध्यम से खाड़ी के देशों में रोजगार के लिए भारतीय कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल कामगरों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करता है । उन कामगारों की संख्या जिनकी नियुक्ति के लिए ऐसी अनुमति जारी की गई है, सभा पटल पर रखे गए विवरणों i तथा ii में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल टी 1082/77]**

(ख) से (घ) . सरकार को समय-समय पर विभिन्न स्थानों से भर्ती एजेंटों द्वारा रुपया वसूल करने तथा अन्य अनाचारों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ङ) और (च) . जून, 1976 में सरकार द्वारा नीति निर्णय के अनुसार कोई भी फर्म, संगठन या व्यक्ति विदेश में नियुक्ति के लिए भारत कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती तब तक नहीं करेंगे, जब तक इस उद्देश्य के लिए वह श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत और विधिवत लाइसेंस प्राप्त न हों, जिसे इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय शाखा (फोकल प्वाइंट) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । विदेशी फर्मों और संगठनों को भी कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की सीधी भर्ती करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि

वे इस केन्द्रीय शाखा के साथ पंजीकृत किसी भारतीय कम्पनी/संगठन को, केन्द्रीय शाखा को मान्य शर्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए अपनी ओर से कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं। विदेशों में परामर्शदाता/निष्पादन कार्य में व्यस्क भारतीय फर्मों/संगठनों को उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में सेवाहेतु श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाने वाली रोजगार की शर्तों पर कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल कामगारों की सीधी भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

P. C. Os and Sub-Post Offices opened in Orissa

769. SHRI JENA BAIRAGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the number of P.C. Os. and Sub-Post Offices and Branch Post Offices opened in Balasore District of Orissa during March to October, 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): During the period from March to October, 1977 two P.C.Os. and three E.D. Branch Offices have been opened in Balasore District of Orissa. No Sub-Post Office was opened during this period in the District for the present.

Strike in H.S.C. Ltd.

771. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the workers of Hindustan Steel Construction Limited. went on strike during September, 1977; and

(b) if so, the reasons for the strike and total loss in production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) The workers of Hindustan Steel works construction Limited at Bokaro went on strike from the 27th August, 1977 to the 10th September, 1977.

(b) The main reasons for the strike were the following demands of workers:—

(i) Adoption of the Steel-wage pattern for H.S.C.L. workers;

(ii) Judicial Inquiry into the incident of police firing at Bokaro on the 27th August, 1977;

(iii) Suspension of the Magistrate who ordered firing;

(iv) Withdrawal of C. R. P. from Bokaro; and

(v) Release of the arrested workers.

The total loss in H.S.C.L's turnover, as a result of he aforesaid strike, was of the order of Rs. 38 lakhs.

कुनैन की नकली गोलियों का निर्माण

772. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "कुनैन की गोलियां खड़िया मिट्टी की" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नकली दवाइयों का निर्माण करने वाली फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव):

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

रूस के सहयोग से इस्पात कारखाने की स्थापना

774. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में रूस के सहयोग से भारत में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की जा रही है जैसा कि 21 सितम्बर, 1977 के "नवभारत टाइम्स" में "रूस के सहयोग से इस्पात का कारखाना" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस इस्पात संयंत्र में रूस कितना सहयोग देगा और इस सम्बन्ध में उसकी शर्तें क्या होंगी तथा कब से यह कारखाना उत्पादन शुरू कर देगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) . बन्दरगाह की सुविधा वाले किसी नगर में निर्यातोन्मुख धमन भट्टी लगाने के बारे में सोवियत रूस के उस तकनीकी प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की गई थी जिसने अगस्त-सितम्बर, 1977 में हमारे देश का दौरा किया था । इस्पात और खान सचिव ने भी जो हाल ही में सोवियत रूस के दौरे पर गए थे, इस प्रकार के प्रस्ताव पर मुख्य रूप से सोवियत रूस की प्रतिक्रिया जानने के लिए, सोवियत अधिकारियों से बातचीत की थी । सोवियत सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर आगे विवरण और प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे । इस समय अंतिम निष्कर्ष के बारे में बताना समयपूर्व होगा ।

देश में कैंसर जांच और उपचार केन्द्रों की स्थापना

775. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंसर की जांच करने के संबंध में देश में वस्तुत : कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) देश में कितने कैंसर जांच केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उक्त केन्द्रों में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

(ग) इन तीनों ही केन्द्रों में ऐलोपैथिक उपचार होगा ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों की नसबंदी

776. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ विभाग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने आपातस्थिति के दौरान नसबंदी कराई है; और

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कि क्या इन कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अथवा अन्यथा नसबंदी कराई, सरकार का कोई जांच कराने का विचार है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) और (ख) . अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते

हीं इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा। जांच कराने के प्रश्न पर इस सूचना की प्राप्ति के बाद ही विचार किया जाएगा।

Jobs to Unempolyed

777. SHRI K. T. KOSALRAM:
SHRI MADHAVRAO SCINDIA:
SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the latest figure of unemployed persons in the country and the number of educated unemployed among them;

(b) the break-up of unemployed persons in the urban and rural areas; and

(c) the schemes undertaken by Government to solve the problem of unemployment and how many unemployed persons are expected to be covered during the current financial year?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Available information relates to the number of jobseekers registered with the Employment Exchanges as on 30-6-77, which was 104.06 lakhs; out of them 53.98 lakhs were educated (Matriculates and above).

(b) Accodring to an *ad hoc* survey conducted in the year 1973 about 47 per cent of the job seekers registered with the Employment Exchanges were found to be from rural areas.

(c) Government proposes to follow Employment Oriented Strategy in the next Five Year Plan. Additional employment is likely to be created among others, in agriculture and allied fields, in irrigation and small and cottage industries' sectors, with appropriate emphasis on area planning.

Permission to ONGC for having own Troposcatter Communication Link

778. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether ONGC has been permitted to have its own troposcatter communication link between Bombay High Offshore platform and the shore based terminal at Karnali Hill; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). The choice of a suitable medium *viz.*, satellite or troposcatter, for the communication link between Bombay High Shore Platform and the shore terminal is still under discussion between the Ministries of Communications and Petroleum. Hence, the question of permission at this stage does not arise.

हज यात्री

779. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम होती है; और

(ख) क्या हज यात्रियों को अपने साथ बहुत कम राशि ले जाने दी जाती है और क्या इस राशि को बढ़ाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) प्रति वर्ष हज पर वस्तुतः जाने वालों की संख्या प्रायः उस वर्ष के लिए निर्धारित संख्या के बराबर ही होती है। उदाहरण के लिए जनवरी 1974, दिसम्बर, 1974,

1975, 1976 और 1977 में हज यात्रियों की निर्धारित संख्या 17000, 19000, 17000, 17000 और 19000 थी जबकि क्रमशः 16940, 18887, 17205, 15996 और 18706 व्यक्ति हज यात्रा पर गये। 1976 में इनकी संख्या कम होने का कारण यह था कि हज के मौसम में यात्रियों के दो जहाज अचानक खराब हो गये थे।

(ख) हज यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा सऊदी अरब की सरकार के नियमों और वहां के तत्कालीन निर्वाह व्यय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। समुद्री मार्ग से जाने वाले हज यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा बढ़ाकर 1977 में 2000/- सऊदी रियाल कर दिया गया है जो कि 1974 में 1100/- सऊदी रियाल था। यह समझा जाता है कि हज सम्बन्धी आवश्यक प्रभारों पर सामान्य रूप से होने वाले खर्च के लिए तथा आवास, भोजन तथा अन्य आमस्मिक खर्चों के लिए यह राशि पर्याप्त हैं। इस समय विदेशी मुद्रा के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु 1978 में होने वाली हज यात्रा से पूर्व इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया जायगा।

ग्रामीण डाकघरों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि

780. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या देश भर में निर्दिष्ट दूरी पर डाकघर खोलने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) विभागेतर एजेंटों के मजदूरी के ढांचे का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जब कि शहरी इलाकों में डाकघर खोलने के लिए कोई खास दूरी निर्धारित नहीं की गई है, सरकार ने देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए दूरी सम्बन्धी खास कसौटी निर्धारित की है।

विभागीय मानदंडों के अनुसार, जिनमें दूरी सम्बन्धी कसौटी भी शामिल है, डाकघर विभिन्न चरणों में खोले जाते हैं।

(ग) देहाती इलाकों के डाकघरों में जहां भी मौजूदा उदार नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन घरों की मंजूरी दी जा सकेगी, वहां उत्तरोत्तर सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित कर दिए जायेंगे।

सीतापुर जिला, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन विभाग के कार्य संचालन में सुधार

781. **श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सीतापुर जनपद (उ० प्र०) में टेलीफोन विभाग का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चल रहा है ;

(ख) क्या सरकार इसमें सुधार करने के लिए कोई कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं। सीतापुर जिले में टेलीफोन सेवा सुचारू रूप से दी जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न हो नहीं उठता।

डाक और तार विभाग में एजेंटों को भत्ता

782. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक और तार विभाग के एजेंटों का भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और कितना ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई): (क) और (ख). विभागेत्तर एजेंटों के भत्तो में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Reduction of Permanent Workers by Foreign Multi-National Corporations

783. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether it has been brought to his notice that the Pfizer, International Business Machines, and Hindustan Lever; foreign Multi-National Corporations operating in India have in a systematic and planned manner, reduced their permanent work force by increasing the number of contracts/casual workers; and

(b) if so, the details thereof and the action taken in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). Government received some representations alleging wrongful termination of permanent employees and increase in casual and contract labour force by some multi-national corporations. The matter falls essentially in the State sphere and has been brought to the attention of the State Governments concerned.

Action against large and medium Companies for not giving Bonus

784. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) how many large and medium companies have not given statutory minimum bonus as per provisions of the recent bonus ordinance; and

(b) what action, if any, is proposed to be taken against those companies?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) The information is not yet available; the 'appropriate Governments' for bulk of the establishments coming within the purview of the Act are the State Governments/Union Territories.

(b) Section 19 of the Payment of Bonus Act, 1965 provides a time limit of 8 months for paying bonus; the time limit can be extended by the 'appropriate Government'. The Act also contains provisions for dealing with the defaulting employers.

Official Study Group on the expansion of Steel Industry

785. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether an official study group on the expansion of the Steel Industry appointed by him has opposed the use of private foreign investment; and

(b) if so, what action, if any, is being taken on the said report?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). The Study Group on Expansion of Steel Industry, comprising representatives of Steel Plants' Managements and Trade Unions, which was constituted by SAIL in April, 1977.

has recently submitted its report. The report, in its recommendations on financing, has stressed the need for finding the necessary finance, to the extent possible, from within the country. The report has also observed that when outside finance is unavoidable, this should be arranged at the State level on Government to Government basis.

The report of the Study Group is presently under examination in Steel Authority of India Ltd. and in Government.

Corruption and favourtism in Indian Council of Medical Research

786. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether he has received reports of irregularity, corruption and favourtism in the Indian Council of Medical Research;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) action, if any taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Copies of an anonymous note, apparently, written by a disgrauntled employee of the Council, containing allegations of irregularities in the functioning of the Council was received from some Members of Parliament some time ago. After looking into the matter, the allegations were found to be baseless.

Strike in Bokaro Steel Plant

787. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the workers in Bokaro Steel Plant went on strike in September, 1977;

(b) the reasons for the strike; and

(c) the steps taken by Government to improve the situation in Bokaro?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) There was a one-day strike in Bokaro Steel Plant on the 21st September, 1977.

(b) The strike was called in response to a charter of demands given by Bokaro Steel Employees Progressive Front which, *inter alia* had asked for the following:—

(i) Election to Union through secret ballot;

(ii) Annual bonus @12.5 per cent;

(iii) Incentive scheme; and

(iv) Reinstatement of employees whose services had been terminated,

(c) The following steps have since then been taken:—

(i) The question regarding election through secret ballot has been referred to the State Government for taking early action;

(ii) *Ex-gratia* payment @ 8.33 per cent has been made for the year 1976-77;

(iii) An incentive scheme has been introduced with effect from 1-10-1977; and

(iv) Conciliation proceedings have been initiated by the Deputy Labour Commissioner.

During October, 1977 no manday was lost in Bokaro Steel Plant. The labour situation there is normal at present.

Prohibition Policy in Diplomatic Missions Abroad

788. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether instructions have been recently issued to the Indian diplomatic missions abroad to observe the new prohibition policy, if so, details thereof;

(b) whether a complete ban is proposed on serving drinks by our diplomatic missions abroad while hosting receptions etc.; and

(c) if so, facts thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) to (c). There are standing instructions governing the consumption of alcoholic beverages by Government servants, whether in India or broad. The Ministry of External Affairs have issued guidelines in the light of India's policy of prohibition regarding the consumption of alcohol. The serving of alcoholic beverages on National Day receptions is banned.

Setting up of Hospitals in Delhi

789. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the present facilities in hospitals in Delhi are insufficient to cope with the increasing rush of patients;

(b) if so, the doctor-patient ratio in Delhi hospitals and how it compares with hospitals in developed countries; and

(c) whether any steps are being taken to set up more hospitals in Delhi to meet the needs of its growinng population and if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) Information regarding doctor-patient ratio is not available. For every 100 beds in Delhi hospitals, 11.9 doctors are in position. The bed population ratio in the hospitals in Delhi is 3 beds per 1000 population. The bed population ratio for India and for some of the developed countries is as follows:-

India	1 bed for 4,000 population
U.S.A.	1 bed for 600 Population
Japan	1 bed for 860 Population
U.K.	1 bed for 760 Population
U.S.S.R.	1 bed for 390 Population
Canada	1 bed for 630 Population

(c) Proposals for opening two 500 bed hospitals—one each at Hari Nagar & Shahdara and seven 100 bed hospitals in rural /peripheral areas of Delhi are under consideration.

Improvised Accommodations for C.G.H.S. Dispensaries

790. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether most of the G.G.H.S. dispensaries in Delhi are located in improvised accommodations and if so, reasons therefor;

(b) the number of dispensaries which are housed in properly built buildings and those housed in improvised premises; and

(c) the steps being taken to provide proper buildings for the affected dispensaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, Sir. Non-availability of land for construction of C. G. H. S. dispensaries and inadequacy of funds for undertaking the construction works are the main reasons;

(b) No. of dispensaries housed in buildings 21 constructed according to standard specifications.

No. of dispensaries housed in 41 improvised Government/rented buildings.

(c) Efforts are being made to

(i) secure suitable plots of land from the D.D.A. and other agencies in various localities; and

(ii) to secure adequate funds for undertaking the construction of C. G. H. S. dispensaries on the plots of land already available for the purpose.

Harassment to the Bonafide Indian Tourists visiting England

791. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints about harassment to the bonafide Indian tourists visiting England;

(b) whether the British Minister visited India recently to look into such complaints and to streamline the procedure regarding Indian tourists' visits to U.K.; and

(c) whether any negotiations have taken place with the British Government on this issue and if so, the full facts?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) No specific complaints have been recived in the Ministry of External Affairs in recent months.

(b) A Minister from the British Foreign Office visited India in early October but his visit was in no way connected with the streamlining of procedures for Indian tourists visiting U. K.

(c) Does not arise.

Patients and Doctors in Central Leprosy Teaching and Research Institute Chingleput

792. SHRI O. V. ALAGESAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of patients and doctors in the Central Leprosy Teaching and Research Institute (CLT & RI) at Chingleput;

(b) the maximum number of patients treated in the CLT & RI in any year;

(c) the research activities of the Institute;

(d) how many research papers were prepared and presented by the Institute before National and International forums during the last three years; and

(e) for how many years the present Director has been in this Institute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) (a) Number of patients treated separately in the hospital wards, O. P. D. and Mobile Clinic for the years 1974, 1975 1976 and upto 30th September, 1977 during 1977 is as follows:—

	Wards	O.P.D.	Mobile Clinic.
1974 .	2,318	46,158	2,398
1975 . .	1,465	32,636	2,320
1976 . .	1,440	38,057	1,887
1977 (upto 30-9-77	1,554	30,426	551

The number of posts of doctors sanctioned and number in position is as follows:—

	1974	1975	1976	1977
No. of posts sanctioned .	24	22	19	19
No. of Doctors in position .	14	15	14	15

(b) 50,874 during 1974.

(c) Research activities of the institute consists of clinical, surgical laboratory and epidemiological studies on leprosy. The total number of studies undertaken during each of the three years 1974, 1975 and 1976 is 9.

(d) The number of research papers prepared and presented by the institute are as follows:-

	1974	1975	1976
Published	7	15	15
Read	8	8	11

(e) The present Director has functioned in the position of Director from 1967 and as Head of Laboratories Division from 1961 to 1967.

नई परिवार कल्याण योजनाएं

793. **श्री बृज राज सिंह :**

श्री डी० वी० चन्नगौडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की नई परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परिवार छोटा रखने के लिए लोगों पर दबाव डालने के स्थान पर उन्हें इस सम्बन्ध में उत्साहित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). परिवार कल्याण कार्यक्रम को बिना किसी दबाव या जोर-जबरदस्ती के पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाता है। जन्म-दर को घटा कर 1979 तक 30 प्रति हजार और 1984 तक 25 प्रति हजार तक लाने के अपने वायदे को सरकार के लिए दोहराया है । जून, 1977 को घोषित नीति के वक्तव्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध है तथा वह लोगों को स्वेच्छा से अपने निजी हित में, अपने बच्चों के हित में तथा राष्ट्र के व्यापक हित में इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। सरकार की नीति शैक्षिक और पूर्णतया स्वैच्छिक होगी। गर्भ-रोधक के सभी तरीकों को जिनमें स्वैच्छिक नसबन्दी भी शामिल है, बढावा दिया जाना है और स्वीकारकर्त्ता कोई सा भी अपना मन-भाता तरीका चुन सकता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली अन्य एजेन्सियों से भी अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम को उच्चतम महत्व दें और यह सुनिश्चय करावें कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन करवाना चाहे, उन्हें इसकी आवश्यक सुविधायें अवश्य दिलाई जायें । इस कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों से विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि इस कल्याणकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कोई शिथिलता अथवा उदासीनता नहीं आनी चाहिए । श्रमिक संघों के नेताओं/कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे छोटे परिवार के सिद्धान्त की स्वीकृति को बढ़ावा दिलाने में सरकार की सहायता करें। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी ने विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों से भी अनुरोध किया है कि वे छोटे परिवार के आदर्श की स्वीकृति को उत्साहित करें । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में, जिसे इसी वर्ष 777 प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में चलाया गया है, इन रक्षकों द्वारा ग्रामीण लोगों को परिवार कल्याण की जानकारी देने की भी व्यवस्था है ।

Waiting list for Telephone connections in major cities

794. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps in the last few months to wipe out the waiting list for telephone connections in major cities; and

(b) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) and (b). Yes, Sir. The Government has taken steps to meet the telephone demand at all places in the country including the major cities. At the beginning of the year, i.e., on 1-4-77, there was a waiting list of about 1,52,000 in the 19 large cities in the country. It is hoped to provide about 1 lac new telephone connections in these places during the current financial year. Of these, approximately 33,000 connections have been provided during the first 6 months of the year.

Labour unrest in Faridabad, Bombay-Poona and Madras Industrial Areas

795. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the industrial areas of Faridabad, Bombay-Poona and Madras have been victims of widespread labour unrest in the last six months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what steps have been taken to remove the cause of this unrest; and

(d) whether Government suspects organised sabotage in these areas and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). The Government has received reports of industrial unrest in the industrial areas of Faridabad, Bombay-Poona and Madras during the last six months. The matter essentially falls in the State sphere.

Bonus to Workers of Burhampur Tapti Mills

796. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state whether Bonus has been given to the workers of Burhampur Tapti Mills, an undertaking of N.T.C.?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Bonus for 1976-77 is reported to have been paid to the workers of Burhampur Tapti Mills.

Losses in Hindustan Zinc Ltd., Udaipur

797. SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Hindustan Zinc, Udaipur the average treated ratio for the zinc cathode to celeine is only 0.39 which is 25 per cent less than the normal efficiency;

(b) is it not also a fact that due to below normal efficiency Hindustan Zinc has incurred a loss of Rs. 40 lakh from June 1976 to February 1977; and

(c) the steps taken to stop the losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) to (c). The average ratio beteeen zinc cathode and calcine during 1976-77 was 0.46 (and not 0.39) against the normal ratio of 0.50 attainable. The reduced recovery was mainly due to disruptions that occurred in the process of change-

over from the old batch leaching/ purification process to sophisticated continuous process, and trial runs of the expanded smelter.

2. Due to reduced recovery the quantity of zinc which found its way into the 'Moore Cake' (which is the leaching and purification residue) was more than normal. The 'Moore Cake' is being accumulated, and will be treated by the company for recovery of zinc. Action has already been initiated for getting the requisite know-how for recovery of zinc from the accumulated 'Moore Cake'.

3. The operations of the expanded smelter at Debari are gradually stabilising, and the recoveries during the current year have improved very considerably.

सौराष्ट्र में टेलेक्स एक्सचेंज

798. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रदेश में धारोजी, जूनागढ़ और वेरावल नगरों में नये टेलेक्स एक्सचेंज खोले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे और प्रत्येक टेलेक्स एक्सचेंज के अधीन कितने टेलेक्स टेलीफोन होंगे; और

(ग) क्या सौराष्ट्र प्रदेश के अन्य नगरों में भी नये टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन नगरों से और उन नगरों में कब टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित हो जायेंगे और प्रत्येक एक्सचेंज के अधीन कितने टेलेक्स टेलीफोनों की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी योजना है कि 20-20 लाइनों की क्षमता के तीनों टेलेक्स एक्सचेंजों को वर्ष 1978-79 में चालू कर दिया जाये ।

(ग) और (घ) सौराष्ट्र क्षेत्र में नये टेलेक्स खोलने का फिलहाल कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

पोरबंदर में डाक छंटाई कार्यालय

799. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के औद्योगिक नगर पोरबन्दर में डाक छंटाई कार्यालय स्थापित करने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) यह कार्यालय कब स्थापित हो जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) उपयुक्त भवन के उपलब्ध न होने और कुछ छोटी-मोटी स्टाफ की समस्या के कारण पोरबन्दर में छंटाई डाक कार्यालय नहीं खोला जा सका ।

(ख) उपयुक्त भवन के उपलब्ध हो जाने पर पोरबन्दर में तुरन्त छंटाई कार्यालय स्थापित कर दिया जाएगा ।

(ग) पोरबन्दर में एक छंटाई कार्यालय स्थापित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । इस कार्यालय के लिए एक इमारत प्राप्त करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं ।

गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में कोयले और तांबे आदि के निक्षेप

800. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में ओसाम, आलेच बार्डी, गिरनार, गिर, कच्छ, सैनरुजय आदि पाहड़ियों और अन्य छोटी पहाड़ियों में कोयले, तांबें, चूने के पत्थर, जस्ता, सीसा, एल्यूमिना, बौक्साइट आदि के निक्षेप हैं;

(ख) क्या सरकार ने गुजरत के सौराष्ट्र प्रदेश में खनिज निक्षपों के लिए सर्वेक्षण कराया है या कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमानतः कितनी मात्रा में यह निक्षेप मिलने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सौराष्ट्र क्षेत्र में अनेक खनिज भंडारों का पता लगाया है और आगे का खोज कार्य जारी है।

(ग) और (घ). अब तक हुए खोज कार्य के फलस्रूप विभिन्न जिलों में अनुमानित खनिज भंडार नीचे दिए गए हैं :—

	भंडार (मिलियन) टनों में)
1. बौक्साइड	
अमरेली . . .	0.146
भावनगर	5.00
जामनगर	16.21, 20.34 (बौक्साइट क्ले)
जूनागढ़	27.98
2. बेन्टोनाइट	
सौराष्ट्र क्षेत्र	12.00
3. केलसाइट	
अमरेली	0.859
जूनागढ़	0.029
4. कोयला	
सौराष्ट्र क्षेत्र	2.9
5. चूना पत्थर	
अमरेली	64.5
भावनगर	20.00
जामनगर	5.00
जूनागढ़	30.00
6. फायर क्ले	
सुरेन्द्र नगर	9.747
7. जिप्सम	
जामनगर	0.175
8. गेरू	
सुरेन्द्र नगर	3.00
राजकोट	0.5

12 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRIMATI INDIRA GANDHI AND OTHERS—*Contd.*

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Sir, I have a point of order. Yesterday when I tried to invite the attention of the House to the rule saying that not more than one motion can be moved on any day about question of privilege, you had given the ruling yesterday referring to the rules and interpreting that more than one motion can come provided other motions are moved by other Members. If that is so, then my point of order today is two-fold. One is that in today's order paper I find that only Shri Madhu Limaye's motion is printed whereas Shri Kanwarlal Gupta's motion is not printed. Today's Order Paper should have both the motions moved yesterday, and both the motions must come in the House today so that the House would know what those motions were. The whole point of Mr. Stephen's argument yesterday was that the House must know what motions of privilege were moved yesterday so that only then we can know how to proceed in the matter. While Shri Madhu Limaye's motion was admitted and preliminary discussion had already started, you also said earlier that there was an identical motion moved by Shri Kanwarlal Gupta. But I find in the order paper that only Shri Madhu Limaye's motion is printed, and not Shri Kanwarlal Gupta's motion also with the result that Shri Stephen's point of view which you upheld yesterday according to which the debate was postponed from yesterday to today still holds because the information supplied by the office is inadequate and incomplete, because we are not in possession of the motion moved by Shri Kanwarlal Gupta. Secondly please see the bulletin and the record of the proceedings of yesterday which say that Shri Kanwarlal Gupta MP participated and supported the motion of Shri Madhu Limaye. Yesterday's proceedings do not say that Shri Kanwarlal Gupta, MP, moved another identical motion on the subject during the day. It is not there. I think this irregularity has to be explained somehow by your ruling. That is why I am seeking your guidance.

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री कवंर लाल गुप्त का आइडेंटिकल मोशन है तो उन का नाम भी उस में जुड़ जाना चाहिए ।

MR. SPEAKER: It is not an identical motion.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am not challenging.

MR. SPEAKER: ou are right. They are not identical motions. The office had to print the motion of Shri Kanwarlal Gupta also and if the bulletin or the record mentions merely that he supported it, it is not correct. The motion was also not worded identically.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am grateful to you for this. But I want to be doubtly assured on this point.

MR. SPEAKER: I can only give one assurance, not double assurances.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I want to be doubly assured about what happened yesterday and what is happening today, now.

MR. SPEAKER: I have allowed the two motions to be moved, one by Shri Madhu Limaye and another by Shri Kanwarlal Gupta and it is on that basis I said that there were two motions and the two motions were allowed.

They overlap one another to many an extent but they are different

[Mr. Speaker]

motions altogether. They have given two different motions. I do not know why the Bulletin was published that way. Anyway I shall look into the matter. They are not identical.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I am grateful to you for the explanation. I want to be doubly assured about another aspect of the matter. It is important.

MR. SPEAKER: If the House is agreeable, in spite of the fact that a separate motion is not printed—I do not think any inconvenience has been caused—we shall discuss both the motions. That is, if the House so agrees.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I abide by your decision, that even though Shri Gupta's motion has not been printed in today's order paper, we take it as printed and we continue the discussion. I only want strengthening of your assurance yesterday and today, your interpretation on the basis of your ruling, that whenever a privilege motion has to be moved by any Member of the House, we need not go according to the practice so far of one motion one day.

MR. SPEAKER: I did not say that.

PROF. P. G. MAVALANKAR: If there are more motions they can be taken up.

MR. SPEAKER: My understanding of the rule is this. That rule follows the earlier rule and therefore it only restricts one Member to move one motion. Anyway that decision has been given.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Let me complete my point. For further guidance, we should know.

MR. SPEAKER: I have given my ruling and it is on record.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Am I right in saying that we can now move several motions on the question of privilege the same day as long as they are moved by different Members and they have secured your consent?

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): I move my amendment No. 1:

That in the motion,—

Omit "and others' (1)

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni): I move my amendment No. 2:

That in the motion,—

After "Shrimati Indira Gandhi", *insert*

"Shri R. K. Dhawan and Shri D. Sen. "

SHRI GAURI SHANKAR RAI: I move my amendment No. 3:

That for the motion, *substitute* the following:—

"That this House resolves that Shrimati Indira Gandhi has committed a grave breach of privilege and contempt of the House by causing obstruction and harassment to the concerned Officers for collecting information in reply to question in Lok Sabha in the discharge of their official duties to the House.

This House further resolves that Shrimati Indira Gandhi be sentenced to imprisonment for the duration of the remainder of the present Session of the House for her offence." (3)

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): Sir, this amendment patently out of order. I invite your attention to rule 226.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): On a point of order.

MR. SPEAKER: How can there be a point of order on a point of order?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let no coal be carried to New Castle. You have ammitted the amendment and circulated it. Is he questioning that.

MR. SPEAKER: I have not admitted the amendment at all; my order is: print and circulate. Please see my order.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is admitted; you have allowed him to move it.

MR. SPEAKER No. I have made a specific order there: print and circulate. The question of admission will come up later.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is admitted and allowed to be moved. That is all. I do not want to say anything more.

SHRI C. M. STEPHEN: I am drawing your attention to rule 226 and 134 According to rule 226, when leave is asked for under 225, House may consider the question and give a decision, that is a course which is open to the House. Or, it may refer to the Committee of Privileges on a motion made by a Member has raised it or any other Member. The motion now before the House is that the matter be referred to the Privileges Committee. Until that motion is rejected, this motion does not come at all. If that motion is accepted, this motion does not come at all. If that motion is rejected, then alone this motion can come up. He is not actually amending it. It is a substitute motion in place of the motion before the House—a motion substituting in entirely a motion before the House cannot be an amendment. Therefore, this cannot be accepted as an amendment at all. Whether the new motion can be accepted or not, this can be decided only after the motion before the House is disposed of. Rule 344 says: "The amendment shall be relevant to end within the scope of the motion to which it is proposed." The motion is "referring to the Privileges Committee". This motion cannot be within the scope of the original motion. "The amendment shall not be moved which is merely giving the effect of a negative vote". If this motion is accepted, then the motion before the House is negatived. It has got that implication. Therefore, on these three grounds, namely, it is not an amendment but a substitute motion, it is not within the scope of the motion and it has got the effect of negativing the motion already before the House, it is out of order. It is based on one of the two alternatives contemplated under Rule 226 and one of the alternatives we are already discussing and unless the House disposes of that, this motion cannot be taken into consideration.

श्री गौरी शंकर राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्ज आफ प्रौसीजर के नियम 226 के अनुसार हमारे सामने दो विकल्प हैं। जिस स्थिति में यह प्रस्ताव सदन के समक्ष पहुंचा है—उस में हम इस को प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज सकते हैं—यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि सदन इस को स्वयं पास कर सकता है, यहां फैसला ले सकता है। सदन के सामने इन दोनों विकल्पों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकते हैं—सिलैक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पेश हो सकता है, उसी तरह से नियम 226 के अन्तर्गत

[श्री गौरी शंकर राय]

यह फसला भी हो सकता है कि इस का यही फसला कर दिया जाय । इस लिये यह इल्लीगल नहीं है .....

श्री बसंत साठे (अकोला) : ये परस्पर विरोधी हैं ।

श्री गौरी शंकर राय : विरोधी नहीं हैं।

Rule 226 says: "If leave is granted under rule 225, the House may consider...."

I have proved this motion under this aspect.

मान्यवर, इन में कोई विरोधाभास नहीं है ।

There is no contradiction nor there is any deviation. The first part of it explains and gives the powers to the House to refer it to the Privileges Committee and the other part gives the power to the House to take a decision now.

इसलिये मुझे यह निवेदन करना था कि विशेषाधिकार का यह प्रश्न है, जिस के सम्बन्ध में इस सदन और सारे देश को तथ्यों की जानकारी है । इस के सम्बन्ध में बहुत जांच करने की आवश्यकता नहीं है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ जो आरोप हैं—उनके सम्बन्ध में सारा सदन, सारा देश और सारी दुनिया आश्वस्त है कि वे अपराध सत्य हैं । शाह कमीशन के सामने जो ब्यान हुए हैं, उन में पिछले मंत्री मंडल के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ये काम किए थे । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं—मेरे मित्र मधु लिमये और कवंर लाल गुप्ता ने जो अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, उस से स्पष्ट है और अब इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्रीमती गांधी ने जो अपराध किया है—सदन के कार्य में लगे हुए, प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने वाले उन अधिकारियों के कार्य में बाधा पहुंचाई है ।

It is an obstruction in the working and doing the official duties of the officers in the service of the House.

यह क्लिअर आब्सट्रक्शन है, इस में कोई भी बहसतलब सवाल नहीं है ।

इस लिये मैं आप के माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सदन का यही फैसला करना चाहिये । मैं एक और निवेदन आप के समक्ष करना चाहता हूं—दुनिया में अब तक जितने कानून बने हैं, वे कल्पना के अधीन बने हैं । जब कानून बनता है तो अपराध के सम्बन्ध में कल्पना होती है

There are imaginations about crimes.

लेकिन दुनिया के देशों में ऐसा अवसर आया है जब कल्पनातीत अपराध हुए हैं ।

Unimaginable crimes have been committed in the history of the World.

MR. SPEAKER: I will come to that after deciding the admissibility of your amendment.

श्री गौरी शंकर राय : मैं तो अपना मोशन पेश कर रहा हूं ।

MR. SPEAKER: You are going into the merits of the case. I will first go into the question whether your amendment is permissible under the rules. I will go into that first.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I invite your kind attention to rule 226 which says:

"If leave under rule 225 is granted"—which you have granted—"the House may consider the question and come to a decision".

So, this House is competent to take a final decision on any motion. The second alternative is "or refer it to a Committee of Privileges". So there are two aspects of the matter. There is no question of negation. This is not a new motion. If you read rule 226 further it says:

> "Or refer it to a Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member".

Rule 228 says:

> "The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure. . . .

So, my submission is that rule 226 is very clear. There are certain motions or resolutions which are passed by the House then and there. There are certain others which are referred to elicit public opinion and there are certain others which are referred to a select committee. This is not a negation of that motion. This is just an amendment, which is very reasonable. The case is such that the lady should be punished here and now. She is the biggest criminal in the country. But we are judicious-minded people believing in democracy. So, we want to give her a chance to explain her case before the committee. That is why we have done this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Under rule 226 the question of privilege has been termed as a motion. So, immediately we are required to refer to rules 345 and 346. You have admitted the motion and you have called on Mr. Rai to move his amendment. Is it not?

MR. SPEAKER: I have not admitted it. I have only allowed him to mention it .

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mentioning is moving. Amendments or substitute motions can be grought on the floor of the House under one channel only, namely, the Speaker allows it to be moved. There is no other channel. Rules 345 and 346 have to be read with rule 226. What Mr .Rai has done is right and he has to be allowed to move his amendment and speak on it.

SHRI GAURI SHANKAR RAI: This is not an amendment but a substitute motion. Rule 226 says:

> "If leave under rule 225 is granted the House may consider question and come to a decision or refer it to the Committees of Privileges".

The motion moved by Mr. Limaye concerns the other part of it. After your consent is given, any member has got a right to give the motion according to the other alternative given in rule 226. So, this is a substitute motion and there is nothing illegal, no contradiction and no negation.

SHRI VASANT SATHE (Akola): One alternative given under Rule 226 is:

> "If leave under Rule 225 is granted, the House may consider the question and come to a decision".

That means, one alternative is that the House itslf can consider the matter and come to a decision. That is the proposition of Mr. Gauri Shankar Rai. He says that the House should itself decide to punish. That is his position. But both the alternatives cannot go simultaneously when the Rule specifically says:

> ". . . .Or refer it to a Committee of Privileges".

Now, in the main motion of Mr. Madhu Limaye, he has chosen this alternative and this remedy and both things cannot be done simultaneously on a motion moved by this Member and the motion moved by the other Member. How can you have these two because one negatives the other?

[Shri Vasant Sathe]

If the first motion is taken up the motion moved by Mr. Madhu Limaye, the other motion cannot be taken up simultaneoulsy unless that motion is rejected. I am not saying that the other motion cannot be considered; all I am saying is that first Mr. Madhu Limaye's motion be considered. Let the House reject it and after that is rejected, we can take up the motion of Mr. Gauri Shankar Rai who wants that this House should decide to punish Mrs. Indira Gandhi. That is his motion of privilege. Go ahead and do what you like, but Sir, do it legally.

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 226 बिल्कुल स्पष्ट है। नियम 225 के अन्तर्गत एक दफा मोशन एडमिट हो जाने के बाद हाऊस उस पर विचार करेगा। इसमें यह कहा गया है कि प्रिविलेज मोशन पर विचार करेगा, इसमें यह नहीं है कि किस आल्टरनेटिव पर विचार करेगा। विचार करने के बाद वह दोनों विकल्पों में से एक पर फैसला कर सकता है। एक पर फैसला हाऊस को करना है। इसके लिए समबडी विल हेव टू मूव इट। अनलेस समबडी मूव्ज इट, हाऊस फैसला नहीं कर सकता है। इसलिए एक पर विचार करने के लिए एक आनरेबल मेम्बर की तरफ से यह मोशन आया है। अब इस पर हाऊस ही विचार करे और नियम के अनुसार हाऊस उस पर विचार करे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई विरोधी बात नहीं है। इस पर हाऊस में विचार करने के बाद हाऊस फैसला करे दोनों में से कौन-सा विकल्प हाऊस चाहता है कि इस पर हाऊस में ही विचार किया जाए या प्रिविलेज कमेटी को इसे भेजा जाए।

SHRI NARENDRA P. NATHWANI (Junagadh): Rule 226 is quite clear. Once leave is granted, the House can do either of the two things: either it can decide the question itself of refer the matter to a Committee of Privileges. But before the House can do it there must be a motion before it. The motion may be for deciding the question by the House itself or the motion may be for referring the matter to a Committee of Privileges. Today we have got both the motions before us. Then it is within the competence of the House to decide which course to adopt. There is no ambiguity in this. This is my view. What is required is, there should be an appropriate motion before the House. If there is no motion moved then the House cannot take action Suppose there is only one motion moved to refer the matter to a Committee of Privileges. Then the House cannot itself decide the matter because Rule 226 requires it. There must be a Motion moved, if the House wants to decide it itself. That has been done in this case. It is left for the House to decide.

MR. SPEAKER: I want your assistance. Under rule 226, it is open to the House either to remit it to the Committee of Privileges or to discuss it. There is no third course. If Mr. Gaudi Shankar Rai's Motion is an amendment of Mr. Madhu Limaye's Motion saying that it should be discussed by the House itself, it is permissible because he is trying to amend the Motion as earlier given. But the real difficulty comes this way: please see the main Motion of Mr. Limaye. It says:

> "That the question of breach of privilege and contempt of the House against Shrimati Indira Gandhi and others be referred to the Committee of Privileges with instructions to report within a period of six months."

That is the main Motion. Mr. Gauri Shankar Rai says:

> "That this House resolves that Shrimati Indira Gandhi has commit-

ted a grave breach of privilege and contempt of the House by causing obstruction and harassment to the concerned Officers.....'

If he had merely said that it should be discussed only by this House, I can understand that amendment. What he wants is to substitute the original Motion with the other Motion. He wants a total substitution. Is it permissible under rule 226?

SHRI NARENDRA P. NATHWANI: I submit that the amendment to the other motion....

MR. SPEAKER: Is it permissible?

SHRI NARENDRA P. NATHWANI: The amendment to the other Motion *viz.* that the House itself should decide.

MR. SPEAKER: It may be permissible.

SHRI NARENDRA P. NATHWANI: It may not be an amendment. You should not view it as an amendment.

MR. SPEAKER: Even if you view it as an amendment, it does not matter. It is permissible under rule 226.

SHRI NARENDRA P. NATHWANI: It is open to the House to take either of the two courses mentioned in the opening part of this rule; but for taking either action, it is absolutely necessary that a Motion should be moved in this House; whether Mr Rai's Motion amounts to an amendment or not, is immaterial for the purpose.

MR. SPEAKER: He has specifically mentioned that it is a substitute Motion.

SHRI NARENDRA P. NATHWANI: In that sense it is an amendment when you say "substitute it"; but he says that you may treat it as a separate, independent Motion. There is that Motion to-day. There is some misunderstanding on the part of the office if they have added the word 'substitute, by way of an amendment. But suppose those words were not there; difficulties seem to be created by printing those words that it may be moved as an amendment.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): As I said, the position is like this: two things have been held in order: that the question has been allowed to be raised; and the matter proposed to be raised has been found in order. At this stage, the House comes into the picture. In what form should the proposal for further action be formulated? (*Interruptions*) I am analyzing the whole thing. The House comes into the picture. It has to decide in what form the proposed action should be taken. The first duty of the House is to decide whether it will decide here and now itself. Then we.. (*Interruptions*) Please Let me analyze objectively. (Interruptions) I really do not understand this. I will analyze the whole thing with the utmost objectivity. The first thing that the House is expected to do is this *viz.* to decide whether this matter can be disposed of by the House itself. And then alone, if the House says that this matter cannot be disposed of here and now, this matter can be referred to the Committee of Privileges. One may take a view, the House may take a view, that this is a matter which does not require any consideration or examination by the Committee of Privileges. The offence is so manifest.

So, the House may take a view that the offence is so manifest that any plea for extenuation of the offence cannot be allowed later and so the matter must be decided here. Here are a few factors which point in that direction; there is no doubt about it; and the factors are that the Minister who was charged with the responsibility of answering the question....(*Interruptions*). I am assisting the House in taking a right decision.

SHRI VASANT SATHE: We have not reached that stage yet.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: From the technical point of view, my first submission is that the House has to decide whether the matter would be decided by the House itself or not. Secondly, whether the hon. Member, Shri Rai's amendment is considered to be a substitute motion or an amendment, in both cases you would find that Shri Rai's motion has to be disposed of first, because that substitute motion relates to the first stage of the consideration by the House, whether the House will decide the matter itself. So that ill have to be disposed of first. Even if it is considered to be an amendment, as amendments are always voted first this amendment will have to be voted first. Therefore, in both cases, from a technical point of view, it is Shri Rai's motion which takes precedence in the matter of voting, so far as the House is concerned. That is one submission. I hope I have made myself quite clear to the Chair on this point that even from the point of view of substance, the first alternative before the House is to decide whether it will decide the matter itself. In that sense also, Shri Rai s motion takes precedence. Secondly, even if it is construed to be an amendment—it is, in fact an amendment—then, it has to be voted first and then the motion of Shri Madhu Limaye can be voted. This is the technical position.

But what I am suggesting is that the House has got certain things before it, which make the offence manifest in the eyes of the House. The other aspect is whether the House should not take into account the natural justice aspect of it, that the accused aslo has to be given an opportunity in the matter. To that matter I will come later. I am just assisting the House to take a decision in the matter and I am submitting that Shri Rai's motion has to take precedence over the other motion.

SHRI J. RAMESHWARA RAO (Mahboobnagar): There is only one motion before the House, and that is by Shri Madhu Limaye. There is no amendment before the House, and the House cannot take into consideration two motions simultaneously. The main motion before the House, moved by Shri Madhu Limaye, is that this matter should be referred to the Privileges Committee. Only this motion is before the House. No other digression is possible. No other motion is before the House.

MR. SPEAKER: Rule 226 provides for two alternatives to the House—one is reference to the Privileges Committee and the other is the House itself taking a decision. Shri Madhu Limaye has mvedo that it oe referred to the Privileges Committee. Now another Member says in his amendment "No, the House itself has to decide it". If it is an amendment, then that amendment must be voted first. If, on the other hand, it is not an amendment but a totally new motion, probably it will not be admissible. The matter we have to consider is whether Shri Gaudi Shankar Rai's motion is an amendment or an entirely different motion.

SHRI J. RAMESHWAR RAO: There cannot be an amendment to the motion.

MR SPEAKER: Why can there not be an amendment?

SHRI J. RAMESHWARA RAO: If the original motion had said that the House should itslf consider it or refer it to the Privileges Committe, it would have been different, but the motion specificially says that it should be referred to the Privileges Committee. So, no second motion can be moved.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): It has to be borne in mind that specific provisions have been made in our rules with regard to privilege in Chapter XX. Under rule 225, a Member has to obtain the leave of the House to raise a question of privilege.

MR. SPEAKER: We have passed that stage.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It is important. Before grant of leave, the Member is permitted to make a short statement relating to the subject matter of the privilege. With regard to that a statement was made yesterday on the floor of the House by Mr. Madhu Limaye. We know what the relevant facts are with regard to which the privilege question has been raised.

Then, after leave has been granted, there is a specific rule with regard to privilege, namely rule 226, which is not there in respect of other matters. It has been specifically provided that two alternative courses of action are open. One has to be necessarily the substitute of the other. Both cannot at the same time remain. Therefore, an alternative procedure having been laid down in rule 226, it has to be decided by the House itself how it is to be done.

At the initial stage, when the Mover was given leave to raise it, he asked for a particular course of action, namely referring it to the Privileges Committee. Now, there is a provision for an amendment. It comes under rule 226 and also rule 344. Rule 344 says:

> "An amendment shall be relevant to, and within the scope of the motion to which it is proposed".

The scope of the motion is a decision on the question of breach of privilege, whether the House itself decides it or the Committee decides it. The scope of Mr. Madhu Limaye's motion is decision of the question of breach of privilege for interfering with the due discharge of the functioning by the officers of this House. Therefore, Mr. Gauri Shankar Rai's motion specifically refers to that question and nothing else, and one cannot take that it is outside the scope of the other motion. Therefore, it is an amendment and comes under rule 226. Even if it is a substitute motion, it is inorder because both have been contemplated. I, therefore, submit that you kindly permit Mr. Gauri Shankar Rai's motion as an amendment or as a substitute motion.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): There are two options before the House and during the discussion we have to decide one way or the other, and both the motions must be before the House before a decision can be taken. We cannot contemplate two debates on the same subject. So, this substitute motion must be there in the two options are to remain open, and that is why whether it is taken as an amendment or a substitute motion, the motion of Mr. Gauri Shankar Rai is perfectly in order, and House can discuss both the options and come to a decision.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): There sems to be a little confusion or misunderstanding about the terminology. Would you kindly refer to rule 186?

SHRI B. SHANKARANAND (Chikkodi): I do not know whether Members who are in the Privileges Committee can take part in this debate.

MR. SPEAKER: Mr. Jethmalani, the advice to you is not to take part.

SHRI RAM JETHMALANI: I am on the question of construction of rules.

MR. SPEAKER: It is better to avoid that.

SHRI RAM JETHMALANI: Then, I will ask my colleague to raise it.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: (Seoni): There is a distinction between question and motion. Kindly see Rule 226. There are two stages provided. "If leave under 225 is granted, the

[Shri Nirmal Chandra Jain]

House may consider the question..." Now the question may come in the form of one motion or in the form of two motions. There is one difficulty also. Kindly see 186.

MR. SPEAKER: I have mentioned that under rule 226, it is open to another Member to amend the motion. I cannot say, no, the House will discuss and take a decision.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: Whether it shall be treated as motion in the strictest sense of the term as envisaged under 186. Kindly see the rule:

> "In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely:—
>
> (v) it shall not raise a question of privilege."

It has a loose terminology for the purpose. For that purpose, it cannot be treated as a motion under 186. Therefore, if the question has been raised that some breach of privilege has been committed by Smt. Indira Gandhi, then the question in wide open. One, two, three motions can come on this. Kindly see what was your observation yesterday. You said specifically that the question is now before the House. On that question, one motion was moved by Mr. Madhu Limaye. Then Mr. Stephen again said:

> "Either you give us a copy of the letter of Mr. Madhu Limaye seeking your leave to raise this matter in the House or kindly adjourn it to tomorrow and in the meantime circulate the copy of the motion so that we can look into the matter and make our contribution to the debate."

So, the debate is going on and this debate is on the point of question as envisaged under 226. Therefore the House is now onsidering the question. One motion may come, another motion may come and, therefore it is permissible for Mr. Rai to raise this motion along with the first motion.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA (Chikamagalur): I would like to draw your kind attention to the fact that the motion moved by the hon. Member, Mr. Madhu Limaye, has been admitted *in toto*. It has not been split. It is very specific that the matter of privilege be referred to the Privileges Committee. This motion cannot be split up. There is no precedent in the House that such a matter of great importance connected with a great....

MR. SPEAKER: I appreciate your point of view, but how can I do it? What can I do? Under 226, it is open for the House to decide either to remit it to the Committee or decide for itself.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: The motion of Mr. Madhu Limaye has not given any chance to the House to consider this matter of privilege.

MR. SPEAKER: Under rule 226, once the House is seized of it, Mr. Madhu Limaye may say, "It must go to the Committee of Privileges" but the House may say, "No. We will consider it" What am I to do?

SHRI VAYALAR RAVI: I rise on a point of order. Rule 226 is very clear. It says:

> "If leave under rule 225 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to a Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member."

Mr. Madhu Limaye raised the question of privilege and moved a motion. The motion is very clear and specific that it should be referred to the Committee of Privileges with in-

structions to report within six months. Now, there is rule 344 regarding the scope of amendments. But here is the Order Paper which says, another resolution or a substitute motion. Another motion cannot be moved to the effect that this House do take a decision on the question of privilege. There is already a specific motion before the House. It is not an amendment. it is another motion. The specific motion before the House is very clear and it cannot be substituted by another motion.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Sir, I would like to submit that the whole House has been surcharged with emotion and we are hearing the same arguments again and again. Nothing new has been said from both the sides.

MR. SPEAKER: I am also thinking on the same lines. So that the House may cool down, I will take time. I will not give the order today.

SHRI P. K. DEO Mr. Gauri Shankar Rai may withdraw his motion. The whole question of privilege could be discussed in the Privileges Committee in a very cool and dispassionate manner the accused could be given a chance to have full say, the evidence could be recorded and all that. If Mr. Gauri Shankar Rai is prepared to withdraw his motion, he may be permitted to withdraw the motion.

SHRI MADHU LIMAYE: The point is very simple. There cannot be two independent motions. The two motions cannot be discussed at the same time. All that you have to decide is whether Mr. Gauri Shankar Rai's amendment is a substitute motion. If it is an independent motion, it is clear that, it is out of order. You please take a quick decision on that.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस में कोई झगड़े का सवाल ही नहीं है । रूल 226 क्लीयर है । यह कोई अलाहिदा मोशन नहीं है । रूल बिलकुल क्लीयर है कि हाऊस फैसला करे और हाउस नहीं करता तो दूसरे कर लें । यह जो सबस्टीच्यूट मोशन की बात है यह इन्होंने इसी रूल के बारे में कही है । इस को सेपरेट मोशन या अमेंडमेंट दोनों शक्ल नहीं दे सकते आप । यह न अमेण्डमेन्ट है और न सब्सटीच्यूट मोशन है या तो रूल 226 में जो प्रोवाइडेड है उसके लिए हाउस को कहा है कि हाउस फैसला करे । यह रूल इतना क्लियर है कि इसमें बहस का सवाल ही नहीं है । यह हाउस फैसला करे या फिर इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दे । इसलिए यह न अमेण्डमेण्ट है और न सब्सटीच्यूट मोशन है । रूल 226 को कैरी आउट करने के लिए कहा गया है कि यह हाउस फैसला करे ।

MR. SPEAKER: I have heard enough of it. I will reserve orders.

SHRI AMRIT NAHATA (Pali): The whole confusion has arisen because of the misinterpretation of rule 225. Rule 225 relates to a question of privilege, not a motion. You admitted a question of privilege. The House has allowed Mr. Madhu Limaye to move that question of privilege and he moved that question of privilege. Once a question of privilege is placed before the House, there are four alternatives before the House.

The House may come to conclusion that there is no *prima facie* case of any breach of privilege and the question may be rejected. Then the house may come to a conclusion that yes. there is a *prima facie* case of privilege and it must be referred to the Committee of Privileges. Or the House may come to a conclusion that though there is a very manifest, very patent, very obvious transparent violation of the privileges of this House and though we are competent to take a decision here, we would like the

[SHRI AMRIT NAHATA]

matter to be reffered to the Committee because even the devil must be given an opportunity to explain his or her position. And the fourth position may be that the House may take a decision, now we will take a decision here and now which is very rare. Ordinarily the demand of justice stipulates that even when the House is convinced that it is transparently clear that the contempt has been committed, still we will refer it to the Privileges Committee. If the House decides to take a decision here and now which will be a very exceptional case how does the House do it without a motion. Now that motion may be an independent motion, a substitute motion or an amendment or whatever may be, I may not agree with that motion; I may agree with Mr. Madhu Limaye's motion. I may not like the House to take a decision here and now. But a motion has to come before the House if it has to take a decision here and now.

Therefore, I submit that though the motion of Mr. Rai is in order, whether it is a substitute motion or a new motion or an amendment, it is in order and the House is competent to take a decision on that motion.

श्री राम नरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मधु लिमये जी का प्रस्ताव है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है, इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाये । श्री गौरी शंकर राय का कोई स्वतन्त्र प्रस्ताव नहीं है बल्कि संशोधन है कि उस पर सदन यहीं विचार करे । मेरा आपसे कहना है कि अगर यह मूल प्रस्ताव का संशोधन है तो मधु लिमये जी का अधिकार है कि संशोधन को स्वीकार करें या नहीं । अगर वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं तब इस सदन को विचार करना होगा कि यह संशोधन माना जाये या नहीं । इसलिए सबसे पहले मधु लिमये जी, जोकि प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, उनका यह अधिकार है कि उसको मानते हैं या नहीं । उसके बाद इस पर सदन निर्णय कर सकता है ।

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): This matter is getting more and more intense every time as we go on discussing. The fact of the matter is that Shri Madhu Limaye moved a privilege motion yesterday giving some persons an opportunity to explain before the Privileges Committee. Shri Stephen from the Opposition chose to refute and brought by delaying it by one more day all these things on the House and on themselves. Here is a clear case of somebody wishing in her own home, 'Oh God! Please save me from my friends'. This must be her attitude now, listening to our great friends on the other side...

MR. SPEAKER: What is your point of order?

SHRI BIJU PATNAIK: I am trying to assist you, Sir. Mr. Gauri Shankar Rai has given...

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): He is ging into the merits. (*Interruptions*)

SHRI BIJU PATNAIK): If the Opposition Members wish to force our hands, we have nothing to say. I am only trying so that we are not forced. The Janata Party is not going to be provoked by this kind of things.

My suggestion is this. We would request Mr. Gauri Shankar Rai to withdraw his motion. Mr. Limaye's substantive motion may be placed before the House.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (श्री राज नारायण) : : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मझे भी सुन लीजिये । मेरा प्वाइण्ट आफ़ आर्डर है ।

MR. SPEAKER: I am not allowing. I do not want any more trouble. No. I have not called you.

श्री राज नारायण : आप कृपा कर मेरा प्वाइण्ट आफ़ आर्डर सुन लीजिए, इस से समस्या का समाधान निकल आयेगा, अगर नहीं सुनेंगे तो समस्या का समाधान नहीं निकल सकेगा । —इस तरह से मैं नहीं बैठूंगा आप मुझे निकाल दीजिए ।

MR. SPEAKER: What is your point of order?

श्री राजनारायण : मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर यह है कि मैं अपनी राय सदस्यों को बतला दूं । आप इस को प्रिवलेज कमेटी को भेज दीजिए, वह अलग चीज है । मगर प्रश्न यह है कि यह प्रिवलेज का प्रश्न है —

The earliest opportunity should be availed of.

श्री मधु लिमये कल जब यहां पर बोले थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 10 अक्तूबर को यह दिया था । इस में इतना डिले आलरेडी हो गया है ।

Justice delayed is justice denied.

अध्यक्ष महोदय, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं—क्या आप जस्टिस को डिले करना चाहते हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि देश इस बात को समझ ले कि इस सदन को पूरा अधिकार है कि इस को पास कर सकता है और श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ एक्शन ले सकता है । फिर भी जनता पार्टी उन को इतना ज्यादा अवसर दे रही है कि इस को प्रिवलेज कमेटी में भेज कर इस पर वहां विचार हो और उस के बाद फैसला हो ।

MR. SPEAKER: Mr. Gauri Shankar Rai are you withdrawing your amendment or are you pressing your amendment?

श्री गौरी शंकर राय : मुझे पहले सुन लीजिए, उस के बाद मुझ से पूछियेगा ।

SHRI G. M. BANATWALLA: (Ponnani): Sir, I have already sent one motion to you...

MR. SPEAKER: You cannot send not now. I have not allowed. You have to give notice.

SHRI G. M. BANATWALLA: I have given a motion that the entire discussion be adjourned without fixing a date....

MR. SPEAKER: That cannot be done now. I am not admitting it because you have not given notice.

SHRI G. M. BANATWALLA: Let me move it first, and then you may allow or disallow. Without my moving it, you are giving your ruling on it.

MR. SPEAKER: I am not allowing it.

13 hrs.

SHRI G. M. BANATWALLA: You must let me move it.

MR. SPEAKER: You should have given notice earlier: not now.

SHRI G. M. BANATWALLA: I am asking for an adjournment of the entire discussion *sine die*: how can you rule it out?

MR. SPEAKER: You have to give notice in time: you are creating further trouble.

SHRI G. M. BANATWALLA: I am within my rights to move a motion.

SHRI VASANT SATHE: The Rule is very clear: it can be moved any time.

MR. SPEAKER: All right; you may move your motion.

SHRI G. M. BANATWALLA: I move:

"That the entire discussion on this motion and also on the substitute motion be adjourned *sine die* without discussion".

This is necessary in order that a proper mind is applied to this serious question that is before the House. (*Interruptions*).

श्री उग्रसेन : बिना आप के आदेश के ये बोल रहे हैं। हम भी बोल सकते हैं। (**व्यवधान**)..... किस कानून के अन्दर ये बोल रहे हैं और किस अध्याय के अन्तर्गत इन को बोलने की अनुमति है, मैं जानना चाहता हूं। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

MR. SPEAKER: Rule 340 allows the motion to be moved.

चौधरी बलबीर सिंह : : बिना आप की अनुमति के ये कैसे बोल सकते हैं। आप ने अभी कहा था कि इन का मोशन वक्त पर नहीं आया है। आप ने अपना फ़ैसला एक मिनट में कैसे बदल दिया। ... (**व्यवधान**) ...

SHRI G. M. BANATWALLA: The Hon. Minister has made a very welcome announcement that the Janata Party is not provoked. Now, this is a good announcement. It means that everyone in the House is prepared to apply a serious mind to this question.

MR. SPEAKER: Now please sit down. You have been allowed to move your motion under Rule 340 and you have moved it. You know the temper of the House and once you have moved your motion there is no point in dilating further. I am trying to cool down the House and get it into a reasonable mood. Your *sine die* adjournment motion is further provoking the House.

SHRI G. M. BANATWALLA: I am taking Minister by his words that the Janata Party is not provoked.

MR. SPEAKER: Now I will put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That the entire discussion on this motion and also on the substitute motion be adjourned *sine die* without discussion".

The motion was negatived.

श्री गौरी शंकर राय : अध्यक्ष महोदय, जरा मुझे सुन लीजिए। यह तो बाद में देखूंगा कि अपना एमेंडमेंट प्रेस करूं या न करूं। इस से पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं सदन की इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं करूंगा लेकिन मैं यह जरूर बतलाना चाहता हूं कि मैंने ऐसा संशोधन क्यों दिया। मुझे सुना जाए। उस के बाद सदन की जो इच्छा होगी, उसके विपरीत मैं नहीं जाऊंगा। मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल दस मिन्ट ही लूंगा। (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: I am reserving my orders on this motion. The matter will be taken up tomorrow. Now, the House stands adjourned for lunch.

13.04 hrs.

The House adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Papers to be laid—Shri Ravindra Varma.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER PAYMENT OF WAGES ACT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to lay on the Table a copy of the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1383 in Gazette of India dated the 15th October, 1977 under sub-section (6) of section 26 of the Payment of Wages Acts 1936. [*Placed in Library. See* No. LT-1063/77.]

NOTIFICATION UNDER INDIAN TELEGRAPH ACT

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BRIJLAL VERMA): I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Third Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1188 in Gazette of India dated the 10th September, 1977, under sub-section 5 of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* No. LT-1064/77.]

STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON VARIOUS ASSURANCES, ETC. GIVEN BY MINISTERS DURING VARIOUS SESSIONS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): I beg to lay on the Table the following statements (Hindi and English versions) showing the action taken by the Government on various assurances, promises and under takings given by the Ministers, during the various sessions of Lok Sabha:—

(1) Statement No. XXVIII—Seventh Session, 1969	Fourth Lok Sabha
(2) Statement No. XXXIX-Second Session, 1971	Fifth Lok Sabha
(3) Statement No. XX-Sixth Session, 1972.	
(4) Statemtnt No. XXVI—Seventh Session, 1973	
(5) Statement No. XXII-Ninth Session, 1973	
(6) Statement No. XXVI-Thirteenth Session, 1975	
(7) Statement No. IX-Fifteenth Session, 1976	
(8) Statement No. IX-Sixteenth Session, 1976	
(9) Statement No. VI-Seventeenth Session, 1976	
(10) Statement No. III-First Session, 1977.	Sixth Lok Sabha
(11) Statement No. II-Second Session, 1977	
(12) Statement No. III-Second Session, 1977	
(13) Statement No. IV-Second Session, 1977.	

[*Placed in Library. See* No. LT-1065/77.]

NOTIFICATION UNDER TELEGRAPH ACT.

SHRI BRIJLAL VERMA: On behalf of Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai, I beg to lay on the Table a copy of the Indian Telegraph (Second Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1165 in Gazette of India dated the 3rd September, 1977 under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885. [*Placed in Library. See* LT-1066/77.]

NOTIFICATIONS UNDER COAL MINES PROVIDENT FUND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM

RPAL SINHA): I beg to lay on the ble:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 7A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948:—

(i) The Andhra Pradesh Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977, published in Notification No. G.S.R. 1231 in Gazette of India dated the 17th September, 1977.

(ii) The Rajasthan Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977, published in Notification No. G.S.R. 1232 in Gazette of India dated the 17th September, 1977.

[*Placed in Library. See* No. LT-1076/77.]

(2) A copy of the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1229 in Gazette of India dated the 17th September, 1977, under sub-section (2) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-1068/77.]

(3) A copy of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Amendment Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1234 in Gazette of India dated the 17th September, 1977, under sub-section (4) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-1069/77.]

(4) (i) A copy of the Audited Accounts (Hindi and English versions) of the Employees' State Insurance Corporation for the year 1975-76 together with the Audit Report thereon, under section 36 of the Employees State Insurance Act, 1948.

(ii) A statment (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above document.

[*Placed in Library. See* No. LT-1070/77.]

14.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ASSAULT BY R.S.S. WORKERS ON SHRI DAMODARAN NAIR, A GUIDE OF GANDHI SMRITI.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported attack and assault on Shri Damodaran Nair, a guide of Gandhi Smriti, by R.S.S. workers for his narrating the facts about Gandhiji's murder and the apprehension of such attacks on the guides and the employees of the Smriti in future.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, the attention of the Government has been drawn through newspapers reports regarding certain incidents at Gandhi Smriti on 9th and 31st October, 1977. The leader of the Opposition also wrote to the Home Minister on the 4th November, 1977 on this subject. Consequent on these reports, the Delhi Administration were asked to send a report in the matter. The Delhi Administration have informed that their enquiries into these incidents have not yet been completed. The Prime Minister has already made a statement in this regard in the House on 14th of November and the Minister of Works & Housing has also answered an Unstarred Question on this subject on the same day.

The Prime Minister had visited the Gandhi Smriti in the evening of 8th of October and he was informed by some people that a guide, Shri Damodaran Nair, was alleging that the R.S.S.S. was responsible for Mahatama Gandhi's murder. The Prime Minister told the guide that this was not correct and that he should not make such statements.

On 9th of October, there was a scuffle between one Shri R. C. Mahajan, reportedly an R.S.S.S. worker and Shri Damodaran Nair when the former visited the Gandhi Smriti in which both the persons received some bruises. On being informed, the police reached the spot and obtained their statements. Their medical examination revealed that they had suffered only minor injuries. According to the statements made to the police, the trouble started when Shri Mahajan objected to Shri Nair's statement that Mahatma Gandhi was killed by Godse, an R.S.S.S. worker. Since no cognisable offence had been committed, the police did not take any further action and only posted a constable as a precautionary measure. Considering the past conduct of Shri Nair, he was transferred to the library after this incident.

In the afternoon of 31st October, a group of students from Gujarat led by Prof. N. J. Bhatt visited the Gandhi Smriti. There was again an altercation between them and Shri Damodaran Nair, who was acting as a guide despite his transfer to the Library. On being informed, the police reached the spot and restored peace. The statements of Shri Nair and the visitors were recorded. Shri Nair, however, refused to get himself medically examined as he had no apparent injury on his person. According to Shri Nair, the dispute arose out of his statement that Nathu Ram Godse was responsible for Mahatma Gandhi's murder and that he had been a worker of R.S.S.S. in Poona. On the other hand, Prof. N. J. Bhatt and others have stated to the police that Shri Nair made some unfavourable references about the R.S.S. As no cognisable offence was made out, no further action was taken by the police.

The Delhi Administration have tightened the security precautions at the Gandhi Smriti to prevent recurrence of any untoward incident.

SHRI C. M. STEPHEN: Mr. Deputy Speaker, Sir, in my judgement this is not merely a matter of minor assault on somebody. Issues of very serious national importance are involved in this incident. In the first place, the statement read out by the Home Minister brought out two facts. First, that Shri Damodaran Nair was attacked on the 9th and that he sustained injuries—minor according to them, but injuries nevertheless. Second, that on the 31st, he was attacked again and a scuffle took place.

These two things are admitted. It is stated that "when Shri Morarjibhai visited that place an allegation was made that Shri Damodaran Nair was telling visitors that RSS was responsible for Mahatma Gandhi's murder." This is only hearsay. The statement very clearly says, somebody told Morarjibhai, that this was what Damodaran Nair had stated. On the 9th October, according to the statement itself, 'the trouble started when Shri Mahajan objected to Shri Nair's statement that Mahatma Gandhi was killed by Godse, an R.S.S. worker.' Now, Sir, there is no allegation to the police by either side that R.S.S. was responsible for the murder of Mahatma Gandhi, but that Godse murdered Mahatma Gandhi as that Godse was an R.S.S. worker. Therefore, Sir, the report made to Shri Morarjibhai on the 8th is not borne out by the subsequent events. The statement about the subsequent incident on the 31st also says this: 'According to Shri Nair, the dispute arose out of his statement that Nathu Ram Godse was responsible for Mahatma Gandhi's murder

[Shri C. M. Stephen]

and that he had been a worker of R.S.S. in Poona'. Let it be clearly noted that the allegation is not that Damodaran Nair said that R.S.S. as such committed the murder, but that Godse committed the murder and that Godse was an R.S.S. worker. This is the statement that Mr. Damodaran Nair made and it is in reprisal of this statement that Mr. Damodaran Nair was attacked. Now, Sir, what we want to know is this. Gandhi Smriti is a place where visitors are going to see the spot where Mahatma Gandhi was murdered. Is it not the duty of the guide to tell these visitors who murdered Mahatma Gandhi? He only told them that Godse murdered Mahatma Gandhi and Godse was an R.S.S. man. Can anybody find fault with Damodaran Nair for that? In spelling out a fact which is borne out by history, is the guide to be attacked? Is not the guide entitled for protection?

It is not Shri Morarjibhai's statement only; the other day I was reading Justice Bhonsle's book. It was he who tried Nathu Ram Godse. According to him Nathu Ram Godse joined the RSS in his 22nd year, and he has been continuing his association with it. He edited 'Hindu Rashtra'; he was all along connected with it. There is no denying of this fact. I would also invite attention to a book by Pyarelal, "The Last Phase" In the first volume and the second volume repeated references are made to R.S.S. training and drills at the Banghi colony where Mahatma Gandhi was felled. Repeated references are made to the activities of the RSS people. Is the guide not entitled to spell out what Morarjibhai has stated? Is the guide not entitled to spell out what Justice Bhonsle has stated? Is the the guide not entitled to spell out what Pyarelal has stated? This is an unchallenged historic truth and historic fact. What has the Government done? Here the statement says:

> "Considering the past conduct of Shri Nair, he was transferred to the Library after this incident".

Now, I would like to ask this: What is the wrong which he has done? He was beaten up. Over and above that, you transferred him to the Library.

Is it a justifiable action? What was the incident in the past which you are referring to? Shri Damodaran Nair had been working as a guide all along. The question arises: Why and how, all of a sudden, somebody has taken umbrage on this and started attacking Shri Damodaran Nair? All along every leader has been saying and all along every guide has been saying ever since 1947 or 1948 that Nathuram Godse was an R.S.S. worker; Nathu Ram Godse murdered Mahatma Gandhi. Nobody has taken so far any objection to that.

Now, what is the special circumstance under which somebody had taken upon himself the courage to challenge it and to attack the poor boy for spelling out what had been done by him. For the last thirty years this was what had been told to us. So, the most significant aspect which I want to bring to the notice of the House is the changed political atmosphere and the changed political condition in this country. The feeling has been that it is the R.S.S. who is ruling the roost in the country and it is they who are controlling the administration. They will be able to do what they have chosen to do now. They have now assumed a new posture so as to see that they will challenge this and oppose it. There was a press conference held by Mr. Krishan Kant on this matter and this matter was put before him. In that Press Conference it was stated that he had taken up the matter with the Prime Minister. What was the statement made? According to Shri Damodaran Nair, the statement made was:

'Nathu Ram Godse Amar Rahe;
Nathu Ram Godse Zindabad;
R.S.S. Amar Rahe;
R.S.S. Zindabad."

Therefore, in the place of narration of a fact that Nathu Ram Godse killed the Father of the Nation, that Nathu Ram Godse was enrolled as an R.S.S. worker, a new slogan appears namely *'R. S. S. Zindabad; Nathu Ram Godse* Zindabad.' And, in the place of *Mahatma Gandhi Amar Rahe'* a new slogan appears namely *'Nathu Ram Godse Amar Rahe'*. This is a most significant fact. Who gets the protection? Not a person who says 'Mahatma Gandhi Amar Rahe' but the person who says *'Nathu Ram Godse Amar Rahe'* gets it; and the person who defends that slogan *'Mahatma Gandhi Amar Rahe'* does not get that protection. Shri Godse was an R.S.S. man. When Shri Nair said that, he got a strangled on his neck. The poor guide simply told that Godse murdered Gandhiji. But, the Government felt that the part played by the guide was not desirable at all and therefore he was transferred by the Government to the Library. This was what was being done. I am not bothered about implicating R.S.S. as such because the history will judge about it. You cannot re-write the history with reference to the identity of this particular person. The Janata Party has been saying that they swear by Gandhiji and his philosophy. Here is a question as to who murdered Gandhiji. The posterity is being told that Gandhiji was murdered by so and so. Who was the murderer of Gandhiji is a historical fact—an R.S.S. man—and for saying that, that guide was being attacked and beaten.

It is said that this is not a cognisable offence. Therefore, you have no responsibility about it; you have no responsibility to protect the guide who has told the historical truth to the people. The truth is got distorted and you are going to sit like that by saying that it is not a cognisable offence. Is that your position?

It is alleged that Shri Mahajan who went and beat Shri Damodaran Nair at the Ajmere Gate is a Janata Party worker. Here I would like to know whether this has come out in the Press Conference or not that Shri Mahajan connected with the Janata Party along with the R.S.S. people operated like that. These forty people combined together attacked that guide. But it is said that this attack is not a cognisable offence. I ask: is not this attack on him in a conspiratorial and calculated manner a cognisable offence? What is the discovery in saying that there is no cognizable offence. If it is 323 well I will say that there is no cognizable offence but when more than five persons go and attack it does become a cognizable offence. The hon'ble Home Minister swears by the rule of law but here under his nose in the Capital of the country and on the sacred spot where Mahatma Gandhi was shot there is no freedom to speak truth and protection goes not to the persons who speak the truth but to the persons who violate the truth and inflict a new system.

Now, I would like to ask the Minister whether the Government intends to take any further action against those persons who collectively attacked Mr. Damodaran Nair? What Mr. Morarji Desai said the other day does not change the situation at all Morarji Bhai was told that Damodaran Nair said that R.S.S. killed Mahatma Gandhi. According to the statement laid before the House the proposition is that Damodaran Nair said that Nathu Ram Godse killed Mahatma Gandhi and Godse is a member of the R.S.S. About that Mr. Morarji Bhai has no dispute. Is not the guide entitled to read out the passage from the Prime Minister's autobiography and in reading it out is he not entitled to protection? Are you going to allow them to run amuck and kill anybody they choose? What is the policy of the government?

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर): नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी का जिस्म खत्म किया था, कांग्रेस ने तो तीस सालों में महात्मा गांधी की आत्मा को खत्म किया।

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, recapitulate the events and circumstances again. On 8th October at five in the evening the Prime Minister along with Shri Sikandar Bakht, Minister of Works and Housing, visited the site. The Prime Minister was told by the people there that Shri Damodaran Nair was alleging that Nathu Ram Godse killed Mahatma Gandhi and he was a R.S.S. worker.

SHRI C. M. STEPHEN: The Minister is saying just opposite to the statement that he has made before the House. He wants to involve the Prime Minister (*Interruptions*).

SHRI DHANIK LAL MANDAL: The Prime Minister told Shri Damodaran Nair that this was incorrect.

SHRI C. M. STEPHEN What is incorrect?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: He is alleging that Nathu Ram Godse who is a member of the R.S.S. killed Mahatma Gandhi.

SHRI C. M. STEPHEN: Was it another statement? Please read this statement. How can he give another statement? We have got his statement—the Minister's Statement. (*Interruptions*)

SHRI DHANIK LAL MANDAL: On the 9th of October, Shri R. C. Mahajan along with his daughter went there at 12.00 Noon. There he met Shri Damodar Nair. Shri Damodar Nair explained, as he did before, that Shri Nathuram Godse who was an RSS worker, killed Mahatma Gandhi. This was objected to by Shri R. C. Mahajan and this led to pushing and pulling and in the scuffle both of them sustained some injuries. The matter was reported to the Police. The Police came on the scene, recorded their statements and because no cognisable offence was made, simply ed their statements and because no posted there so that such kind of incident may not recur. Shri Damodaran Nair was transferred to Library Division. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Balbir Singh, why do you unnecessarily keep on giving a running commentary. Please listen to him.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: In his own statement under section 364 Cr.P.C. before the Judge, Special Court, Shri Atma Charan, ICS, he had stated in para 29, "I have worked for several years in RSS and subsequently joined the Hindu Maha Sabha and volunteered myself to fight as a soldier under its pan--Hindu Flag.." So Shri Nathuram Godse, according to his statement, had served relations with the RSS. He was not a member of the RSS at the time of murder of Mahatma Gandhi. In the Judgement delivered on 21st June, 1949, by the High Court of East Punjab in the appeal filed by Godse against his conviction by the Special Judge, the learned Judges had observed "Nathuram V. Godse is the Editor of a newspaper. He was born in a devotional Brahmin family of the Bombay Presidency. He worked for several years in the RSS and subsequently joined the Hindu Maha Sabha of which Mr. Savarkar was the president." Then the J. L. Kapur Commission which enquired into the conspiracy to murder Mahatma Gandhi has observed in para 19.82 as follows:—

> "On May 15, 1942, V. D. Savarkar, President of the Hindu Maha Sabha addressed the volunteers at the training camp of that organisation at Poona and emphasised the necessity of forming a volunteer organisation for secret activities as that could not be undertaken by the

Sabha. As a consequence of these, Hindu Maha Sabha leaders such as S. R. Date, V. V. Gogte, N. D. Apte and N. V. Godse, founded the Hindu Rashtra Daily at Poona with the object of assisting the Hindu Maha Sabha activities."

SHRI C. M. STEPHEN: It makes no difference.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: It makes all the difference. Damodaran Nair, as you say, was alleging..

AN HON. MEMBER: Was not Mr. Sathe in the RSS?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Let us have an enquiry how many of them were in the RSS? ..(*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE (Akola): I did.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to what the Minister has to say; you can make your submissions later.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: For providing protection to Gandhi Smriti, as I have said, a constable was posted there so that peace may be maintained. So there is no question of any failure on the part of the government.

SHRI VASANT SATHE: This is probably the first time that the hon. Minister of State is answering a call attention motion and therefore, I sympathise with him. Unfortunately your leader has put the ball in your court. There is the first point that needs to be clarified by the government. What they have said in their statement as alleged to have been stated by the Prime Minister is one thing. The Prime Minister stated here the other day in the House that Damodaran Nair was alleged to have said that RSS murdered Mahatma Gandhi. He Said: this is not what I had said in the book. And correctly so. If this is what he was saying then he should not say that that also is correct. But the fact remains. Now the Minister has admitted, contrary to what he has stated in his written statement here, that what Damodaran Nair was saying was that Nathuram Godse who killed Mahatma Gandhi was a member of the RSS. All in the past tense. The person who killed him was a member of the RSS. What is the difference between this statement and the statement which Morarjibhai had made in the book? In the book he says: "Nathuram Godse was the man responsible for the murder. He had been a worker of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh".....(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: 'HAD BEEN' a member.

SHRI VASANT SATHE: 'Had been' and 'was' are both past tense; this book is in the past tense..(*Interruptions*) Shri Vasant Sathe will reply when you come to him. What is the difference? Nathuram Godse was admittedly a member of the RSS. At what time did he get promoted to Hindu Mahasabha is like saying at what time some of those members got promoted from Jan Sangh to Janta Party..(*Interruptions*) You may say that you have ceased to have separate identities. Balasaheb Deoras has stated that a member of the R.S.S. can be a member of any political party. Do you accept that or not?

(*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Almora): "An RSS Member can be a Member of any political party"—this can be quoted only by an RSS Member.

SHRI VASANT SATHE: I will ask the Minister. It has been said by Balasaheb Deoras, the Head of the RSS, that an RSS Member can be a Member of any political party.

(*Interruptions*)

This is digressing. If you want to know. I was a Member of RSS from the age of 13 to 15 till 1942 and I came out of RSS because RSS refused to

[Shri Vasant Sathe]

participate in the Independence movement.

(Interruptions)

The second reason was, I refused to accept the definition of 'Hindu'.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Can you deny that you were expelled from RSS on account of your misconduct?

(Interruptions)

SHRI VASANT SATHE: I said, "I do not accept the definition of 'Hindu'". And I still do not.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now order please.

(Interruptions)

SHRI VASANT SATHE: I have said, I had been there not for two months as Deoras has alleged, but for three years.

(Interruptions)

Gopal Godse has written this book. उसके पृष्ठ 85 पर वे यह कहते हैं । मैं इस को पढ देता हूं :

"नथूराम को संघ की भूमिका उपयुक्त प्रतीत हुई । रत्नागिरि का पतित पावन मन्दिर तो ईंट-पत्थर का एक ढांचा-मात्र था और वह भी रत्नागिरि तक ही सीमित । किन्तु संघ तो सभी हिन्दुओं को आत्मसात् करने के निस्सीम एवं विशाल वास्तुविहीन मन्दिर था । समस्त भारत उस का कार्यक्षेत्र था । राष्ट्र को बलवान बनाने का संघ का संकल्प था । अतः स्वाभाविक ही स्वराज्य प्राप्ति का हेतू संघ की प्रतिज्ञा में समाविष्ट था । संघ की शाखाएं शनैः-शनः बढ़ रही थीं ।

सांगली में भी संघ की शाखा चालू हुई । श्री काशीनाथ पंत लिमये उस के संघ चालक थे । नाथूराम तन्मयता से संघ के कार्य में जुट गये । थोड़े दिनों में वे वहां बौद्धिक कार्यवाही हो गये ।"

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have some patience. I keep a watch on time.

SHRI VASANT SATHE: This was the role of Nathuram Godse in the RSS.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing the incident at Gandhi Smrithi and not about Nathuram Godse.

SHRI VASANT SATHE: Has he verified the factual position whether Mr. Nair was telling an unturuth? Secondly, according to Gopal Godse, the last words on the lips of Nathuram on the day he was hanged were the prayer, which is the official prayer of RSS. He says at page 105:

"फांसी के बरामदे में पहुंच कर दोनों ने 'अखण्ड भारत अमर रहे' और 'बन्दे मारतरम्' का घोष किया —

नमस्ते सदा वत्सलू मातृभूमि,
त्वया हिन्दुभूमे सुखं बिर्द्धतो हं
महामंगले पूण्य भूमे त्वदर्थे
पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ।

एक बार कारागार के वायुमण्डल में यह स्वर गुंजायमान हुआ और फिर फांसी देने वाले ने फांसी का फदा खींचा कि दो प्राण पंचत्व में विलीन हो गए ।"

That means, till the last breath of Nathuram, he was a devoted; dedicated and committed member of the RSS. What is the falsehood in Mr. Damodaran Nair saying that he is quoting verbatim Shri Morarji Desai and nothing more?

Sardar Patel in his letters said....

An HON. MEMER: What are you trying to prove?

SHRI VASANT SATHE: I want to prove that Mr. Damodaran Nair is being victimised unnecessarily for speaking the truth. That is my charge against the Home Minister. You are unnecessarily trying to protect the Prime Minister. (*Interruptions*) At page 66, Sardar Patel writes to Shri Shyamaprasad Mookherjee....

SHRI KANWAR LAL GUPTA: On a point of order, Sir. मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जो कालिंग अटेंशन मोशन है वह इसलिए है कि श्री दामोदर नायर को वहां पर असोल्ट किया गया और उनका ठीक से प्रोटेक्शन नहीं हुआ । यह इस्यु है । इसमे वह यह इस्यु कहां से ले आये कि नाथूराम गोडसे आर० एस० एस० का वर्कर था या नहीं था और आर० एस० एस० क्या है । श्री नायर का प्रोटेक्शन नहीं हुआ या हुआ, इसके बारे में उनकी जो फीलिंग्स हैं वह कहें ।

This is very important. Are we here to discuss the ideology and working of the RSS? I want a ruling on this because Mr. Stephen discussed what is RSS and my old RSS worker, Shri Sathe is again discussing the same thing.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अगर वह आर० एस० एस० का मेम्बर था तो उसने हिन्दू सेना की स्थापना क्यों की ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: So, I want a ruling on whether the persons who are being called now will discuss what is R.S.S. Is it the motion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why you would have observed that when he was going on quoting certain things, I asked him to confine himself to the issue under discussion. But he said there are certain related things which he wants to say. But you should not disgress into a discussion of the RSS or its ideology or what it stands for.

SHRI VASANT SATHE: Sir, if you see the Calling Attention notice, you will find that it is directly related to the point of quotation. The wording in this notice is: "To call the attention of the Minister of Home Affairs ...."

MR. DEPUTY-SPEAKER: You come to the point. That is all.

SHRI VASANT SATHE: Do not say that I am going off the Calling Attention Notice which says:

> "....reported attack and assault on Shri Damodaran Nair, a guide of Gandhi Smriti, by R.S.S. workers for his narrating the facts about Gandhiji's murder and the apprehension of such attacks on the guides and the employees of the Smriti in future."

That is where it comes in, I am not going beyond this at all. The following is from Vallabhbhai Patel to Dr. Shyama Prasad Mukherjee—page 66 of "Sardar Patel's Correspondence":

> "I quite agree with you that the Hindu Mahasabha, as an organisation, was not concerned in the conspiracy that led to Gandhiji's murder; but at the same time...."

चौधरी बलबीर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप इन को बड़ा लैटीट्यूड दे रहे हैं ।

MR. DEPUTY SPEAKER: You are unnecessarily dragging on. (*Interruption*).

Mr. Balbir Singh you are giving him latitude. By interrupting him you are giving him more and more time.

SHRI BALBIR SINGH: Rule 197(2) says:

"There shall be no debate on such statement at the time it is made, but each Member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a question."

Nothing more and nothing less. But what is this? *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep quiet. If you go on like this whatever you say will go off the record.

CHOWDHRY BALBIR SINGH: It may be on record or off the record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not get interrupted by anybody. You have one more minute. Please finish it in one minute. Otherwise I will arbitrarily ask you to sit down.

SHRI VASANT SATHE: Everybody is disturbing me. Should I read even when I am disturbed?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You please read. Do not get diverted to anybody.

SHRI VASANT SATHE: "....but at the same time we cannot shut our eyes to the fact that an appreciable number of members of the Mahasabha gloated over the tragedy and distributed sweets....'

"....The same would apply to the R.S.S. with the additional danger inherent in an organisation run in secret on military or semi-military lines."

This is by Vallabhbhai Patel about R.S.S.: "gloated over and distributed sweets" on the death of Mahatma Gandhi.

My last point is that here is a poster which shows that R.S.S. today has gone to the extent of displaying Mahatma Gandhi as a member of the R.S.S. saluting the flag of the RSS and Hegde was patting the author on the back. This is distributed officially now. I would say, to what extent your love for Mahatma Gandhi is understandable. I understand the love of the Home Minister for Mahatma Gandhi. But have you considered this that Mahatma Gandi will be stirring wherever he is? Will he agree that he was a member of the R.S.S. saluting the flag? And this for a disciple of Gandhi speaking the truth and quoting only the truth and nothing but truth from his own autobiography supported and corroborated by the writtings of Gopal! Would you penalise Mr. Damodaran Nair? That is the question for which I would like to get the answer from the hon. Home Minister.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will now call the Minister to reply.

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मुझको यह देख कर खुशी हुई है कि श्री साठे साहब को महात्मा गांधी की स्मृति ताजा हो गई। मुझको ऐसा लगता है कि, मैं यह तो यकीन नहीं कर सकता कि उनकी स्मृति में कोई गलती है, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम गांधी था तो ऐसा लगता है कि गांधी के नाम से ही उनके विचार और आस्था जुड़ी हुई है, चाहे वह महात्मा गांधी हों, या श्रीमती इन्दिरा गांधी हों। इस नाम से उनका इतना अटैचमेंट है यह मुझे जानकर खुशी है। महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी शिक्षायें थीं उन शिक्षाओं को तो उधर के मेरे मित्र भूल चुके थे 20 महीने तक। खुशी की बात है कि उनको उसकी याद आ गई।

सीधा-सा सवाल है, उस बात को ले कर कनफ्यूज करने की जनता में भ्रम डालने की कोशिश की जाये इस सदन के जरिए

ताकि अखबारों में छपे, तो उनकी यह कोशिश बेकार होगी । प्रश्न यह है कि दामोदरन नायर ने कोई बात कही गांधी स्मृति में जो दर्शक वहां गये उनके बिना पूछे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी । यह बात दुनिया में हर आदमी जानता है, जो भी महात्मा गांधी की स्मृति को देखने जाता है वह पहले से ही जानता है कि गोडसे ने उनकी हत्या की । मुझे ऐसा लगता है कि दामोदरन नायर बहुत जोशीले आदमी हैं, वह अपनी तरफ़ से वौलेण्टीयर करते है यह बताना कि गोडसे ने हत्या की जो आर० एस० एस० का वर्कर था । यह भी डिसप्यूटेड बात है कि वह आर० एस० एस० का वर्कर था कि नहीं । तो यह कहने को उनको जरूरत नहीं है । अगर किसी को बुरा लगता है तो जो वहां पर सरकार की तरफ़ से गाइड है उसको किसी पोलिटिकल डिसप्यूटेशन में नहीं पड़ना चाहिए ।... (**व्यवधान**)

मैं यह कह रहा था कि वह एक प्रकार से पब्लिक सर्वेण्ट हैं, इंस्टीट्यूशन की तरफ़ से वहां उसके नुमाइन्दे हैं । जो लोग देखने जाते हैं अगर कोई सवाल पूछा जाय, जो बात उनको अगर यह ख्याल हो कि दर्शकों को मालूम नहीं है वह तो बता सकते हैं । लेकिन किसी विवाद में पड़ना यह उनका कर्त्तव्य नहीं है । नहीं पड़ना चाहिए । लेकिन मालूम ऐसा होता है कि वह आउट आफ़ दी वे जा कर, अपने रास्ते को छोड़ कर, अपने कर्त्तव्य को भुला कर, हर आदमी से ऐग्रेसिवली यह कहते हैं कि वह आर० एस० एस० का वर्कर था । जिसका मतलब यह है कि यह कनवे करना चाहते हैं, सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आर० एस० एस० ने महात्मा गांधी का मर्डर किया । और कोई माने नहीं । इसमें कोई फ़र्क नहीं है..

"Mahatma Gandhi was murdered by R.S.S. or "Mahatma Gandhi was murdered by a man who was a worker of the R.S.S."

जो माननीय स्टीफ़न ने डिफ़रेंस करने की कोशिश की तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या उसमें डिफ़रेंस है ? जो लोग देखने जाते हैं, फिर उसमें बहस होती है, अब वह कि लोगों ने उन पर अटैक किया, यह स्टीफ़न साहब का ख्याल है, यह साबित तो नहीं है कि किसने अटैक किया या नहीं किया । कहा सुनी हुई, गरमा गरमी हो गई, कुछ मारपीट हो गई, किसने शुरू की यह अभी साबित नहीं है । वह मारपीट भी इतनी हल्की हुई कि पुलिस के कहने के बावजूद नायर साहब ने हास्पिटल में जाना जरूरी नहीं समझा ।

डिस्पूट दो बातों पर है । प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो कहा है, वह इर्रेलिवेंट, ग़ैर-मुताल्लिक है, लेकिन चूंकि वह बात बहुत दोहराई गई है, इसलिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, मैं उसके पृष्ठ 248 पर लिखे शब्दों को पढ़ देता हूं :

"Nathu Ram Godse was the man responsible for the murder. He had been a worker of the RSS in Poona and also the editor of a paper."

इसका मतलब यह हुआ कि नाथूराम गोडसे इस हत्या के लिए जिम्मेदार था, नाथूराम गोडसे पूना में आर० एस० एस० का वर्कर और एक पत्र का सम्पादक रहा । मालूम नहीं, श्री साठे ने अंग्रेजी की कौन सी व्याकरण पढ़ी है कि वह "वाज" और "हेड बिन" में फ़र्क नहीं कर पाये ।

SHRI C. M. STEPHEN: May I point out to the Minister that until the last moment he was the Editor of the paper—the same "had been". He "had been" the Editor of the paper and "had been" a member of the R.S.S.

SHRI C. M. STEPHEN]

The fact remains that he was the Editor of the paper on the day of the murder. Therefore, the same "had been" applies meaning thereby that he continues to be in the RSS. It is very clear.

श्री चरण सिंह : अगर वह किसी पेपर का एडीटर है, और उस से पहले वह आर० एस० एस० में रहा था, और आर० एस० एस० को छोड़ कर वह हिन्दू महासभा का मेम्बर हो गया, तो क्या इस का मतलब यह निकला कि वह आर० एस० एस० का मेम्बर है, क्योंकि पहले जिस पत्र के वह सम्पादक थे, वह अब भी है ?

खुद साठे साहब ने माना है कि वह आर० एस० एस० के मेम्बर थे, लेकिन चूंकि आर० एस० एस० 1942 में स्वतन्त्रता-संग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने आर० एस० एस० को छोड़ दिया और कांग्रेस के मेम्बर हो गये। लेकिन उन की दलील यह है कि गोडसे आर० एस० एस० का मेम्बर था, वह बाद में हिन्दू महासभा का मेम्बर हो गया, तो फिर भी वह आर० एस० एस० का मेम्बर रहा। तो क्या मैं यह नतीजा निकालूं कि साठे साहब आज भी आर० एस० एस० के मेम्बर हैं, क्योंकि वह कभी आर० एस० एस० के मेम्बर थे ?

श्री बसन्त साठे : मैंने कहा है कि मैंने आर० एस० एस० को छोड़ दिया। मंत्री महोदय मुझे गोडसे के ये शब्द दिखा दें कि उस ने आर० एस० एस० को छोड़ दिया। उस के भाई ने एक किताब लिखी है, मगर उसने भी यह बात नहीं कही है। (**व्यवधान**)

श्री चरण सिंह : हम ने पुरानी बात पढ़ी है, पुराना तजुर्बा बताता है कि जिस आदमी के पास कोई तर्क न रहे, वह गुस्सा हो जाता है। वही साठे साहब का हाल है। मेरे इस तर्क का जवाब उन के पास नहीं है कि गोडसे भले ही कभी आर० एस० एस० का मेम्बर रहा हो, लेकिन जिस वक्त उसने गांधी जी की हत्या की, उस वक्त वह आर० एस० एस० का मेम्बर नहीं था। दामोदरन नायर अपनी बातों से यह साबित करना चाहते थे कि चूंकि गोडसे एक बार आर० एस० एस० का मेम्बर था, और चूंकि जब उसने महात्मा गांधी की हत्या की, तब भी वह आर० एस० एस० का मेम्बर था, इस लिए आर० एस० एस० ने महात्मा गांधी की हत्या की। यह गलत है। इस पर झगड़ा हो जाता है। अब वह एक कर्मचारी है। उनके लिए आर्डर हुआ कि तुम लाइब्रेरी में चले जाओ। 31 तारीख को वहां कुछ साहब गए, कुछ लड़के गये, भट्ट साहब गए, प्रोफेसर थे गुजरात के, वह वहां बरामद थे, वहां मौजूद थे। क्यों ? दैट वाज नाट हिज डयूटी। इस से मालूम होता है कि उन के मन में भी है कि आर० एस० एस० के खिलाफ़ प्रचार करें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। महात्मा गांधी की मेमरी के प्रति जितना साठे साहब या उधर बैठे हुए लोगों के अन्दर पवित्रता और आदर का भाव है, हम में से जितने यहां बैठे हैं, किसी को उस से कम नहीं है, उस से ज्यादा ही हैं शायद। सवाल यह होता है कि गवर्नमेंट को इस मामले में क्या करना चाहिए।

15 hrs.

श्री बसंत साठे : उसी आदर का यह नमूना है.... (**व्यवधान**) ....

श्री चरण सिंह : अब रहने दीजिए। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि सब्र रखें। कमीशन बैठ रहे हैं, राज नंगे हो रहे हैं। अभी आप अपनी चीजों को रहने दें।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब सवाल आता है कि गवर्नमैंट की तरफ से इसमें कोई कोताही हुई है ? नहीं हुई है क्योंकि वह कोई काग्निजेबल आफेंस नहीं था । मारपीट हुई, मारपीट भी कोई जोर की नहीं हुई, न किसी की हड्डी टूटी, न किसी को आंख गई । कुछ भी नहीं हुआ । पुलिस ने आफर भी किया । नहीं गए वह । तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस कालिंग अटेंशन में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो यह प्रस्ताव आया यह प्रस्ताव किस लिए आया ? लोगों से मतलब गवर्नमैंट से है । किस चीज की बाबत वह यहां लाया गया ? क्या करे गवर्नमैंट ? गवर्नमैंट की तरफ से या प्रधान मंत्री की तरफ से जो उस के अध्यक्ष थे यह इशारा हुआ उस को कि तुम यहां से हट जाओ, या बाद में उनको आर्डर दिया गया कि तुम लाइब्रेरी में चले जाओ । इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है । मैं नहीं समझता कि इसके लिए कोई आकेजन था इस प्रस्ताव को यहां लाने के लिए ।

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Is the Home Minister giving a new interpretation to the Indian Penal Code and criminal law in this country by saying हड्डी नहीं टूटी तो कोई आफेंस नहीं हुआ ?

SHRI HITENDRA DESAI (Godhra): I thought the issue involved was of such great importance that even the members of the ruling party would support to some extent our views in the matter. At least I was very sorry to note that the old Gandhian Home Minister only found fault with the guide and did not find fault with the administration of the Gandhian Smriti.

The relevant point is that two incidents have taken place, both on two historical days, one during Gandhi Jayanti on 9th October ....

SOME HON. MEMBERS: Second October.

SHRI HITENDRA DESAI: I was referring to the Gandhi Jayanti Week; and the other on 31st October, Sardar Jayanti Day.

After all, what was the duty of the guide? He has not been saying merely on this occasion. I understand he has been a guide for more than two years, right from March, 1975, and I understand he has been saying this when visitors come there and visit the Samadhi. They ask how Mahatma Gandhi was murdered. What do you expect the Guide to say? If he merely says that he was murdered by Nathuram Godse, naturally people will ask who was he. Was it outside his purview to say that Nathuram Godse had been an RSS worker? What is wrong about it? That is the main point about which I want the Home Minister to consider.

A passage from the autobiography of the Prime Minister was read. It has been clearly said that the murderer Nathuram Godse had been an RSS worker. Apart from that, I will refer to Chapter 34—Assassination of Gandhiji. These worlds have to be read in that context.

> "Communal volunteer organisations were declared illegal in the first quarter of 1948. They included organisations like Khaksars, the Muslim National Guards and the RSS. These worders were passed under the Bombay Public Security (Measures) Act which kept a check on anti-social and communal elements. This enabled us to put a stop to incidence leading to riots. The Govt. had wide powers under the Act. We were at pains to use these powers with great care and caution."

When the RSS was declared illegal under this Act, he says:

> "The purpose of the steps taken was to prevent the incitement of communal passions and the spreading of false rumours."

[Shri Hitendra Desai—contd.]

What the guide was doing He was merely narrating what the Prime Minister has said in his autobiography. I do not think it will be possible for anyone to re-write the assassination history of Mahatma Gandhi.

In reply to my Unstarred Question on 14th November, it has been clearly stated that on 9th October, 1977, a visitor to the Gandhi Smriti who is reported to be an RSS worker—Shri Mahajan was the RSS worker—protested and exchanged hot words with the Guide, Shri Damodaran Nayar when the latter described the assassin of Mahatma Gandhi as Nathuram Godse, an RSS worker. This is what the Guide has said. If he was in the wrong, he should have been called and told the true facts. But instead of protecting him, a transfer order was given on 4th of November—a copy of which I have got with me—and he was posted in the Library. What was his fault?

Apart from this, even on 31st of October, a much worse incident took place when 40 students from Gujarat who were members of RSS, went there. Four buses were there. If they really wanted to pay homage, all should have gone there. But a few of them went there and the rest of them were sitting in the buses, and confronted the Guide: "Why do you say like this?". Therefore, merely because a few persons protest against the historical fact about the assassination of Mahatma Gandhi, is it proper for a Gandhian like the Home Minister to say that Shri Damodaran Nayar should have stopped at that. I would have certainly expected the Home Minister to come out and say, "It is a historical fact. The guide was quite right in saying that; it was within his duties and what he said was correct and, therefore, he should have been protected." It is not for the first time that the guide has said this; it is not for the first time even in the last six months. He has been saying it right from the beginning.

Let us not forget that, after all, Gandhi Smriti is a national memorial to Mahatma Gandhi. I have gone there several times. The moment we enter that premises, there is a plaque there. Shall I read what is written in that plate? It is written:

> "This national memorial honours the virtues of truth, non-violence, unity and equality. The hallowed house which treasures many cherished memories of the last days of Mahatma Gandhi now forms a part of our rich national heritage. The walls of the building reverberate with his massage, 'All men are brothers'. Gandhiji's life and teachings have left an indelible mark on human history and the purpose of preserving the memorial is to foster and propagate his ideals."

This is the task for which Gandhi Smriti has been established.

It is not quite correct to say that the Government has nothing to do with Gandhi Smriti. In fact, Gandhi Smriti comes under the Works and Housing Ministry. I understand, the Prime Minister is the President of that Smriti; the Works and Housing Minister is the Vice-President of that Smriti and the Joint Secretary of the Works and Housing Ministry is the ex-officio Secretary of that Smriti. In fact, I put this Question to the Works and Housing Minister. It is not merely a question of law and order. It is a question of the failure of the Ministry to safeguard Gandhi Smriti which is really a national memorial to Mahatma Gandhi revered throughout the country by all Indians.

I am glad to say that even those who were opposed once to Mahatma Gandhi and those who were opposed to his ideals and philosophy have at least now, after the elections, taken the oath at the Rajghat. I would expect them and I would still expect the Home Minister to come forward and say that Gandhi Smriti will be protected, that ideals and principles fol-

lowed by Mahatma Gandhi will be revered and respected and that history will not be attempted to be re-written.

श्री चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि मैंने अभी जो थोड़ा-सा कथन किया था, उस के बाद माननीय हितेन्द्र देसाई जी के बोलने का ढंग कुछ और होगा, लेकिन संगत से आदमी बच नहीं सकता है । उन का कहना है कि कम से कम अब जनता पार्टी के लोग सच्चाई की बात करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी की समाधि पर उन के पद-चिह्नों पर चलने की कसम खाई है । मैं आप के जरिये माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के लोग इस मुल्क में कभी भी एमर्जेंसी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इण्डिविजुअल-फ्रीडम को जब्त न करने की कसम खाई है । वे कभी भी इस के पक्ष में वोट नहीं देंगे—इतना यकीन में दिला सकता हूं । आप जितने कर्म कर गये हैं, वह जो अन्याय की इमारत बन गई है, इस को ढाने में थोड़ी देर लगेगी, समय लगेगा, वह ढाई जा रही है · · · (**व्यवधान**) · · · ·

एक माननीय सदस्य : हमने जितना एमर्जेंसी में नहीं किया, उससे ज्यादा आप कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह : मैं यह समझता हूं कि अगर शोर मचाने की बात हो, तो हमारा हित शोर मचाने में नहीं है, हम चाहते है कि शान्ति से बातें हों । शोर का जवाब शोर से दिया जाये तो यह हाउस नहीं चल सकेगा ।

मैं अर्ज कर रहा था—उनका कहना है कि वह गवर्नमैंट बाडी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस के प्रेसिडेण्ट है और मिनिस्ट्री का फलां सैक्रेटरी उस का सैक्रेटरी है । इस का मतलब है—हाई कोर्ट स में जजों का प्वाइन्टमैण्ट होम मिनिस्टर या प्रेसिडेण्ट करता है, हाई कोर्ट का सारा खर्चा गवर्नमैंट उठाती है, इस तरह से तो वह भी गवर्नमैंट की संस्था हो गई, लेकिन यह गलत है, इस प्रकार से उस को गवर्नमैंट की संस्था नहीं कहा जा सकता है—मेरा केवल यही प्वाइण्ट है । तो इसी तरीके से गांधी स्मृति की जो समिति है वह गवर्नमैंट की संस्था नहीं कही जा सकती ।

श्री वसंत साठे : 10 गुंडे अगर किसी जज को मार दें, तो आप देखते रहेंगें । यही आप का एडमिनिस्ट्रेशन है, वंडरफुल ।

This is a wonderful understanding.

SHRI SAUGATA ROY: He is giving his own interpretation of the Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody is entitled to give his own interpretation. You are also entitled to give your own interpretation. Please listen to him.

श्री चरण सिंह : जनतंत्र का तकाजा यह है कि आप शान्ति से सुनें । जिस तरह से, ग़लत तर्क आप दे रहे थे, तो मैं शान्ति से सुन रहा था । इसलिए अगर आप को बुरा भी लगे तो भी आप शान्ति से सुनिये चाहे उस में कड़वाहट हो सच्चाई हो और चाहे आप को सच्चाई कितनी ही नापसन्द क्यों न हो । · · · (**व्यवधान**) · · ·

माननीय देसाई ने सीधी सी बात यह कही है कि गोडसे महात्मा जी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे । साथ ही यह कहा है कि वे आर० एस० एस० के मेम्बर रहे थे, 'वाज' और 'ड्रेड' में इतना फ़र्क है, जिसका मतलब यह है कि जिस वक्त उन्होंने हत्या की, उस वक्त वे आर० एस० एस० के मेम्बर नहीं थे । फिर प्यारे लाल की पुस्तक में कुछ

[श्री चरण सिंह]

लिखा हो या किसी और की पुस्तक में कुछ लिखा हो, गोडसे ने कोर्ट में यह बयान दिया था कि मैं कभी आर० एस० एस० का मेम्बर था लेकिन बहुत दिनों से मैं आर० एस० एस० छोड़ चुका हूं और अब मैं हिन्दु महासभा का मेम्बर हूं। हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जिस वक्त उस ने कत्ल किया था, वह आर० एस० एस० का मेम्बर नहीं था और हिन्दु महासभा का मेम्बर था। यह मोटी सी सच्चाई है।

SHRI VASANT SATHE: Please quote where the High Court has said that when you say that he left RSS. Otherwise accept that.

SHRI CHARAN SINGH: The High Court said:

"Nathu Ram Godse is the editor of a newspaper. He was born in a devotional brahmin family of the Bombay Presidency. He worked for several years in RSS and subsequently joined the Hindu Mahasabha of which Mr. Sawarker was the President. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: Accept this if you have some honesty in you. Accept that this is not what the High Court says. (*Interruptions*).

SHRI C. M. STEPHEN: Unless you say that a person could not be a member of the RSS and the Hindu Mahasabha together, a mere statement that he joined the Hindu Mahasabha cannot obviously mean that he left RSS. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: At least he you have been proved untrue wrong. (*Interruptions*). At least he you have been proved false. (*Interruptions*).

श्री चरण सिंह : मैं यह उम्मीद करता था कि इस बात को आप समझेंगे। डा० मुरली मनोहर जोशी भी यहां पर बैठे हुए हैं। वे भी जानते हैं। जो बयान दिया गया था, उस में उन्होंने यह कहा था :

"I have worked for several years in RSS and subsequently joined the Hindu Mahasabha."
(*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): It is a goonda organisation.
(*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: He also does nat say that he left. You have doubly proved wrong. (*Interruptions*).

SHRI SAUGATA ROY: His logic is unfounded. (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE: Unless you positively say that he left, unless you have quoted him wrongly.... (*Interruptions*). He is misleading the House, misleading you by telling the falsehood. (*Interruptions*). Let him admit.

श्री चरण सिंह : मैं आपकी इजाजत से आपके दोस्तों की उपेक्षा करता हूं और साथ ही अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त यहां कांग्रेस की हकुमत थी, उस समय सरदार पटेल और कांग्रेस की गवर्नमैंट का यह ख्याल था कि इस में आर० एस० एस० का हाथ है। इसलिए आर० एस० एस० के लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हकीकत के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि महात्मा गांधी के मर्डर में आर० एस० एस० का हाथ नहीं था। 12 जुलाई, सन् 1949 को जो गवर्नमैंट का बयान निकला उससे यह साफ़ जाहिर हो गया और उसके बाद जितने भी आर० एस० एस० के वर्कर्स थे, लीडर्स थे, एसोसिएट्स थे, सब की रिहाई एक साथ हो गई। (व्यवधान) अगर आपने इसी तरीके से

रखा तो फिर आपमें से कोई नहीं बोल पाएगा। आप कदम-ब-कदम पर बोल रहे हैं । (व्यवधान)...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. If anybody gets up and shouts, it is not going to help anybody. Please hold your patience. We have had enough of this noise. It is not going to help anybody. Let the Minister continue.

श्री चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कंसीड करने के लिए तैयार हूं कि श्री नैयर या और किसी को भी हमारी डेमोक्रेसी में और किसी भी डेमोक्रेसी में यह हक हासिल है कि वह गलत बात कह सके। यहां तक कि किसी को झूठी बात कहने का भी हक हासिल है। लेकिन जब हम नैयर साहब की बात करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है। वह एक संस्था के कर्मचारी हैं और उसको आप गवर्नमेंट की संस्था कहते हो। इस नाते उनको यह हक हासिल नहीं है और इसलिए नहीं है कि दूसरों को वह बात बुरी लगती है और दूसरे लोग इसको डिस्प्यूटड या विवादास्पद मानते हैं। मैं यह माने लेता हूं कि एक प्राइवट नागरिक होने के नाते उनको यह हक हासिल हो लेकिन जब दूसरों को इस पर एतराज हो तो उन्हें यह बात खत्म कर देनी चाहिए। वह तो एक संस्था के कर्मचारी हैं लेकिन वे इस बात को एग्रेसिवली कहते हैं। प्रधान मंत्री ने समझाया, और सबने उन्हें समझाया। प्रधान मंत्री, माननीय देसाई ने बुला कर उन्हें समझाया तब भी वे नहीं माने।

अब सवाल यह है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटि है, वह क्या कर सकती थी? एक मामूली मार-पीट होती है और रोजाना हजारों-लाखों इस किस्म की मारपीटें होती हैं लेकिन पुलिस उनका चालान नहीं करती हैं क्योंकि नान-कागनेजिबल आफेंस है। अगर कागनेजिबल आफेंस होता, कोई ग्रीविश मारपीट होती, हर्ट हो जाता तो पुलिस का फर्ज बनता था कि वह उस सूरत में चालान करती और पुलिस चालान नहीं करती तब गवर्नमेंट का फेल्योर था और अगर हम पुलिस वालों से जवाब-तलब नहीं करते तो यह चीज आ सकती थी।

15.23 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

(i) MINUTES

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the Committee on Papers Laid on the Table held on 27th November and 30th December, 1976 and 1st September, 1977.

(ii) FIRST REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I beg to present the First Report of the Committee on Papers Laid on the Table.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SIXTEENTH REPORT

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I beg to present the Sixteenth Report of the Public Accounts Committee on paragraph 32 relating to 5th International Film Festival included in the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75, Union Government (Civil).

RAILWAY COVENTION COMMITTEE

FIRST REPORT

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to present the First Report of the Railway Convention Committee on 'Rate of Dividend for 1977-78 and 1978-79 and other Ancillary Matters'.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

THIRD REPORT

DR. BAPU KALDATY (Aurangabad): I beg to present the Third Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

15.25 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 16th November, 1977, with the corrigendum which has been circulated."

SHRI P. K. DEO: Sir, I would like to submit in this regard that the time allotted for discussion on floods is only two hours. The damage done by floods has been colossal. I most respectfully submit that at least six hours should be allotted for this purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 16th November, 1977, with the corrigendum which has been circulated."

The motion was adopted.

15.27 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) STATEMENTS MADE BY THE CENTRAL MINISTERS ABOUT CHIEF MINISTER OF TAMIL NADU

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): Sir, you will agree that the Centre-State relationship is a delicately balanced one and nothing should be done to disturb it. This is more so when the ruling Party in a State is different from the ruling Party at the Centre. Responsible Central Ministers should bear this in mind when they visit States and should not speak as though the State Governments are Departments administered by them. Nor should they feel free to give unasked-for advice.

The Janata Party, in their election manifesto, proclaimed they would uphold the principle of Federalism if they were returned to power. It would be better if the Janata Ministers keep this assurance in mind and do not do anything to undermine the federal set-up in this country.

Now, Sir, when there was a delicate law and order situation prevailing in Tamilnadu, the Hon. Minister for Health and Family Welfare who visited the State at that time said something which would rather aggravate the situation and not soothen it. It is very unfortunate that he should have said so. In connection with the visit of Mrs. Indira Gandhi to Tamilnadu, the DMK Party wanted to have a peaceful Black-flag demonstration. They said it would be perfectly peaceful and the Anna DMK Government therefore, in perfect good faith and believing the words of the DMK Leaders, permitted this demonstration to be held in Madurai, Tiruchirapalli and Madras. Now, on the very first day, when Mrs. Gandhi visited Madurai, the demonstration was anything but non-violent. It turned very violent and there was a murderous attack on the processionists and, in the words of the Chief Minister of Tamilnadu, it was lucky that Mrs. Gandhi escaped with her life. It was a murderous attack preplanned and aimed at Mrs. Gandhi and her followers. When this happened, the Tamilnadu Government revoked the permission given to the demonstrators because it was proved beyond doubt that they never intended to remain peaceful, and prohibitory orders were imposed in other

places which Mrs. Gandhi was to visit, namely Madras city and also Kanchipuram. At this juncture or soon after, the Hon. Minister for Health and Family Welfare goes there and this is what he says, according to the Press:

> 'Shri Raj Narain took strong exception to the Tamilnadu Chief Minister Mr. M. G. Ramachandran calling on the former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi during her visit here last week'.
>
> 'He told newsmen at the airport that by meeting Mrs. Gandhi, Mr. M. G. Ramachandran has lowered his prestige. The Shah Commission was going into various charges. "Does he bow down before corruption?' he asked.
>
> "She is no longer the Prime Minister but only an ordinary citizen. Does the Chief Minister ordinarily go and see an ordinary person?"

This was what he said, according to what was reported. I did not think that Shri Raj Narain, who is a follower of late Dr. Lohia and who is an arch socialist, would mouth this opinion that when a man becomes a Minister he should not go and see an ordinary person. Shrimati Indira Gandhi has ceased to be the Prime Minister and is now an ordinary person and the Chief Minister should see only persons who are occupying high positions. This is what he said. When did Central Ministers assume responsibility to regulate the ordinary visits of Chief Ministers in the States? Are they incharge of fixing interviews for the Chief Ministers of various States? It is very strange that this gentleman, a very responsible Central Minister, should go and say that the Chief Minister should not see ordinary persons. He says and it was reported in the press:

> "He had come to know that prohibitory orders had been promulgated in Madras following violent incidents at Madurai at Mrs. Gandhi's instance."

He said:

> "I am told that she had phoned him (Shri M. G. Ramachandran) and the Chief Minister acted on her suggestion."

Is it fair on the part of a responsible Central Minister to insinuate, to tell the public that here is a Chief Minister who acts on instructions from Shrimati Indira Gandhi. What evidence did he have in his possession to make this statement? How does he make this allegation? I want you to consider whether this is not a direct interference in the affairs of the State in the matter of law and order which is an exclusive subject within the jurisdiction of the State Governments. If this is the way the Central Ministers are going to behave? One should give serious thought, this House should give very serious thought and the Government headed by Shri Morarji Desai should give very serious thought to this. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has refuted this statement. He said that the Central Ministers should not come and make statements like this in the States without verification of facts. He has put it in a very respectable and polite manner. He has also denied the allegation that Shri Raj Narain made that the demonstrations were banned at the instance of Shrimati Indira Gandhi.

The Chief Minister of Tamil Nadu has written, I am told,—I do not know whether it is correct or not—to the Prime Minister here that he should put some restraint on the Central Ministers in the matter of making statements without verification of facts.

Another Central Minister, a very responsible person, the Minister for Industry went there after that. As a

[Shri O. V. Alagesan]

result of all these turbulent activities, violent demonstrations, arson and loot, and after railway property, public and government property worth lakhs was destroyed by the demonstrators, the State Government, which is incharge of the law and order, took some action.... (*Interruptions*).

श्री उग्रसेन : (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो उन दिनों बंगलौर में था; कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, पाटिल साहब के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, माननीय स्टीफ़न की पार्टी के लोग उसमें थे जिन्होंने प्रदर्शन किया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ugresen, if you had not interrupted Shri Alagesan, other Members would not have stood up.

SHRI O. V. ALAGESAN: Again I appeal to you that I should not become the victim of these interruptions...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Some members want to have the cake and eat it too. It is not possible. If you interrupt another member, he will take more time and there is no point in complaining that he takes a long time. Please don't interrupt him. I have given him 5 minutes. Let him have his say and be done with it.

SHRI O. V. ALAGESAN: After all these violent incidents, the State Government took some steps. They got Shri Karunanidhi and others arrested and this Central Minister for Industry goes there and criticises the State Government for having arrested those leaders. He may be paying a debt of gratitude to Shri Karunanidhi because he gave him refuge at a time when he wanted it the most. But that is a private affair. He cannot interfere in the affairs of the State Government in the matter of law and order. In order to protect the situation and prevent further violent happenings in the State when the State Government goes and takes certain steps and that too, in accordance with the law, I would like to know under what authority and under what article of the Constitution the Central Minister goes and says that this should not have been done. This is a very serious matter. The conduct of the two Central Ministers is highly unconstitutional, illegal and highly reprehensible and not conceived in in the interests of the people of the State.

So I would like to appeal to the Prime Minister, Shri Morarji Desai that he should properly discipline his Ministers and see that such things are not repeated in future.

(ii) WORKING OF GRINDLAYS BANK LTD.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I rise to bring to the notice of this House a matter of great importance under Rule 377.

For some time past, the Grindlays Bank Ltd. which is a foreign bank operating in India under the licence of the Reserve Bank of India has been indulging in activities which are contrary to public interest. In recent times it has been acting in definance of the code of ethics and the rules of conduct of Banks and also of the wishes of the Reserve Bank of India. This Bank arbitrarily raised the minimum amount of deposits in Savings Bank accounts and fixed deposit accounts as a result whereof common people and depositors of small amounts are not allowed to maintain any account with the Bank. The bank is denying all facilities to small depositors. Their attempt is to make more profits by allowing only big accounts to be operated and it is acting as financial advisers of big business and monopoly houses, both Indian and foreign.

Very recently, the bank has taken a most arbitrary decision to shift uni-

laterally the accounts from one Branch to another without the consent of the account-holders which will result not only in great inconvenience to the account-holders but is a practice unheard of in the banking business. This has created justifiably a serious resentment among the depositors. They have formed an association and are carrying on an agitation there.

In the Grindlays Bank for the last 2-3 years no vacancies have been filled up. As a result the strength of the employees has come down by about 120. It is apprehended that within the next few years the present strength of the staff will be reduced to half. By restricting their activities with big business and big account-holders only, the job potential in the Bank has been substantially reduced and the future of the present employees has become uncertain.

So, it is urgently necessary for the Reserve Bank of India to intervene in the matter. Under Section 35A of the Banking Regulation Act the Reserve Bank of India can issue directions to all banks including foreign banks and unless the Reserve Bank moves in the matter and the central government takes action, not only this agitation will go on and account-holders are being arbitrarily asked to go from one branch to another and employees are being transferred from one place to another without any consultation and the staff pattern is being altered. This is creating great difficulty and resentment among the account-holders and employees and demonstrations are going on. I request the hon. Labour Minister who is present in the House. We have met the Finance Minister also and it seems no action is being taken. It is high time that some action it taken in the matter. Particularly I request the Labour Minister who is here to look into the matter.

15.40 hrs.

MOTION *RE.* TWENTYETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND DISCUSSION ON EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES AGAINST RESERVED QUOTA- *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate.

Shri Kacharulal Hemraj Jain to continue his speech.

श्री कचरु लाल हेमराज जैन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है । मैं सर्वप्रथम यहां चुन कर आए हुए सदस्यों को आगाह कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 60 प्रतिशत आबादी में बसे हुए हरिजन और आदिवासी हैं और आज उन की क्या हालत है यह अच्छी तरह से हर निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य जानता है । आज हम इस बात को देख रहे हैं इस सदन में 8 महीने से कि पुरानी सरकार ने यह किया और वह किया ।

15.41 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, अभी यहां हमारे श्रम मंत्री बैठे हुए हैं, मैंने पिछले भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में 70 लाख लोग बीड़ी मजदूर हैं और वे हरिजन आदिवासी हैं । पिछले बजट सत्र में बीड़ी पर कर लगाया गया । आज तीस सालों की आजादी के बाद भी बीड़ी उद्योग में काम करने वालों के लिए कोई नियम लागू नहीं है । उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि वें दाने-दाने को मोहताज हैं । बीड़ी उद्योगपति सब गुजरात के लोग हैं और वे शासन के साथ मिल कर 70 लाख लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं । सरकार की ओर से उसके लिए उनको कोई प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है ।

[श्री कचरु लाल हेमराज जैन]

अभी भूमिहीन हरिजन आदिवासियों को भूमि का जो वितरण हुआ हैं वह एक मखौल किया गया है, एक मजाक किया गया है और आज भी सरकार का कोई कदम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है । उनको ऐसी जमीन बांटी गई है जिसमें वे तो क्या उन के नाती-पनत भी अनाज नहीं बो सकते हैं । हरिजन आदिवासियों की दोहाई देने वाली सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों में उस भूमि का वितरण हुआ है उन्हें भूमि दुरुस्त करके और खेती लायक बना कर दें। आज दुनिया भर की बातें आ रही हैं । गांवों में जाते हैं तो देखते है कि जो हरिजन आदिवासी गांवों में बसे हैं उनकी ऐसी दुर्गती है कि जिस की कोई सीमा नहीं । बीड़ी के मालिक वहां खुले आम नंगी लूट कर रहे हैं । हमारे मध्य प्रदेश में उन ग्रामीण लोगों को, हरिजन और आदिवासियों को जो काम मिलता है मध्य प्रदेश शासन के पी०डब्ल्यू डी० या इरीगेशन की तरफ से उसमें उन का जो रेट हैं वह करीब ढाई रुपये रोज है । ढाई रुपये रोज पर आज भी उन से वहां काम लिया जा रहा है। इस सरकार के आने के बाद भी उन की कोई वेतन-वृद्धि नहीं हुई है और पुरानी सरकार ने पिछले तीस सालों में उन की खाल निकाल ली है । क्या इस सरकार का इस ओर भी ध्यान है कि उन गरीबों को उनकी मेहनत का वाजिब पैसा मिले ? इस के लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा ।

आज मैं कह देना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा, पूरे भारत के लिए संसार के अन्दर एक कलंक है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में एक कोटवार होता है जिस की तनख्वाह 25 रुपये महीना है । शर्म की बात है हमारे लिए, तीस साल की आजादी के बाद तीसों दिन काम करवे के बाद 25 रुपये उनको तनख्वाह के मिलते हैं और तनख्वाह के वितरण का तरीका भी सुन लें । तीन महीने में उन को तनख्वाह मिलेगी और उसके लिए गांव का रहने वाला कोटवार तहसील के हेडक्वार्टर पर जायेगा । तीन बार उस का बुलावा होगा, तीस रुपये उस के उस में खर्च हो जाएंगे, 70 की जगह पर उसको 40 रुपये मिलेंगे । यह व्यवस्था हमारे लिए कलंक का विषय बनी हुई है । इन कोटवारों में भी कोई ब्राह्मण या अन्य जाति का आदमी काम नहीं कर रहा है, 99 फीसदी हरिजन काम कर रहे हैं । उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार भारत की आजादी के बाद भी चल रहा है । बड़ा शोचनीय विषय है ।

जो हमारे हरिजन और आदिवासी भाई हैं उन के लिए जो साधन और सुविधाएं दी जानी चाहिएं उस पर पुरानी सरकार ने दुर्लक्ष्य किया है और हमारी नई सरकार के आने के बाद भी उस पर कोई लक्ष्य, कोई कदम, कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है । इस-लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर वह ध्यान दे और अति शीघ्र इस पर निर्णय ले अन्यथा यह जो आज गरीब लोगों की आत्मा तड़प रही है अगर यह ज्वाला भड़क गई तो कोई सरकार इसके सामने बचने वाली नहीं है ।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हरिजन आदिवासियों के लिए जितने आयुक्त और उच्च अधिकारी नियक्त हैं वे जन्मजात उन के दुश्मन हैं । चौबे, पांडेय, दुबे, शुक्ला, मिश्रा यही उनके उच्च अधिकारी बने हुए हैं । जिन्हे पुरानी सरकार ने रखा है वही आज भी नई सरकार में कायम हैं । मैं नयी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो ये उच्च अधिकारी है वे उन्हीं में से हों। उन्हीं में से योग्य व्यक्तियों को लेकर उन पदों पर रखा जाये । आज जबकि उनके लिए रिजर्वेशन है और

उनके अन्दर काफी योग्य व्यक्ति हैं तब भी वे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं । उनको मौका नहीं मिलता है । उसी तरह से वह काम चालू है । मैं खासतौर पर सरकार से कहना चाहता हूं और श्रम मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि याद रखिए, बीड़ी कामगारों के लिए अगर अच्छी नीति नहीं अपनाई तो उनमें बड़ा असंतोष फैलेगा । वहां पर आज भी ठेकेदारी प्रथा चलती है, सरेआम कत्लेआम हो रहा है । यदि समय रहते सरकार ने मुनासिब कदम नहीं उठाये तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है । आज इस देश में नई सरकार बनने के बाद लोग बड़ी-बड़ी आशायें लगा कर बैठे हैं । हम जब अपने निर्वाचन-क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो हम कहते हैं रघुपति राघव राजाराम हुआ क्योंकि यहां से हमको कोई ऐसी चीज बतलाई नहीं जा रही है जो हम वहां जाकर उनको बता सकें । आज ग्रामीण अंचलों में हरिजन और आदिवासी तड़प रहे हैं । वहां पर रास्तों का कोई ठिकाना नहीं है । छोटी-छोटी पुलियों को बनाने और रास्तों को बनाने का कोई काम चालू नहीं हैं । लोग बेचारे काम पाने के लिए तरस रहे हैं । उनको एक रुपया रोज को मजदूरी भी नहीं मिल रही हैं ।

कल यहां पर वित्त मंत्री महोदय ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करदी जिस पर सालाना 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे । लेकिन मैं पूछता हूं कि उन लोगों को कौन महंगाई भत्ता देगा जिनको गांव में एक रुपया रोज भी नहीं मिल रहा है । तो इस प्रकार की अनियमितता इस देश में नहीं चलनी चाहिए । मैं कहता हूं कि आप इस पर जल्दी से जल्दी विचार कीजिए क्योंकि अगर कहीं इस देश में इस विषय को लेकर ज्वाला भड़क गई तो उसमें कोई भी नहीं बचेगा । आज महंगाई अपनी चर्म सीमा को पहुंच गई है, देश की जनता तड़प रही है और हर तरफ बेकारी तथा बेरोजगारी छाई हुई है ।

हरिजन और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट बनाया जाता है । पिछली सरकार ने ऋण मुक्ति का एक ड्रामा खेला था, मैं आज यह भी बता दूं कि उसका क्या नतीजा निकला । सैकड़े में दस प्रतिशत लोगों को साहूकारों से जबर्दस्ती माल दिलाया गया लेकिन 90 प्रतिशत लोगों को माल नहीं मिला । आज लोगों को अगर दस रुपये की आवश्यकता होती है और उनके पास सौ रुपये का जेवर हो तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है । मैं जानता चाहता हूं इस सम्बन्ध में नई सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है ? जो लोग पहले अपना जेवर रख कर कर्जा लिया करते थे उनको पैसा दिलाने का सरकार ने कौन सा प्रबन्ध किया हैं ? कौन सी पद्धति का विस्तार किया गया है जिससे कि उनको पैसा मिल सके ? आप शहरों की बात ही देख रहे हैं लेकिन अगर आप देहातों में जायें, तो देखेंगे कि वहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है ।

जिन हरिजनों ने बौद्ध धर्म गृहण किया है उनके सम्बन्ध में जो नयी पद्धति अपनाई गई हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म नहीं है ? पुरानी सरकार ने यह बात कह कर नव बौद्ध हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं और सहूलियतों पर प्रतिबन्ध लगाया । 17 अगस्त को हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री खोबरगढ़े के साथी श्री डी० जी० गवई साहब, संसद सदस्य प्रधान मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि उनको यह सुविधाएं जरूर दी जानी चाहिएं लेकिन अगस्त के बाद अब नवम्बर चल रहा है, उस बात को लेकर कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका कोई अंजाम नहीं निकल रहा है । क्या बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म नहीं है ? अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन

[श्री कचरु लाल हेंमराज जैन]

कर लिया तो क्या उनकी परिस्थिति बदल गई, वे पैसे वाले हो गए? क्या एक दिन में उनका नकशा बदल गया ? इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आज गांवों में हरिजनों को सस्ते रेट पर अनाज देने की बात कही जा रही है । बड़े-बड़े अखबारों और प्रचार सामग्री के माध्यम से घोषणा की जाती है लेकिन आप गांवों में जा कर देखें तो पता चलेगा कि उनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है । सरेआम उनकी लूट हो रही है । उन्होंने इस नई सरकार से बड़ी आशायें लगा रखी हैं । मैं आशा करता हूं हमारी नई सरकार अपनी श्रम नीति के द्वारा उनको सम्पूर्ण अधिकार और साधन दिलाने की चुनौती स्वीकार करेगी और उसको कार्यान्वित भी करेगी । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित जो रिपोर्ट सदन में पेश की गई हैं, उन पर आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया है, इस के लिये मैं आप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

बड़े दुख के साथ मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूं–इन चार रिपोर्टों पर जो आज इस सदन में पेश हैं, इन पर पिछले सदन में बहस शुरू हुई, लेकिन उस समय बहस पूरी न हो सकी । हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि हम लोगों को बोलने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया, इसीलिये इस अधिवेशन में इस बहस को बढ़ाया गया । अभी कुछ सज्जन कह रहे थे कि जब भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयुल्ड ट्राइब्स के मामलों को लेकर इस सदन में बहस होती है एक उपेक्षित सा वातावरण सदन में बना रहता है । जब समय बचता है तब थोड़ी सी बहस हो जाती है, जैसे कल आधा घन्टा बहस हुई, आज शायद एक दो घन्टे बहस हो जाये, इसी तरह से कल भी आधा या एक घन्टा बहस हो जायेगी । इस तरह का जो उपेक्षित रवया हम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है–मैं भविष्य के लिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं–जब भी पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोई प्रश्न आये, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की उपेक्षा का व्यवहार न हो, इस तरह का वातावरण न बनने पाये । मैं सरकार के जिम्मेदार लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वे जानते हैं कि आज जनता सरकार के प्रति हरिजनों के प्रश्न को लेकर एक तूमार मचा हुआ है । इस तूमार में यह बात नहीं है कि यह कोई बनावटी तूमार है पिछली सरकार ने जो उपेक्षित दृष्टिकोण हरिजनों के प्रति रखा, उसमें वर्तमान सरकार कोई सुधार नहीं कर पाई है । ऐसा वातावरण अभी नहीं बन पाया है, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी जनता सरकार देखेगी और विचार करेगी और ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेगी ताकि हरिजनों और उपेक्षित वर्ग के लोगों का विश्वास वह प्राप्त कर सके ।

अधिष्ठाता महोदय, जबसे देश में कांग्रेस राज्य बना, मैं भी कांग्रेस में रहा । सन् 1952 से लेकर आज तक मैं देखता आया हूं– इस पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये चाहे सामाजिक उन्नति हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने की बात हो–तरह-तरह की मदद करने के प्रयास किये गये । लेकिन दुर्भाग्य

यह रहा कि मदद के तौर-तरीके जो रहे, वे समझ के बाहर रहे। जैसे आर्थिक दृष्टि से मदद करने की बात कही गई, तो हम हरिजनों से कहा गया कि आप सूअर पालिये, मुर्गी पालिये, बकरी पालिये, यह कभी नहीं कहा गया कि गाय पालिये, भैंस पालिये या दूसरे रोजगार धन्धे कर लीजिये। वे काम जिन से दूसरी जातियों के लोग घृणा करते हैं, उन को इस समाज में कराने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि यह वर्ग पिछले तीस सालों में तरक्की नहीं कर पाया।

इस तरह से आप शिक्षा में देखिये—यह सही है कि शिक्षा इस समाज के लोगों को मिले। ऐसा प्रयास किया गया, वजीफा और किताबें भी दी गयीं। लेकिन मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा—जब सन् 1947 या 1948 से वजीफे दिये जाने शुरू हुए और लड़कों ने पढ़ना शुरू किया, 10—15 साल के बाद उन में बहुत से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद वे एम० बी० बी० एस०, एल० एल० बी० और दूसरी उच्च शिक्षा के लिये जा सकते थे लेकिन धनाभाव के कारण, अर्थाभाव के कारण वे पढ़ नहीं सकते थे। तो इस की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिस से हायर ऐजूकेशन उन को मिल सके। इसलिए मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस को अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए और इन जगहों के लिये उन लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं बहुगुणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वे उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे, तो उन्हों ने इन लोगों के लिए एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये रिजर्वेशन दिया। पहले 3 परसेन्ट रिजर्वेशन था लेकिन उन्होंने पहले इस को 12 परसेन्ट बढ़ाया और उस के बाद 18 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दिया। इसी तरीके से उन्हों ने एल० एल० बी० कोर्स के लिए भी कुछ किया था कि किताबें खरीदने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी थी। मैं वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करना चाहूंगा और करता हूं कि वह भी इस बारे में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएगी और ऐसा रुख अपनाएगी कि इस समाज के अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों और शिक्षित हो कर उन्नति करें। इस के लिये यह सरकार प्रयास करेगी, यह मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों का नाम ले कर प्रत्येक दल, चाहे यह सत्तारूढ़ दल हो चाहे दूसरा कोई दल हो, चाहे मैं हूं और चाहे इस सदन के दूसरे सदस्य हों, और चाहे किसी विधान सभा के सदस्य हों, हर एक व्यक्ति यह कहता है कि शोषित पीड़ित सर्वहारा पर अन्याय हो रहा है और यह कह कर अपनी लम्बी आवाज में बोलता है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम ने इस बात का प्रयास किया कि आखिर इस शोषित, पीड़ित और सर्वहारा वर्ग के लिए, जिस के पास न धन है, न खेत है और न खलिहान है, कोई ठोस या कारगर कदम उठाया जिस से इस वर्ग की उन्नति हो। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बात की छानबीन होनी चाहिए कि कितने परिवार, कितने लोग इन वर्गों के हमारे देश के अन्दर ऐसे हैं जिन के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकारों को इस बात के आदेश दिये जाने चाहियें कि वे इस तरह की छानबीन करें और आश्रम टाइप के स्कूल इन लोगों के लिए चलने चाहियें और उन का पूरा खर्च और व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर आप इन बेसहारा, बेघर शोषित और पीड़ित लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो आप को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

[श्री राम लाल राही]

एक सज्जन ने अभी सवाल किया था कि मिलिट्री सेवाओं में हरिजनों की संख्या नगण्य है। यह बात सही है। मिलिट्री सेवाओं की बात तो आप छोड़ दें। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सैनिक स्कूल भारतवर्ष में हैं उन में हरिजनों की भर्ती नहीं होती है। सारे हिन्दुस्तान में सिर्फ दो सैनिक स्कूल इम्फाल और गोलपारा में ऐसे हैं जहां पर कुछ हरिजन बच्चों की भर्ती होती है बाकी सैनिक स्कूलों में उनकी भर्ती नहीं होती हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि उन स्कूलों में इन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसी शिक्षा हमारे देश में चल रही है, उस तरह की शिक्षा से हरिजन वर्ग के बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं जाने पावेगें। इसलिए शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए। जब तक शिक्षा का स्तर एक सा नहीं होगा, इस समाज के लोग ऐसे स्कूलों में नहीं जा सकेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे कि सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए समुचित प्रतिनिधित्व उन्हें मिले।

भूमि आवंटन के बारे में भी इन रिपोर्टों में सिफारिश की गई है। भूमि आवंटन की तरफ भी इस सरकार को प्रगतिशील रुख अपनाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं, हो सकता है कि इस बात से किसी को तकलीफ हो कि इमर्जेन्सी के पीरियड में जो भूमि आवंटन का आन्दोलन चला था और जो भूमि आवंटित की गई थी चाहे गलत पट्टे हों या सही इस में मैं नहीं जाना चाहता, निश्चित रूप से उस में गरीब लोगों को कुछ भूमि मिली थी और उस पर उन का कब्जा हुआ था। आज वह इमर्जेन्सी समाप्त होने के बाद जनता सरकार आने के बाद उस गति में बिल्कुल धीमापन आ गया है। ऐसा लगता है कि उस दृष्टिकोण में कमी आ गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हरिजनों को जीतना चाहते हैं, उन को अपने साथ रखना चाहते हो, मिलाना चाहते हो तो इस काम में आप को तेजी के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। अन्यथा हरिजन का जो अब तक दृष्टिकोण रहा है, जो विरोधी भावना वह अपनाये रहा है उस को आप दूर नहीं कर पायेंगे। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

यही नहीं, हम को थोड़ा-सा और आगे जाना चाहिए। जिन लोगों को पीछे जमीनें दी गई हैं वे जमीनें ऊसर, बंजर क्षेत्र में जमीनें दी गई हैं। वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं छोटे छोटे काश्तकारों को गांवों से बहुत दूर जमीनें दी गयी है। न वहां सिंचाई के साधन हैं न और साधन है। जो उन्हें दो-चार एकड़ जमीन मिली है उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैदा नहीं कर सकते। उन को प्रायोरिटी के साथ सिंचाई के साधन मुहैया करने चाहियें। जब यह होगा, वहां कुएं खुदेंगे तभी जा कर खेतिहर हरिजनों का उद्धार होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में जो कर्जे बांटे गये थे, जिन्होंने बैंकों से, कोआपरेटिव बैंकों से, तकावी का पैसा ले लिया था उनके बारे में मैं लोकल अखबारों में, प्रांविसियल अखबारों में पढ़ रहा हूं कि उन की जमीनें उन कर्जों को वापस लेने के लिए नीलाम की जा रही हैं। छोटे छोटे और मध्यम दर्जे के काश्तकारों की दो-दो, चार-चार एकड़ जमीनें नीलाम हो रही हैं। क्योंकि वे कर्जा अदा नहीं कर पाये। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीनें नीलाम हो गई हैं उन से जमीन का मूलधन ले कर उन्हें जमीनें वापिस की जायें और जिन लोगों पर कर्जे बाकी हैं उन से ब्याज मुक्त मूलधन ले कर के उनकी जमीन कर्जों से मुक्त की जाए जिस से कि उन्हें अपनी जमीन के मालिकाना हक फिर से हासिल हो सकें; तभी जा कर उन का कल्याण हो सकता है।

हमारे पिछड़े समाज में आवास की समस्या है। यह बड़ी भीषण समस्या है। जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था तब मुझे दक्षिण भारत जाने का अवसर मिला मैंने दक्षिण में केरल, कर्नाटक, आंध्

प्रदेशों में आवास की व्यवस्था को देखा । वहां की राज्य सरकारों ने सराहनीय व्यवस्था की हुई है । किन्तु उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि वहां इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया । उत्तर प्रदेश में गांव के बाहर, बहुत दूर एक छोटी सी जगह में ये भाई रहते हैं जहां कुत्ता और सवार भी रहने को तैयार नहीं हो सकता है । ऐसी छोटी-छोटी जगह इन पिछड़े लोगों के लिये बनाई गयी हैं । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं है, उन के लिए सारे देश में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए और एक समान और एक तरीके से होनी चाहिये । तभी जा कर के हम इन पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम कर पायेंगे अन्यथा नहीं ।

आम हरिजनों की बात तो दूर रही, जो सब से पिछड़े हरिजन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें हम बाल्मीकी कहते हैं, मेहतर कहते हैं, उन की हालत देख लीजिये । वे सार्वजनिक शौचालय की दीवार के साथ छप्पर या टीन डाल कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं । पचासों जगह मैं ने ऐसा देखा है । तीस साल की आजादी के बाद भी अगर समाज का यह अंग जो हमारे सभ्य परिवारों की सफाई करता है, उन के मकान स्वच्छ करने में जुटा हो, उन्हें रोग मुक्त करने में जुटा हो ऐसे समाज के लोगों को हम ऐसी जगह पर डालें जहां पर बीमारी फैल सकती है, रोग फैल सकते हैं, जिस जगह से हम घृणा और द्वेष रखते हैं तो यह सर्वथा अनुचित है । इस की तरफ भी आप को ध्यान देना होगा । उन्हें शौचालय के पास छप्पर और टटिया लगा कर रहने की हम इजाजत देंगे तो इस को किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकेगा । आप ऐसी नीति बनायें ताकि सफाई कर्मचारियों को सार्वजनिक शौचालयों के नजदीक न रखा जा सके । अगर यह कदम उठाया गया तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा काम एक किया गया है ।

बंधक प्रथा खत्म हो गई है देश में । लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आज भी देश में जबरिया काम विभिन्न प्रान्तों में हरिजनों से लिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि शासन की मशीनरी चुस्त हो और ईमानदारी और निष्ठा के साथ वह काम करे और इस तरह की चीज को होने न दे और अगर होती है तो उस को समाप्त करे, कड़ाई से पग उठा कर इसका मुकाबला करे । नहीं तो आप के पास हरिजनों के साथ अत्याचार होने की घटनायें आती ही रहेंगी । कहीं पर बेलची कांड जैसा कांड होता ही रहेगा, हरिजन औरतों के साथ बलात्कार की घटनायें होती ही रहेंगी । मेरे पास कितनी ही कैटेगरीज की इस प्रकार की घटनायें रखी हुई है । जिन में हरिजनों के साथ अत्याचार और अन्याय, बलात्कार आदि की वारदातें हुई हैं । अगर आपने इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अखबारों में इन का उल्लेख आता ही रहेगा और तब आप हम लोगों को भले ही बोलने न दें । लेकिन सामाजिक वातावरण दूषित होगा । मैं चाहता हूं कि ऐसे जालिम लोगों के साथ सख्ती बरती जानी चाहिये । ऐसा नहीं किया गया तो न हम बच पायेंगे और न ही आप बच पायेंगे । दोनों की बदनामी होगी । अगर समाज के कमजोर और दुर्बल वर्ग इसी तरह से दुखित और त्रस्त रहे और आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए तो, कांग्रेस तो चली गई है और हम भी नहीं बच पायेंगे । कोई भी बच नहीं सकेगा । फिर क्या होगा कोई भी भविष्य-वाणी नहीं कर सकता है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इंसान की, मनुष्य की, श्रमजीवी की, सर्वहारा की कराह—अगर कराह ईमानदारी और निष्ठा की है—निश्चित रूप से सारे देश को भस्मासात करे देगी । तब कोई बच नहीं पाएगा । इसलिए आवश्यकत

[श्री राम लाल राही]

इस बात की है कि समय रहते आप चेतें, जो नारा आप देते हैं—गरीबों की रक्षा का, शोषणमुक्त समाज बनाने का, समाजवाद लाने का, उस नारे को आप साकार करें। हमको पिछड़े हुए वर्ग को राहत देनी पड़ेगी। हमारे बहुगुणा जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब उन्हों ने हरिजनों के लिए एक वित्त निगम बना दिया था और जो परम्परा सूअर पालने, मुर्गी पालने, बकरी पालने की थी उस को समाप्त कर के उन्होंने इस समाज के लोगों को भी समान स्तर पर लाने की कोशिश की थी, यह किया था कि ये लोग भी कोई भी उद्योग धंधा या व्यवसाय कर सकते हैं। और वित्त निगम से आज उन को सहायता और मदद इसके लिए मिलती है। मैं उन्हें आज इस सदन में इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना उन्हों ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में हरिजनों के लिए वहां किया शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा हो जिस ने उस से अधिक किया हो या कर सके।

हमारे यहां हायर सर्विसिस की प्रतियोगिताओं में जाने के लिए इन के आयोजित होने से पहले ट्रेनिंग देने के लिए लखनऊ में एक सेन्टर बनाया गया था। उस सेंटर को डेढ़ दो साल काम करते हो गये हैं। वहां के कर्मचारियों को पता नहीं तनख्वाह भी मिल पाई है। या नहीं, यह जो स्थिति एक प्रदेश में है हो सकता है कि इसी प्रकार की स्थिति दूसरे प्रदेशों की भी हो। मैं चाहता हूं कि ये जो सेंटर चालू किए गए हैं ये केवल दिखावामात्र न रहें। इस समाज के लोगों के दिलों को जीतने के लिये अगर उन्हों ने दिखावे का रूप धारण कर लिया तो निश्चित रूप से आदमी की बुद्धि में जो परिवर्तन इन तीन सालों में आया है, वह कुछ सोचने समझने लग गया है, आप याद रखें कि वह अब दिखावे में आने वाला नहीं है। जो आप कहते हैं उसे आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इन पिछड़े हुए लोगों, सर्वहारा, शोषित, पीड़ित लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Chairman, Sir, we have been listening with great interest and with a sense of distress to the speeches made by Members from both sides of the House on the conditions of Harijans, in this country. Yet full facts have not been given in the reports presented to the House by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They do not contain the events which have taken place after the Janata Party has taken over. One of the very senior Cabinet Ministers said recently in Chandigarh that the conditions of the Harijans have become worse after the Janata Party took over. Only a few members have dwelt on the atrocities committed on Harijans who have converted themselves from Hinduism to Islam, Buddhism and Christianity. I want to make it clear and to put it as vehemently as possible, that by conversion, their condition has not improved either socially or economically. There is no reason whatsoever as to why there should be discrimination against these people who are Harijans among the Harijans, the most oppressed among the oppressed. Even the Hindu Harijans do not look at them with kindness. They look down up these converts from Hinduism. The main argument to deny them the privileges of Scheduled Castes is that neither the Christian nor the Muslim nor the Buddhist religion recognises the caste system and hence the question of any of these classes of converts being included among the Scheduled castes does not arise.

The first thing I would like to say is that it is a quite a debatable point as to whether the Hindu religion itself recognises the caste system. It has been said by many authorities

that the concept of caste is not inherent in the Hindu religion. The caste system is said to be a phenomenon. There cannot be any doubt that there is no caste system recognised by Sikh religion. Yet though the Sikh religion does not recognise the caste system, the weaker sections of the Sikhs are being protected as Scheduled Castes. The neo-buddhists who are the most progressive and most dynamic segment of the Harijans and they converted themselves to buddhism after the death of their mentor, Dr. Ambedkar. At that time, in 1957 or so, they were derecognised from the Scheduled Castes and all the privileges were withdrawn.

I should like to say that we are living in a country which is basically and genuinely a secular State. Though 80 per cent of our population consists of Hindus we have a Constitution with a truly liberal attitude towards all the religions. Yet, this discrimination on the basis of religion when it comes to Scheduled Castes is a great blot on the prevasive secular spirit and tenor of our Constitution, and of our Society as a whole.

Sir, there is no reason whatsoever why the neo-Buddhists should not be granted the privileges which are available to the other members of the Scheduled Castes. This is discrimination, I will say it again and again. This is a discrimination on the basis of religion. This is a diserimination, I will say it again with my limited knowledge of law, contravenes Article 15. Apart from law, I should say this is against the seculer spirit of the nation to which we all equally belong.

The neo-Buddhists had to wage a very long and grim struggle to get some benefits in their home State of Maharashtra. These benefits had been snatched away from them by the then Maharashtra Government when its then Chief Minister was the one whom we are fortunate to have as our Prime Minister today. They waged a very great struggle and ultimately they had succeeded in getting all the benefits that the Maharashtra Government could give them and now they are recognised as a backward class and all the benefits available to backward classes are availaable to neo-Buddhists in Maharashtra.

Now the problem concerning neo-Buddhists is in the hands of the Central Government. There are substantial privileges in the matter of reservation of jobs available to Scheduled Caste. Thirty-four per cent of the Government jobs are reserved for Scheduled Castes and the neo-Buddhists deserve a quota in these jobs. In other words, the entry into this quota must be available to them. A couple of months ago a letter was written by the veteran Buddhist leader from Maharashtra, Mr. Rajbhoj to the hon. Prime Minister demanding that the facilities which are available to Scheduled Castes should be available to neo-Buddhists also. The Prime Minister very promptly passed on that letter to the Home Minister and the matter is now pending with the Home Ministry.

The other day we saw some young men in the public gallery of Lok Sabha shouting some slogans; such acts cannot be justified, but then putting them in jail is not going to solve any problem. We have to look at the cause and the cause is deep frustration. It is utter frustration and utter despair and this despair is manifested in whatever neo-Buddhists are doing today. If they do not succeed by persuation, they will believe that only with force and violence they can succeed. What I say about neo-Buddhists is on the basis of a principle, the principle that there should never be discrimination on the basis of religion. And then I must submit that these benefits must be extended also to the weaker sections of the Muslim community and the Christian community.

SHRI L. K. DOLEY (Lakhimpur): qually to Buddhists also?

SHRI EDUARDO FALEIRO: First nd foremost to the Buddhists and hen to the other communities. Neither the Muslim religion nor Christianity believe in caste but religious belief is one thing and practice is another. Among Muslims there are some sections which are said to be superior castes and there are other sections which constitute the so-called inferior castes. In Muslim community, Sheikhs, Pathans, Mughals and Syeds are some of them higher castes and they do not have any social intercourse with the so-called lower castes. This is the actual position. About Christianity no one can say anything better than I because I belong to that community. In Goa, Christians are the converts from Hinduism and Muslim religion. We have changed the religion but we are Indian Christians. In Goa, there are so called Brahmin Christians, Kshatriya Christians and Sudra Christians. This may appear to be funny to you, but it is true. Brahmin Christian is a contradiction in terms, but it is a social reality in Goa, Mangalore and other places. The divisive forces of caste here in these areas are stronger than the divisive force of religion.

Even in the temples of God, *viz.*, churches, till very recently separate seats were being kept for the so-called caste Christians and the so-called Harijan Christians in South India. In South India, the caste differences among Christians are as deep and as strong as they are in the Hindu society. Several leaders of the Christian community have represented this position to the Government. The matter is pending with the Government and it is for them to take a decision as early as possible.

The whole House should express its appreciation for the recent gesture of the Chief Minister of Tamil Nadu. He has promised to extend all the privileges available to the Hindu Harijans to the Christian Harijans also. This will benefit 11 lakhs of people in that State. This step must be followed by the Central Government also. We are not doing any favour to the weaker sections by making reservations. They are their right. Those people were deprived of them for hundreds of years. When doing this don't discriminate on the basis of religion. The argument sometimes adduced is that foreign missionaries are helping the Harijan Christians, and as such they do not require any help. It is said that foreign money is coming to help them. It is not coming. As far as the Portuguese were concerned, they could not help their own people. They could only take things from Goa, but not bring in anything to give to the Goanese.

My plea is this: if you wish to maintain the secular character of the country—which has always been there as a shining example to the entire world —all the benefits available to the Hindu Harijan should be extended first and foremost to the neo-Buddhists who are recent converts, and who have converted on a matter of principle and also to the Harijans professing other religions. Government seems to be paying lip service to the principle of abolition of the caste system. But the present system is putting a premium on the maintenance of the caste system itself. If a person is a Hindu Harijan he will get all the benefits; but if he converts to Christianity or Neo-Buddhism, all the benefits are withdrawn immediately. By such acts you punish those who want to abolish caste and get away from it. I once again appeal to the conscience of this House to extend all the benefits available to the Scheduled Caste to the neo-Buddhists before their struggle became a violent one as well as to

the weaker sections of other religious groups.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, when I am participating in the debate today, I have a feeling of great distress and sorrow, because of the fact that during these last 30 years of independence, whether this party is in power or the other party is in power, we have not been able to do much in terms of concrete measures for removing this black spot from our country. What we have been doing for the last thirty years is a kind of patch work. We did not go down to the deep malady, the deep root of the problem. Unless we tackle the problem at its roots, I am afraid this patch work will not go on for ever, it will not last at all.

The short of indifference to this problem is in a way reflected in the kind of debate that is taking place. Look at the motion moved by the Railway Minister. It talks about the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970-71, 1971-72, 1972-73 and 1973-74. In 1977 we are discussing the reports of the Commissioner which are five years old. Of course, the credit must go to the Janata Government that they have at least brought up for discussion these reports in 1977. For the last four or five years this Parliament, unfortunately, had no time to discuss some of these basic issues connected with India's social, economic and political maladies and we seemed to be discussing all kinds of short-lived issues, issues which have no relevance for the present day. This is the tragedy of the situation, and it is aggravated further that this discussion is taking place after four or five years. It is also truncated, partly last session and partly this session.

SHRI L. K. DOLEY (Lakhimpur): On a point of clarification. This is a question which is facing us not for 30 years but for the last 300 years or more.

PROF. P. G. MAVALANKAR: My hon. friend is taking of 300 years. I can go back to 3,000 years, because I am also a student of history. But that is not relevant. What is relevant is, after we became independent as one nation, what have we done to remove the cast barriers? As I was telling you, I want to go to the root of the problem and try and see how to tackle the problem effectively and in time. From that point of view, I want to address myself to some of the very fundamental points in the limited time at my disposal.

First of all, let us take note of the spate of atrocities on harijans during the last seven or eight years, which is something unprecedented. Anybody would be ashamed of the fact that there is a continuous phenomena of first class citizenship, second class citizenship and so on. What is more, even among the second class, there are some who feel that some others should be in the third class, and in the third class some feel that some others should be in the fourth class. They have got this idea of keeping somebody else below them so that if somebody above them exploits them, they can have their revenge on somebody below. It really affects us all. It is a national problem which has to be solved from a national angle.

Apart from the atrocities, look at the dismal conditions of the harijans, girijans and the backward classes. In this great and ancient country of India there are millions of people who do not belong to either Scheduled Castes or Scheduled Tribes but who are still backward. They are called by the name "Other Backward Classes". If you total up the Scheduled Castes, Tribes and Other Backward Classes, it will come to a sizable number and I wonder what remains of India! They are in a very backward and dismal condition. They know only of disease, hunger, squalor, illness and death. It is a living hell! The tragedy is that this living hell is something which we are tolerating, because for the last 30 years we have

(Prof. P. G. Mavalankar.)

become almost insensitive to what is happening around us.

We do not want to take any bold and conerete steps. In a large number of villages Harijans cannot have their buckets filled with water, if buckets they have, because they cannot go to the same well and take water out of it.

After this rather long and distressing backgrond and preface. I want to say that the Janata Government must now take courage in both hands and adopt certain bold and innovative policies and take certain urgent steps on the basis of such policies. It is no use making patchwork provisions of reservations etc. That, of course, is good up to a point, but not beyond that. Even the scheduled castes and scheduled tribes who get certain advantages out of this reservation, after having got it, tend to forget that others of the same classes, their own brothers and sisters, have been denied all these privileges. Therefore, let us not create another new class of reservationist scheduled castes, reservationist scheduled tribes etc. What we want is a general kind of equality, equality of opportunity for all.

What can we do to achieve it? Of course, the Scheduled Castes Commissioner is there, but if I may suggest, Government must think of appointing a special commission of knowledgable and seasoned people belonging not only to the Harijan community but to all sections, to go into the whole problem and make recommendations to the Government in terms of concrete proposals as to what should be done for removal of these maladies and agonies at their very root. If that is done, I am sure we shall be taking a great stride.

I also want to give a warning which is coming not only from awakened caste Hindus—who are unfortunately very few, who believe in a casteless if not a classless society and equality —but from the fully or partially awakened scheduled castes and scheduled tribes who are now getting more and more literate, more and more educated. They are not going to keep quiet now. The new youth among the Harijans and Girijans are now giving us a red signal, and if we do not pay heed to this the Dalit panthers and others will cease to have faith in the parliamentary and democratic institutions and will begin to believe that perhaps not through democratic means but through others means only a revolution can take place. It is for us, therefore, to see that that kind of frustration and lack of faith in our existing political institutions to create a revolution of a fundamental type, what Shri Jaya Prakash Narayan calls total revolution, does not grow. We should do this if we want to win the confidence of all the scheduled castes and scheduled tribes and the socially and politically oppressed and depressed people of this vast country, India's teeming millions about whom Dr. Bool Chand had written a book quite a long times back, and who are increasing in numbers every day. The tragedy of the situation is that these teeming millions are living below the poverty line. Therefore, the administration—here comes the Home Minister and his colleagues—at the Central level must give an object lesson to all the State Governments in the country.

One difficulty is that the officials—the Home Minister may note this—including bureaucrats and police at various levels are caste Hindus and when it comes to implementing Government decisions their own prejudices and angles are brought in, and even though Government at the policy level wants to do certain things, they refuse to implement the orders.

It is here that the administration must become stern and must see to it that the officials and the police implement these orders as effectively and honesty as possible.

One finds increasingly certain bullying and aggressive tactics of the caste Hindus, particularly in the rural areas. In urban areas, comparatively, the position is slightly better.

But in Rural India the caste Hindus, wherever they are, have adopted tactics of bullying and tactics of aggression. That is why, you have this spate of atrocities.

Then, coming to law and order problem, let us not forget that this is also an economic problem, an educational problem, a social welfare problem, a culture development problem. In fact, it is a multi-faceted problem, and so this has to be tackled from all these angles.

Coming to the question of reservations, the purpose and practice of reservations have been to a large extent, fulfilled. The purpose and practice of reservations were laid down in the Constitution by no less a person than Dr. Babasaheb Ambedkar and no less a person than Pandit Jawaharlal Nehru. I do not think Dr. Ambedkar laid it because he was a Harijan. They were doing this job because they were guided by the spirit and message of Mahatma Gandhi; they were guided by the practices and precepts of Mahatma Gandhi: What are the practices and precepts? These practices and precepts are: All men are our brothers. If that is so, then some of our brothers who are backward and behind, they must be given weightage—weightage in admissions in universities and colleges, weightage in employment. But wherever there are technical jobs of expertise, please do not relax reservations for Harijans and Girijans on that basis because that involves inefficiency, insecurity, damage to life and property also. If Harijans and Girijans are not coming up to the level of technical education, give them additional facilities to get such education. That is why, I am saying that this is a problem of education.

About this whole matter, I can also look at it from another angle, namely that this problem is a problem of arrogance on one side, ignorance on the other and prejudice in between! On one side, there is the arrogance of those who are in power—social, economic, political, financial and monetary power—and on the other there is the ignorance of vast teeming, millions who do not know what their rights are. Therefore, we have to tackle this problem from the point of view of eliminating arrogance, removing ignorance and trying to get rid of prejudices through persuasion.

Our friends and fellow-countrymen, who are Harijan and Girijans, must also take courage in their hands through education and see to it that they do not have inferiority complex. I do not want them to become violent. I want my friends my brothers and sisters of SC & STs, to become intellectually militant, not violently militant. I want certainly this intellectual militency on the part of these people to assert their rights and once that is done, the public opinion will be created and when this public opinion is created, such a conscious and cultivated public opinion will see to it that these matters are effectively dealt with.

Let us, in conclusion, touch a few other important aspects of the matter. Acute economic conditions of SC & ST have to be looked into and have to be removed. Therefore, the whole problem of reservations employment, conditions of Harijans and Girigans, has to be looked into and tackled with education and economic welfare measures. The Home Minister here must take advantage and assistance of his colleagues the Minister of Finance and the Minister of Education. The Minister of Finance must never say 'no' so that we have enough funds for the betterment of these people. They must pour in lots and lots of funds purposefully and meaningfully in the next couple of years, may be in the next couple of decades. Only then we can solve this massive problem.

The Government's role in todays India is undoubtedly, positive, assertive and massive. But if Government's role is massive, positive and assertive, no less positive, assertive and massive is the role of voluntary agencies doing the work in political,

[Prof. P. G. Mavalankar]

social, cultural, educational and other matters, and fields and no less important is the role of an enlightened individual who will go on striving for social reforms. Where are today men like Dhondo Keshav Karve? Where are the Jyotiba Phules? Where are the Dadabhai Naurojis? Where are the Tilaks and Gokhales? Where are the people who will look into the welfare of Harijans and Girijans?

The trouble is that we look at the problem only from a short-lived angle of getting votes. You may get the votes of Harijans. But by getting the votes of Harijans, you do not necessarily bring about their welfare. The welfare of Harijans and Girijans is much more important. Some of us must have the courage to look beyond shortterm purpose and have a long-term policy. If we do that, then we can have social reforms—I may say in Hindi, *roti beti* and *vyavahar*. We must encourage people to have inter-caste marriage, inter-provincial marriages and inter-religion marriages. When that happens, this country will have a certain new Indianness. When the people go to America from all parts of the world, they begin as Norwegians, Swedish, Chinese, Tibetans and so on and, after they go there, they forget that they are Norwegians or Swedish or Chinese or Tibetans. They are all Americans. The same thing is with Russia, Britain and other big countries Why can't we have the same thing in India? No matter from which part of India the people come, from which caste or religion they come, they are, first and last, Indians. That can happen only with education and persuasion. That must be the role of awakened individuals and enlightened souls.

With these words, I ought to say that it is not sufficient that this matter could be discussed in one debate nor can it be adequately discussed in one debate. It is an important and fundamental matter. Let us go to the root of the problem. Let us begin effectively, purposefully, sincerely and earnestly. If we do that, I am quite sure posterity will have no chance to say that we have failed in our mission today.

श्री लखन लाल कपूर (पूर्णिया) : सभापति महोदय शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्टों पर हम चर्चा कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस तरह की चर्चा इस सदन में सैंकड़ों बार हो चुकी होगी और एक रस्म अदायगी के तौर पर यहां पर बहस हो जाती है और फिर इन रिपोर्टों की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश नहीं की जाती और वे एक तरह से कोल्ड स्टोलेरेज में डाल दी जाती हैं ।

आज हम इस कमीशन की बीसवीं, इक्कीसवीं और बाइसवीं रिपोर्टों पर बहस कर रहे हैं । ये 71–72, 72–73 और 73–74 की रिपोर्टें हैं । इसी से पता चलता है कि 71 से 77 तक इन छः वर्षों तक हमें इन पर चर्चा करने तक का कष्ट नहीं उठा पाये । इसलिए यह मान कर चलना पड़ता है कि समाज के जिन अंगों के विषय मे यह सदन चर्चा कर रहा है, उन को काफी महत्व नहीं दिया जा रहा है । अगर महत्व दिया जाता तो जब से यह कमीशन बहाल हुआ, तब से 1954 से चार हजार से ऊपर रिकमण्डेशंस आयी हैं उन में से कितनी पर सरकार ने अमल किया, यह हम सरकार से जानना चाहेंगे । जिन के विषय में कमिश्नर ने सिफारिशें कीं, हिदायतें दीं समाज के उन दबे हुए अंगों को सरकार ने कितनी सहायता दी ? 15 अगस्त, 1947 को हम आजाद हुए, भारत की जनता हजारों बरसों की गुलामी के बाद आजाद हुई । हम यह मान कर चल रहे थे कि हम सब आजाद शहरी हैं, आजाद इंसान की तरह भारत में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार हमारे लिए जीने की व्यवस्था होगी, अमन चैन से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सब को

समान अवसर मिलेंगे और समानता के आधार पर समारी समाज की रचना होगी। लेकिन इस बात को पिछली सरकार ने मानने से इंकार किया है कि भारत में भारतीय समाज के कई ऐसे अंग है जो अब भी परतन्त्र हैं या गुलाम हैं। विदेशी लोगों ने बार बार इस चीज को कहा है कि आप के यहां अभी भी गुलामी की प्रथा चल रही है लेकिन सरकार ने बार बार इस से इन्कार किया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट में जब यह बात आई कि भारत में एक दो नहीं लाखों लोग बंधुआ मजदूरों के नाम से गुलाम हैं तब जा कर भारत सरकार ने इस को स्वीकार किया। कितनी लज्जा की बात है। तीस बरस हो गये हैं, एक पूरी पीढ़ी ने अपनी जिन्दगी गुलामी में व्यतीत कर दी है, वह पीढ़ी समाप्त हो गई है लेकिन वे गुलाम आजाद मुल्क में भी गुलाम रह कर ही मरे। इमरजेंसी के दौरान में इसी सदन में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया था जिस में उन को मुक्त कराने की व्यवस्था की गई। जो वस्तुस्थिति है उस की तरफ हम को ध्यान देना पड़ेगा। जो हालत आज भी विद्यमान है उस के कारण हमारे देश में शान्ति और व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है और केवल शान्ति व्यवस्था ही नहीं बल्कि जिस लोकतन्त्र के लिए हमने अपनी जद्दोजहद की है, लोगों ने फांसी के तख्तों को चूमा है, जेल की चार दीवारी में अपनी जवानियों को जलाया है, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वह लोकतन्त्र भी आज खतरे में है। कब तक यह स्थिति चलती रहने दी जा सकती है ?

आज देखें कि शोषित, पीड़ित और दलितों अर्थात् हरिजन आदिवासी की संख्या 25 प्रतिशत है। एक चौथाई ही नहीं बल्कि काका कालेलकर साहब ने अपनी रिपोर्ट में चार हजार जातियों का वर्णन किया है, उनके जीवन का वर्णन किया है और बताया है कि उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर हरिजनों और आदिवासियों से भी बदतर है। 1953 और 1955 में बैकवर्ड क्लास कमिशन रिपोर्ट में जो रिपोर्ट उन्होंने दी और जो सदन में भी पेश हुई, उसकी सिफारिशों पर आज तक अमल नहीं किया गया, एक भी मुद्दे पर अमल नहीं हुआ। मैं समझता हू कि भारत में नब्बे प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है और जानवरों की तरह रह रहे हैं। मुट्ठी भर लोग जो सुविधा प्राप्त लोग हैं उनके चरणों के नीचे वे दबे हुए हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, और मैं समझता हूं कि एक भंयकर बगावत की चिंगारी पैदा हो रही है, उनकी आत्मा आज चीख रही है, पुकार रही है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता गरीबी तथा अज्ञानता जैसी कुरीतियों के प्रति, जिस जनता का एक—बहुत बड़ा भाग—प्रभावित है, सामाजिक चेतना तभी उत्पन्न की जा सकती है जबकि बड़े पैमाने पर लोग स्वेच्छा से इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। जब तक हमारे समाज में गरीब और पददलित लोगों के प्रति अमानवीय भेदभाव मौजूद है तब तक भावात्मक एकता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के लिये किये जा रहे हमारे सभी प्रयत्न बेकार साबित होंगे।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में हमने क्या किया ? जिस अवस्था को देख कर महात्मा गांधी ने कहा था आज 30 वर्ष बाद भी वही अवस्था मौजूद है। क्या यह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है ? आज उससे बदतर हालत हमारे यहां है। आये दिन लोगों को जिन्दा जलाया जा रहा है घर में घुसकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, हरिजनों को, पिछड़ी जाति के लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। और उस के ऊपर एक छोटा कमीशन बहाल हो जाता है

[श्री लखन लाल कपूर]

जिसकी रिपोर्ट आ जाती है जो दफ्तरों की अलमारियों में बन्द कर दी जाती है ।

आज मैं सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आज जो भयंकर स्थिति है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है इसके खिलाफ़ बगावत की तैयारी करें । वह चाहे शांतपूर्ण ढंग से हो या अहिंसात्मक ढंग से हो । हम चाहेंगे शांतमय हो । लेकिन अगर इसी तरह रोके जाने का अधिकार छिन जाता रहा तो पता नहीं क्या रूप लेगा । इसलिये बाबा साहब अम्बेदकार ने कहा था :

"हम 26 जनवरी, 1950 को एक ऐसे जीवन में पदार्पण करने जा रहे हैं जो अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है । राजनीति की बुद्धि से हम में समानता होगी, किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता के शिकार होंगे ।" और शिकार हैं । "राजनीति में हम एक आदमी के लिये एक वोट और एक वोट के मूल्य का सिद्धान्त अपनायेंगे, किन्तु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की, हम अपने सामाजिक और आर्थिक ठांचे की वजह से हर आदमी एक ही मूल्य के सिद्धान्त से वंचित रहेंगे।" और हम वंचित हैं । "हम कब तक अन्तर्विरोधों का यह जीवन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से वंचित रहेंगे ? यदि हम बहुत दिन तक इन से वंचित रहेंगे तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल कर ही ऐसा करेंगे । हमें इस अन्तर्विरोधों को यथाशीघ्र दूर करना चाहिये, अन्यथा असमानता के पंजे में जकड़े लोग इस राजनीतिक ठांचे को चकनाचूर कर देंगे जिसे इस विधान सभा ने बड़े प्रयत्न से खड़ा किया था ।"

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेलची कांड हो गया, और भी दूसरे कांड हुए हैं । लेकिन ज्यों ज्यों दवा की जा रही है मर्ज बढ़ता ही जा रहा है । इसके पीछे कारण क्या है ? जो आये दिन हत्यायें हो रही हैं, दंगे हो रहे है, इसके पीछे कारण क्या हैं ? आज ला ऐंड आर्डर कमजोर क्यों पड़ रहा हैं ? महसूस करना पड़ेगा कि उन में आज चेतना आ रही है । जो दबा हुआ तबका है उसमें चेतना आयी है अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिये । और जो तत्व उसका शोषण कर रहा है, जिनकी कमाई पर वह गुलछर्रे उड़ा रहे हैं उनके सामने यह खतरा है । इसलिये वह चेतन्य हो कर और सामूहिक तौर से उन्हें दबाना चाहते हैं, और लाठियों और गोलियों के बल पर दबा देना चाहते हैं । नहीं तो यह घटनायें क्यों होतीं ? 10 अक्तूबर को भोजपुर जिले के धरमपुरा में एक घटना हुई । जब कोई बात होती है तो पुलिस की रिपोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में या कमीशन की रिपोर्ट में एक ही तरह की बात लिखी जाती है क्योंकि वह लोग जिनके हाथ में शासन की बागडोर रही है, बराबर राजनीतिक अधिकार रहा है वही लोग इन रिपोर्टों को लिखते हैं, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि यह गुंडे हैं, ये चोर, डकैत और क्रिमिनल हैं, और ऐसा कह कर सारी बातों को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है । वहां पर एक महंत की जमीन पर एक हरिजन पट्टादारी कर रहा था, जिस को वह बदखल करना चाहते थे । उस हरिजन ने सरकार को प्रार्थनापत्र दिया कि हम अपने बाप-दादा के समय से इस जमीन को जोत रहे हैं, इस लिए यह जमीन हमारे नाम पर लिख दी जाय । लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह झगड़ा बढ़ता रहा । एक दिन अधिकारियों और पुलिस की कनाइवेंस से समहंत महोदय गुस्से में उठे और अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए रास्ते या मैदान में नहीं, बल्कि जिस झोंपड़ी में वह हरिजन रहता था, उस में घुस कर

गोलियों से पांच आदमियों को धराशायी कर दिया। जब इस के विरुद्ध आरा शहर में जलूस निकाला गया, तो पुलिस ने उस जलूस को भंग कर दिया, लाउडस्पीकर छीन लिया, लोगों को लाठियों से पीटा और गिरफ्तार किया।

धरमपुरा में दो तीन दिन बाद बेगूसराय जिले के मटिहानी गांव में एक हरिजन को मार कर जला दिया गया। यह समाचार अखबारों में छपा है और सरकार के पास इस की रिपोर्ट आई है।

इसी तरह भोजपुर जिले के सहारखंड में एक मजदूर को मार दिया गया। 6 नवम्बर, 1977 को भागलपुर जिले में पीरपैंती के निकट गौरीपुर गांव में एक संथाल को, जो बरसों से जमीन जोत रहा था, उस जमीन से बेदखल करने के लिए जमीन-मालिक ने गोली से मार दिया--उसी खेत में मार दिया, जिसे वह जोतता था, और उसकी लाश को खींच कर अपने खेत में ले आया। पुलिस खड़ी यह सब कुछ देखती रही, और अब भी वह उस का साथ दे रही है।

गृह राज्य मंत्री को इन घटनाओं के तथ्यों का पता लगाना चाहिए। बिहार के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर, और संसद-सदस्य, श्री रामानन्द तिवारी, ने इस सम्बन्ध में बयान दिया है।

जनता पार्टी की सरकार को यह सोचना होगा कि यह सामाजिक तनाव और आर्थिक शोषण बुनियादी तौर से कैसे खत्म होगा। पिछले तीस वर्षों में यही होता रहा है कि संसद ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। अब इस की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

17.05 hrs.

ये झगड़े क्यों होते है? इस के चार कारण है। जब तक इन चार कारणों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक न तो शान्ति और व्यवस्था कायम होने वाली है और न ही ग़रीबों को निजात मिलने वाली है। ये सब झगड़े ज़मीन को ले कर होते है। यह एक आर्थिक संघर्ष है, जिसे क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष कह सकते हैं। हमारे देश में वर्गों का अस्तित्व इस लिए है कि सम्पत्ति के बंटवारे में असमानता तथा विषमता हैं। यहां 90 फ़ीसदी लोग धनहीन है और 10 फ़ीसदी लोग धनपति है। जो आदमी कुंआं खोदता है, वह प्यासा क्यों है? जो आदमी जमीन जोतता है, अनाज उत्पन्न करता है वह भूखा क्यों है? जो आदमी जमीन जोतता है वह भूमिहीन और जो जमीन नहीं जोतता है वह भूमिपति। जो कपास उगाता है, कपड़े बनाता है वह तो नंगा रहता है और जो यह सब कुछ नहीं करता उस की अलमारियों में रेशम के कपड़े पड़े सड़ते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें जो मजदूर बनाते हैं, जो सिर पर ईंट, चूना, गारा, पत्थर ढो ढो कर ले जाते है वे तो रहते हैं दरख्त के नीचे अपने बाल बच्चों के साथ और ये बड़े बड़े लोग इन एयर कंडीशंड मकानों में, शीश महलों में रहने है। यह जंगली व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि बटाई दारी का कानून आप को बनाना पड़ेगा। अगर वह कानून बना है तो उस को लागू करना पड़ेगा। बटायीदारी का कानून लागू किया जाय। मुश्तैदी के साथ लैंड टु दि टिलर, अर्थात जो जमीन को जोतने वाला है उस को उस जमीन का मालिक बनाया जाय। इस के लिए आप को कदम उठाना पड़ेगा।

दूसरी बात--मजदूरी के लिए झगड़े होते हैं। आप ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाया है। उस के हिसाब से मिनिमम वेजेज उन को नहीं मिलते है। इसलिए मजदूरी के लि

[श्री लखन लाल कपूर]

झगड़े होते हैं जिस से गोलियां चलती हैं और घरों को आग लगायी जाती है । तीसरा कारण है बास गीत भूमि की और एक यह बड़े अफसोस की बात है कि पौने छः लाख गांवों में पौने दो लाख गांव ऐसे है जहां पीने का पानी भी नहीं मिलता हैं । यह शर्म की बात है । पांच पंचवर्षीय योजनाएं हमारे यहां चलीं । 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए और ये बेचारे जो रात दिन मेहनत करते हैं, दुनिया को बनाते, सजाते और खिलाते है उन के लिए एक गिलास शुद्ध पीने के पानी का हम इंतजाम नहीं कर सके । यह लानत है भारत के समाज पर ।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि होम स्टेड लैंड के ऐक्ट को मुश्तैदी के साथ लागू करना पड़ेगा । इन को घर बना कर देना पड़ेगा । होम स्टेड लैंड देना पड़ेगा ।

पांचवीं बात टेनेंसी ऐक्ट की है । यह जीर्ण शीर्ण टेनेंसी ऐक्ट अंग्रेजों के वक्त का चला आ रहा है । उस टेनेंसी ऐक्ट के पन्नों को फाड़ कर फंकना पड़ेगा, नयी व्यवस्था करनी पड़ेगी । अगर नयी व्यवस्था कायम करनी है, सामाजिक तनाव दूर करना है, आर्थिक विषमता को मिटाना है, उन को राजनैतिक अधिकार देना है तो टेनेंसी ऐक्ट में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा ।

इसी तरह से पुलिस और मजिस्ट्रेसी में कौन है ? उसी शोषक वर्ग से लोग उस में आते हैं । प्रधान मंत्री से ले कर नीचे के वी डी ओ तक कौन है ? उन्हीं दस प्रतिशत लोगों में से है । आज तक इन लोगों को मौका नहीं मिला है पालिसी मेकिंग बाडी से आने का । पालिसी मेकिंग बाडी में कौन है ? वही है जो शोषण करते है, शोषक है । आप इन को जब तक पालिसी मेकिंग बाडी में शामिल नहीं करेंगे तब तक इन के जीवन में परीवर्तन नहीं होने वाला है ।

इसी तरह जो सी आर पी सी और आइपीसी के एविडेंस ऐक्ट है वे बहुत पुराने हैं । आज इन के मातहत उन बेचारों पर जो अपना हक मांगते है तरह तरह के मुकदमे कर दिए जाते हैं । दो चार मुकदमों में जाते जाते इन का दम टूट जाता है । इन को क्रिमिनल डकैत और पाकेटमार करार देते है । इसलिए आज एविडेंस ऐक्ट में, और सी आर पी सी तथा आई पी सी में परिवर्तन करना पड़ेगा । वर्तमान एविडेंस ऐक्ट में क्या हैं जिसके जिस आदमी की हत्या कर दी जाती है उसे ही सबूत पेश करना पड़ता है? वह अपने बचाव के लिए गवाही नहीं देगा बल्कि जिसकी हत्या की है उस को पेश करना पड़ता हो कि उस की हत्या हुई है । बेनीफिट आफ डाउट भी हत्यारे को ही दिया जाता है । यह कैसी बात हुई ? इसलिए इस में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा । सी आर पी सी और आइ पी सी में परिवर्तन करना पड़ेगा और लोगों को उन का सही सही जीने का अधिकार देना पड़ेगा ।

17.05 hrs.

[SHRI D:RINDRANATH BASU *in the Chair*]

श्री मही लाल (बिजनौर) : मैं आप के माध्यम से सब से पहले अपने गृह मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति और आदिम जातियों की दशा का अन्वेषण करने के लिए कोई आयोग बैठाने जा रहें है । उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं । लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात आप से जरूर निवेदन करना चाहूंगा । मैं राज्य मंत्री जी के द्वारा अपनी भावनाएं गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा कि यह आयोग इसी प्रकार का न हो जैसा कि पुलिस आयोग बैठाया गया ।

वे प्रशासक जो अंग्रेजी शासन के प्रशासक थें, जो गोलियां और डंडें चलाना जानते हैं, जिन्होंने गोलियां चलाकर जनता पर राज किया उनको यदि आप पुलिस कमीशन में बैठायेंगे तो क्या वे उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकगे ? मुझे उसमें पूरा सन्देह है । जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके प्रति पूरा

सम्मान प्रदर्शित करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जजेज के सामने जो फाइल आती है उसी के आधार पर वे अपना फैसला देते हैं । यदि हम यह उम्मीद करें कि जज साहब कमीशन में बैठ कर हमारी जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे तो मुझे इसमें सन्देह है । जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व जनसेवी ही करेंगे जिन जन-सेवियों को आयोग में मौका नहीं मिला है । इसलिए मैं समझता हूं जिस बात को दृष्टि में रखकर यह आयोग बिठाये जा रहे हैं उसकी पूर्ति संदेहास्पद रहेंगी । मैं गृह राज्य मंत्री के माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों एवं जन जातियों के लिए जो कमीशन बिठाया जाये उसकी अध्यक्षता काका कालेलकर जैसे समाजसेवी, गांधियन थ्यूरी में विश्वास रखने वाले किसी नेता को सौंपी जाये । इसके अतिरिक्त इस सदन, उस सदन तथा सदन के बाहर के समाजसेवी जिनकी गांधियन विचारधारा रही है, जो वर्गविहीन समाज में विश्वास करते हैं, उनको आयोग का सदस्य बनाया जाये । यह सिश्वास करना कि रिटायर्ड जज साहब हरिजनों का बहुत बड़ा हित करेंग, मुझे इसमें सन्देह है । उन्होंने तो जीवन भर फाइलों के शब्द लेकर, गवाही देखकर फाइलों के आधार पर फैसले दिए हैं । उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है । उनसे हम यह उम्मीद करें कि वे दुखी पीड़ित जनता जो तीस साल की स्वतंत्रता के बाद भी दासता का जीवन बिता रही है उसको दूर करने के लिए कोई ठोस सुझाव दे सकेंगे मुझे इसमें सन्देह हैं । मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मेरी यह भावनायें गृह मन्त्री जी तक पहुंचा दी जायें ।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की जिस रिपोर्ट पर बहस हो रही है वह 1971 से लेकर आजतक सदन के सामने नहीं आई । मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वही रफ्तार बेढ़ंगी जो पहले से चली आ रही है उसी रास्ते पर हम भी चलते रहें तो वह समस्यायें जिनको हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं और जो हमारे समाज पर एक कलंक है उसको हम कभी भी धो नहीं पायेंगें । इसलिए आपको पुराना तरीका और पुरानी रफ्तार बदलनी होगी । जिस ढंग से अभी तक हरिजनों की सेवा हुई है उसको बदलने के लिए जरूरी है कि या तो आप आयोग को बिल्कुल समाप्त ही कर दें और यदि समाप्त नहीं करना चाहते तो फिर जैसी जन प्रतिनिधियों की मांग है, आयोग को कुछ अधिकार दिये जायें । उसकी सिफारिशों पर किसी को दण्डित किया जा सकेगा या किसी को इनाम दिया जा सकेगा—यह शक्ति उसमें आज तक नहीं आई हैं । यदि आगे भी आपने ऐसे ही रखा तो एक कहावत है—दिखाने का तीहल बनकर रह गया है । कमिश्नर की पोस्ट जिसपर इतना रुपया खर्च हो रहा हो वह अगर बिल्कुल यूजलेस रहे तो मैं समझता हूं यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा ।

तीसरी बात यह है कि अब तक की रिपोर्टों में जो संस्तुतियां आई हैं, कृपा करके आप उनका संकलन करा लीजिए और उसके बाद विचार कीजिए कि उनमें से कितनी संस्तुतियां ऐसी है जिनको शासन ने कार्य रूप में परिणत किया है और कितनी संस्तुतियां अभी तक ऐसी शेष हैं जिनपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उसके लिये समय-बद्ध कार्यक्रम बनाइये, टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम को ले कर चलिये । हमें यह समस्या ज्यादा दिनों तक अपने समाज में कायम नहीं रखनी है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुझे दुख होता है—मैं आप को बता नहीं सकता कि मेरे हृदय की क्या गति होती है—जब मैं रिजर्व्ड सीट से चुन कर आता हूं । मैं नहीं चाहता हूं कि मैं रिजर्व्ड सीट से चुन कर आऊं, लेकिन राष्ट्र की इन परिस्थितियों के साथ मुझे

[श्री मही लाल]

अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है । मैं उन विचारों का हूं कि जितनी जल्द सम्भव हो सके, हमें अपने इस समाज के इस कलंक को धोना चाहिये । इस कलंक को धोने के लिये हम ने गांधी जी की समाधि पर शपथ ली है । गांधी जी ने हरिजन समस्या के सम्बन्ध में स्पष्ट किया था, उन का लेख मौजूद है, जो अपने को स्वर्ण कहते हैं, जो साधन-सम्पन्न हैं, व अपने परिवार में एक हरिजन बालक को रख कर अपने बच्चों की तरह उस को शिक्षा-दीक्षा दिलायें । मैं दूसरी तरफ़ की बात भी कहता हूं—जो हम में सम्पन्न और समर्थ है उन को सवर्ण वर्ग के निर्धन से निर्धन बालक को अपने परिवार में रख कर शिक्षा-दीक्षा दिलानी चाहिये । तब हम एक नया समाज बना सकेंगे और समाज के बीच में जो घृणा का वातावरण है, उस को मिटा सकेंगे, दूर कर सकेंगे । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है—सुबह से शाम तक हम गांधी जी का नाम लेते हुए नहीं थकते, जब बोलते नहीं थकते, वर्तमान शासन तो बिलकुल गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है—जब यह गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है तो आप मेरी इस भावना को गृह मंत्री जी तक पहुंचा दीजिये कि हमारे नेताओं को कम-से-कम एक हरिजन बच्चे को अपने परिवार में रख कर शिक्षा-दीक्षा दिलानी चाहिये ।

श्री धनिक लाल मंडल : आप स्वयं भी इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से मिल सकते हैं ।

श्री मही लाल : लेकिन इस समय तो आप उन का और पूरे शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । वे यदि यहां होते तो मैं उन से भी इन्हीं शब्दों में निवेदन करता ।

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) : हरिजन नाम को ही खत्म कर दो । जब तक हरिजन नाम रहगा, तब तक जाति चलती रहगी ।

श्री मही लाल : मैं आप की बात पर भी आता हूं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दोनों सदनों की मूल्यांकन समिति जल्द से जल्द बैठाइये जो यह देखे कि आज क्या स्थिति हैं और अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर दे । अब तक कितना कार्य हो चुका है, कितना शेष है और जो शेष है उस को हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं । यह मूल्यांकन समति, दोनों सदनों के जनप्रतिनिधियों को अविलम्ब बैठाने की कृपा करें ।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के नाम पर अनुसूचित जातियां और जन-जातियों के लिये बहुत से कानून बना दिये गये हैं । इन कानूनों से अल्मारियां भरी पड़ी हैं । अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, दो-तीन बार उस में संशोधन हुए, लेकिन आज भी हरिजन मन्दिर में नहीं चढ़ सकता है, आज भी उस के लिये देव-स्थान बन्द है । तो इन कानूनों के बनाने से, आदेशों के निकालने से यह काम पूरा होने वाला नहीं है । आप की वर्तमान सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि जहां-कहीं भी कोई अत्याचार या उत्पीड़न होगा, वहां के ज़िला अधिकारी और पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे । क्या भारतवर्ष में किसी कलैक्टर या एस०पी० को आप के इस वर्तमान शासन ने कोई सज़ा दी ? नहीं दी होगी । आप एक और उदाहरण देखिये—देश की सभी सरकारों को बारबार यह आदेश दिया गया कि जो रिज़र्वेशन की उपेक्षा करेगा, उस अधिकारी को ब्लैक-एन्ट्री दी जायगी । लेकिन मैं समझता हूं आज तक शायद ही किसी को भूल से भी

बैंड-एन्ट्री मिली होगी । आज तक न किसी अधिकारी को बैंड-एन्ट्री मिली, न सज़ा मिली और न ही पदोन्नति की गई । तब फिर इस तरह के कानून बनाने से, गज़ट करने से, कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

कल, अधिष्ठाता महोदय, मेरे ज़िला मुरादाबाद का पी०ए०सी० का एक कांस्टेबिल मेरे पास रोता हुआ आया । उसने अपने अफ़सर का हुक्म मानने से इन्कार कर दिया था कि वह घर के बर्तन नहीं मांजेगा, कपड़े नहीं धोयेगा । उसको मुअत्तिल कर दिया गया । मैंने उसे डी०आई०जी० के पास भेजा, डी०आई०जी० बजाये इसके कि उसके साथ कोई न्याय करता, उसने कमरा बन्द करके उससे इस्तीफ़ा लिखा लिया । वह रोता हुआ मेरे पास आया । मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं । एक घटना गत वर्ष की मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज की है, जहां पर जाति के नाम पर दो सब-इंस्पैक्टरों में झगड़ा होता है । झगड़ा होने पर शेड्यूल्ड कास्ट का सब-इंस्पैक्टर जब बराबर में जवाब देता है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के सब-इंस्पैक्टर को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उसे ट्रेनिंग कालेज से निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और उस सब-इंस्पैक्टर के खिलाफ़ जिसने जातीयता के नाम पर गाली दी थी, कोई कार्यवाही नहीं की गई । शेड्यूल्ड कास्ट का सब-इंस्पैक्टर आई०जी० और पुलिस मिनिस्टर के पास बराबर रोता रहा । मेरा विश्वास यह है कि जब तक आर्थिक विषमता नहीं मिटेगी, जब तक भूमि का बटवारा नहीं होगा, तब तक इस वर्ग का उत्पीड़न बराबर होता रहेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक ब्राह्मण ग़रीब होगा और दूसरी जाति के लोग समृद्ध, धनवान और भूमिपति होंगे चाहे वह शेड्यूल्ड कास्ट के ही क्यों न हों, वह उस ग़रीब ब्राह्मण को दबा लेगा । आज यह प्रश्न विवादास्पद नहीं रह गया है कि भूमि किसी की बपौती नहीं है । भूमि ईश्वर की देन है और ईश्वर की देन पर हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है लेकिन आज जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, वे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, आज वे उन लोगों को ज़िन्दा जला रहे हैं, उन लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और उनकी बहू-बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि आपकी पार्टी का, सरकार का यह फैसला होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी सम्भव हो सके, भूमि जोतने वालों के हाथों में दी जाए । जो भूमि पर काम करेगा, वही किसान है । बिरला, टाटा आदि किसान नहीं हैं और यहां तक कि मैं और श्री बलबीर सिंह भी नहीं हैं क्योंकि हम दोनों हल नहीं चलाते हैं ।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : आप नहीं चलाते होंगे । मै तो हल चलाता हूं ।

श्री मही लाल : ज़मीन का मालिक मैं भी हूं । हम हरिजनों के पास भी ज़मीन है और हम इसके बारे में जानते हैं ।

मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि बंगाल और केरल को छोड़ कर भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है । उत्तर प्रदेश ने भूमि व्यवस्था के बारे में कानून बनाए हैं जबकि हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में इतने प्रगतिशील अधिनियम नहीं बने हैं जैसे उत्तर प्रदेश में बने हैं । उन अधिनियमों को बनाने का बहुत बड़ा श्रेय हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी को जाता है जो वहां के माल मंत्री रहे हैं । सबसे पहले उन्होंने वहां पर 30 एकड़ की ज़मीन की सीलिंग रखी थी और उसके बाद उसको साढ़े बारह एकड़ कर दिया । कंसोलीडेशन्स आफ होल्डिंग्स के बारे में मेरा बराबर उनका साथ सन् 1952 से रहा है और

[श्री मही लाल]

भूमि के अधिनियम बनाने में बराबर उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है। मैं उनके साथ उनके सहायक के रूप में रहा हूं। चकबन्दी में उन्होंने यह व्यवस्था कर दी थी कि जब किसी गांव की चकबन्दी हो, तो हरिजनों की आबादी के लिए, विशेषरूप से उनकी आबादी के लिए जमीन वहां पर छोड़ी जाएगी और उत्तर प्रदेश में चकबन्दी के अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि छोटे किसान को गांव के पास ही जमीन दी जाएगी लेकिन चाहे आप जितने अच्छे कानून बना दें जब तक उन पर अमल नहीं होगा, तब तक हालत सुधर नहीं सकती है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामलाल राही शिकायत कर रहे थे कि छोटे किसानों को गांव से दूर जमीन दी जा रही है। यह व्यवस्था अधिनियमों में है कि छोटे किसानों को गांव के करीब जमीन दी जाए और हरिजनों की आबादी के लिए जमीन छोड़ी जाए लेकिन उनके लिए जमीन नहीं छोड़ी जाती और छोटे किसानों को गांव के पास जमीन नहीं दी जाती। इस तरह से कानून, अधिनियम और सरकार के आदेश निरर्थक न हो जाएं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आगे आप नए कानून बनाएं बल्कि जो आदेश और कानून बने हुए हैं, उनको मूर्तरूप दिया जाए और ठीक तरह से प्रैक्टिस में लाया जाए।

अब मैं नौकरियों में आरक्षण की बात कहता हूं। वह मैं जब कहता हूं कि मुझे चिराग तले ही अंधेरा दिखायी देता है। शायद नौकरियों में लोक सभा सचिवालय में ही आरक्षण पूरा नहीं होगा, और किसी को बात क्या कहूं। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात तो दूर रही, केन्द्रीय सरकार के विभागों में, उसको वित्त पोषित संस्थाओं में आरक्षण पूरा नहीं है। इन अर्धपोषित संस्थाओं की बात तो छोड़िए शासन के अपने विभागों में रिजर्वेशन पूरा नहीं है। यह आपको देखना होगा। माननीय राज्य मंत्री जी यह हरिजनों का मामला है, यह आपको देखना होगा कि यह सब विभागों में पूरा है, सब संस्थाओं में पूरा है या नहीं। और अगर नहीं है तो पूरा क्यों नहीं हुआ है?

यह कहे बिना मुझसे नहीं रहा जाएगा कि कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन का कानून पास किया। हमारे बड़े भाई श्री राममूर्तिजी थे इनसे सीनियर नेताओं ने कांग्रेस के कानून बनाने से पहले ही किसानों से मालगुजारी लेना बंद कर दिया। हमारे उन्नाव जिले के माननीय विश्वंभर दयाल त्रिपाठी और खुशवक्त राय ऐसी विभूतियां थीं जिन्होंने कांग्रेस के कानून पास करते ही किसानों से लगान लेना बन्द कर दिया। वहां हमारे कांग्रेस के ऐसे भी साथी थे जिन्होंने यह देखा कि सीलिंग का कानून पास हो गया है और सीलिंग में जमीन निकलने जा रही है तो हाई कोर्ट में जा कर उसके खिलाफ स्टे आर्डर ले आए और स्टे ले कर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं।

बहुगुणाजी ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री में यह तय किया कि गांव समाज की आठ फीसदी से कम जमीन भी अगर छूटी हुई है तो वह खेत मजदूरों को दे दी जाए। लेकिन जैसे ही श्री नारायण दत्त तिवारीजी चीफ मिनिस्टर बन कर आए, तो उन्होंने उस समय को प्रधान मंत्रीजी के इशारे पर यह फैसला कर दिया कि अब गांव समाज की जमीन

बांटी ही नहीं जाएगी। आठ फीसदी, पांच फीसदी या दो फीसदी की बात तो अलग है। चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए कानूनों पर बहुगुणाजी ने अमल करना शुरू किया और कहा कि बेनामी खातों को मौके पर जा कर चेक करो, यदि कोई जमीन किसी के एक्चुअल पोजेशन में नहीं है। तो वह जमीन उसके नाम दिखा दी जाय जो कि उसे जोत रहा है। लेकिन इंदिराजी के लाडले नारायण दत्त तिवारीजी ने जो पहला काम किया वह यह था कि जो भी प्रगतिशील नीतियां थीं उन सबको खत्म कर दिया। जो जमीन सीलिंग में से निकल गयी थी उसको उन्होंने बंटने से रोक दिया।

माननीय मंत्री जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि भू-क्रांति किए बिना, जमीन जोतने वाले को मालिक बनाए बिना आप इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। क्योंकि बहुसंख्यक हरिजन देहातों में रहते हैं और देहातों के लोगों का काम खेती करना है। वे खेती पर निर्भर करते हैं। चाहे भाई राममूर्ति जी की जमीन हो, चाहे भाई उग्रसेन जो की जमीन हो, उनकी जमीन का मालिक आप उस जमीन के जोतने वाले को बना दीजिए; इस समस्या का हल स्वतः होता चला जाएगा।

रेलवे मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं। पता नहीं रेलवे राज्य मंत्री मेरी बात उन तक पहुंचा पायेंगे या नहीं। मैं रेलवे मिनिस्टर साहब श्री मधु दण्डवतेजी को बड़ा प्रगतिशील मानता हूं। लेकिन जो केन्टीनों के ठेके पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दिए जा रहे थे, उनके रहते हुए अब हरिजनों से वे दुकानें छीनी जा रही हैं और वे दुकानें स्वर्ण जाति के लोगों को दी जा रही हैं, वे ठेके उन लोगों को दिए जा रहे हैं।

अनुदानों का जो रुपया भारत सरकार राज्य सरकारों को देती है उस रुपए में से बीस प्रतिशत रुपए का भी सदुपयोग नहीं हुआ है और इस तरफ आपका खास ध्यान जाना चाहिए। जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम में वह खर्च होना चाहिए। वह लैप्स भी नहीं होना चाहिए। शासन का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है। हरिजनों के लिए जो रुपया जिला परिषद् के पास गया मैंने देखा है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष ने मिर्जापुर में श्री रूप नाथजी ने उस रुपए से अपने फार्म में क्वार्टर बना लिए और वहां ट्यूबवेल बनवा लिया। भिन्न-भिन्न प्रकार से उस रुपए का दुरूपयोग होता है। आप स्टेट गवर्नमैंट्स पर पाबन्दी लगाएं, चैक लगाएं, प्रजातंत्र बिना चैक्स और बैलैंसिस के कामयाब नहीं हो सकता है और अगर आप चैक नहीं लगाएंगें और राज्य सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ देंगे तो फिर आप समझें कि स्टेट गवर्नमेंट्स में मंत्री लोग सब दूध के धुले हुए नहीं हैं, पैसे का दुरूपयोग होगा।

सभापति महोदय, मुरादाबाद और बिजनौर का मुझे निजी अनुभव है। हरिजनों को वहां पर जो जमीन के पट्टे दिए गए थे वे सैंकड़ों की तादाद में नहीं हजारों की तादाद में खारिज हो रहे हैं। एक-एक हरिजन पर जिसको पट्टा मिला है दस-दस मुकदमे बनाए जा रहे हैं। डी० एम० और एस० पी० हमारे एम० एल० एज और मिनिस्टर के डर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे है और जो थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं और कोशिश करते है तो उनका स्थान जिले में न हो कर सचिवालय में होता है, उनको वहां बुला लिया जाता है, उनको वहां जगह दे दी जाती हैं। वे जिले में नहीं रह सकते हैं।

[श्री मही लाल]

मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं इनकी तरफ भी आपका ध्यान जाए।

वर्तमान शासन की नीयत पर मुझे सन्देह नहीं है। गृह मंत्रीजी को मैंने बहुत निकट से देखा है और बहुत निकट से मैं उनको जानता हूं। गरीबों के लिए वह रो भी पड़ते हैं, आंसू भी उनके निकल जाते हैं। सही मानों में अगर आपको गरीबों की सेवा करनी है तो जो रुपया आपको मिलता है उस रुपए को खर्च करने का तरीका आपको बिल्कुल बदलना होगा, पैटर्न को आपको चेंज करना होगा, छोटे-छोटे उद्योग आपको देहातों में लगाने होंगे। हरिजनों को डेरी के वास्ते जमीन मिलनी चाहिए, रहट और कुओं के लिए कर्जे मिलने चाहिएं। एक हजार रुपया मकान बनाने के लिए आप देते हैं, ढाई सौ रुपया भैड़ा पालने के लिए देते हैं लेकिन आप क्या जानते है कि जो हजार रुपया उनको मिलता है उसके बदले उन बेचारों का डेढ़ हजार खर्च हो जाता है? नीचे से ऊपर न मालूम कितने लोगों को उनको रिश्वत देनी पड़ती है। समाज का पूरे का पूरा ताना बाना बिखरा हुआ है। वे पूरे के पूरे भिखारी बना दिए गए हैं। उन दोस्तों को जिनको मैं अभी छोड़ कर आया हूं, उनके वास्ते लड़ते-लड़ते मैं हार गया हूं और मैं अपनी हार मानता हूं, अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं कामयाब नहीं हो पाया इसको मैं मानता हूं। मैं मजबूर हो गया था हार मानने को इंदिराजी के बाद संजय गांधी नजर आने लग गए थे।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पार्लियामैंट के मैम्बरों की एक कमेटी बनाएं जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उन पर विचार करे। साथ ही साथ जो रुपया प्रान्तों में जाता है वह उन कामों पर खर्च हो जिन कामों के लिए वह दिया जाता है। इसको देखने की भी आप कृपा करें और यह कमेटी उसको भी देख सकती है।

नव बौद्धों की मागों पर भी आपको विचार करना चाहिए। उनकी रिश्तेदारियां, नातेदारियां बेटी, बेटा सब हमारे साथ ब्याहे जाते हैं। वे अलग नहीं हैं। उनको अनुसूचित जातियों में आपको शामिल करना चाहिए और उनको भी वही अधिकार आपको देने चाहिएं। वे कोई दूसरे नहीं है। ऐसा करके आप उन पर कोई दया नही करेंगे। यह उनका राइट है, हक है। जो हरिजन पढ़-लिख गए थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, धर्म परिवर्तन किया हैं, वर्ण व्यवस्था से तंग आकर किया हैं। जातपांत के नाम पर जो अन्याय हों रहा हैं उससे तंग आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। लेकिन वे हमसे अलग नहीं हैं। उनकी मांग को आप स्वीकार कर लें और जितनी जल्दी आप कर लें उतना ही अच्छा होगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा जो शोषण का एक बड़ा भारी साधन है इसको भी आप समाप्त करें।

लोकबाडीज, नगर पालिकायें महापालिकायें जो व्यापारिक संस्थाऐं

बना रही है, दुकानें बना रही है या और काम कर रही है, मेहरबानी करके आप नीति बना दें कि उनमें भी हरिजनों को उनकी संख्या के अनुपात में दुकान और मकान आदि दिए जाएंगें।

अपने उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, बिहार के मंत्री जी, आप जानते होंगे कि पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आयोग में जनसेवी लोग होंगे। मैं एक उदाहरण सुना दूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के पुलिस कमीशन का मेम्बर रहने का जिसमें आई० ए० एस० आई०पी०एस० और, रिटायर्ड जजेज सदस्य थे मैंने 1958–59 में यह कहा कि महिला पुलिस की व्यवस्था कीजिए। मेरा अकेला नोट आफ सिसेंट था, लेकिन मेरी बात को कमीशन में किसी ने नहीं माना। लेकिन मेरे कहने के पांच साल बाद महिला पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी उत्तर प्रदेश में, और आज महिलायें कांस्टेबिल, दरोगा, डी० एस० पी०, एस० पी० के पदों पर काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अधिकारियों का ऐसा दृष्टिकोण होता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI K. PRADHANI (Nowrangpur): Mr. Chairman, Sir, before I speak on this Commissioner's Report, I would like to speak something about my substitute motion which stands against my name under serial No. 1. There is a Scheduled Tribe in the districts of Kalahandi and Koraput of Orissa State, it is enlisted in the Schedule Tribe Order under Serial No. 5 and that tribe is known as 'Bhattara' in the two districts of Kalahandi and Koraput. According to the Schedule Order, there is no area restriction in this State and the scheduled tribes mentioned in that list are meant for the whole State. In the year 1976, we passed a Bill known as the Area Restriction Removal Bill. Accordingly all area restrictions within the States were removed. There is also a judgement of the Supreme Court regarding the spelling variation between the name of the scheduled tribe community mentioned in the List and in the names held by the persons belonging to the schedule tribe community. For instance, the name of the scheduled tribe community 'Bhattara' is mentioned in the List as 'Bhatara'. Therefore, such spelling mistakes should be condoned and they should be accepted. The Supreme Court judgement also said that this kind of anomaly should not be viewed seriously. Sir, I have also written a letter to the Home Minister on 15th July 1977 requesting him to consider this and extend all the privileges to the scheduled tribes of Kalahandi district. The privileges that are allowed to this scheduled tribe residing in the other district of Koraput are not being allowed to the scheduled tribes of Kalahandi district for the last 20 years.

Then, Sir, I come to the reservaion of posts to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the Commissioner's report of 1973-74, I find that in Clauses 1, 2, 3 and 4, the percentage of scheduled castes employed is 3.58, 4.85, 10.34 and 17.86 respectively. The figures for the Schedule Tribes are, respectively, 0.65, 0.50, 2.35 and 4.25 per cent. This is with regard to the Central Services upto 1-1-1974. The reservation for the Scheduled Castes is 15 per cent, for the Scheduled Tribes it is 7.5 per cent. But the figures I quoted show how meagre the actuality is and how the backlog is more than expected, especially for the Scheduled Tribes, which is so negligible. That it is regrettable to say in this House. Even in respect of class III and IV services as against 7.5 per cent we have only 2.35 per cent in class III and 4.25 per cent in class IV. The appointing authorities generally say that candidates are not available with them and the vacancies are sometimes dereserved and they are given to the other people. In Delhi when they call people for interview for class III

[Shri K. Pradhani]

or class IV posts, they say that no Scheduled Tribe candidate is available. I submit there are no Schedule Tribes in Delhi, Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Schedule Tribe people are there in Orissa Madhya Pradesh, Gujarat and Assam....(An Hon. Member.....West Bengal). So, when there is an advertisement in Delhi for some posts reserved for Scheduled Tribes, they cannot expect people to come from Assam or Orissa to work as clerks or peons. So automatically all these posts get dereserved. That is why I suggest that there should be regional reservation. For instance, in Orissa the Scheduled Tribes constitute 24 per cent and the Scheduled Castes 15 per cent. There may not be much difficulty for Scheduled Castes getting their quota filled in respect of class III and IV posts because they are there all over the country. But it is not so with regard to Scheduled Tribes and so regional reservation will have to be there. Therefore, I ask the hon. Minister to adopt a new policy of regional reservation for class III and IV posts.

Regarding class I and II posts they say that suitable candidates do not come for interview. Article 335 says that the claims of members of the Scheduled Castes and Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration.

Article 16(4) of the Constitution contains the provision about reservation but article 335 takes away almost all the privileges given in that article. Taking advantage of the words 'consistently with the maintenance of efficiency of administration', the appointing authorities take the plea that those people who appear for interview are not competent to fill class I or II posts. Even if they may be first class MAs, they are rejected as unfit for that job Government has clarified in the standing orders that this phrase 'consistently with efficiency' means that they would be given relaxation to an extent of 5 marks. It is not a reservation but only a simple concession. Unless the Government gives more concessions and accepts all the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who have passed the degree examination or post-graduate examination, the reserved vacancies in class I and II are not going to be filled up. Therefore, I would like to urge the Minister to give some more concessions to remove the back-log.

Then I come to Tribal development. The latest strategy of the Government of India with regard to Tribal Development, is to eliminate exploitation and to gear up economic development. In pursuance of this, the Government of India have taken steps to stop the exploitation of the tribal people. They have taken several steps to stop money-lending and liquor vending etc.

श्री छबिराम अंगल (मुरैना) : सभापति महोदय, बड़े जोर शोर से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को इतना भी ख्याल नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर चर्चा चल रही है, वे यहां मौजूद रहें। उनकी सारी बेंचेज खाली हैं।

SHRI K. PRADHANI: Integrated Tribal Development Projects have been started to eliminate exploitation and to accelerate economic development. Large scale multipurpose co-operative Societies have been started to provide necessary financial assistance to the tribal people, and to help them in marketing their agricultural produce. In Tribal areas, the money-lenders and businessmen take the utmost advantage in exploiting the tribal people. That is the reason why, the Government was pleased to put an end to this exploitation.

I would like to read a letter which was written by Shri C. P. Majhi, a Deputy Minister for Petroleum and Chemicals, very recently on 14th September, 1976. He has stated:

> "While coming from Koraput to Vizag on the morning of 6th September, I happened to pass through a weekly market at a place caled Railgada....As the tribal farmer is not

capable of expressing himself properly and is also not knowing the actual price of his produce, the purchaser who is invariably a man from outside, takes advantage of his ignorance and cheats the tribal. The tribal is also incapable of defending himself when his stock is forcibly taken by the purchaser, putting whether amount he pleases into the hands of the tribal. I saw myself a man forcibly taking away about 3 Kilos of ginger from a tribal, putting only three one rupee notes in his hand. Thus the tribal becomes helpless and is not capable of protecting himself."

This letter was addressed to Shri Rama Chandra Ulaka, Minister of Tribal and Rural Welfare, Government of Orissa. I would urge the Minister to gear up all the institutions started under the Integrated Tribal Development Programme to minimise the exploitation of the tribal people.

Lastly, there are Project Directors appointed as the Heads of the integrated Tribal Development Projects. I come from a place where there is a Tribal Development Project for a subdivisions, which is known as Nowrangpur. It has got ten ITDP blocks. There is a Project Director who is of the rank of an Additional District Magistrate. According to the latest policy decided by the Government of India, the law and order situation should be under the direct control of the project administrator and he should be the administrative authority of that project area. But I am sorry to say that this practice is not being followed. The A.D.M. who has been posted as the ITDP officer has a very small room in a very small office in a corner of the town. He is quite aloof from the administrative authorities. The S.D.O. is different. The Collector is somewhere else. He is only entrusted with the development work. He has no jeep. Whenever he wants to go on tour he has to approach somebody else for a jeep for carrying on the ITDP propaganda work. The integrated tribal development project, which has been conceived recently as the new pattern of administration, will not succeed unless both law and order and development are linked together. At present, the tehsildar and revenue officers are separately appointed and these people are only meant for development projects. These should be linked together. So, I request the hon. Minister to pass necessary orders to the State Government of Orissa to revise this pattern of administration.

फादर एन्थनी मुरमू (राजमहल) : सभापति महोदय, यह जो कमिश्नर की रिपोर्ट है, अनुसूचित जाति और जन जाति के सम्बन्ध में, हम जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसको पढ़ने से तो बहुत अच्छा लगता हैं लेकिन जहां तक उसको कार्यान्वित करने का सवाल है उसमें यह टोटल फेल्योर है । जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं जो कि मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र है तो हम देखते हैं कि वहां पर कितनी असमानता और गरीबी है । तीस वर्षों की आजादी के बाद भी हम देखते हैं कि हमारी हरिजन और आदिवासी जातियों के के साथ अन्याय हो रहा है । उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं । उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं दी जा रही है । उनके स्वास्थ्य के लिए जो अस्पताल खुलने चाहिएं वह नहीं खोले जा रहे हैं । उनके क्षेत्र में आवागमन के कोई साधन नहीं हैं । इस प्रकार हर क्षेत्र में वे पिछड़े हुए हैं ।

इस बार जब हम अपनी कांस्टीट्यून्सी का दौरा कर रहे थे तो देखा कि मकई न होने के कारण वहां बिल्कुल भुखमरी की हालत थी (यहां पर हमने सरकार से राहत के लिए प्रार्थना की तो वह भी समय पर नहीं पहुंची । इसका नतीजा यह हुआ कि जो महाजन लोग हैं उन्होंनें गरीब आदिवासी लोगों के बर्तन ले लिए, महिलाओं के जेवर ले लिए, उनके पास जो बैल थे वह भी ले लिए । जब सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको खेती के लिए बैल चाहिए तो ब्लाक के बी डी ओ

[फादर एन्थनी मुरमु]

बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से जो हम एक विशस सर्किल में पड़ गए हैं उसका समाधान होना चाहिए। इसलिये मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि हमारे लोगों को न्याय मिले, जो खेती करने योग्य हैं उन को अपनी उपज का उचित दाम मिले और जो मजदूरी करते हैं उन को सरकारी नियम के अनुसार मजदूरी मिले। तब बहुत अंशों में यह गरीबी, दरिद्रता, दूर होगी। समय समय पर हम देखते हैं कि महाजन और आदिवासियों में मुठभेड़ हो जाती है। जमीन आदिवासी की है, लेकिन जोत रहे हैं–महाजन लोग और इस मुठभेड़ में गोली भी चल जाती है। हमारे लोगों के पास चूंकि बन्दूक नहीं हैं, इसलिए मारे जाते हैं। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि मंडल बेसरा सन्थाल पीरपैंती थाथ-ग्राम बारभसिया का इस तरह की मुठभेड़ में मारा गय। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन महाजन लोगों के पास जो आदिवासियों की जमीन जोतते हैं, बन्दूक न रहने दी जाये। बन्दूक न रहने से वे गोलियां नहीं चला सकेंगे।

सिचांई की व्यवस्था होनी चाहिए

हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की योजनायें हैं, लेकिन इस काम के लिए जो जमीन ली जाती है—कैनाल बनाने के लिए, उस जमीन की कीमत समय पर उन लोगों को नहीं मिल पाती है। यह आप के लैंक एक्वीज़ीशन डिपार्टमेण्ट की कमी है जो समय पर उन को यथार्थ रूप में जमीन की कीमत नहीं देते हैं। इस से पब्लिक ओपीनियन खराब हो जाती है और जो सचमुच अच्छी योजनायें भी हैं उन में लोग सहयोग नहीं करते हैं।

इसके बाद मैं कुछ रीजनल भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आदिवासी भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कचहरियों में भी आदिवासी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। सतांली भाषा का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग कानून को दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो अफसर लोग हमारे आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, उन को वहीं की आदिवासी भाषा को सीखना चाहिए ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सके।

इस के साथ-साथ प्राइमरी लेबल से कालिज लेबल तक हमारे बच्चों को आदिवासी संताली भाषा की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस भाषा को बोलने वाले 60–70 लाख लोग हैं। हमारे बच्चे जो कमिशन स्कूलों में पढ़ते हैं वहां तो टाप करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण नहीं होते हैं। इस का कारण है—अवहेलना। आदिवासियों को हर समय सौतेला व्यवहार मिलता है—राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तथा आर्थिक दृष्टि से उन को जितना उठना चाहिए, उतना उठ नहीं पाते हैं। लेकिन यदि उस के साथ सच्चे रूप में व्यवहार हो तो वह अवश्य ऊपर उठ सकता है।

यह जो रिपोर्ट हम को मिली है—इससे भी आप को पता चलेगा—जहां तक एमप्लायमेण्ट का सवाल है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे हैं। शिक्षा के मामले में तो अभी तक 10 फीसदी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में हम लोग बहुत से डिपार्टमेण्ट्स में एक प्रतिशत भी नहीं हैं। तो यह बहुत अफ़सोस की बात है और लज्जा की बात है कि हमारे स्वतन्त्र भारत में यह असमानता अभी तक है। इस को दूर करना ही चाहिए और जब तक हम मानवता की भावना को लेकर आग नहीं

बढ़ेंगे तब तक हमारे देश में करोड़ों लोगों की हालत ऐसी ही रहेगी और वे दबाए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं वे भी मानव हैं और उन को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए मानवता की भावना को लेकर चलना चाहिए। मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि संसद् सदस्यों को हर सुविधा मिलनी चाहिए जिस से वे अपने क्षेत्रों में घूम सकें और इस कारण मिनिस्टरों और संसद् सदस्य में बहुत कम रहना चाहिए क्योंकि एक संसद् सदस्य को 10 लाख या 12 लाख आदमियों को देखना पड़ता है और उसकी पार्लियामेंटरी कास्टीटुयेन्सी एक हजार वर्ग मील की हैं और कहीं कहीं पर डेढ़ हजार और दो हजार वर्ग मील भी है। इसलिए उस के पास कन्वीयेन्स का होना बहुत जरूरी है और तभी यह सही रूप से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वह मानव की सेवा करें तो उसको सब तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ़ से उस के लिए एक क्लर्क की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ एक ड्राइवर भी होना चाहिए और पोस्टेज उसे फ्री मिलनी चाहिए। 10 लाख लोगों की जो तकलीफें होंगी, उन की दरिद्रता को दूर करने के लिए उसे हर ब्लाक और हर क्षेत्र में जाना पड़ेगा। इस के अलावा जो इर्रीगेशन आदि की योजना वहां पर चलेंगी, उन पर सही रूप से चैक रखने के लिए इन सुविधाओं की उस को बहुत जरूरत है अगर वह अपना चैक नहीं रखेगा, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और ब्योरोक्रेसी के भरोसे हम देश में सुधार नहीं ला सकते हैं। इन बातों पर आप को ध्यान देना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि संसद् सदस्यों को आप पूरी सुविधाएं देंगे क्योंकि संसद् सदस्यों के प्रयत्नों से ही हमारे देश में सच्चा सोशलिज्म आएगा।

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, Sir, I am supporting the Motion moved by Prof. Madhu Dandavate about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this Session. One Member from the Janata Party said that only 2 Congress Members are present in the House. I feel the same way about the Janata Party and about Government also. There is no Cabinet Minister present now; and the attendance in the House is only about 37, i.e. not more than 9 per cent This shows that the House and the Members are not showing adequate interest on this Motion. The people of India are watching very closely as to what this Government and this House are going to do for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There may be a false propaganda that the Government is doing much for the SCs and STs. We should do something concrete for the SCs and STs. Merely giving reservation of seats and some jobs to them is not enough.

MR. CHAIRMAN: Mr. Visvanathan will get his chance to continue the speech. The House now stands adjourned.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 18, 1977/Kartika 27, 1899 (Saka)

GMGIPND—PMR—2416 L.S—16-12-77—9,000